चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

मूल्य 5 रुपये

1986 से प्रकाशित | 25 नवंबर– 01 दिसंबर 2013 | Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467

जनता के अधिकार पर क़ब्ज़ा

सभी फोटो– *प्रभात पाण्डेय*

सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद देश की जनता को राइट टू रिजेक्ट यानी मतदान के दौरान नापसंद उम्मीदवारों को नकारने का जो अधिकार मिला है, अब सरकारें उस अधिकार को छीनने पर उतर आई हैं. इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से हो चुकी है. वहां पर चुनाव आयोग ईवीएम मशीन में दिए गए नये विकल्प नन ऑफ द एबव (नोटा) के बारे में लोगों को जागरूक करने की कोशिशों पर लगाम लगाने का प्रयास कर रहा है. प्रदेश के मुलताई विधानसभा क्षेत्र में जनसंसद अभियान समिति के प्रदेश संयोजक डॉ. सुनीलम ने 'नोटा' का प्रचार-प्रसार करने के लिए रिटर्निंग अधिकारी से आवेदन देकर अनुमति मांगी तो रिटर्निंग ऑफिसर ने इसकी अनुमति नहीं दी. क़ायदे से देखा जाए तो यह ज़िम्मेदारी चुनाव आयोग की है कि वह मतदान प्रक्रिया में हुए बदलाव के बारे में मतदाताओं को जागरूक करे, लेकिन चुनाव आयोग ख़ुद तो यह पहल नहीं कर रहा है और जो लोग मतदाताओं को जागरूक करने की कोशिश कर रहें हैं, आयोग उनपर नकेल कस रहा है. यह जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है.

नीरज सिंह

जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर देश की जनता को उम्मीदवारों की नापसंदगी का हक़ मिला तो एकबारगी यह लगा कि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश राजनीतिक दलों को अब संवैधानिक और संसदीय आदर्शों की राह दिखाएगा. साथ ही देश की जनता को भी यह हक़ मिला कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत वह न केवल अपनी पसंद के उम्मीदवार को चुने, बल्कि यह भी ज़ाहिर कर सके कि उसे कोई उम्मीदवार पसंद नहीं है. यह मामला 2001 से ही क़ानून मंत्रालय के पास अटका हुआ था. जब सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे जी ने राइट टू रिजेक्ट और राइट टू रिकॉल को अपने 25 सूत्री कार्यक्रम में शामिल किया तो देश में इस मांग को लेकर एक माहौल बनना शुरू हुआ. सुप्रीम कोर्ट ने जब इस बाबत आदेश दिए, तभी इस बात की आशंका जाहिर की गई थी कि जो पहल सरकार और चुनाव आयोग को करनी चाहिए थी, वह कोर्ट कर रही है, इसलिए सरकार इस दिशा में दमनकारी रवैया अपनाएगी यह तो तय है. और देश की इस आशंका को सबसे पहले सही साबित किया चुनाव आयोग और मध्य प्रदेश सरकार ने.

मध्य प्रदेश में चुनाव आयोग नन ऑफ द एबव (नोटा) के बारे में लोगों को जागरूक करने की कोशिशों पर रोक लगा रहा है और इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश के मुलताई विधानसभा क्षेत्र से हो चुकी है. वहां पर जनसंसद अभियान समिति के प्रदेश संयोजक डॉ. सुनीलम ने 'नोटा' का प्रचार-प्रसार करने के लिए वाहन और सभा के आयोजन के लिए रिटर्निंग अधिकारी को आवेदन देकर अनुमति मांगी थी तो रिटर्निंग ऑफिसर जीआर पटले ने यह कहते हुए नोटा के बारे जागरूकता फैलाने पर रोक लगा दी. रिटर्निंग ऑफिसर ने यह तर्क दिया कि डॉ. सुनीलम उक्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार नहीं है और न ही किसी पार्टी के सदस्य हैं, इसलिए विधान सभा निर्वाचन 2013 की आदर्श आचार संहिता के तहत उन्हें इस प्रकार नोटा के प्रचार की अनुमति नहीं दी जा सकती. वास्तव में रिटर्निंग ऑफिसर का यह क़दम न केवल देश के हर नागरिक को मिली अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन है, बल्कि देश की गौरवशाली लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भी गंभीर चोट है. साथ ही यह रोक एक सवाल भी खड़ा करती है कि देश की जनता को उनके हक़ के प्रति जागरूक करने की ज़िम्मेदारी क्या केवल चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों और पार्टियों के सदस्यों की ही है?

बीते वर्षों में समाज सेवी अन्ना हजारे ने देश को बदलाव की राह पर ले जाने का नेतृत्व करते हुए अन्य सुझावों के साथ-साथ चुनाव सुधारों की भी बात की है. अन्ना हजारे का मानना है कि राजनीति पर अब धनबल और बाहुबल का वर्चस्व है. उनके मुताबिक, चुनाव अब आम चुनाव रह ही नहीं गए हैं क्योंकि उम्मीदवार तो पक्ष और पार्टियों के होते हैं. आम जनता के उम्मीदवार तो होते ही नहीं. इसलिए जनता के सामने यह विकल्प भी रखा जाए कि अगर उसे कोई भी उम्मीदवार नहीं पसंद है तो वह अपनी इस इच्छा को ज़ाहिर कर सके. देशभर में अन्ना हजारे के इस प्रयास को समर्थन मिला. इसलिए जब उम्मीदवारों की नापसंदगी का हक़ जनता को मिला तो जनसंसद अभियान समिति ने अन्ना हजारे जी के नेतृत्व में देशभर भर में मतदाताओं को इस अधिकार के प्रति जागरूक करना शुरू किया. हालांकि यह काम चुनाव आयोग को करना चाहिए था, क्योंकि चुनाव आयोग इस बात का दंभ भरता रहता है कि वह देश भर में मतदाता जागरूकता अभियान के माध्यम से लोगों को वोटिंग के प्रति जागरूक करता है. लेकिन चुनाव आयोग ने अभी देश के किसी हिस्से में इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन में 'इनमें से कोई नहीं ' के विकल्प या जनता को मिले इस अधिकार के बारे में कोई जागरूकता अभियान क्यों नहीं चलाया है? जबकि लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं.

अन्ना हजारे जी ने पिछले दो वर्षों से लगातार चल रही अपनी जनतंत्र यात्रा के दौरान यह महसूस किया कि लोगों में चुनावों और उम्मीदवारों के चयन को लेकर अभी भी जागरूकता की कमी है. इसी गैप को पूरा करने के लिए उनके नेतृत्व में बनी जनसंसद अभियान समिति आगामी पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र लोगों को जागरूक कर रही है, जनसभाएं कर रही है. जिसके माध्यम से लोगों को यह बताया जा रहा है कि उनके मत की क़ीमत क्या होती है. 'नोटा ' के विकल्प के इस्तेमाल के क्या मायने हैं.

यह जागरूकता इसलिए भी ज़रूरी थी, क्योंकि सरकार और चुनाव आयोग इस दिशा में मात्र खानापूर्ति कर रहे हैं. केंद्र सरकार ने अपने चुनावी फ़ायदे के लिए 180 करोड़ रुपये का चुनाव प्रचार बजट तैयार किया. इस बजट से तैयार टीवी-प्रिंट, रेडियो और इंटरनेट पर जारी सरकार के विज्ञापनों में कांग्रेस सरकार ने कौन-कौन सी जनहितकारी योजानाएं लागू कीं, इसका तो उल्लेख है, लेकिन इस बात का उल्लेख एक लाइन में भी नहीं है कि मतदाताओं को नापसंदगी का अधिकार मिल गया है. देश की राजनीति को अवांछित तत्वों से मुक्त करने के लिए इसका उपयोग करें. मध्य प्रदेश सरकार जिसने देश में सबसे पहले इस अधिकार की जागरूकता के लिए रोक लगाई है, उस सरकार के मुख्यमंत्री पर नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने आरोप लगाया है कि पिछले तीन महीने में शिवराज सिंह चौहान अपनी ब्रांडिंग पर तीन सौ करोड़ रुपये ख़र्च कर चुके हैं.

> **जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नन ऑफ द एबव की व्यवस्था बनी, तभी राजनीतिक दलों ने ख़ुद के ऊपर मंडराने वाले इस ख़तरे को नकारात्मक रूप से पेश करना शुरू किया. इसका विरोध करने वालों का तर्क रहा कि भले ही नन ऑफ द एबव की व्यवस्था लागू हो गई है, लेकिन जिसको सबसे ज्यादा मत मिलेगा वो तो विजयी होगा ही, फिर इस व्यवस्था का क्या मतलब. वास्तव में चुनाव सुधार की किसी भी नई व्यवस्था का तुरंत ही असर हुआ हो, ऐसा कभी भी देखने को नहीं मिला है.**

अन्ना हजारे व उनके सहयोगी मतदाताओं को इस दिशा में जागरूक करने के लिए देश के हर हिस्से में महती भूमिका निभा रहे हैं. अन्ना हजारे ने अपनी ओर से चुनाव आयोग को यह भी सुझाव दिया था कि चूंकि पहली बार देश के मतदाता इस अधिकार का प्रयोग करने जा रहे हैं, इसलिए चुनाव आयोग लोगों को बताए कि वह ईवीएम में इसके लिए किस तरह का प्रतीक चिन्ह देने जा रहा है. इस संदर्भ में एक लोगो अन्ना हजारे की ओर से सुझाया भी गया था. लेकिन चुनाव आयोग ने न तो नापसंदगी के अधिकार के बारे में अभी तक कोई अभियान सुझाया, न ही मतदाताओं को इस बात की जानकारी दी जा रही है कि देश की चुनावी व्यवस्था में पहली बार इस तरह का प्रावधान किया गया है.

जनसंसद अभियान समिति के प्रदेश संयोजक डॉ. सुनीलम ने इस संदर्भ में मध्य प्रदेश राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त जयदीप गोविंद को एक पत्र भी लिखा. पत्र में डॉ. सुनीलम ने यह अनुरोध किया कि प्रदेश चुनाव आयोग ने हर पोलिंग बूथ के आस-पास मतदाता जागरूकता अभियान के तहत जो फ्लैक्स लगाए हैं, उसमें 'नोटा ' के विकल्प का उल्लेख करवाने का भी कष्ट करें, क्योंकि वस्तुस्थिति यह है कि अधिकतर मतदाताओं को इस अधिकार की जानकारी ही नहीं है. एक अनुमान के मुताबिक मध्य प्रदेश चुनाव में कुल मिलाकर तकरीबन 2000 करोड़ रुपये ख़र्च होंगे, लेकिन इस पूरे ख़र्च में से एक रुपया भी 'नोटा ' के प्रचार के लिए ख़र्च नहीं हुआ.

हाल ही में चुनाव आयोग ने अपनी पीठ थपथापते हुए कुछ आंकड़े मीडिया के साथ साझा किए थे, जिसमें कहा गया था कि 64 फ़ीसद मतदाता उम्मीदवारों का चयन अपने विवेक से करते हैं. धार्मिक, जातिगत और पारिवारिक दबाव महज 25 फ़ीसद होता है. और तक़रीबन आधे वोटर मतदान केंद्र तक इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्हें अपना अधिकार जताने का मौक़ा मिलता है.

आयोग के मुताबिक, मतदान जागरूकता के लिए अब तक चलाए जा रहे कार्यक्रम में आयोग ने पाया है कि जातिगत आधार पर 10.5 फ़ीसद लोग वोट डालते हैं, जबकि 7.6 फ़ीसद मतदाता उम्मीदवारों के धर्म से प्रभावित होते हैं. अगर चुनाव आयोग के यह आंकड़े सही हैं तो इसी अपने सर्वे के दौरान वह यह भी बताने का कष्ट क्यों नहीं करता कि देश के इतने प्रतिशत मतदाता किसी भी उम्मीदवार को पसंद नहीं करते और नापंसदगी के अधिकार का स्वागत करते हैं? आयोग के ही आंकड़ों की बात करें तो आधे वोटर मतदान केंद्र तक केवल इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्हें अपने अधिकार का मौक़ा मिलता है तो वास्तव में ये वही मतदाता हैं जो मौजूदा उम्मीदवारों से नाराज़ हैं और 'इनमें से कोई नहीं ' का विकल्प चाहते हैं. दूसरे जो 64 फ़ीसदी मतदाता उम्मीदवारों का चयन अपने विवेक से करते हैं उन्हें इस बात की जानकारी दी जाए कि इस बार से चुनावों में आपके पास यह भी विकल्प है कि आप इनमें से किसी को भी नहीं चुनने का बटन दबा सकते हैं तो संभवत: वे अपने विवेक का इस्तेमाल और बेहतर तरीक़े से करेंगे. और सबसे बड़ा सवाल जब चुनाव आयोग ख़ुद यह बात स्वीकार कर रहा है कि वह मतदाता

(शेष पृष्ठ 2 पर)

जनता का फ़ैसला अभी बाक़ी है **04**

उत्सव की बजाए व्यवस्था सुधारिए नीतीश जी **05**

मुस्लिम जा सकते हैं भाजपा की ओर **06**

साई की महिमा **12**

जनता के अधिकार पर क़ब्ज़ा

फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

पृष्ठ एक का शेष

जागरूकता अभियान चला रहा है तो चुनाव आयोग का ही प्रतिनिधित्व कर रहा एक रिटर्निंग ऑफिसर 'नोटा' को लेकर किए जा रहे मतदाता जागरूकता अभियान पर रोक कैसे लगा सकता है?

एक और बड़ा सवाल है कि आख़िर मध्य प्रदेश में ही 'नोटा' को लेकर राजनीतिक दलों के भीतर इतना आतंक क्यों है? वास्तव में जनसंसद अभियान समिति की मध्य प्रदेश इकाई और प्रदेश संयोजक सुनीलम लंबे समय से प्रांत की जनता को इस अधिकार के बारे में जागरूक कर रहे हैं. समिति के इसी अभियान के चलते प्रदेश की जनता के भीतर से ऐसी आवाज़ें उठने लगीं कि वे उन उम्मीदवारों को नकारने जा रहे हैं जो नाकारा हैं और उनके ऊपर थोपे गए हैं. राजनीतिक दल जनता के इस रूप को देखकर घबरा रहे हैं और उन लोगों पर अनेक बंदिशें लगा रहे हैं जो 'नोटा' के पक्ष में हैं या इसे प्रचारित कर रहे हैं. डॉ सुनीलम पर भी पिछले दिनों छिंदवाड़ा में आपराधिक तत्वों ने हमला किया था. बीते 17 अक्टूबर को भोपाल में माप तोल विभाग में कार्यरत एक क्लर्क उमा शंकर तिवारी को जिलाअधिकारी ने मात्र इसलिए सस्पेंड कर दिया, क्योंकि वे लोगों को 'नोटा'अधिकार के बारे में जागरूक कर रहे थे. वास्तव में शिवराज सरकार का यह दमनकारी रवैया ख़ुद उसके लिए ही मुसीबत खड़ी करने वाला है और इसकी झलक दिखनी शुरू हो गई है. भोपाल गैस दुर्घटना कांड के पीड़ितों ने मिलकर फ़ैसला किया है कि विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों की वादाष्ठि लाफ़ी का जवाब प्रत्याशियों को ष्ठ ारिज करने वाले 'नोटा ' बटन को दबाकर देंगे.

चुनाव आयोग के इस क़दम पर सवाल खड़ा करने की एक और वजह है. 'नोटा' का प्रावधान भारतीय संविधान या चुनाव नियमों पहले से ही है. अब इसे ईवीएम में शामिल कर लिया गया है. चूंकि यह व्यवस्था पहले से ही है फिर भी लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है इसलिए स्पष्ट है कि खोट संविधान के स्तर पर या चुनाव से जुड़े नियमों के स्तर पर नहीं है. यह खोट है चुनाव आयोग की ओर से, क्योंकि वह इसके प्रति मतदाताओं को जागरूक नहीं कर रहा है. अभी तक जो व्यवस्था है उसमें अगर मतदाता अगर पोलिंग बूथ पर जाकर मतदान नहीं करना चाहता तो बूथ पर मौजूद रिटर्निंग ऑफिसर मतदाता को फॉर्म 17 (ए) देता है, जिसपर मतदाता अपनी आपत्ति दर्ज करा देता है. यह व्यवस्था लंबे समय से है. लेकिन इस व्यवस्था को लेकर कोई गोपनीयता नहीं है और यह उल्लिखित है कि जिस तरह देश के हर नागरिक को मतदान का अधिकार है उसी तरह उसे गुप्त रखने का भी अधिकार है. इसी अधिकार को क़ायम रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि ईवीएम में अंतिम विकल्प के तौर पर 'नोटा' (नन ऑफ दि एबव) का विकल्प दिया जाए. यह सुधार पहले से ही चली आ रही काग़ज़ी व्यवस्था का डिजिटल रिफॉर्म है तो इसके बारे में लोगों को बताना कहां का गुनाह है?

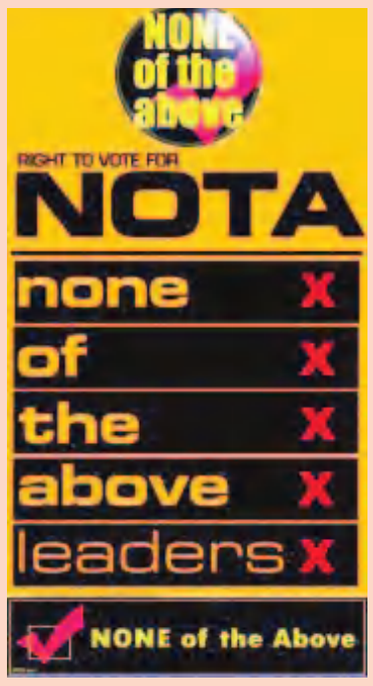

जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नन ऑफ द एबव की व्यवस्था बनी तभी राजनीतिक दलों ने ख़ुद के ऊपर मंडराने वाले इस ख़तरे को नकारात्मक रूप से पेश करना शुरू किया. इसका विरोध करने वालों का तर्क रहा कि भले ही नन ऑफ द एबव की व्यवस्था लागू हो गई है, लेकिन जिसको सबसे ज्यादा मत मिलेगा वो तो विजयी होगा ही, फिर इस व्यवस्था का क्या मतलब. वास्तव में चुनाव सुधार की किसी भी नई व्यवस्था का तुरंत ही असर हुआ हो, ऐसा कभी भी देखने को नहीं मिला है. नन ऑफ द एबव व्यवस्था को औषधि विज्ञान की अवधारणाओं के आधार पर समझने की ज़रूरत है. इसका परिणाम होम्योपैथी दवाओं की तरह रोग के संपूर्ण निदान के तौर पर दिखेगा, न कि एलोपैथी की तरह तात्कालिक लाभ के रूप में. यही वजह है कि सरकारें भले ही ऊपरी तौर इसका कोई असर न होता दिखने की बात कर रही हैं, लेकिन इसको लेकर उनके मन में भय तो है ही.

इतिहास की घटनाओं को अगर पैमाना मान कर देखें तो 1857 का ग़दर भले ही असफल हो गया था, लेकिन उसने देश के लोगों में एक उम्मीद ज़रूर भरी थी कि अगर हम एकजुट होकर और तैयारी के साथ लड़ें तो हम अपने उद्देश्य में कामयाब हो सकते हैं. वास्तव में राइट टू रिजेक्ट का यह विकल्प भी हमें उसी सोच की ओर ले जाता है. इसीलिए भले ही आगामी कुछ चुनावों में इसके असरकारी परिणाम न दिखें, लेकिन बदलाव के इस क्रम में राइट टू रिजेक्ट के बाद जिस असली हथियार राइट टू रिकॉल की बात हो रही है, वह इसी मांग और उम्मीद के भरोसे हासिल होगा.

मौजूदा चुनावी व्यवस्था पर ग़ौर करें तो कई बार ऐसे उदाहरण सामने आते हैं जब यह ज़ाहिर होता है कि मतदाताओं में नकारा उम्मीदवारों को लेकर रोष है. जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे तो मतगणना करने वाले अधिकारियों को कई ऐसे बैलेट पेपर मिलते थे, जिनमें लिखा रहता था कि सब चोर हैं. ऐसे बैलेट पेपर भी मिलते थे, जिनमें सभी उम्मीदवारों के सामने मुहर लगी होती थी. ऐसा नहीं है कि यह मतदाता ने अनजाने में किया है. वास्तव में यह उनके भीतर का रोष है जिसे वे मतदान केंद्र तक आकर दिखाना चाहते हैं. अब वह रोष दिखाने का एक वैधानिक माध्यम उन्हें मिल गया है. दूसरे, जब अपने रोष को दिखाने का मौक़ा मिलेगा तो उसे ज़ाहिर करने के लिए लोग बाहर आएंगे, इससे मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा.

एक और बड़ा असर जो सबसे असरकारी प्रभाव होगा कि अगर प्रत्याशियों के मत प्रतिशत में कमी हुई तो साफ़ ज़ाहिर है कि उन्हें जनता पसंद नहीं कर रही है. इसलिए राजनीतिक दल मज़बूर होंगे कि अगले चुनाव में वे वैसे उम्मीदवार को उतारें जिसकी छवि साफ़ हो और उसे अधिक मतदाताओं का समर्थन मिल सके. यहीं पर आकर राजनीतिक दल असफल हो रहे हैं जिसके चलते 'नोटा ' उनके मन में भय पैदा कर रहा है. मतदाता भी यह समझ रहा है कि 'नोटा ' लौकिक हथियार नहीं, नैतिक हथियार है जो बदलते वक्त के साथ राजनीतिक पार्टियों को स्वच्छ छवि वाले उम्मीदवारों के साथ आगे बढ़ने को मजबूर करेगा.

समाजशास्त्री रॉबर्ट डहल ने एक बार कहा था कि भारत में लोकतंत्र के फलने–फूलने के एक भी लक्षण नहीं हैं. 66 वर्ष बीत गए और भारतीय लोकतंत्र न केवल फलता–फूलता गया, बल्कि और मज़बूत होता गया. रॉबर्ड डहल की इस अवधारणा को देश की जनता की लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति श्रद्धा ने कभी फलने–फूलने नहीं दिया. लेकिन 66 वर्ष के लोकतांत्रिक इतिहास पर गौर करें तो देश की जनता लोकतंत्र के भीतर कभी भी दवाब समूह के तौर पर नहीं उभर पाई. कुछ एक संदर्भों जैसे सूचना के अधिकार और जनलोकपाल जैसे मुद्दों को छोड़ दें तो कभी भी हमें राजनीतिक फ़ैसलों में शामिल नहीं किया गया. अब राइट टू रिजेक्ट के रूप में हमें वह नैतिक हथियार मिलने जा रहा है, जब चुनाव सुधारों की दिशा में जनता दबाव समूह बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है. देश की जनता एक बार फिर रॉबर्ड डहल की सोच को ग़लत साबित करेगी और मध्य प्रदेश के मुलताई विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर के इस अलोकतांत्रिक प्रयास को भी. ■

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 05 अंक 38
दिल्ली, 25 नवंबर–01 दिसंबर 2013
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार–झारखंड)
प्रथम तल, विराट कॉम्प्लेक्स के पीछे, सरदार पटेल पथ, कृष्णा अपार्टमेंट के नज़दीक, बोरिस्रा रोड, पटना–800013
फोन : 0612 2570092, 9431421901

ब्यूरो चीफ (लखनऊ)
अजय कुमार
जे–3/2 डालीबाग कॉलोनी, हजरतगंज, लखनऊ–226001
फोन : 0522–2204678, 9415005111

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210–211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के – 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के–2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ–2, सेक्टर –11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश–201301

फोन न.
संपादकीय 0120–6451999, 6450888
विज्ञापन व प्रसार 022–42296060, +91–8451050786, +91–9266627379
फैक्स न. 0120–2544378

पृष्ठ–16+4 (बिहार–झारखंड, उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड) हर शुक्रवार को प्रकाशित

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

दिल्ली का बाबू

दिलीप चेरियन

चोटी पर बदलाव

अगले कुछ महीनों में वित्तमंत्रालय में उच्च पदों में कई बड़े बदलाव दिख सकते हैं. इसकी शुरुआत 1978 बैच के आंध्र प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी रतन वातल से हो चुकी है. वे अगले व्यय (एक्पेंडिचर) सचिव होंगे. वे इस माह के अंत में सेवानिवृत्त हो रहे वित्त सचिव आर एस गुजराल की जगह लेंगे. तब तक वातल व्यय विभाग में ओएसडी (ऑफीसर ऑन स्पेशल ड्यूटी) के रूप में पदस्थ रहेंगे. सूत्रों के अनुसार उन्हें आर्थिक विकास से समझौता किए बगैर ख़र्च में कमी लाने का दुष्कर कार्य सौंपा गया है. यदि वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कोई हैरान करने वाला निर्णय नहीं लिया तो तत्कालिक राजस्व सचिव सुमित बोस अगले वित्त सचिव हो सकते हैं. 1976 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी बोस वित्त मंत्रालय में कार्यरत पांच सचिवों में सबसे वरिष्ठ हैं. इनमें बोस को वरीयता मिलेगी. ऐसे भी 2014 का बजट भी कोई मुद्दा नहीं है. ■

नाराज़ पुलिस अधिकारी का विरोध

ईमानदार नौकरशाहों के लिए उत्तर प्रदेश हमेशा से ही एक मुश्किल कर्मभूमि रहा है जैसा कि हाल ही में आईएएस अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल के मामले से भी ज़ाहिर हुआ. दुर्गा शक्ति के निलंबन को वापस लेने के लिए हुए व्यापक प्रदर्शन के बावजूद प्रदेश में ज़मीनी हालात में कोई बदलाव नहीं हुआ है. नया मामला एक और महिला अधिकारी मंजिल सैनी का है जिन्हें उस वक्त विवादास्पद रूप से मुरादाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पद से हटा दिया गया था जब शहर दंगों की चपेट में था इस वजह से विरोध की लहर उठने लगी. अखिलेश यादव सरकार ने श्रीमती सैनी के केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने के अनुरोध को नकार दिया है. वह केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के लिए कार्य करने की इच्छुक थीं. नाराज़ पुलिस अधिकारी ने सरकार के निर्णय के विरोध में पांच महीने की छुट्टी की मांग की है. संयोगवश, पूर्व में उनका नाम हाई प्रोफाइल किडनी बेचने वाले रैकेट का पर्दाफाश करने की वजह से सुर्ख़ियों में आया था. स्पष्ट तौर पर आने वाले दिनों में कुछ और सुनने को मिलेगा. ■

कयामत आई

शायद चंडीगढ़ प्रशासन के नौकरशाह देश के दूसरे भागों की तुलना में ज्यादा दिग्भ्रमित हैं. वे शहर में परमाणु अथवा रासायनिक हमला होने की दशा में भी सुरक्षित रहना चाहते हैं. इसे लेकर वे चिंतित हैं और इस दिशा में काम करना भी शुरू कर दिया है. उन्होंने अंडरग्राउंड सेफ हाउस के निर्माण का प्रस्ताव रखा है जिसमें आलाधिकारी आपात स्थिति में रहेंगे. ज़ाहिर तौर पर केंद्र शासित प्रदेश के गृह सचिव अनिल कुमार ने इस विषय पर कई दौर की बातचीत में पूर्व आईजी पी के श्रीवास्तव द्वारा भेजे गए मेमो के आधार पर आकलन किया कि इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में 40 करोड़ की लागत आएगी. प्रस्तावित भवन में 10 से 12 अति विशिष्ट लोगों के रहने, कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी और वे सभी सुविधाएं होंगी जो परमाणु हमले की दशा में प्रशासन चलाने के लिए आवश्यक होगी. नि:संदेह दूसरे बड़े महानगरों के नौकरशाहों को इस निर्णय से जलन हो रही होगी कि उनके जेहन में इस बारे में सबसे पहले विचार क्यों नहीं आए. लेकिन नि:संदेह यह विचार ऐसा है जिसपर जल्दी ही अन्य लोग भी अमल करेंगे. ■

चण्डीगढ़ प्रशासन
CHANDIGARH ADMINISTRATION

dilipcherian@gmail..com

साउथ ब्लॉक

श्रीनिवासुलु संयुक्त सचिव बने

1994 बैच के सिक्किम कैडर के आईएएस अधिकारी के श्रीनिवासुलु को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है. प्रीति मदान (भारतीय आर्थिक सेवा–1981) के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय में संयुक्त सचिव नियुक्त होने से यह पद ख़ाली हुआ था.

अरविंद राजदूत बने

1988 बैच के महाराष्ट्र कैडर के आईएएस अरविंद सिंह को जापान के टोक्यो में राजदूत नियुक्त किया गया है, जो भारतीय दूतावास में मंत्री (वाणिज्यिक एवं आर्थिक) के रूप में कार्य संभालेंगे. सिंह 1985 बैच के केंद्र शासित कैडर के आईएएस अरुण गोयल की जगह लेंगे. वर्तमान में अरविंद महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक (प्रधान सचिव रैंक) के रूप में कार्यरत हैं.

मनीषा का स्थानांतरण

1992 बैच भारतीय डाक सेवा अधिकारी मनीषा सिन्हा कपड़ा मंत्रालय से जल्द ही किसी दूसरे मंत्रालय जा सकती हैं.
1988 बैच के सिक्किम कैडर के आईएएस एन. के. मिश्रा वाशिंगटन डीसी स्थित भारतीय दूतावास में जल्द ही मंत्री (कार्मिक एवं सामुदायिक) के रूप में भेजे जाएंगे.

व्यास वाणिज्य मंत्रालय से जुड़े

2000 बैच के आईएएस अधिकारी मधुप व्यास वाणिज्य विभाग के निदेशक के रूप में कार्यभार संभालेंगे. व्यास 1994 बैच के असम–मेघालय कैडर के आईएएस ए.पी.दास जोशी की जगह लेंगे. वर्तमान में मधुप शहरी विकास मंत्रालय के तहत दिल्ली विकास प्राधिकरण के आयुक्त हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

हरियाणा की राजनीति भजनलाल, देवीलाल और बंसीलाल के इर्द गिर्द ही घूमती रही है. हरियाणा की राजनीति के जानकार हुड्डा के बारे में कहते हैं कि हरियाणा के जाटों में चौधरी देवीलाल के प्रति जो लगाव था उसे अपने राजनीतिक कौशल से हुड्डा ने अपनी ओर मोड़ लिया. इस लिहाज़ से देखें तो हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर न सिर्फ़ हरियाणा की पांच सीटों, बल्कि हरियाणा के पड़ोसी राज्यों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब के जाट वोटों को भी सहेजने की ज़िम्मेदारी है.

हरियाणा कांग्रेस में दंगल

मुख्यमंत्री भूपेंदर सिंह हुड्डा की जुगाड़ की राजनीति ने हरियाणा कांग्रेस में फूट डाल दी है, जिसकी वजह से वहां गुटबाज़ियों का दौर शुरू हो चुका है. दलित बनाम अगड़ी जाति की राजनीति हो रही है. केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा और राज्यसभा सांसद चौधरी वीरेन्द्र सिंह, मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर गन्दी और विकासविरोधी राजनीति का आरोप लगा रहे हैं. लेकिन अन्दर की सेटिंग में माहिर मुख्यमंत्री हुड्डा ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी तक अपनी सियासत की ऐसी बिसात बिछा रखी है कि उनके ख़िलाफ़ आने वाली शिकायतें अनसुनी कर दी जाती हैं. नतीजतन हरियाणा कांग्रेस में असंतुष्टों की संख्या में इज़ाफ़ा हो रहा है. इससे हुड्डा की राह तो मुश्किल हो ही रही है, दिल्ली की सियासत पर भी असर पड़ने की आशंकाओं से इनकार नहीं किया जा सकता.

रूबी अरुण

हरियाणा की राजनीति इन दिनों मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और केन्द्रीय मंत्री तथा दलित नेता कुमारी शैलजा के आपसी दंगल की गवाह बन रही है. इन दोनों की आपसी कड़वाहट आने वाले चुनावों में कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ा सकती है. हुड्डा और शैलजा कभी भाई–बहन की जोड़ी के रूप में जाने जाते थे. इन दोनों की आपसी खींचतान की वजह से हरियाणा कांग्रेस में गुटबाज़ी और अनुशासनहीनता का बोलबाला हो चुका है.

हालांकि कांग्रेस ने हरियाणा में इस क़िस्म का सियासी खेल पहले भी खेला है. वह जानबूझ कर पहले भी प्रदेश में दलितों और अगड़ों का नेतृत्व एक रणनीति के तहत अलग–अलग विकसित करती रही है. जब बंसीलाल और भजनलाल थे, तब भी यही होता था. क्योंकि अगड़ों और दलितों की लड़ाई में कांग्रेस हमेशा फ़ायदे में रही है. लिहाज़ा कयास ये लगाया जा रहा है कि कांग्रेस अब हुड्डा और सैलजा के रूप में यही काम कर रही है.

बहरहाल, फ़ौरी तौर पर जो माहौल नज़र आ रहा है वह कांग्रेस के पक्ष में नहीं दिख रहा. सियासी खींचतान जमकर चल रही है और इसमें फिलहाल हुड्डा का पाला भारी नज़र आ रहा है. वैसे भी हुड्डा अपने विरोधियों को निपटाने की कला में माहिर माने जाते हैं. कहा ये जा रहा है कि शैलजा, हुड्डा के निशाने पर हैं. इसकी वजह पिछले दिनों सोनिया गांधी की बीमारी में कुमारी शैलजा का उनके क़रीब होना बताया जा रहा है. हुड्डा का यह इतिहास रहा है कि हरियाणा के जिस किसी नेता ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी या उपाध्यक्ष राहुल गांधी से निकटता बनाने की कोशिश की, उन्होंने उसका पत्ता हरियाणा की राजनीति से साफ़ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी. आजकल केन्द्रीय मंत्री कुमारी शैलजा का क़द छोटा करने का कोई मौक़ा वे नहीं चूकते. शैलजा, हुड्डा के इस रवैये से ख़ासी आहत हैं. उन्होंने कांग्रेस आलाकमान से भी अपना दर्द बयान किया है, लेकिन हुड्डा जोड़ –तोड़ और जुगाड़ में दक्ष हैं. उन्होंने सोनिया गांधी से राहुल गांधी तक अपनी मज़बूत दखल बना रखी है. शैलजा पर ट्रेन के सफर के दौरान हमला हुआ. कुमारी शैलजा कालका–सांईनगर शिरडी सुपरफास्ट एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने के बाद उसी ट्रेन से अपने संसदीय क्षेत्र पहुंची थीं. सोनिया गांधी को दिए गए अपने शिकायती पत्र में शैलजा ने साफ़ तौर पर कहा है कि उन्हें साज़िशन बिना सुरक्षा की खिड़की वाली सीट पर बैठने को मजबूर किया गया. फिर चलती ट्रेन की उस खिड़की पर रास्ते में पत्थर फेंके गए, जिससे उन्हें गंभीर चोटें लगीं हैं. केंद्रीय मंत्री शैलजा ने स्पष्ट तौर पर इस घटना का ज़िम्मेदार प्रदेश कांग्रेस में चल रही ओछी राजनीति को ठहराया है. इतना ही नहीं, हुड्डा पर राज्य में दलितों का विरोध करने और उनका शोषण करने के भी आरोप कुमारी शैलजा की तरफ़ से लगाए गए हैं. लेकिन हुड्डा की शातिर सियासत के आगे शैलजा के आरोप रद्दी के टोकरे में डाल दिए जाते हैं. न सिर्फ़ शैलजा, बल्कि राव इन्द्रजीत सिंह जैसे धाकड़ नेता की भी हुड्डा के आगे एक न चली और उन्होंने अपनी विरासत की राजनीति को भी तंग आकर छोड़ दिया. अब वे नए ठिकाने की तलाश में हैं. हरियाणा की राजनीति में ख़ास मकाम रखने वाले चौधरी वीरेंदर सिंह भी, भूपिंदर सिंह हुड्डा के दांव–पेच से परेशान हैं. सर छोटूराम के पुत्र होने के बाद भी वे केंद्र में मंत्री नहीं बन सके. यह भी हुड्डा की ही करामात थी. हरियाणा में स्वतंत्रता सेनानियों को कांग्रेस के पाले में रखने की राजनीति करते करते भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व प्रधानमंत्री नरसिंह राव के ड्राइंग रूम तक पहुंच गए. जुगाड़ की राजनीति में सिद्धहस्त हुड्डा ने 1991 में तो मामूली अंतर से जीत हासिल की, पर उसके बाद उन्होंने हरियाणा की राजनीति के स्तम्भ चौधरी देवीलाल को रोहतक की लोकसभा सीट से लगातार तीन बार पटखनी दी.

हरियाणा में विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के बाद होने हैं, लेकिन अभी से राजनीतिक पारा चरम सीमा पर पहुंच चुका है. राज्य में विधानसभा चुनाव को लगभग एक वर्ष पड़ा है, लेकिन उससे पहले होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने हरियाणा में अपनी पूरी ताक़त झोंक दी है, क्योंकि हरियाणा की राजनीति का जमा घाटा का गणित भी लोकसभा चुनावों के परिणामों पर निर्भर करेगा और भविष्य की राजनीतिक दिशा भी इसी आधार पर आगे बढ़ेगी. लेकिन हरियाणा कांग्रेस जिस तरह आपसी फूट का शिकार हो रही है, वह कांग्रेस के लिए चिंताजनक है.

हरियाणा की राजनीति भजनलाल, देवीलाल और बंसीलाल के इर्द गिर्द ही घूमती रही है. हरियाणा की राजनीति के जानकार हुड्डा के बारे में कहते हैं कि हरियाणा के जाटों में चौधरी देवीलाल के प्रति जो लगाव था उसे अपने राजनीतिक कौशल से हुड्डा ने अपनी ओर मोड़ लिया. इस लिहाज़ से देखें तो हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर न सिर्फ़ हरियाणा की पांच सीटों, बल्कि हरियाणा के पड़ोसी राज्यों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब के जाट वोटों को भी सहेजने की ज़िम्मेदारी है. लेकिन पिछले कुछ दिनों से हुड्डा अपनी ही पार्टी के नेताओं द्वारा लगाए गए इल्ज़ामों के घेरे में हैं. और इन्हीं बढ़ते इल्ज़ामों के बीच में हुड्डा को कांग्रेस के लिए अपनी उपयोगिता साबित करनी है. हुड्डा इसी जुगत में लगे हैं. पर उन्हें इसमें ख़ासी सफलता मिलती नहीं दिख रही है, क्योंकि हुड्डा के घोर विरोधी राज्यसभा सांसद चौधरी वीरेन्द्र सिंह ने खुलकर हुड्डा की मुख़ालफ़त शुरू कर दी है. दरअसल, चौधरी वीरेन्द्र की नाराज़गी उस वक्त से है, जब उनसे महासचिव का पद भी छिन गया और केंद्रीय मंत्री बनने की राह भी नहीं खुली. चौधरी वीरेन्द्र सिंह इसके लिए खुले तौर पर आरोप मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा पर लगाते हैं. वीरेन्द्र सिंह को इस बात की तकलीफ़ ज्यादा है कि हुड्डा के ख़िलाफ़ शिकायत करने पर भी पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया. उनकी नाराज़गी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि चंडीगढ़ में नए प्रभारी शकील अहमद के साथ बैठक में चौधरी वीरेन्द्र ने सीएम से न तो दुआ सलाम की और न ही राम–राम. और अगले ही दिन कुरुक्षेत्र में उन्होंने ज़रूर ये टिप्पणी कर दी कि मुख्यमंत्री हुड्डा की सोच पहेलियों से निकलती है. वो छकाकर खेलते हैं.

हुड्डा की परेशानी महज़ इतनी भर नहीं है. दरअसल, हरियाणा की राजनीति में आरोपों–प्रत्यारोपों का दौर भी चरम पर है. सत्तारूढ़ दल के विधायकों पर आरोप हैं कि वे विभिन्न स्थानों पर ज़मीन के लिए सीएलयू दिलवाने, टेंडर व लाइसेंस के लिए मोटी रक़म की मांग करते हैं. जिसका स्टिंग ऑपरेशन करके सीडी भी तैयार करके जारी की गई है. ज़ाहिर है जैसे–जैसे विधानसभा और लोकसभा चुनाव का समय निकट आ रहा है, अनियमितताओं के और भी ख़ुलासे होंगे. सरकार के भ्रष्टाचार की और भी ख़बरें निकल कर सामने आ रही हैं. ये शिकायतें दस जनपथ तक पहुंच भी रही हैं, लेकिन अन्दर की सेटिंग में माहिर हुड्डा ने अपना इंतज़ाम इतना पुख़्ता कर रखा है कि राहुल गांधी तक हुड्डा के ख़िलाफ़ शिकायतों से मुंह मोड़ लेते हैं, जबकि यही राहुल गांधी कांग्रेस की छवि सुधारने और साफ़ सुथरी पार्टी बनाने का दावा करते हैं. भूपेंदर सिंह हुड्डा ने अपने सांसद बेटे दीपेंदर सिंह हुड्डा को इसी काम के लिए राहुल गांधी के साथ लगा रखा है ताकि दीपेंदर, अपने पिता के ख़िलाफ़ आनेवाली शिकायतों को राहुल गांधी तक न पहुंचने दें. उधर, मुख्यमंत्री भी गांधी परिवार पर अपना एहसान लादने का कोई मौका नहीं गंवाते. रॉबर्ट वाड्रा प्रकरण में, हुड्डा खुलकर उनका साथ देते नज़र आए. ज़मीन विवाद में रॉबर्ट पर लगे हर दाग़ को हुड्डा ने धोने की कोशिश की. हरियाणा की राजनीति में हुड्डा ने अहमद पटेल के सहारे जिस तरीक़े से भजनलाल को किनारे लगाकर मुख्यमंत्री की कुर्सी हथियाई थी, उससे हरियाणा की गैर जाट बिरादरी बेहद नाराज़ थी. लेकिन गुज़रते वक़्त के साथ हुड्डा ने भजनलाल के समर्थकों में भी अपनी पैठ बनाई और जाट बिरादरी को भी एकजुट किया. जिसका सकारात्मक प्रभाव राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली में भी देखा गया. लिहाज़ा सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के अन्य रणनीतिकारों को ये लगता है कि इस बार के राजस्थान और दिल्ली विधानसभा चुनावों में भी हुड्डा का असर काम करेगा. साथ ही पड़ोसी पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी स्थितियां कांग्रेस के हक़ में रहेंगी. मतलब ये कि जाट वोट बैंक भी हुड्डा के लिए कवच का काम कर रहा है. लेकिन हालत उतने सहज नहीं हैं. कुमारी सैलजा के लगाए गए आरोपों के तहत अब प्रदेश में जाट बनाम दलित की राजनीति भी करवट लेने लगी है. दलितों के शोषण और उनके विकास में बाधा डालने का आरोप भी मुख्यमंत्री पर लग रहा है. हरियाणा में 2014 में चुनाव होने हैं लेकिन राजनीतिक पार्टियां अपने–अपने दांव अभी से चलने लगी हैं. हुड्डा की मुश्किल ये है कि उन पर न सिर्फ़ विरोधी दलों के हमले तेज़ हो रहे हैं, बल्कि उनकी अपनी पार्टी के लोग भी उनके ख़िलाफ़ लामबंद हो रहे हैं. हालांकि, हुड्डा समर्थक ख़ासकर रोहतक, सोनीपत और झज्जर ज़िलों में मजबूती से कांग्रेस पार्टी और हुड्डा के साथ खड़े हैं और यही मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुख्य ताक़त भी हैं. लिहाज़ा हुड्डा की सफलता ख़ासतौर पर इन्हीं तीन ज़िलों पर निर्भर है. दो बार मुख्यमंत्री बने हुड्डा तीसरी बार मुख्यमंत्री तभी बन सकते हैं जब इन तीन ज़िलों से पहले जैसे ही चुनावी नतीजे आएं. वैसे भाजपा की गठबंधन को लेकर असमंजस की स्थिति, इनेलो के शीर्ष नेताओं का राजनीतिक परिदृश्य से बाहर होना भी हुड्डा के पुन: मुख्यमंत्री बनने के कारणों में शुमार हो सकते हैं. लेकिन कांग्रेस की अंदरूनी फूट भूपिंदर सिंह हुड्डा और प्रदेश कांग्रेस के लिए यक़ीनन दुश्वारियां बढ़ा सकती है. ■

feedback@chauthiduniya.com

चुनाव जीतने का दावा कर रहे अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी एक साल पहले बनी थी. इस एक साल में लगातार प्रचार के ज़रिये वह चर्चा में तो आ गई है, लेकिन दिल्ली की कुर्सी तक पहुंचने के लिए राहें इतनी आसान नहीं हैं. एक तरफ़ कांग्रेस सरकार का पंद्रह सालों का शासन है, जिसे भुनाने के लिए मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जनता के बीच पहुंच गई हैं तो दूसरी तरफ़ मोदी की लहर पर सवार भाजपा है. अनुभवहीन आम आदमी पार्टी को इनसे निपटना होगा.

दिल्ली विधानसभा चुनाव और आम आदमी पार्टी

जनता का फ़ैसला अभी बाक़ी है

एक साल पहले अन्ना आंदोलन के बाद अस्तित्व में आई अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा में चुनाव में भाग्य आज़मा रही है. पार्टी का दावा है कि वह इस बार दिल्ली में बहुमत लाएगी और सरकार बनाएगी. हालांकि पार्टी को न तो किसी सर्वे में बहुमत मिलता दिख रहा है, न ही उनके प्रचार के दौरान जनता का वैसा समर्थन मिलता दिख रहा है, जिससे कि यह अंदाज़ा लगे कि आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता पर काबिज़ होने जा रही है. उसकी स्थिति बस भाजपा और कांग्रेस को असहज करने वाली ही है. हालांकि कई बार चुनावों के नतीजे बेहद चौंकाने वाले और अप्रत्याशित होते हैं. जैसा अरविंद केजरीवाल का दावा है, यदि वैसा होता है तो भारत के चुनावी इतिहास में इसे एक चमत्कार माना जाएगा. फिलहाल पार्टी के खाते में बस इतनी सफलता दर्ज है कि वह महज़ एक साल में अस्तित्व में आकर चुनावी चर्चा में भी आ गई है. इसके आगे पार्टी की भूमिका जनता तय करेगी.

कृष्णकांत

दिल्ली का रोहिणी इलाक़ा. अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का रोड शो. दिन का समय है. लोग अपने कामों में मशरूफ़ हैं. अरविंद केजरीवाल का क़ाफ़िला बढ़ता जाता है. केजरीवाल और उनके क़ाफ़िले के लोग हाथ हिलाकर लोगों का अभिनंदन करते हैं और लोगबाग जो जहां हैं, वहां से ही क़ाफ़िले की ओर देखते हैं. हाथ हिलाकर उनका स्वागत करते हैं. बीच-बीच में कुछ लोग आकर केजरीवाल से हाथ भी मिलाते हैं. लेकिन यह क़ाफ़िला वैसा नहीं है, जैसा कि किसी बड़े नेता का होता है, जिसमें अपार भीड़ शामिल होती है. उनके साथ सौ से दो सौ लोग इलाक़े में घूम रहे हैं. उनके साथ घूमकर यह नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल को आगामी विधानसभा चुनावों में भारी जनसमर्थन मिलेगा, जैसा कि वे दावा करते हैं कि दिसंबर में दिल्ली में आप की सरकार बन रही है. अरविंद केजरीवाल अपने प्रचार में कहते सुने जा सकते हैं कि दिसंबर में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है और सरकार बनते ही रामलीला मैदान में विशेष सत्र बुलाकर अन्ना हजारे का लोकपाल बिल पास किया जाएगा.

अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लोग ख़ुद दिल्ली में 33 सीटें जीतकर सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं. पार्टी ने ख़ुद से अपना फ़ैसला सुना दिया है कि वह चुनाव जीतकर सरकार बना रही है. लेकिन अभी जनता का फ़ैसला आना बाक़ी है, जो कि वास्तविक फ़ैसला होगा. पार्टी का यह दावा पांच सितंबर से पांच नवंबर के बीच कराए गए उस सर्वे के आधार पर है, जो जाने-माने राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव के निर्देशन में हुआ है. योगेंद्र यादव चुनावी सर्वे और विश्लेषण के मामले में एक विश्वसनीय चेहरा रहे हैं, लेकिन यहां मामला थोड़ा अलग है. अलग इन अर्थों में कि अब वे मात्र राजनीतिक विश्लेषक नहीं, बल्कि स्वयं उसी पार्टी में शामिल हैं, जिसके जीतने का दावा कर रहे हैं. वह भी तब, जब मुक़ाबला भाजपा और कांग्रेस जैसी दो बड़ी पार्टियों से है. कोई भी पार्टी इतना ईमानदार सर्वे नहीं कराती है कि किसी चुनाव में ख़ुद के हारने की भविष्यवाणी करे. तीन बार से दिल्ली की सत्ता पर काबिज़ कांग्रेस और विपक्षी पार्टी भाजपा भी अपनी-अपनी जीत का दावा कर रही हैं. इस सर्वे के आधार पर योगेंद्र यादव का कहना है कि दिल्ली में पार्टी का समर्थन लगातार बढ़ रहा है. दिल्ली में आम आदमी पार्टी की लहर चल रही है. योगेंद्र यादव का कहना है कि यदि जनता का इसी तरह से समर्थन मिलता रहा तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी.

नतीजे क्या होंगे, यह कहना अभी जल्दबाज़ी होगी. चार दिसंबर को होने वाले चुनावों में जनता किसे वोट करेगी, इसका ठीक-ठीक अनुमान लगाना संभव नहीं है. लेकिन यह तथ्य है कि पार्टी ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार में जुटी है. आम आदमी पार्टी यह दावा कर रही है कि उसने दिल्ली में भाजपा और कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाई है. हालांकि, यह बात सही है कि एक ख़ास तबके में अरविंद केजरीवाल अपनी पहुंच बनाने में सफल रहे हैं. युवाओं में उनकी स्वच्छ छवि और कर्मठता की चर्चा है और कांग्रेस तथा भाजपा से आजिज़ आ चुके मध्य वर्ग के लोग केजरीवाल की तरफ़ जा सकते हैं. पिछले पंद्रह दिनों में दिल्ली में निजी तौर पर मुझे सात-आठ ऑटो चालकों ने आम आदमी पार्टी को वोट देने को कहा. वे अपने ऑटो पर बैठने वाले से पूछते हैं कि आप इस बार किसे वोट दे रहे हैं? यात्री पूछता है कि आप बताइए, आप किसे देंगे? वे कहते हैं कि झाड़ू वाले को. आम आदमी पार्टी को वोट दीजिए. वह भाजपा और कांग्रेस से अच्छी पार्टी है. ऑटो वालों की इस तरह हर यात्री से आम आदमी पार्टी की वकालत करना पार्टी को निश्चित ही फ़ायदा पहुंचाएगा. दूसरी बात पार्टी के साथ प्रचार करने, पोस्टर लगाने और दरव-ज़े-दरवाज़े घूमने वाले सभी लोग युवा वर्ग के हैं. युवाओं में पार्टी ने अच्छी पैठ बनाई है. लेकिन युवा वर्ग का मतदान करने को लेकर रिकॉर्ड बेहद ख़राब है. हाल ही में चुनाव आयोग ने सर्वे कराया था जिसमें युवाओं की मतदान में हिस्-सेदारी को लेकर बेहद निराशाजनक तथ्य सामने आए थे.

अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लोग ख़ुद दिल्ली में 33 सीटें जीतकर सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं. पार्टी ने ख़ुद से अपना फ़ैसला सुना दिया है कि वह चुनाव जीतकर सरकार बना रही है. लेकिन अभी जनता का फ़ैसला आना बाक़ी है, जो कि वास्तविक फ़ैसला होगा. पार्टी का यह दावा पांच सितंबर से पांच नवंबर के बीच कराए गए उस सर्वे के आधार पर है, जो जाने-माने राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव के निर्देशन में हुआ है.

अप्रवासी भारतीयों का समर्थन

अरविंद केजरीवाल को समर्थन देने वालों में अप्रवासी भारतीयों की बड़ी संख्या है. वे वोट भले नहीं आएंगे, लेकिन पार्टी के पक्ष में प्रचार ज़रूर कर रहे हैं. दुनिया के कई शहरों में अप्रवासी भारतीयों के कई समूह अरविंद केजरीवाल के पक्ष में सोशल मीडिया और अन्य ऑनलाइन माध्यमों पर प्रचार करने में जुटे हैं. वे दिल्ली में बदलाव की बात कहकर आप का प्रचार कर रहे हैं. वे लोग दिल्ली के निवासियों को फोन करके, ईमेल करके आम आदमी पार्टी को वोट देने के लिए प्रेरित कर रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, जर्मनी, अमेरिका आदि देशों में रह रहे अप्रवासी भारतीयों द्वारा आम आदमी पार्टी के पक्ष में प्रचार करने की बात सामने आई है. ऐसे क़रीब 18 एनआरआई समूह हैं, जो केजरीवाल के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं. वे प्रचार के साथ-साथ फंड जुटाने, लोगों की समस्याएं जानने, सोशल मीडिया पर लोगों को जोड़ने और वोट देने के लिए प्रेरित करने जैसा काम कर रहे हैं. पार्टी नेता मनीष सिसौदिया का कहना है कि एनआरआई लोगों के सहयोग की वजह से हमें काफ़ी मदद मिली है. हम ग्राउंड वर्क पर ज्यादा ध्यान दे पा रहे हैं. कई अप्रवासी भारतीय तो छुट्टियां लेकर दिल्ली आ गए हैं और बाक़ायदा पार्टी का प्रचार कर रहे हैं. इन लोगों से पार्टी को बड़ी मात्रा में धन भी मिल रहा है.

विवादों में फंसी आप

चुनाव जीतने का दावा कर रहे अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी एक साल पहले बनी थी. इस एक साल में लगातार प्रचार के ज़रिये वह चर्चा में तो आ गई है, लेकिन दिल्ली की कुर्सी तक पहुंचने के लिए राहें इतनी आसान नहीं हैं. एक तरफ कांग्रेस सरकार का पंद्रह सालों का शासन है, जिसे भुनाने के लिए मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जनता के बीच पहुंच गई हैं तो दूसरी तरफ मोदी की लहर पर सवार भाजपा है. अनुभवहीन आम आदमी पार्टी को इनसे निपटना होगा. पार्टी बनने के बाद से कई तरह के विवादों में फंसी है, जिससे जनता में यह संदेश गया है कि सियासी गलियारे का एक ख़ास क़िस्म का चरित्र है, जिससे लाख चाहकर भी कोई दल बच नहीं सकता. केजरीवाल पर सांप्रदायिक छवि वाले मठाधीशों की मदद लेने से लेकर अवैध ढंग से विदेशी आर्थिक मदद लेने के आर-ोप लग रहे हैं.

विदेशी चंदे पर विवाद

हाल ही में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया कि अरब देशों में नागरिक विद्रोह के लिए फंडिंग करने वाली आवाज़ नाम की संस्था ने अरविंद केजरीवाल की पार्टी को चार लाख डॉलर यानी करीब ढाई करोड़ रुपये की फंडिंग की है. स्वामी ने आप को मिले चंदे की जांच कराने की मांग की. पार्टी को विदेशों से मिले चंदे की छानबीन करने के लिए गृह मंत्रालय ने आदेश दे दिया है. यह मसला काफ़ी अहम है, क्योंकि यह पार्टी भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ नारा बुलंद करके ही चुनाव मैदान में उतरी है और जनसमर्थन मांग रही है. पार्टी को मिले चंदे के स्रोत पर उठे सवाल के जवाब पार्टी को देने होंगे क्योंकि भाजपा और कांग्रेस इसे लेकर आप पर हमले कर रही हैं. गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने जांच की घोषणा करते हुए कहा कि उन्हें आम आदमी पार्टी को मिले विदेशी चंदे को लेकर कई शिकायतें मिली हैं.

चंदे में मिले 19 करोड़

विदेशों से मिले चंदे संबधी विवाद पर आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो जांच के लिए तैयार है, क्योंकि उसे जितने भी चंदे मिले हैं, सबका हिसाब पार्टी ने अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक किया है. पार्टी की वेबसाइट के मुताबिक, आठ नवंबर तक पार्टी को 63 हज़ार दाताओं की ओर से चंदा दिया गया, जिसमें कुल 19 करोड़ रुपये प्राप्त हुए. इन दाताओं में कुछ उद्योगपति हैं तो कुछ विदेशों में बसे भारतीय हैं. इसके अलावा आप को चंदा देने वालों में से 90 फ़ीसदी लोग देश के अन्य राज्यों से हैं, जो पैसे से तो समर्थन दे रहे हैं, लेकिन मतदान में वे हिस्सा नहीं लेस सकेंगे. आप की वेबसाइट पर उसे की गई फंडिंग के सारे आंकड़े उपलब्ध हैं.

पार्टी में असंतोष

पार्टी में असंतोष व्याप्त है, जिसका कई बार सार्वजनिक प्रदर्शन हो चुका है. पार्टी बनने के कुछ ही समय बाद अरविंद केजरीवाल के कुछ समर्थक असंतुष्ट होकर आप से अलग हो गए और बाप (भारतीय आम आदमी परिवार) बनाई. हाल ही में पार्टी के सदस्य राकेश अग्रवाल ने एक प्रेस कांफ्रेंस कर दावा किया कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल से अपील की थी कि पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिसे उन्होंने नज़रअंदाज़ कर दिया. उसी प्रेस कांफ्रेंस के दौरान कुछ ऑटो ड्राइवर पहुंचे और अग्रवाल पर अपने एनजीओ में वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाया. इसके बाद पार्टी ने राकेश अग्रवाल को पार्टी से बाहर कर दिया. यह विवाद इस बात का प्रमाण है कि पार्टी में अंदरख़ाने सब ठीक नहीं है. इतिहास गवाह है कि सत्ता मिल जाना ही काफ़ी नहीं होता. 1977 में बनी जनता पार्टी सरकार अपनी अनुभवहीनता और आंतरिक कलह की वजह से ही गिर गई थी और बुरी तरह हारीं इंदिरा गांधी को जनता ने दोबारा जनादेश दिया था. अगर आम आदमी पार्टी को सत्ता मिलती है तो उसे आपसी झगड़े और असंतोष को लोकतांत्रिक ढंग से सुलझाने की चुनौती होगी. पार्टी को दिल्ली की जनता को अभी यह विश्वास दिलाना बाक़ी है कि अगर वो सत्ता में आती है तो सरकार कैसे चलाएगी. क्योंकि वैसे भी पार्टी बनते ही चुनाव मैदान में उतरना ही अपने आप में एक रिकॉर्ड है. इसका अंजाम क्या होगा, यह चुनाव नतीजे बताएंगे. ■

feedback@chauthiduniya.com

> जब बिहार की शिक्षा व्यवस्था अपने सबसे नाज़ुक दौर से गुज़र रही है तो ऐसे में समारोह मनाना कहीं से उचित नहीं है. अधिकारियों और विभाग की लापरवाही की वजह से हमारे शिक्षक अपनी अधिकतम योग्यता का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं. अब तक पूरे सूबे में 60 प्रतिशत बच्चों को किताबें नहीं मिली हैं, जो उन्हें क़ायदे से मार्च तक ही मिल जानी थीं. हैरत की बात है कि सरकार किताबों के नाम पर पैसे का रोना रोती है और समारोह के नाम पर करोड़ों ख़र्च करती है.

चौपट शिक्षा व्यवस्था पर नीतीश सरकार का उत्सव

बिहार में देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती पर तीन दिवसीय शिक्षक दिवस समारोह मनाया गया, जिसमें करोड़ों रुपये ख़र्च किए गए. पूरा महकमा एक महीने तक इस आयोजन की तैयारी में व्यस्त रहा. जितनी ऊर्जा राज्य सरकार ऐसे आयोजनों को मनाने में ख़र्च करती है, उतनी ही ऊर्जा राज्य की शिक्षा व्यवस्था को भी दुरुस्त करने में लगाती तो तस्वीर कुछ और ही होती. कई ज़िलों में शिक्षकों के बड़े वर्ग ने इस आयोजन को फिज़ूलख़र्ची बताकर इसका विरोध भी किया, लेकिन इस विरोध को कोई तवज्जो नहीं दी गई.

शशि सागर

भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जयंती समारोह पर राजधानी पटना में तीन दिवसीय शिक्षा दिवस समारोह का आयोजन किया गया. आयोजन का उद्घाटन स्वयं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया. सूबे के कई मंत्रियों व आला–अधिकारियों ने भी इस दौरान शिरकत की. ढेर सारी घोषणाएं हुईं, ढेरों वादे किए गए. और तो और, इस बार के शिक्षा दिवस की थीम विद्यालय सशक्तिकरण रखा गया. इस दौरान शिक्षा मंत्री पीके शाही और प्रधान सचिव अमरजीत सिन्हा ने कहा कि वे सभी को अच्छा वेतन देना चाहते हैं, लेकिन राज्य की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है. इस दौरान गांधी मैदान और श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में कई आयोजन भी हुए. शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले सम्मानित भी हुए. इस पूरे आयोजन के लिए शिक्षा विभाग का पूरा महकमा कई महीने से व्यस्त था. जानकार कहते हैं कि जितनी ऊर्जा राज्य सरकार ऐसे आयोजनों को मनाने में ख़र्च करती है, उतनी ही ऊर्जा राज्य की शिक्षा व्यवस्था को भी दुरुस्त करने में लगाती तो तस्वीर कुछ और ही होती. बहरहाल, ऐसे आयोजन उत्साह और ऊर्जा को बनाए रखने के लिए आवश्यक भी हैं, लेकिन बिहार की शिक्षा व्यवस्था के कुछ और भी पहलू हैं. लगातार सरकार पर यह आरोप भी लगते रहे हैं कि इन आठ सालों में दो काम बड़ी ही प्रमुखता से हुए हैं. पहला यह कि द्वार–द्वार तक दारू पहुंचा दी गई है और दूसरा यह कि सूबे की शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल ही चौपट हो गई है. आंकड़े बताते हैं कि सरकार के लाख प्रयासों के बावजूद भी सूबे में ड्रॉप आउट रेट घटने का नाम नहीं ले रहा है. हाल के दिनों में शिक्षा और शिक्षकों से जुड़े कई मसले देश भर में चर्चित भी हुए हैं. जहां पूरा महकमा गांधी मैदान में आयोजित शिक्षा दिवस मनाने में व्यस्त था, वहीं शिक्षकों और बच्चों की बड़ी संख्या उसे अपना उपहास ही समझ रही थी.

सूबे के कई जिलों में शिक्षकों का बड़ा वर्ग इस आयोजन को फिजूलख़र्ची और बकवास ही क़रार दिया. वहीं कई ज़िलों में इसका शांतिपूर्ण तरीक़े से शिक्षकों ने विरोध भी किया. यह अलग बात है कि शिक्षकों का यह विरोध समारोह की चकाचौंध में नज़र नहीं आया. बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघर्ष साझा मंच के सदस्यों ने इस दौरान उपवास पर रहकर काम किया. मंच के सदस्यों ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर लापरवाही और

संवेदनहीनता बरतने का आरोप भी लगाया. साझा मंच के इस विरोध के कई कारण भी हैं. बताते चलें कि 95 प्रतिशत से ज्यादा स्कूल बिना प्रधानाध्यापक के ही चल रहे हैं. दो साल पहले पटना उच्च न्यायालय ने यह कहा था कि विभाग चार महीने के अंदर सारे स्कूलों में प्रधानाध्यापक की पदस्थापना करे. अगर ऐसा नहीं करती है तो विद्यालय बिना प्रधानाध्यापक के ही चलेगा. और इसके लिए राज्य सरकार ज़िम्मेवार होगी. दो साल बीत जाने के बाद भी उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में शिक्षा के विभाग के कान पर जूं तक नहीं रेंगी है.

सूबे की सरकार ने शिक्षकों को ठेके पर बहाल करना भी शुरू किया. इससे जुड़ी ढेरों समस्याएं उनके सामने सुरसा की तरह मुंह बाए खड़ी हैं. आए दिन ये नियोजित शिक्षक विभाग को तो छोड़िए, ख़ुद सीएम तक को परेशानी में डाल देते हैं. इस समय कई शिक्षाविदों ने यह कहकर आलोचना भी की थी कि यह कैसा निर्णय है कि जिनके हाथों में हमारे बच्चों का भविष्य होता है, जो उसे बनाते–सवांरते हैं, उन्हीं को ठेके पर बहाल किया जा रहा है. पठन–पाठन से जुड़े जो भी फ़ैसले सरकार द्वारा लिए जाते हैं, उसमें दूरदर्शिता का अभाव भी दिखता है. पिछले साल नवंबर–दिसंबर के महीने में सरकार ने पूरे बिहार में 18 हज़ार शिक्षकों को स्नातक प्रशिक्षित पदों पर प्रोन्नत किया था. ये शिक्षक आने वाले 18 दिसंबर को प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नत होने के योग्य हो जाएंगे, लेकिन विभाग और उसके अधिकारी साज़िशन उन शिक्षकों को प्रधानाध्यापक पद पर रिक्तियों के बावजूद प्रोन्नत करने से वंचित करने जा रहे हैं. 31 दिसंबर 2013 को स्नातक वेतनमान पाने वाले लगभग 18 हज़ार शिक्षकों को विभाग यह कह कर प्रोन्नति में अड़ंगा लगा रहा है कि जिनकी नियुक्ति 1994 के बाद हुई है, उन्हें प्रोन्नत नहीं किया जाएगा. विभाग का यह निर्णय किसी के गले नहीं उतर रहा है. हैरत की बात यह है कि सरकार अपने ही नियम के विरुद्ध जा रही है. प्रोन्नति नियमावली 2011 में कहा गया है कि जो भी शिक्षक स्नातकोत्तर हैं और जिन्हें एक साल तक स्नातक वेतनमान में काम करने का अनुभव है, उन्हें हेडमास्टर पद पर प्रोन्नत किया जा सकता है. सरकार के इस फ़ैसले के बाद से ऐसी आशंका जताई जा रही है कि उसके इस निर्णय के बाद नियोजित शिक्षकों के साथ साथ अब ये 18 हज़ार शिक्षक भी नीतीश की आगामी संकल्प यात्रा के दौरान उनका कड़ा विरोध करेंगे.

शिक्षा दिवस के उद्घाटन समारोह के दौरान शिक्षा मंत्री ने यह घोषणा की कि राज्य के सभी विद्यालयों को अगले साल उत्कृष्ट विद्यालय में तब्दील किया जाएगा. इस बार 274 विद्यालयों को उस श्रेणी में तब्दील किया गया है. शाही के अति उत्साही बयान की सच्चाई यह है कि कुल 76 हज़ार प्रारंभिक विद्यालयों में से पूरे सूबे में मात्र 274 ही उत्कृष्ट की श्रेणी में आने लायक थे, जो दशमलव पांच प्रतिशत के आंकड़े से भी कम है. इससे सरकार की उदासीनता और उसके खोखले प्रयासों की झलक साफ मिलती है. बावजूद इसके, सरकार समारोह आयोजित कर अपनी पीठ ख़ुद थपथपाती है.

इसी तरह एक साथ सूबे के कई स्कूलों को उत्क्रमित कया गया. अधिक फंड जुटाने के फेरे में सरकार ने उन स्कूलों को भी उत्क्रमित कर दिया, जिनके पास संसाधनों का घोर अभाव था. उदाहरण के तौर पर आप बेगूसराय जिले के सुघरन मध्य विद्यालय को देख सकते हैं. भूमि व भवनहीन प्राथमिक विद्यालय सुघरन को उत्क्रमित कर मध्य विद्यालय बना दिया गया. अधिकारियों की लापरवाही यहीं ख़त्म नहीं हुई. उन्होंने इसी विद्यालय में एक भवनहीन प्राथमिक विद्यालय सुघरन को भी शिफ्ट कर दिया. अब उत्क्रमित मध्य विद्यालय सुघरन की स्थिति काफी दयनीय है. इसे देखकर तबेला भी आपको इससे बेहतर लगेगा. स्थिति यह है कि पूर्व के तीन कमरे और चार निर्माणाधीन कमरों में दो स्कूलों की 13 कक्षाएं चलती हैं. और इस दयनीय स्थिति में कुल 1200 बच्चे पढ़ने को विवश हैं. ऐसा नहीं है कि राजधानी के सरकारी स्कूलों की स्थिति बहुत बेहतर है. जब पूरी राजधानी शिक्षा दिवस के समारोह में व्यस्त थी, पुरस्कार वितरण, व्याख्यानों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सिलसिला जारी था, तो राजधानी के कुछ बच्चे अफसोस में डूबे ख़ुद को कोस भी रहे थे. शास्त्री नगर मध्य विद्यालय, उच्च विद्यालय टीके घोष, मध्य विद्यालय धीराचक सहित कई ऐसे विद्यालय हैं, जहां संसाधनों का घोर अभाव है. विद्यालय को देखकर लगता है कि ये हादसे को आमंत्रित कर रहे हों.

बिहार के माध्यमिक और उच्च शिक्षा की बात छोड़ भी दें तो प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति तो बहुत ही भयावह है. मानक कहता है कि 40 छात्र पर एक शिक्षक होना चाहिए. लेकिन आयोजनों में व्यस्त सरकार को शायद पता नहीं है कि यहां प्राथमिक विद्यालयों में कुल सवा दो करोड़ बच्चे हैं, जिन्हें पढ़ाने के लिए मात्र तीन लाख शिक्षक हैं. इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि शिक्षकों की कितनी कमी है. अब तक सरकार नियोजन के ही मामले में अपने लक्ष्य को नहीं पूरा कर सकी है. सूबे में टीईटी उत्तीर्ण शिक्षकों की कुल संख्या एक लाख पच्चीस हज़ार के आसपास बताई जाती है, जबकि ढाई लाख पद रिक्त हैं. बावजूद इसके, अभी तक मात्र पच्चीस हज़ार शिक्षकों को ही नियोजित किया जा सका है. आयोजनों में व्यस्त विभाग को उन्हें पदस्थापित करने का समय नहीं है. हैरत की बात है कि उन पच्चीस हज़ार शिक्षकों को नियुक्ति के बाद दस माह बीत जाने के बाद भी वेतन नहीं दिया गया है. अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिना वेतन के ये शिक्षक कितनी कुशलता से पठन–पाठन कराते होंगे. इतना ही नहीं, उन शिक्षकों से बिहार में और भी काम लिए जाते हैं. मसलन जनगणना करना, आपदा के वक्त राहत वितरण कार्य करना, मतदाता सूची बनाना, गाय–बकरी गिनना और कभी कभी बड़े अधिकारी अपने यहां उन्हें क्लर्की करने के लिए भी बुला लेते हैं. बिहार में शिक्षा की स्थिति को आंकड़े कुछ और साफ कर देते हैं. सूबे में प्राथमिक और मध्य विद्यालय मिलाकर कुल 76 हज़ार के आसपास स्कूल संचालित होते हैं. इनमें से 8600 स्कूल भवनहीन हैं. नियम क़ानून की बात करें तो प्राथमिक विद्यालय के लिए जब तक साढ़े सात कट्ठा जमीन न हो और माध्यमिक विद्यालय के लिए 16 कट्ठा ज़मीन न हो, तब तक स्कूल नहीं खोला जा सकता, लेकिन बिहार में 8600 स्कूल शैक्षणिक ग्राफ बढ़ाने और अधिक फंड लेने के लिए आनन–फानन में खुले. 7276 स्कूलों की रसोई को शेड तक मयस्सर नहीं हैं. 72 हज़ार स्कूलों में मिड डे मील योजना चलती है. प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में क़रीब दो करोड़ बच्चे नामांकित हैं, उनमें एक करोड़ तीस लाख बच्चों को मिड डे मील मिलता है. शेष बच्चों के लिए या तो अभी तक व्यवस्था नहीं हो सकी है या फिर वे स्कूल आते नहीं हैं. जब नियोजित शिक्षकों की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठने शुरू हुए तो सरकार ने उन्हें प्रशिक्षित करवाया. अब इग्नू ने जो प्रमाणपत्र उन्हें दिए हैं, वही एनसीटीइ मान नहीं रही है. गत साल ही यूनिसेफ ने *समझें–सीखें* नाम से अध्ययन रिपोर्ट भी तैयार की थी. रिपोर्ट में कहा गया था कि बिहार में 89 प्रतिशत शिक्षण तालिका यानी रूटीन का अनुपालन नहीं करते. 65 विद्यालयों में शिक्षक ब्लैकबोर्ड का ही प्रयोग ही नहीं करते. 98 प्रतिशत कक्षाओं में शिक्षक पाठ योजना का उपयोग नहीं करते. 86 प्रतिशत कक्षाओं में पाठ से संबंधित गतिविधियां ही नहीं होती. 81 प्रतिशत कक्षाओं में किसी भी रूप में उसका मूल्यांकन नहीं होता और 97 प्रतिशत शिक्षकों को उनकी कक्षाओं के शैक्षिक लक्ष्य के बारे में ही जानकारी ही नहीं रहती. बिहार में शिक्षा, उसकी आधारभूत संरचना वाकई ख़तरनाक दौर से गुज़र रही है. उस पर से अधिकारियों की लापरवाही, दृष्टिहीनता उसे और भयावह बनाती है. इस संदर्भ में प्राथमिक शिक्षक साझा मंच के रंजन कुमार कहते हैं कि जब बिहार की शिक्षा व्यवस्था अपने सबसे नाज़ुक दौर से गुज़र रही है तो ऐसे में समारोह मनाना कहीं से उचित नहीं है. अधिकारियों और विभाग की लापरवाही की वजह से हमारे शिक्षक अपनी अधिकतम योग्यता का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं. रंजन कहते हैं कि अब तक पूरे सूबे में 60 प्रतिशत बच्चों को किताबें नहीं मिली हैं, जो उन्हें क़ायदे से मार्च तक ही मिल जानी थीं. हैरत की बात है कि सरकार किताबों के नाम पर पैसे का रोना रोती है और समारोह के नाम पर करोड़ों ख़र्च करती है. ■

> **बिहार के माध्यमिक और उच्च शिक्षा की बात छोड़ भी दें तो प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति तो बहुत ही भयावह है. मानक कहता है कि 40 छात्र पर एक शिक्षक होना चाहिए, लेकिन यहां प्राथमिक विद्यालयों में कुल सवा दो करोड़ बच्चे हैं, जिन्हें पढ़ाने के लिए मात्र तीन लाख शिक्षक हैं. इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि शिक्षकों की कितनी कमी है. अब तक सरकार नियोजन के ही मामले में अपने लक्ष्य को नहीं पूरा कर सकी है.**

feedback@chauthiduniya.com

> नॉर्थ ईस्ट रीजनल पॉलिटिकल फ्रंट का गठन होने के बाद संयोजक नेफ्यू रियो ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट रीजनल पॉलिटिकल फ्रंट एक पॉलिटिकल पार्टी होगी. यह प्रादेशिक राजनीतिक दलों की सामूहिक ताक़त होगी. लोकसभा चुनावों में भी मिल-जुल कर आपस में सहमति से अपना प्रतिनिधि घोषित करेंगे. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर को एक ही नज़र से देखती है. उनके लिए पूर्वोत्तर का मायने असम है, इसलिए बाक़ी राज्यों को उपेक्षा का शिकार होना पड़ता है.

जातीय गणित में उलझा उत्तर प्रदेश

अजय कुमार

उत्तर प्रदेश की जनता दिल्ली की गद्दी के लिए किसे अपना रहनुमा चुनेगी? चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा? बढ़ती मंहगाई और भ्रष्टाचार का मुद्दा चुनाव में क्या भूमिका निभाएगा? वोट बैंक की राजनीति लोकसभा चुनाव में भी हावी रहेगी? अगड़े वोटर किधर जाएंगे, पिछड़ों का वोट किसे मिलेगा? दलित बसपा के ही साथ जमे रहेंगे? मुसलमान क्या पाला बदलेंगे? या फिर अबकी पुरानी रवायतों को तोड़कर जनता प्रदेश के विकास की बात करने वालों को चुनेगी? तमाम ऐसे ही सवालों का जबाव तलाशने में उत्तर प्रदेश के लगे हुए हैं. जनता भी इन सवालों में ख़ूब दिलचस्पी ले रही है, पर किसी के हाथ में सही नंबर की चाबी नहीं लग रही है, जिससे उसकी क़िस्मत का ताला खुल जाए. विभिन्न दलों के नेताओं के बीच दिल्ली की सत्ता के लिए चूहे-बिल्ली जैसा खेल चल रहा है. चरित्र हनन से लेकर राजनीतिक चीरहरण तक सब कुछ राजनीति के मंच पर घटित हो रहा है. राज-नेताओं की *मैं हीरो बाकी सब ज़ीरो* की अवधारणा ने राजनीति को बाज़ार और जनता को ग्राहक बना दिया है. फ़िलहाल, ख़ामोशी की चादर ओढ़कर जनता सबको सुन रही है, लेकिन इसे इस बात का मलाल ज़रूर है कि नेताओं के बड़े-बड़े वायदों-इरादों और बड़बोलेपन ने लोकतंत्र को शर्मसार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है. मैं सही, बाक़ी सब ग़लत, राजनेताओं में पनपती यह सोच देश के लिए ख़तरे की घंटी साबित हो रही है, लेकिन उसकी किसी को रत्ती भर भी परवाह नहीं है.

आज हालात यह हैं कि जो नेता खोजने पर भी नहीं मिलते थे, वह जनता के क़रीब आने का मौक़ा तलाशते रहते हैं. सामाजिक से लेकर निजी कार्यक्रमों तक में नेताओं की भागीदारी अचानक काफ़ी तेजी से बढ़ गई है. बड़ी-बड़ी जनसभाएं करके मतदाताओं को लुभाया जा रहा है. राजनीति के मैदान में कांग्रेस-भाजपा और समाजवादी पार्टी तो काफ़ी समय से ताल ठोंक ही रही थीं, अब बसपा नेत्री मायावती भी मैदान में कूद पड़ी हैं. गत दिनों वह लगभग तीन माह के बाद लखनऊ पहुंची तो उनके तेवरों ने विरोधियों के छक्के छुड़ा दिए. संगठन के पेंच कसने, प्रत्याशियों की ज़मीनी हक़ीक़त का अंदाज़ा लगाने के अलावा बसपा सुप्रीमो मायावती के पहले ही वार में साफ़ हो गया कि वह किसी को छूट नहीं देंगी. भाजपा ने उन्हें तिकड़ी की उपमा दी तो माया ने आडवाणी-मोदी और राजनाथ को तिकड़ी कह कर संबोधित किया. उन्होंने कहा कि

इस तिकड़ी के बीच चल रहे आपसी संघर्ष का फ़ायदा बसपा को मिलेगा. इसके साथ ही कांग्रेस को भी बता दिया कि वह इस ग़लतफहमी में न रहे कि बसपा उनके साथ मिलकर आम चुनाव लड़ने जा रही है. माया के बयान से इन कांग्रेसियों को करारा झटका लगा है, जो 2014 के आम चुनाव मे बसपा की बैसाखी से कांग्रेस को मज़बूती देने की कोशिश में लगे थे. इस मामले में एक केन्द्रीय मंत्री और बसपा की तरफ़ से कोई बयान नहीं जारी करने की वजह से गठबंधन को लेकर अफवाहों का बाज़ार काफ़ी समय से गर्म था. बसपा नेतृत्व को क़ानूनी मामलों से राहत दिए जाने के बाद तो कांग्रेस-बसपा के बीच कुछ पक रहा है, इसको लेकर चर्चा काफ़ी ही गंभीर हो गई थी. माया ने न केवल कांग्रेस के साथ गठबंधन की बात नकार दी, बल्कि उन्होंने राहुल को भी आड़े हाथों लिया. माया ने राहुल पर तंज कसते हुए कहा कि वह चाहें तो हज़ार दलित नेता पैदा कर सकते हैं, उन्हें किसने रोका है. ग़ौरतलब हो राहुल ने गत दिनों आरोप लगाया था कि मायावती ने किसी दूसरे दलित नेता को नहीं उभरने दिया था. वैसे, गठबंधन वाली बात पर राजनीतिक पंडितों का कहना है कि मायावती ऐसे ही नहीं कांग्रेस से गठबंधन की बात से इन्कार कर रही हैं. उनका 1996 में कांग्रेस के साथ का अनुभव अच्छा नहीं है. तब दोनों ने मिलकर उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव लड़ा था. इस प्रयोग से बसपा को नुकसान उठाना पड़ा था और बसपा नेतृत्व ने कहा भी था कि दलित वोट बैंक तो कांग्रेस में ट्रांसफर हो गया, लेकिन कांग्रेस के वोटरों ने बसपा प्रत्याशियों को वोट नहीं दिया. बसपा के एक नेता का कहना था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दंगों के बाद कांग्रेस को अपने सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल पर भरोसा नहीं रह गया है, इसीलिए वह बसपा की ओर देख रही है. माया का कहना था आगामी लोकसभा और चार राज्यों के चुनाव में बसपा बैलेंस ऑफ पॉवर बन कर उभरेगी.

बसपा सुप्रीमो ने एक तरफ तो लम्बे समय से चल रहे कयासों को विराम देते हुए स्पष्ट कर दिया कि न तो उनका गठबंधन कांग्रेस से होगा, न ही भाजपा से, वह अपने दम पर चुनाव लड़ेगी तो दूसरी तरफ मायावती ने सबसे तगड़ा हमला अपनी प्रबल प्रतिद्वंद्वी सपा पर किया. समाजवादी पार्टी के पिछड़े कार्ड की हवा निकालने की तैयारी करके दिल्ली से लखनऊ पधारीं माया ने पिछड़ों को मुलायम से सचेत रहने का आ वान किया. समाजवादी पार्टी की सामाजिक न्याय यात्रा को उन्होंने छलावा करार देते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी ने पहले ही ओबीसी (पिछड़ा वर्ग) का ख़ासा नुकसान किया है, अब इसे और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. बसपा सुप्रीमो ने कहा कि सपा को सामाजिक न्याय यात्रा पर जाने से पूर्व इन 17 जातियों के साथ किए गए पहले अपराध पर मांफ़ी मांगनी चाहिए थी. बताते चलें कि सपा सरकार ने पिछले शासनकाल में भी एक शासनादेश जारी किया था, जिसे कोर्ट ने अवैध क़रार दे दिया था. बसपा समाजवादी पार्टी पिछड़ा कार्ड खेलने को लेकर पूरी तरह से तत्पर है.

बसपा नेत्री ने मुसलमानों पर भी डोरे डाले. मुज़फ़्फ़रनगर दंगों के आरोपियों को कठोर क़ानूनी सज़ा न मिल पाने का मुद्दा उठाते हुए मायावती ने इसे सपा और भाजपा के बीच मिलीभगत से जोड़कर पेश किया. माया का हमला तीखा था. यही वजह थी कि समाजवादी नेता बुरी तरह से बौखला गए. सपा के प्रवक्ता और अखिलेश सरकार में मंत्री राजेन्द्र चौधरी ने माया पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वह पुराने पन्ने पढ़ने की आदी हैं. सपा-भाजपा के बीच मिलीभगत का अरोप लगाते समय मायावती अपने राखी के बंधन को भूल गईं. भाजपा के ही चलते वह तीन बार मुख्यमंत्री बनी थीं. भाजपा ने भी माया को नसीहत दी कि वह भाजपा नेताओं के लिए परेशान न हों और अपनी चिंता करें.

बहरहाल, इसे देश का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि हमारे नेतागण अपने राजनीतिक हित साधने के लिए देश महापुरुषों को भी जाति के फंदे में कसने से बाज़ नहीं आते हैं, जो महापुरुष ताउम्र जातिवाद से दूर रहे, उनकी जातियों को खंगाला जा रहा है. सरदार पटेल कभी भारत की आन-बान-शान हुआ करते थे, लेकिन अब उनका नाम पिछड़ों को लुभाने के लिए इस्तेमाल होता है. पटेल की विरासत को लेकर भाजपा और कांग्रेस में ही नहीं, कई क्षेत्रियों दलों तक में ठनी हुई है. इसी प्रकार से महात्मा गांधी कभी देश के बापू हुआ करते थे, लेकिन वो दिन लद गए. अब गांधी जी बनिया जाति के हैं. स्वामी विवेकानंद कभी राष्ट्र के गौरव होते रहे होंगे, अब कायस्थ जाति के हैं. समाजवादी विचारधारा के चिंतक डॉ. राम मनोहर लोहिया जी अब अग्रवाल हो गए हैं. राष्ट्र के लिए त्याग तपस्या और शौर्य के लिए कभी स्थापित रहे होंगे महाराणा प्रताप, कभी बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान का मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया होगा, लेकिन आज महाराणा प्रताप राजपूत जाति के तो बाबा साहब दलित जाति का होने के कारण अपनी पहचान बना रहे हैं. सरदार वल्लभभाई पटेल कभी राष्ट्रीय एकता के पर्यायवाची रहे होंगे, लेकिन आज कुर्मी जाति के हैं. सारे महापुरुष किसी न किसी जाति के फ्रेम में बांध दिए गए हैं. बात पिछले कुछ दशकों की करें तो इस दौर में भी कई सर्वमान्य नेताओं को भी उनके समर्थकों ने समय-समय पर जातिवाद की चाशनी में खूब डुबोया. भाजपा ने अटल बिहारी वाजपेयी, कलराज मिश्र, मुरली मनोहर जोशी को ब्राहमण, कल्याण सिंह को लोध, राजनाथ सिंह को क्षत्रिय, ओम प्रकाश सिंह को पिछड़ा समाज, विनय कटियार को हिन्दुत्व का चेहरा बनाकर खूब राजनीति की. इसी तरह से कांग्रेस ने पहले कमलापति त्रिपाठी, नारायण दत्त तिवारी, राम प्रकाश गुप्ता, महावीर प्रसाद जैसे तमाम नेताओं का इस्तेमाल जातिवाद की राजनीति को हवा देने के लिए किया और अब यही काम केन्द्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल, सलमान खुर्शीद, बेनी प्रसाद वर्मा जैसे नेता कर रहे हैं. तीन बार मुख्यमंत्री बने मुलायम सिंह यादव हमेशा अपने आप को पिछड़ों और मुसलमानों के नेता के रूप में प्रचारित-प्रसारित करते रहे. यही काम अब उनके पुत्र अखिलेश यादव कर रहे हैं. सपा में आजम खां अपने आप को अल्पसंख्यकों का रहनुमा, नरेश अग्रवाल वैश्य समाज का ठेकेदार समझते हैं. मायावती तो अपने आप को दलितों का मसीहा ही मानती हैं. भले ही उनके विरोधी कहते रहते हैं कि मायावती दलित की नहीं दौलत की बेटी हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

नॉर्थ ईस्ट रीजनल पॉलिटिकल फ्रंट

क्षेत्रीय राजनीति का नया प्रयोग

एस. बिजेन सिंह

पूर्वोत्तर की लगभग सभी प्रादेशिक पार्टियों ने मिलकर नॉर्थ ईस्ट रीजनल पॉलिटिकल फ्रंट का गठन किया है. 20 अक्टूबर को इस फ्रंट के गठन के बाद फ्रंट की ओर से कहा गया कि इसका मक़सद पूर्वोत्तर से जुड़े विभिन्न मसलों पर एकजुट होकर आवाज़ उठाना है. फ्रंट जल, जंगल, जमीन के मुद्दों को उठाने के साथ उन मसलों को भी उठाएगा, जो भाजपा और कांग्रेस की चिंताओं में शामिल नहीं हैं. पूर्वोत्तर के ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकारें रही हैं, लेकिन पार्टी पूर्वोत्तर के वास्तविक मुद्दों को सुलझाने में असफल रही है. अब देखना यह है कि यह फ्रंट कितना सफल हो पाता है.

फ्रंट में शामिल दस पार्टियां

- नागा पीपुल्स फ्रंट, नागालैंड
- असम गण परिषद, असम
- यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी, मेघालय
- मणिपुर पीपुल्स पार्टी, मणिपुर
- मणिपुर स्टेट कांग्रेस पार्टी
- डेमोक्रेटिक पीपुल्स फ्रंट
- इंडिजीनस पीपुल्स फ्रंट, त्रिपुरा
- पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल
- मिजो नेशनल फ्रंट, मिजोरम
- हिल्स स्टेट्स डेमोक्रेटिक पार्टी, मेघालय

पूर्वोत्तर के कई अहम मसलों पर एक साथ सामना करने और पूर्वोत्तर की सारी प्रादेशिक पार्टियों को मज़बूत करने के उद्देश्य से नॉर्थ ईस्ट रीजनल पॉलिटिकल फ्रंट का गठन 20 अक्टूबर को किया गया है. इस फ्रंट का संयोजक नागा पीपुल्स फ्रंट (एनपीएफ) नागालैंड के नेता और वर्तमान मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो को बनाया गया है. मुख्य सलाहकार असम के पूर्व मुख्यमंत्री और असम गण परिषद (एजीपी) के अध्यक्ष प्रफुल्ल कुमार महंत, सलाहकार सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन चामलिंग, मिजोरम के पूर्व मुख्यमंत्री जोराम थांगा और मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री दोंकूपर राय को बनाया गया. गुवाहाटी स्थित ब्रह्मपुत्र होटल में आयोजित पूर्वोत्तर की क्षेत्रीय पार्टियों की इस बैठक में क्षेत्रीय पार्टियों के नेताओं ने हिस्सा लिया था. बैठक में साथ देने अकाली दल के सुरजीत सिंह बरनाला, तेलुगूदेशम पार्टी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू भी शामिल थे. हाल ही में प्रफुल्ल कुमार महंत ने दिल्ली में चंद्र बाबू नायडू से मुलाकात की थी. साथ में मणिपुर पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष एन सोभाकिरण, उपाध्यक्ष एच. मनिसना और प्रवक्ता हैक्रुजम नवश्याम, मणिपुर स्टेट कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष वाई मणि और मणिपुर पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के अध्यक्ष जी. तोनसना शर्मा आदि ने हिस्सा लिया था.

इस फ्रंट का हेडक्वार्टर गुवाहाटी में बनाया जाएगा. पूर्वोत्तर की सभी रीजनल पार्टियों से तीन-तीन प्रतिनिधियों को समन्वयक के तौर चुना गया है. मिजो नेशनल फ्रंट अपने राज्य में चुनाव के चलते बैठक में शामिल नहीं हो पाया. मगर उसने यह आश्वासन ज़रूर दिया कि इस फ्रंट में वो भी हिस्सा लेगा.

बहरहाल, फ्रंट का गठन होने के बाद संयोजक नेफ्यू रियो ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट रीजनल पॉलिटिकल फ्रंट एक पॉलिटिकल पार्टी होगी. यह प्रादेशिक राजनीतिक दलों की सामूहिक ताक़त होगी. लोकसभा चुनावों में भी मिल-जुल कर आपस में सहमति से अपना प्रतिनिधि घोषित करेंगे. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर को एक ही नज़र से देखती है. उनके लिए पूर्वोत्तर के मायने असम, इसलिए बाक़ी राज्यों को उपेक्षा का शिकार होना पड़ता है. इससे बचने के लिए सभी प्रांतीय राजनीतिक पार्टियों का समूह यह फ्रंट बना रहा है. राज्यों के सार्वजनिक मुद्दों को मिल कर सामना करेंगे. आने वाले लोकसभा चुनाव में भी फ्रंट के घटक दल एक साथ सामना करेंगे. उन्होंने साफ किया कि हम कांग्रेस और बीजेपी का साथ कभी नहीं देंगे.

इस फ्रंट का मक़सद पूर्वोत्तर के राज्यों में व्याप्त कई महत्वपूर्ण समस्याओं का मिलकर सामना करना है. कल्चर, सीमा, सोशल पॉलिटिकल और इकॉनोमिक्स फ्रंट की रक्षा करना और संविधान के अनुसार सिक्स शिड्यूल के तहत राज्यों को जो लाभ मिलना चाहिए, वह अब तक नहीं मिला. फ्रंट का मकसद उसके लिए आवाज़ उठाना है. चीन का अरुणाचल प्रदेश पर सीमा बढ़ाने और अवैध कब्ज़ा करने के विरोध में केंद्र को तत्काल सूचित करेंगे, ताकि अवैध कब्ज़ा रोका जा सके. केंद्र सरकार को चीन पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करनी चाहिए. ऊपरी ब्रह्मपुत्र पर डैम बनाकर नदी को मोड़ने की चीन की प्रक्रिया को रोकना होगा. ब्रह्मपुत्र पूर्वोत्तर की जान है, ऐसे में केंद्र सरकार की असंवदेन-शीलता पर फ्रंट द्वारा असंतुष्टि व्यक्त की गई. पूर्वोत्तर को लेकर केंद्र सरकार चीन पर सख़्त क़दम उठाने होंगे. वैसे कांग्रेस सरकार कई वर्षों से पूर्वोत्तर के कई राज्यों में राज कर रही है. मगर जनता के दुख-दर्द समझने में सक्षम नहीं है. मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मेघालय में कांग्रेस की सरकार है. वहां के आदिवासियों की मूलभूत समस्याएं आज भी वैसी की वैसी बनी हुई हैं. कहने को तो आज़ादी के 65 वर्ष हो गए, मगर भ्रष्टाचार का स्तर इतना बढ़ गया है कि आम जनता गरीबी का जीवन जीने के लिए विवश है. छोटे-मोटे सरकारी काम के लिए भी घूस देनी पड़ती है. फ्रंट मणिपुर के मुद्दों पर भी आवाज़ उठाएगा. हाल में इंडो म्यांमार बॉर्डर फेंसिंग का मुद्दा गरम रहा. बर्मा द्वारा बॉर्डर फेंसिंग में अवैध कब्ज़ा किया गया है. इस कब्जे को तत्काल रोकना होगा, क्योंकि बांग्लादेश 15 किलोमीटर मणिपुर की तरफ़ बढ़ा कर फेंसिंग कर रहा है. आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट (अफस्पा) के बारे में भी फ्रंट आवाज़ उठाएगा. पूर्वोत्तर में वर्षों से लागू अफस्पा वहां की जनता से जीने का अधिकार छीन रहा है. यह कितना भयानक क़ानून है, इसका उदाहरण इरोम शर्मिला प्रकरण को देखकर समझा जा सकता है. शर्मिला इस क़ानून को हटवाने के लिए पिछले 13 सालों से आमरण अनशन कर रही हैं. मगर सरकार कभी तैयार नहीं हुई.

दूसरी बात कि नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो अपने राज्य में एक महत्वपूर्ण नेता के तौर पर जाने जाते हैं. फ्रंट बनाने के बाद लग रहा है कि वे अपने राज्य में ही न सिमट कर पूरे पूर्वोत्तर में अपनी ख्याति पाना चाहते हैं. वे पूर्वोत्तर के नेता बन कर राष्ट्रीय राजनीति के फलक में उभरना चाहते हैं. त्रिपुरा और नागालैंड में कांग्रेस की सरकार नहीं है. नागालैंड में क्षेत्रीय पार्टी नागा पीपुल्स फ्रंट और त्रिपुरा में सीपीआई (एम) की सरकार है. त्रिपुरा में सीपीआई (एम) की छवि एक ईमानदार सरकार की है. वहां के आदिवासियों के लिए कोई ठोस क़दम अब तक नहीं उठाया गया. इसी वजह से वहां के आदिवासी अपने ही क्षेत्र में बेगाने हो गए. वहां के आदिवासी जो असली त्रिपुरावासी हैं, बाहरी बांग्लादेशी लोगों के अवैध कब्ज़े से जंगल में जीवन यापन करने को मजबूर हो रहे हैं. नागालैंड एकमात्र राज्य है, जो अपनी मर्जी का करता है, क्योंकि वहां की सरकार क्षेत्रीय पार्टी से बनी है. बीजेपी तो पूर्वोत्तर में आज तक कोई ख़ास जगह बना नहीं पाई है.

वैसे घोटालों और महंगाई से त्रस्त पूर्वोत्तर के लोग इस बार के लोकसभा चुनाव में अपने मतदान के दम पर अपने प्रतिनिधि चुनेंगे. विकास के नाम पर कांग्रेस सरकारें जनता की ज़मीन हड़प रही हैं. कम दामों में कभी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने के नाम पर तो कभी नेशनल हाइवे के नाम पर ग़रीब जनता से ज़मीन हड़प रही हैं. ये सरकारें विदेशी कंपनियों को प्राकृतिक संसाधनों को हड़पने की इजाज़त खुल कर दे रही हैं. वे विरोध करने वालों पर गोली चलवाती हैं. ऐसे में जनता अगर कांग्रेस से परेशान है तो वह लोगों की बात सुनने वाले और समझने वाले जनप्रतिनिधि चुनेंगे. अगर नहीं तो स्थिति जस की तस बनी रहेगी. जब तक वोट में अपने अधिकार का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक कोसते रहेंगे.

मजे की बात यह है कि पीए संगमा के नेतृत्व वाली पार्टी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी को नहीं बुलाया है. 2009 में भी एनसीपी लीडर पूर्व लोकसभा स्पीकर पीए संगमा ने पूरी कोशिश कर क्षेत्रीय पार्टियों का गठन किया था- नार्थ ईस्ट पीपुल्स फ्रंट. संगमा को पता था कि लोसकभा में पूर्वोत्तर के 25 एमपी हैं. इसके द्वारा संसद में एक बड़ा बदलाव लाया जा सकता है. मगर यह प्रयोग सफल नहीं हुआ. एक आश्चर्यजनक सवाल यह भी है कि सबसे ज्यादा अलगाव की भावना पूर्वोत्तर में है. इन राज्यों के लोग केंद्र सरकार पर यक़ीन नहीं करते, मगर चुनाव में वोट कांग्रेस को ही दिया जाता है. जल, जंगल, ज़मीन की बात करने वाली स्थानीय पार्टियों का तो एक भी प्रतिनिधि सफल नहीं हो पाता है. उदाहरण के तौर पर पिछली बार मणिपुर की क्षेत्रीय पार्टी मणिपुर पीपुल्स फ्रंट द्वारा एक भी प्रतिनिधि नहीं ला पाने की वजह से चुनाव आयोग ने इसकी मान्यता बर्ख़ास्त कर दी थी.

इन हालातों में कमज़ोर पड़ीं क्षेत्रीय पार्टियां कैसे अपनी ताक़त जुटा पाएंगी और वर्षों से शासन कर रही कांग्रेस सरकार का सामना कर पाएंगी? अब देखना यह है कि कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ यह फ्रंट आने वाले चुनाव में क्या चमत्कार दिखाएगा और कितने उम्मीदवार संसद में भेज पाएगा, इसकी पहली झलक मिजोरम विधानसभा चुनाव के दौरान देखने को मिलेगी. ■

sbijensngh@gmail.com

> कोटा में रहने वाले जमील अहमद एडवोकेट जिनका किसी पार्टी से कोई व्यावहारिक संबंध नहीं है, कहते हैं कि कांग्रेस की सबसे बड़ी कमी यह है कि उसके राज में दंगे बहुत होते हैं और इससे भी अधिक दुखद बात यह है कि दंगों को नियंत्रित भी नहीं कर पाती. मुसलमानों को लेकर उसकी नीयत साफ़ नहीं है. वह मुसलमानों से वादे तो बहुत करती है, लेकिन इन पर अमल नहीं करती.

राजस्थान विधानसभा चुनाव

मुस्लिम जा सकते हैं भाजपा की ओर

राजस्थान में पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने मुसलमानों से बड़े-बड़े वादे किए थे, लेकिन सरकार बनने के बाद कांग्रेस पार्टी की गहलोत सरकार का रवैया वैसा ही रहा जैसा कि कांग्रेस और अन्य कथित मुस्लिम समर्थक पार्टियां करती रही हैं. गहलोत सरकार ने मुसलमानों के कल्याण के लिए कोई ऐसा क़दम नहीं उठाया, जिससे मुसलमानों में कोई उम्मीद जगती. इसे लेकर मुस्लिम समुदाय में नाराज़गी है. प्रदेश के मुस्लिम नेताओं का कहना है कि कांग्रेस हमसे वोट तो लेती है लेकिन हमारे कल्याण पर ध्यान नहीं देती. वह धर्मनिरपेक्षता के नाम पर मुसलमानों को सिर्फ़ धोखा देती रही है, इसलिए हम अन्य राजनीतिक विकल्पों पर विचार करेंगे. ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि राजस्थान में इस बार 15-20 फ़ीसद मुस्लिम वोट भाजपा को मिल सकते हैं.

शाहिद नईम

आगामी दिसंबर में राजस्थान विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की गहलोत सरकार को कई चुनौतियों का सामना होगा, जिसका कारण मुस्लिम हैं, जिनकी आबादी राज्य में 11.3 प्रतिशत है. मुसलमान कांग्रेस से बेहद नाराज़ दिखाई दे रहे हैं. उनका कहना है कि जब से देश आज़ाद हुआ, कांग्रेस उन्हें धोखा देती आ रही है. चुनावी मौसम आते भाजपा का डर दिखाकर धर्मनिरपेक्षता के नाम पर मुसलमानों से वोट ले लेती है, लेकिन जब चुनाव ख़त्म हो जाते हैं, वह उन्हें पराया समझने लगती है. कांग्रेस का यह रवैया पिछले 66 वर्षों से जारी है. मुसलमानों को यह भी शिकायत है कि कांग्रेस मुसलमानों को केवल वोट बैंक ही समझती है, विकास की राह में वह उन्हें शामिल ही नहीं करना चाहती. वह तो महज़ वादों के सहारे उन्हें ज़िंदा रखना चाहती है. व्यावहारिक रूप से वह उनके लिए कुछ भी नहीं करना चाहती. कांग्रेस ने मुसलमानों को लेकर पिछले विधानसभा चुनावों में अपने घोषणापत्र में बड़े-बड़े वादे किए थे, लेकिन मौजूदा सरकार का कार्यकाल पूरा हो गया और कांग्रेसी वादे मुसलमानों को अभी तक मुंह चिढ़ा रहे हैं. ऐसी स्थिति में लगता है कि कांग्रेस से नाराज़ मुसलमान बेहतर विकल्प के लिए कोई भी निर्णय ले सकते हैं और भाजपा व अन्य छोटी पार्टियों का रुख़ कर सकते हैं. अनुमान लगाया जा रहा है कि भाजपा को इस बार 15-20 प्रतिशत मुस्लिम वोट मिल सकता है. क्योंकि कांग्रेस का हाल कुछ वैसा ही है कि जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा करने लगे. इसका अनुमान राजस्थान के विभिन्न ज़िलों में होने वाले माइनॉरिटी एजूकेशनल वेलफेयर सोसायटी के द्वारा पिछले 6 माह में आयोजित कराए गए सेमिनारों और विभिन्न व्यक्तियों से हुई बातचीत से होता है.

इन सेमिनारों से यब बात स्पष्ट रूप से सामने आई है कि मुसलमान राजस्थान की गहलोत सरकार के झूठे वादों और घोषणाओं से स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं. जिसका कारण यह बताया गया है कि अल्पसंख्यकों के नाम पर सरकार ने जिन योजनाओं की घोषणा की थी, उन पर अमल नहीं हुआ है. शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार और सरकारी नौकरियों में उनकी साझेदारी बस नाम की रह गई है. सच्चर कमेटी की अनुशंसाओं को भी अभी तक लागू नहीं किया गया है. बैंकों को मुसलमानों से एलर्जी है और वे इन्हें क़र्ज़ नहीं देते, जबकि सरकार की ओर से मुसलमानों को विशेष छूट देने का बराबर ढिंढोरा पीटा जाता रहा है. केवल आधिकारिक रूप से मुसलमानों को सुविधाएं देने का महज़ प्रचार ही किया जा रहा है, जबकि ज़मीनी सच्चाई कुछ और ही है. सरकार की इस उपेक्षा से राज्य के मुसलमानों में असंतुष्टि और आक्रोश पैदा हो गया है.

दरअसल मुसलमानों में अब यह जागरूकता आने लगी है कि कांग्रेस ने अब तक मुसलमाना को महज़ वोट बनाकर कर रखा है. चुनाव आते ही कांग्रेस धर्मनिरपेक्षता का चोला पहनकर वोट मांगने उनके पा आ जाती है, लेकिन जब मुस्लिम समस्याओं का मामला सामने आता है तो वह सुर बदलने लगती है. समस्या तो यह भी है कि जब मुस्लिम प्रतिनिधित्व के लिए कांग्रेस से टिकट मांगा जाता है तो उसे धर्मनिरपेक्षता ख़तरे में दिखाई देने लगती है, जबकि चुनाव चाहे लोकसभा के हों या विधानसभा के, राजनीतिक पार्टियों के भविष्य का फैसला मुस्लिम मतदाता ही करते हैं. यही कारण है कि प्रत्येक राजनीतिक पार्टी चुनावी मौसम में ख़ुद को मुसलमानों की हमदर्द और शुभचिंतक बताते हुए नहीं थकती और जब चुनावी मौसम चला जाता है तो वही पार्टी जिसे वे सत्ता की बागडोर सौंपते हैं, उनके लिए बेगानी बन जाती है. 2008 के विधानसभा चुनावों में मुसलमानों ने कांग्रेस पर बहुत विश्वास और भरोसे के साथ वोट दिया था, लेकिन कांग्रेस ने उनकी समस्याओं पर हमेशा की तरह कोई ध्यान नहीं दिया. सरकार को चेताने के लिए माइनॉरिटी एजूकेशन एंड वेलफेयर सोसायटी के अध्यक्ष असग़र अली एडवोकेट ने जयपुर, बीकानेर, भरतपुर, अल्वर, कोटा और टोंक जैसे राज्य के मुस्लिम बहुसंख्यक ज़िलों में सेमिनार आयोजित कराए, जिनमें प्रत्येक ज़िले की ब्लॉक यूनिट और पंचायत से स्थायी मुस्लिम लोग शामिल हुए और सरकार को मुसलमानों की समस्याओं से अवगत कराया, लेकिन सरकार के कान में जूं नहीं रेंगी. इसी से तंग आकर मुसलमान अब कांग्रेस किसी विकल्प के बारे में सोच रहे हैं.

जयपुर में एडवोकेट असग़र अली एडवोकेट कहते हैं कि पिछले 6 महीनों में माइनॉरिटी एंड वेलफेयर सोसायटी के तहत जयपुर, बीकानेर, भरतपुर, अल्वर, कोटा और टोंक में राजस्थान विभिन्न ज़िलों के गांवों में पंचायत से लेकर शहरों में नगर निगम के सभी मुस्लिम प्रतिनिधियों व अन्य क्षेत्रों के प्रभावशाली मुसलमानों को लेकर जो कांफ्रेंस हुई हैं, वह इस दृष्टि से बहुत सफल प्रतीत होती हैं कि मुस्लिम वोट पर प्रभाव रखने वाले सभी लोग पहली बार संगठित होकर हर जगह कांग्रेस की परफॉरमेंस रिपोर्ट मांग रहे हैं और अपनी घोर निराशा व आपत्ति ज़ाहिर कर रहे हैं. असगर अली एडवोकेट चौथी दुनिया को यह भी बताते हैं कि कांग्रेस ने मुस्लिम समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दिया है और उसने जनता के उचित प्रतिनिधि को इस बार विधानसभा के लिए टिकट भी नहीं दिया है और अगर वह पार्लियामेंट के लिए यही रवैया रखती है, तब मुसलमान किसी न किसी विकल्प की तलाश कर ही लेगा. लिहाज़ा कांग्रेस मुसलमानों को विवश न समझे और उनके समर्थन को बिना किसी शर्त अपने लिए निश्चित न समझे.

बूंदी (राजस्थान) वक़्फ़ समिति के अध्यक्ष नूरुद्दीन जो कि पेशे से वकील हैं, का कहना है कि कांग्रेस सरकार मुसलमानों की समस्याओं में कोई रुचि नहीं ले रही है. ऐसा लगता है कि जैसे हम यहां के नागरिक ही नहीं, इसलिए हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है. निर्दोष मुसलमानों पर फ़र्ज़ी मुक़दमे लगाकर जेल में डाला जा रहा है, कोई उनकी हालत पूछने वाला नहीं है. शिक्षा के क्षेत्र में, रोज़गार में, सरकारी नौकरियों में मुसलमान बेहद पिछड़ा हुआ है और निर्धन जीवन जी रहा है, लेकिन सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है. वक़्फ़ संपत्तियों पर भी अवैध क़ब्ज़े हैं, अगर यह संपत्ति हमें वापस मिल जाए तो इससे भी मुसलमानों की निर्धनता में कमी आ सकती है. उन्होंने सरकार के कार्यों पर निराशा जताते हुए कहा कि अगर सरकार मुस्लिम समस्याओं का कोई हल नहीं निकालती है तो फिर ज़ाहिर है हमें कोई विकल्प की तलाश करनी होगी, अब कांग्रेस सरकार से लोग क्षुब्ध हो चुके हैं, यह हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ वोट बैंक समझती है.

कोटा में रहने वाले जमील अहमद एडवोकेट जिनका किसी पार्टी से कोई व्यावहारिक संबंध नहीं है, कहते हैं कि कांग्रेस की सबसे बड़ी कमी यह है कि उसके राज में दंगे बहुत होते हैं और इससे भी अधिक दुखद बात यह है कि दंगों को नियंत्रित भी नहीं कर पाती. मुसलमानों को लेकर उसकी नीयत साफ़ नहीं है. वह मुसलमानों से वादे तो बहुत करती है, लेकिन इन पर अमल नहीं करती.

उन्होंने 2008 में जयपुर में हुए बम धमाकों की घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि इस घटना के आरोपियों का मुक़दमा लड़ने के लिए कोई वकील तैयार नहीं हुआ था, क्योंकि वह मुसलमान थे. बहरहाल मैंने यह सेवाएं दीं और मैंने साढ़े तीन साल के परिश्रम के बाद उन निर्दोषों को बरी कराने में सफलता प्राप्त की. अब उन लोगों का कोई पूछने वाला नहीं, कोई राजनीतिक पार्टी उनकी मदद को तैयार नहीं. कांग्रेस सरकार के बारे में उनका कहना है कि मुसलमानों को लेकर उसकी कार्यशैली अत्यंत निराशाजनक है, उसकी ओर से घोषणाएं तो बहुत होती हैं, लेकिन अमल के लिए मुसलमान तरसते हैं. यही कारण है कि अब मुसलमान नये विकल्प की तलाश में हैं.

समाजसेवी अख़्तर ख़ान का कहना है कि कांग्रेस का नज़रिया मुसलमानों को लेकर साफ़ नहीं है. उसने मुस्लिम संस्थानों में ऐसे लोग भर्ती किए हैं, जो मुसलमानों को नुक़सान पहुंचा रहे हैं. उनका यह भी कहना है कि अब लोग कांग्रेस से निराश हो गए हैं और नये विकल्प की तलाश में भाजपा, मीणा और बैंसला की पार्टियों से जुड़ रहे हैं. इस स्थिति से कांग्रेस का लगभग 20 प्रतिशत वोट कट जाएगा, जिसके नतीजे में आगामी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को लगभग 20-25 सीटों का नुक़सान होगा और वह राजस्थान में सरकार अपने दम पर बनाने की स्थिति में नहीं होगी.

छपरा के रहने वाले निज़ामुद्दीन पेशे से किसान हैं और मुस्लिम समस्याओं को लेकर बेहद गंभीर रहते हैं. उनका कहना है कि कांग्रेस सरकार ने मुसलमानों के लिए बहुत सी योजनाओं की घोषणा की, लेकिन उनको लागू नहीं किया गया, जिस कारण मुसलमानों में गहरी चिंता पाई जाती है. सरकार को चाहिए कि जल्द ही अपने वादों को पूरा करे. उनका यह भी कहना है कि पिछले चुनावों में कांग्रेस ने हमें 17 सीटें दी थीं, जोकि बहुत कम हैं. उनके अनुसार 25 सीटों पर मुस्लिम वोट बहुत महत्वपूर्ण हैं और वहां मुसलमानों को टिकट मिलना ही चाहिए.

राजस्थान में होने वाले मुस्लिम माइनॉरिटी के सेमिनारों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दिसंबर में होने वाले असेंबली चुनावों में सत्ताधारी गहलोत सरकार अपनी असफलता के कारण मुसलमानों में अपना भरोसा खो चुकी है और मुसलमान इस सरकार से क्षुब्ध हो चुके हैं. ज़ाहिर है इसका सीधा लाभ भाजपा व अन्य पार्टियों को होगा. सियासी पंडितों की राय और मतदाताओं के रुझान से यह बात खुलकर सामने आ रही है कि मुसलमानों का लगभग 20 प्रतिशत वोट कांग्रेस से खिसक सकता है और यह वोट वसुंधरा राजे सिंधिया, किरोड़ीमल मीणा और किरोड़ी सिंह बैंसला की झोली में जा सकते हैं, जिसके नतीजे में कांग्रेस को 20-25 सीटों का नुक़सान उठाना पड़ सकता है और वह सरकार से बेदख़ल हो सकते हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

www.kamalmorarka.com

कमल मोरारका

प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र मोदी को कहना चाहिए कि अगर मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो मैं पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारूंगा ताकि सेना पर दबाव कम हो. फिलहाल ऐसा करने में मौजूदा सरकार असफल रही है और कश्मीर व सीमा पर मौजूद सेना दबाव में है. यह इस सरकार की असफलता है कि वह पाकिस्तान सरकार से बातचीत का दौर नहीं शुरू कर रही है. यह कहकर कि वह सेना का इस्तेमाल पाकिस्तान को सबक़ सिखाने के लिए करेंगे, नरेंद्र मोदी ख़ुद को एक राजनीतिज्ञ के तौर पर नहीं रख रहे हैं. नेताओं को ऐसे विषयों पर उदार दृष्टिकोण रखना चाहिए जो कि वे नहीं रख पा रहे हैं.

वास्तविक मुद्दों से बच रहे हैं नेता

सचिन तेंदुलकर ने मुंबई में अपना 200वां खेला और इसी मैच के बाद उन्होंने क्रिकेट जीवन से सन्यास ले लिया. 1989 में जब उन्होंने अपने क्रिकेट जीवन की शुरुआत की, तब वे तक़रीबन 16 वर्ष के थे. 24 वर्ष के लंबे सफर के बाद उन्होंने क्रिकेट जगत को अलविदा कहा. नि:संदेह सचिन का क्रिकेट कैरियर विश्व के किसी भी क्रिकेट खिलाड़ी की तुलना में सबसे शानदार रहा. डॉन ब्रेडमैन से भी सचिन की तुलना की जाती है, लेकिन इसे पूरी तरह सही नहीं कहा जा सकता. उन दिनों जब डॉन ब्रेडमैन खेलते थे, तब केवल टेस्ट क्रिकेट ही खेला जाता था. डॉन ब्रेडमैन ने कुल 52 मैचों में 80 पारियां खेलीं, जिनमें दस पारियों में वे नाबाद रहे. इस तरह 80 पारियों में उन्होंने 6996 रन बनाए. आख़िरी मैच में वे शून्य पर आउट हो गए, जिसके चलते 100 रन के औसत से वे मात्र चार रन दूर रह गए. अब टेस्ट मैचों में कभी 100 रन का औसत बन भी पाएगा, यह कह पाना मुश्किल है.

लेकिन दूसरे कई मायनों में सचिन तेंदुलकर डॉन ब्रेडमैन की तरह ही थे. वह भारतीय क्रिकेट टीम के लिए अंतिम सहारे के तौर पर थे. जब भी टीम मुश्किल में होती, वह मैदान में जाते और टीम ख़ुद को सुरक्षित महसूस करने लगती और उसे अपना खोया हुआ आत्मविश्वास वापस मिल जाता. सचिन डॉन ब्रेडमैन से मिलने ऑस्ट्रेलिया भी गए. ब्रेडमैन को भी सचिन से मिलकर काफ़ी खुशी हुई और कुछ समय पहले प्रेस से बातचीत में सचिन ने बताया कि जब वे डॉन ब्रेडमैन से मिले तो उन्हें ऐसा लगा जैसे अर्जुन को द्रोणाचार्य मिल गए हों. वास्तव में यह उस मुलाक़ात का सबसे सटीक वर्णन था और इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि डॉन ब्रेडमैन एक शाश्वत गुरु के तौर पर स्थापित हैं.

सचिन तेंदुलकर के कैरियर में भी काफ़ी उतार-चढ़ाव आया. ज़ाहिर सी बात है कि जिसका क्रिकेट खेलने का कैरियर ही 25-26 साल का होगा, उसमें उतार-चढ़ाव तो आएंगे ही. आप हर पारी में बड़ा स्कोर नहीं कर सकते. हर मैच में अच्छा नहीं खेल सकते. हर देश में बेहतर नहीं खेल सकते. यह भी ज़रूरी नहीं कि आप सभी सीरीज में अच्छा ही खेलें. बावजूद इन सबके सचिन के खेल जीवन में एक ग़ौर करने वाली निरंतरता थी. एक और बात जो ग़ौर करने लायक है कि जब वे कप्तान नहीं रहते तो ज्यादा बेहतर खेलते थे, बनिस्बत इसके कि जब कप्तान की ज़िम्मेदारी निभाते थे. हो सकता है कि बतौर कप्तान खेलते हुए वे इसका दबाव महसूस करते रहे हों, जिसका असर उनके खेल पर पड़ता था. यह सब कुछ याद करते हुए हमें यह मानना पड़ेगा कि देश में अब तक जितने क्रिकेटर हुए, सचिन का क़द उन सबसे बड़ा है.

शुरुआती दिनों में मैच बहुत कम खेले जाते थे. सी के नायडू का उदाहरण लें तो उन्होंने बहुत कम मैच खेले. बावजूद इसके उनके नाम कई सारे विश्व रिकॉर्ड हैं. इन रिकॉर्ड की तुलना मौजूदा दौर से नहीं की जा सकती, क्योंकि अब पहले की तुलना में बहुत ज्यादा क्रिकेट खेला जाता है. न ही हम खेलने की शैली की तुलना कर सकते हैं, क्योंकि अब क्रिकेट में तकनीक का महत्व बहुत बढ़ गया है. मैच के दौरान तीसरे अम्पायर की मौजदगी है, साथ ही हॉक आई से मिलने वाला बड़ा व्यू भी. वास्तव में अब क्रिकेट वह क्रिकेट नहीं रह गया जो इंग्लैंड में शुरू हुआ था और वहां से भारत आया था. अब तो क्रिकेट तकनीकी अजूबा हो गया है. आपको प्रैक्टिस कराने के लिए भी मशीनें हैं, ऐसी मशीनें जो बैट्समैन की तरफ अलग-अलग प्रकार से गेंद फेंकती हैं, ताकि बैट्समैन बेहतर प्रैक्टिस कर सके. यह सभी बदलाव पिछले 10-20 वर्षों में हुए.

हालांकि तेंदुलकर तब से खेल रहे हैं, जब यह नए गैजेक्ट्स और नई तकनीक क्रिकेट में दाख़िल नहीं हुई थी. लेकिन उन्होंने हर तकनीक पर महारत हासिल कर ली और इसका फ़ायदा भी उठाया. यही उनकी सबसे बड़ी ख़ूबी थी जिसके चलते उनके खेल में हमेशा ताज़गी बनी रही. सचिन हमेशा ख़ुद को वक्त के साथ लेकर चले. आईसीसी द्वारा लागू किए गए नए नियमों को अपनाया और भी बहुत कुछ. कई बार ऐसा हुआ कि वह अंपायर के निर्णय से नाख़ुश दिखते. कई बार चीज़ें उनके अनुरूप नहीं होतीं थीं, लेकिन सचिन ने हमेशा खेल भावना का ख्याल रखा और इसे खेल की तरह ही लिया. सचिन ने न कभी किसी मसले को लेकर कोई विवाद खड़ा किया, न ही कभी अंपायर या प्रबंधन से उलझे. उनकी छवि हमेशा गैर-विवादास्पद बनी रही और इसे बनाए रहने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है. आम तौर पर जो खिलाड़ी इस स्तर तक पहुंच जाते हैं उनके अंदर अहंकार जन्म लेने लगता है और वह अहंकार उनके पूरे आचरण को बिगाड़ देता है, लेकिन सचिन के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ और उन्होंने कभी अपना धैर्य कभी नहीं खोया. वास्तव में इन सभी का श्रेय सचिन को ही जाता है. सचिन को शुभकानाएं.

क्रिकेट की दुनिया से निकलकर देश के राजनीतिक परिदृश्य पर गौर करें तो चुनावों के मद्देनज़र नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर बहस छिड़ गई है. दोनों ही तथाकथित तौर पर प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि मीडिया और कुछ अन्य लोगों ने यह मान लिया है कि देश में केवल राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं. दोनों ही बहस-मुबाहिसे के दौर से गुज़र रहे हैं. लेकिन यह बहस मुद्दों को लेकर नहीं है. एक-दूसरे पर व्यक्तिगत छींटाकशी है. एक दूसरे की टांग खींची जा रही है और बहसों का स्तर बेहद नीचे गिर गया है. अगर निर्विवाद रूप से देश के सामने प्रधानमंत्री पद के दो दावेदार हैं तो उन्हें मुद्दों पर बहस करनी चाहिए. उन्हें इस बारे में बात करनी चाहिए कि अगर देश की जनता उन्हें बहुमत देती है तो वे क्या करेंगे. पाकिस्तान-चीन के मसले पर उनकी नीति क्या होगी? माओवादियों को लेकर उनका रवैया क्या होगा? ग़रीबी, बेरोज़गारी और महंगाई पर उनका क्या स्टैंड होगा? लेकिन नरेंद्र मोदी इनमें से किसी मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं. वे केवल एक ही बात कर रहे हैं कि वे सेना के माध्यम से पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे. क्या एक राजनेता को ऐसी बातें करनी चाहिए? अगर सेना और पुलिस ही सभी समस्याओं का हल खोज सकती हैं फिर चुनावों की क्या ज़रूरत है. फिर तो हमें प्रधानमंत्री की भी ज़रूरत नहीं है. वास्तव में ऐसा कहकर वे अपनी ही मौजूदगी को नकार रहे हैं. हमें अपने पड़ोसी देशों से कुछ सीखना चाहिए. अगर हम सेना पर ज़रूरत से ज्यादा निर्भर हो जाएंगे तो सेना एक दिन लोकतंत्र पर कब्ज़ा कर लेगी. इसलिए सेना के इस्तेमाल की बात करना ही ख़तरनाक साबित हो सकता है.

वास्तव में प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र मोदी को कहना चाहिए कि अगर मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो मैं पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारूंगा ताकि सेना पर दबाव कम हो. फिलहाल ऐसा करने में मौजूदा सरकार असफल रही है और कश्मीर व सीमा पर मौजूद सेना दबाव में है. यह इस सरकार की असफलता है कि वह पाकिस्तान सरकार से बातचीत का दौर नहीं शुरू कर रही है. यह कहकर कि वह सेना का इस्तेमाल पाकिस्तान को सबक़ सिखाने के लिए करेंगे, नरेंद्र मोदी ख़ुद को एक राजनीतिज्ञ के तौर पर नहीं रख रहे हैं. नेताओं को ऐसे विषयों पर उदार दृष्टिकोण रखना चाहिए जो कि वे नहीं रख पा रहे हैं.

प्रधानमंत्री पद के दूसरे उम्मीदवार राहुल गांधी जैसा व्यवहार कर रहे हैं, उससे ज़ाहिर होता है एक राजनीतिज्ञ के तौर पर वे अभी अपरिपक्व हैं. उनके परदादा एक महान राजनीतिज्ञ थे. उनकी दादी एक निपुण प्रधानमंत्री थीं. उनके पिता केवल पांच वर्ष ही नेतृत्वकारी भूमिका में रह पाए, जिसके बाद उनकी हत्या कर दी गई. राहुल गांधी को अब सक्रिय राजनीति में तक़रीबन 8 से 10 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन दुर्भाग्य से आज तक उन्होंने ऐसा कोई एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया जिसके आधार लोगों में यह आत्मविश्वास कायम हो सके कि वे देश को नेतृत्व दे सकेंगे. मैं आशा करता हूं कि दोनों नेताओं के भाषण लिखने वाले लोगों की समझ बेहतर हो, उनकी पार्टियों के वरिष्ठ नेता उन्हें बेहतर सलाह दें, ताकि उनके तर्क-वितर्कों का स्तर उठ सके. अभी भी उनके पास छह महीने का वक्त है और इतना वक्त ज़रूरी मुद्दों पर बहस करने के लिए काफ़ी है. वे सार्थक बहस करें ताकि देश की जनता उनका सही आकलन कर सके. ■

feedback@chauthiduniya.com

भ्रष्टाचारी सरकार का अधिनायकवाद

ठाकुर दास बंग

वर्तमान भारतीय सरकार की नीतियां आज के संकट का निकटवर्ती कारण हैं. साधारण लोगों ने सत्ता द्वारा प्रदत्त जो सुविधा और संरक्षण प्राप्त किया था उसे सरकार ने नष्ट कर दिया. औद्योगिक उत्पादन और कृषि उत्पादन की भेदभाव सरकारी मूल्य-नीति के कारण कृषि क्षेत्र का शोषण और तेज़ हुआ है. इससे छोटे किसान और दरिद्र होकर अपनी बची-खुची ज़मीन भी खो रहे हैं. ग्रामीण और लघु उद्योगों को जो संरक्षण और सुविधाएं दी जाती थीं, उन्हें समाप्त करके अब बड़े उद्योगों और बहुराष्ट्रीय उद्योग समूहों को बढ़ावा मिल रहा है. इसके चलते हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में बड़े और बहुराष्ट्रीय उद्योगों के पांव मज़बूत होते जा रहे हैं. सरकार जिन शर्तों पर विश्व बैंक जैसे अंतरराष्ट्रीय वित्त-संगठनों से बड़ी मात्रा में ऋण स्वीकार कर रही है उससे हमारी राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता को भारी ख़तरा पैदा हो गया है. सम्प्रति खादी और ग्रामोद्योग के अंतर्गत चलने वाले उद्योगों के बारे में भी थोड़ा संकेत कर दूं. इसके लिए संबद्ध खादी ग्रामोद्योग-आयोग द्वारा जो कुछ किया जा रहा है, वह दिखावा मात्र होकर रह गया है, क्योंकि जिन समस्याओं का निराकरण वह करना चाहता है उन समस्याओं को वह आंशिक रूप से ही स्पर्श कर रहा है. सत्ताधारी दल ने भ्रष्टाचार को अपनी नीति की आधारशिला बना लिया है. लघु किसानों, पिछड़े वर्ग के लोगों आदि के लिए जो बहु-प्रचारित धनराशि निर्धारित की जाती है उसका 40 से 95 प्रतिशत तक हिस्सा भ्रष्टाचार द्वारा चूस लिया जाता है. आम लोगों की क्रय-शक्ति समाप्त होती जा रही है. इसलिए औद्योगिक उत्पादन गिनी-चुनी विशिष्ट आबादी के लिए अथवा विदेशी बाज़ार की आवश्यकता पूर्ति हेतु ही किया जाने लगा है. आम लोगों में जीवन के लिए अत्यन्त आवश्यक सामग्री खरीदने की ही क्रय शक्ति नहीं बची है. फिर भला वे नई-नई औद्योगिक सामग्री कैसे ख़रीद सकते हैं?

संकट का मूल कारण

राष्ट्र के राजनैतिक संकट का मूल कारण सत्ताधारी दल की अलोकतांत्रिक और सत्तावादी अकांक्षा है. वर्तमान सत्ता देश पर एक वंशगत अधिसत्ता लादने पर तुल गई है. संसदीय संस्थाओं की गरिमा और अधिसत्ता को क्षीण करके, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को नष्ट करके, प्रेस को सत्ता के प्रति समर्पित होने के लिए भयभीत करके और नौकरशाही को भ्रष्ट तथा पतनोन्मुख बनाकर वर्तमान सत्ता अपने उदेश्य की प्राप्ति करना चाहती है. सबसे भयानक बात यह है कि सत्ता अब जनता को भी भ्रष्ट और दब्बू बनाने पर तुल गई है, ताकि आम लोग अधिनायकवाद के आगे आसानी से घुटने टेकने के लिए विवश हो जाएं. राष्ट्रीय संकट का यह सबसे गंभीर पहलू है, जिसका एक आध्यात्मिक आयाम भी है. और वह यह है कि राजनीतिक दृष्टि से दब्बू और अपुरुषार्थी लोग आध्यात्मि दृष्टि से भी शक्तिहीन हो जाते हैं.

सत्ताधारी दल की इन कोशिशों को सड़क और फुटपाथ पर पनपने वाली छोटी विकेन्द्रित तानाशाही से भी बल प्राप्त हो रहा है. गुंडे और बदमाशों का गिरोह नगर और ग्रमीण क्षेत्रों में अपनी सत्ता स्थापित कर रहा है. इन गिरोहों को सत्ताधारी दल की भीतरी मदद मिलती है जिसके बूते पर वे स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था को प्रभावशून्य बनाने में सफल सिद्ध होते हैं. सारे देश में होने वाले अपराधों की असाधारण वृद्धि के मूल में कुछ अन्य सामाजिक कारण भी हैं, लेकिन स्थानीय दादागिरी की बढ़ोत्तरी इसका एक बहुत बड़ा कारण है. यहां एक मुद्दा बहुत स्पष्टता के साथ रेखांकित करने की आवश्यकता है. ऐसे कुछ लोग हैं, जो मानते हैं कि ऊपर जिन बातों का उल्लेख किया गया है, वह मूलत: केंद्रित राजनीतिक और आर्थिक सत्ता का ही परिणाम है, लेकिन बात ऐसी नहीं है. व्यवस्था की अपनी कुछ भीतरी त्रुटियां हैं, जो दूर होनी चाहिए और इसके लिए भारी फेर-बदल करना होगा और शायद पूरी तरह उसे रद्द भी करना पड़े, लेकिन केंद्रित उत्पादन पद्धति के कारण ही अधिनायकवाद अथवा नाज़ीवाद का अभ्युदय हुआ ऐसा नहीं है, क्योंकि केंद्रित उत्पादन-पद्धति के होते हुए भी इंग्लैंड, अमेरिका या स्केण्डिनेविया के देश या स्विट्जरलैंड में अधिनायकवाद नहीं उभरा. अधिनायकवाद के अभ्युदय के साथ स्थानीय समाज की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और उसमें निहित सामाजिक मूल्यों का कुछ-न-कुछ आंतरिक अनुबंध होता ही है. यह एक अन्य प्रकार की व्यवस्था है जिसे बदलना आवश्यक है.

भारत में लगभग आधा दर्जन व्यवस्थाएं विद्यमान हैं, जो मनु द्वारा प्रारम्भ की गई व्यवस्था पर एक के बाद एक बनती चली गई हैं. वे एक दूसरे से भी संबद्ध हैं. लेकिन उनका अपना-अपना अलग जीवनक्रम भी है, जिसके साथ अलग-अलग ढंग से पेश आना पड़ेगा. यह सब कुछ होते हुए भी विश्व इतिहास के निर्माण में गांधी जी, लेनिन, हिटलर, मुसोलिनी और इनके बीच में स्थान रखने वाले अनेक अन्य व्यक्ति अपनी एतिहासिक भूमिका निभा चुके हैं. विश्व व्यवस्था द्वारा हमारे देश में जिन परिस्थितियों और प्रक्रियाओं का सूत्रपात हुआ है और उनके कारण देश में जो आर्थिक सामाजिक परिवर्तन हुए हैं उनका विचार हम कर चुके हैं. किंतु कांग्रेस का अधिनायकवाद के औज़ार के रूप में जिस प्रकार प्रकटीकरण हुआ है वह विश्व-व्यवस्था से एक अलग किस्म की वस्तुस्थिति का परिचायक है.■

feedback@chauthiduniya.com

राष्ट्र के राजनैतिक संकट का मूल कारण सत्ताधारी दल की अलोकतांत्रिक और सत्तावादी अकांक्षा है. वर्तमान सत्ता देश पर एक वंशगत अधिसत्ता लादने पर तुल गई है. संसदीय संस्थाओं की गरिमा और अधिसत्ता को क्षीण करके, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को नष्ट करके, प्रेस को सत्ता के प्रति समर्पित होने के लिए भयभीत करके और नौकरशाही को भ्रष्ट तथा पतनोन्मुख बनाकर वर्तमान सत्ता अपने उदेश्य की प्राप्ति करना चाहती है.

पाठकों की दुनिया

जनमत संग्रह रोकना ग़लत

जनमत संग्रहों के नतीजों पर कांग्रेस का तिलमिलाना लाजमी है भला कांग्रेस तिलमिलाए भी क्यों न, क्योंकि नतीजे जो उसके खिलाफ हैं. अभी कुछ महीने पहले जब जनमत संग्रह कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस को जीत हासिल करते हुए दिखा रहे थे तब उसने एक बार भी नहीं कहा कि इस पर रोक लगना चाहिए. राजनीतिक पार्टियों की आदत है कि उनके पक्ष में हो तो सही विपक्ष में गलत. यही हाल भाजपा का है, जो आज इसके पक्ष में बोल रही है. 2004 में वह भी कहती थी कि चुनाव की अधिसुचना जारी होते ही इस पर रोक लगा देनी चाहिए. कभी-कभी जनमत संग्रह गलत साबित हुए हैं, लेकिन बार-बार ऐसा नहीं होता. अभी हाल में हुए चुनावों में उत्तर प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक के जनमत संग्रह सटीक साबित हुए हैं. दलील जो दी जा रही है कि चुनावी सर्वे भ्रमित करते हैं. 2004 में जनमत संग्रह एनडीए के खिलाफ और यूपीए के लहर के बारे में अनुमान लगाने में विफल थे. ऐसा होता तो उस समय एनडीए एक बार फिर सत्ता में आया होता. इसलिए जनमत संग्रह पर रोक लगाना सही नहीं है. यह अब अलग बात है कि जनमत संग्रह किस मकसद के लिए किया जा रहा है, लेकिन जनमत संग्रह निष्पक्ष होना चाहिए.

सोमनाथ, *रांची*

सरकार और सीबीआई

केंद्र ने सीबीआई के स्वर्ण जंयती समारोह के मौके पर उसके हदों को बता दिया कि अपने हद में रहे ज्यादा उड़ने की कोशिश मत करे. केंद्र सरकार ने साफ कर दिया कि उसका सीबीआई को स्वतंत्र करने का कोई ईरादा नहीं है. स्वर्ण जंयती समारोह के मौके पर पहले दिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने हद में रहने की नसीहत तक दे डाली. वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने दूसरे दिन कहा कि जांच एजेंसिया अतिक्रमण न करे न ही अपनी सीमाए लांघे. चिदंबरम ने कहा कि सीबीआई न ही पिजरे में बंद तोता है औन नहीं कांग्रेस ऑफ इंवेस्टीगेसन ऑफ ब्यूरो. चिदंबरम यहीं नहीं रूके उन्होंने आगे कहा लगता हैं सीबीआई असहाय होने का ढ़ोंग कर रही है. सुप्रीमकोर्ट कहता है कि पिजरे में बंद तोते को आजाद होने की जरूरत है और सरकार नहीं चाहती है कि तोता आजाद हो. वितमंत्री ने कहा कि जांच एजेंसियां और सीएजी जैसी संस्थाएं कार्यपालिका के उचित फैसलों को अपराध या पद के दूरूपयोग का मामला बताकर अपनी सीमाए लांघ रही हैं. सीएजी ने ही सरकार के कोयला घोटाले से लेकर 2 जी घोटालों तक से पर्दा उठाया है. सरकार इन घोटालों को कहती है कि इनमें कोई घाटा नहीं हुआ है, जिससे सीएजी पहले से ही सरकार के निशाने पर है. अब यह देखना होगा कि सीबीआई को लेकर न्यायपालिका और कार्यपालिका में टकराव की स्थिति बनती है या कोई रास्ता निकलता है.

भुपेंद्र, *लखनऊ*

दिशाहीन होती राजनीति

आज की राजनीति लगता है दिशाहीन होती चली जा रही है. नेता किस ओर जा रहे हैं यह उनको खुद नहीं पता. आज एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में नेता कितने नीचे गिरता जा रहा है उसको खुद पता नहीं चल पा रहा है. प्रत्येक दिन नेता किसी न किसी पर ऐसी टिप्पणी करते हैं, जो अमर्यादित होती है. नेताओं को ऐसी टिप्पणी करने की आदत होती जा रही है या मीडिया में बने रहने के लिए उनका नया हथियार है. चुनावी मौसम में ऐसी टिप्पणियों की तो बहार सी आई हुई है. 2014 लोकसभा चुनाव को अभी 6 महीने हैं, लेकिन अभी चुनावी माहौल बना हुआ है. जिससे नेता एक-दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगा हुआ है. नेताओं को यह पता ही नहीं चल पा रहा है कि कीचड़ उछालते-उछालते वह खुद कीचड़ में धसता चला जा रहा है. यह लोकतंत्र या राजनीति में कीचड़ उछालने की कोई नई परंपरा तो शुरू नहीं हो रही है, क्योंकि कोई भी पार्टी हो सारे पार्टियों के नेताओं का यही हाल है. इससे विकास, रोजगार, भ्रष्टाचार और महगाई का मामला पीछे छुटता चला जा रहा है. इसलिए राजनीतिज्ञों को चाहिए कि कीचड़ उछालने से बाज आएं और मुख्य मुद्दो को उठाएं.

संदीप, *दरभंगा*

चंदे की जांच हो

राजनीतिक चंदे को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. आम आदमी पार्टी के चंदे के स्त्रोंतो को लेकर जांच कराने का फैसला राजनीतिक सुधारों की दिशा में एक सही कदम साबित हो सकता है. सभी राजनीतिक पार्टियों के चदों के स्त्रोतो की जांच होनी चाहिए, जिससे आम आदमी पार्टी चंदे के जांच के ऊपर सवालिया निशान न लग पाए. सरकार को बताना चाहिए कि वह राजनीति में पारदर्शिता लाना चाहती है. चंदो के नाम पर कालेधन का खूब इस्तोमाल होता है इसलिए जांच होनी चाहिए. किस पार्टी को कहां से कितना चंदा मिला है. जनप्रतिनिधि कानून और विदेशी अनुदान विनियमन कानून(एफसीआरए) दोनों में प्रावधान है कि राजनीतिक पार्टियां विदेशी चंदा नहीं ले सकती. कांग्रेस या दूसरों दलों किस स्त्रोत से पैसा मिलता है उसकी जांच होनी चाहिए. क्यों केवल आम आदमी पार्टी के ही चंदे की जांच हो सभी चार्टियों के चंदों की जांच होनी चाहिए.

आशीष, *बलियां*

पाठक पूरा नाम, पता व फोन नंबर के साथ अपने स्वतंत्र विचार व प्रतिक्रियाएं इस पते पर भेजें :

चौथी दुनिया, एफ.2, सेक्टर-11, नोएडा (उत्तर प्रदेश) पिन-201301

ई-मेल पता : feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

सांप्रदायिकता की राजनीति

सांप्रदायिकता का विरोध सिर्फ़ इसलिए करना क्योंकि नरेंद्र मोदी सांप्रदायिक हैं या नरेंद्र मोदी की पार्टी सांप्रदायिक है या फिर कांग्रेस का विरोध इसलिए करना क्योंकि कांग्रेस सांप्रदायिकता का विरोध कर रही है और जो सांप्रदायिकता का विरोध करते हैं, उन्हें कांग्रेस को वोट देना चाहिए. ये ऐसे तर्क हैं, जिन तर्कों पर अगर फ़ैसले लिए जाएं तो फ़ैसले निहायत ग़लत होंगे. सांप्रदायिकता एक ऐसा शब्द है, जिस शब्द की परिभाषा आज तक हर-एक ने अपनी-अपनी तरह से की है. लेकिन सांप्रदायिकता का रिश्ता जब एक बड़े तबके से हो यानी हिंदुस्तान की 80 प्रतिशत या 90 प्रतिशत जनता से हो, तब सांप्रदायिकता का मतलब समझने में न केवल सावधानी बरतनी चाहिए, बल्कि उसका वही मतलब समझना चाहिए, जिस मतलब का रिश्ता 80 प्रतिशत लोगों से जुड़ता हो.

सांप्रदायिकता का आरोप झेलने वाले दल या व्यक्ति ये कैसे मान लेते हैं कि मुसलमानों का विरोध करना ही सांप्रदायिकता है या जो लोग मुसलमानों का विरोध करते हैं, वे लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे ही देंगे. क्या भारतीय जनता पार्टी ने ये घोषित कर दिया है कि उन्हें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए या उन्होंने ये घोषित कर दिया है कि 2014 के चुनाव में यदि भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो मुसलमानों को इस देश में दोयम दर्जे के नागरिक के रूप में माना जाएगा या जाना जाएगा? उन्हें जो संविधान ने हक़ दिए हैं, वो हक़ छीन लिए जाएंगे. सांप्रदायिकता की पहचान लिए भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी क्या उन आर्थिक नीतियों का विरोध करते हैं, जिन्हें सांप्रदायिकता विरोध के नाम पर अपने को पेश करने वाले कांग्रेस पार्टी के लोग कर रहे हैं. क्या सांप्रदायिकता के आरोप से सनी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को ये अधिकार मिल जाता है कि गुजरात में कुपोषण पैदा करना या कुपोषण को अनदेखा करना उनका हक़ है? क्या भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को इस बात का भी हक़ मिल जाता है कि किसानों के फ़सलों की क़ीमत किसानों को सीधे न मिलने देना है? क्या उनका कोई ज़िम्मा नहीं बनता? या फिर क्या नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को इस बात का भी हक़ मिल जाता है कि शिक्षा में सबको हिस्सा न मिले, इसके ऊपर उनसे कोई सवाल नहीं पूछ सकता.

सांप्रदायिकता का आरोप झेलने वाले दल या व्यक्ति ये कैसे मान लेते हैं कि मुसलमानों का विरोध करना ही सांप्रदायिकता है या जो लोग मुसलमानों का विरोध करते हैं, वे लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे ही देंगे. क्या भारतीय जनता पार्टी ने ये घोषित कर दिया है कि उन्हें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए या उन्होंने ये घोषित कर दिया है कि 2014 के चुनाव में यदि भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो मुसलमानों को इस देश में दोयम दर्जे के नागरिक के रूप में माना जाएगा या जाना जाएगा? उन्हें जो संविधान ने हक़ दिए हैं, वो हक़ छीन लिए जाएंगे.

लेकिन क्या ये भी नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को हक़ मिल जाता है कि वो अपनी आर्थिक नीतियां भी न स्पष्ट करें. वो ये भी न बताएं कि विकास के दायरे से 70 प्रतिशत जनता बाहर है, उसे विकास के दायरे में कैसे लेकर आएंगे या फिर वो लोगों को ये भी नहीं बताना चाहते कि उनके रिश्ते किनसे, कैसे होंगे.

इससे विपरीत सवाल कांग्रेस से पूछे जा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी सांप्रदायिकता विरोध के नाम पर सड़कें, शिक्षा, अस्पताल, भ्रष्टाचार जैसी चीज़ों को मुद्दा मानती है या नहीं मानती है? या केवल सांप्रदायिकता का विरोध या नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का विरोध ही उसका एकमात्र एजेंडा है? क्या कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र को, जिसे उसने 2004 और 2009 में देश के सामने रखा, ये आंकलन पेश करेगी कि उसने इसमें से कितनी चीज़ें लागू कीं और कितनी चीज़ें नहीं लागू कीं. कांग्रेस पार्टी के सरकार के एक मंत्री कहते हैं कि सच्चर कमेटी की सिफ़ारिशों को 90 प्रतिशत के आसपास लागू कर दिया गया है. ज़मीन पर कहीं कुछ दिखाई नहीं देता और समझ में तो ये भी नहीं आता कि सच्चर कमेटी की सिफ़ारिशें थीं क्या? दरअसल, सच्चर कमेटी ने बीमारी की पहचान की, लेकिन उस बीमारी की दवा सुझाने का काम रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने किया. इस पूरी दौड़ में, इस पूरे शोर में कांग्रेस पार्टी ने सच्चर कमेटी का तो नाम लिया, लेकिन कभी भी रंगनाथ मिश्रा कमीशन का नाम ही नहीं लिया. इसलिए मुझे ये लगता है कि सच्चर और रंगनाथ मिश्रा के बीच का अंतर कांग्रेस कभी पाटना भी चाहती है या नहीं पाटना चाहती और इन सवालों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को क्या कहना है? नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ऐसे सवालों के ऊपर ख़ामोश हैं.

अगर हम देखें तो दोनों की आर्थिक नीतियां एक हैं. लोगों के प्रति कैसी जवाबदेही होनी चाहिए, उसके बारे में दोनों पार्टियां बिल्कुल एक हैं. भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोज़गारी, शिक्षा और स्वास्थ्य के सवाल पर दोनों पार्टियां कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ख़ामोश हैं और दोनों के ही प्रधानमंत्री पद के दावेदार एक तरफ़ नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ़ राहुल गांधी इन सवालों को छूना ही नहीं चाहते. एक सांप्रदायिकता का विरोध करता है और दूसरा कहता है कि सांप्रदायिकता एक छद्म शब्द है. लेकिन दोनों ही चाहते हैं कि जो बुनियादी सवाल हैं, वे देश के लोगों के सामने ही न आएं. देश का छात्र और देश का नौजवान इस बाज़ीगरी में तमाशबीन बनकर खड़ा हुआ है. दोनों ही पार्टियां छात्रों और नौजवानों की 18 साल से लेकर 25 साल के उम्र तक की इस पीढ़ी को एक नई अंधेरी सुरंग में धकेल रही हैं. ज़रूरत इस बात की है कि इस पीढ़ी को ज़िम्मेदार लोग बताएं कि देश के बुनियादी सवाल क्या हैं और उन बुनियादी सवालों पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का रुख़ क्या हो, इसका सवाल पूछने का नौजवानों को और छात्रों को हौसला दें, क्योंकि अगर छात्र और नौजवान ये सवाल नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी से पूछेगा तो उसे समझ में आएगा कि किसे वोट देना है, किसे नहीं वोट देना है या दोनों में से किसी को वोट नहीं देना है. ■

editor@chauthiduniya.com

मंगल अभियान और आधुनिक भारत

मेघनाद देसाई

कांग्रेस एक हथियार था जिसका इस्तेमाल महात्मा गांधी ने जनता के संघर्ष के लिए किया. लेकिन इसका इस्तेमाल उन्होंने अपने तानाशाही नियमों के तहत किया. कांग्रेसियों ने हमेशा गांधी का पालन किया लेकिन उनके नियमों का नहीं. कांग्रेसियों ने गांधी जी के नेतृत्व का स्वागत तो किया, लेकिन सिर्फ़ आज़ादी पाने तक. उसके बाद वे गांधी जी से परे हो गए और कांग्रेस को शासन करने के हथियार की तरह इस्तेमाल किया, जबकि गांधी चाहते थे इसका विलय कर दिया जाए.

लगभग एक शताब्दी पूर्व लंदन में दो भारतीयों की मुलाक़ात हुई. उनमें जो ज्यादा उम्र का था, वह दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीयों के मानवाधिकार के मामले को लेकर वहां पहुंचा था और दूसरा नौजवान ऊर्जा से भरपूर था और भारत से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए समर्पित. दोनों में भारत के भविष्य को लेकर लंबी बहस हुई. नौजवान ने मज्जिनी और गरीबाल्डी के बारे में सूक्ष्मता से अध्ययन किया था. इन लोगों (मज्जिनी और गरीबाल्डी) ने इटली के एकीकरण और उसे स्वंतत्रता दिलाने में बड़ा योगदान किया था. नौजवान मज्जिनी की आत्मकथा का मराठी में अनुवाद करने पर भी विचार कर रहा था. नौजवान चाहता था कि औद्यो-गीकरण और आधुनिकता के मामले में भारत यूरोप का अनुकरण करे. लेकिन उम्रदराज व्यक्ति इस विचार से भयग्रस्त था. वह चाहता था कि भारत आधुनिकता, मशीनों, पश्चिमी दवाओं और शहरीकरण को ख़ारिज करे. उम्रदराज व्यक्ति ने वापस दक्षिण अफ्रीका लौटकर अपनी पहली क़िताब लिखी, जिसमें उन्होंने तर्क दिए कि क्यों भारत को आधुनिक मशीनीकरण को ख़ारिज कर देना चाहिए. यह क़िताब थी हिंद स्वराज.

अगले चालीस वर्षों में दोनों के रास्ते भिन्न रहे. उम्रदराज व्यक्ति राष्ट्रपिता बना और उसे भारत की आज़ादी का श्रेय दिया गया. नौजवान ने अपने तमाम साल एकांत कारावास में गुज़ारे और उसके बाद अपना जीवन लेखन और विचारों को प्रतिपादित करने के लिए समर्पित कर दिया. एक पश्चिमी सभ्यता के पैरोकार और आधुनिकतावादी से वह हिंदू सभ्यता के स्वर्णिम अतीत की तरफ़ लौट गया. उसे उम्रदराज व्यक्ति की हत्या में भी फंसाया गया. उसकी पहचान गुप्त रही और एक विभाजनकारी के रूप में हुई. वहीं उम्रदराज व्यक्ति को अंतरराष्ट्रीय ख्याति मिली.

यह दोनों व्यक्ति थे गांधी और सावरकर, जिन्होंने 1909 में आज़ादी के लिए भारत द्वारा अख़्तियार किए जाने वाले रास्ते को लेकर आपस में बहस की थी. गांधी चाहते थे कि कम से कम सरकार और हस्तशिल्प के साथ भारत गांवों का गणतंत्र बने. भारत ने उनकी तो पूजा की, लेकिन उनके सुझाए रास्तों को बुरी तरह नकार दिया. उनके सबसे अच्छे शिष्य जवाहर लाल नेहरू के विचार सावरकर से पूरी तरह मिलते थे. वे भी भारत के लिए आधुनिकीकरण और औद्योगीकरण चाहते थे. मंगलयान को अपने रास्ते भेज कर भारत ने एकबार फिर गांधी के विचारों को नकारकर सावरकर और नेहरू के विचार को चुना है. सावरकर को अब आधुनिकतावादी के बजाए हिंदुत्ववादी के तौर पर पहचाना जाता है. हालांकि, उनकी भारत के बारे महात्वाकांक्षा उसी प्रकार विकासोन्मुखी थी जैसी किसी भी दूसरे की होती है.

कांग्रेस एक हथियार था जिसका इस्तेमाल महात्मा गांधी ने जनता के संघर्ष के लिए किया. लेकिन इसका इस्तेमाल उन्होंने अपने तानाशाही नियमों के तहत किया. कांग्रेसियों ने हमेशा गांधी का पालन किया लेकिन उनके नियमों का नहीं. कांग्रेसियों ने गांधी जी के नेतृत्व का स्वागत तो किया, लेकिन सिर्फ़ आज़ादी पाने तक. उसके बाद वे गांधी जी से परे हो गए और कांग्रेस को शासन करने के हथियार की तरह इस्तेमाल किया, जबकि गांधी चाहते थे इसका विलय कर दिया जाए. सिर्फ़ गांधीवादी ही गांधी के सिद्धांतों में विश्वास करते रहे, लेकिन उनके जाने के बाद गांधीवादियों की कोई क़ीमत नहीं रह गई.

भारत की स्थिति इस समय विश्व में सशक्त रूप में मौजूद है. न केवल इसलिए क्योंकि यह एक आध्यात्मिक और नैतिक शक्ति है, बल्कि इसलिए कि यह आर्थिक और सैन्य ताक़त बन चुका है. मंगल पर भेजा गया यह यान सिद्ध करता है कि अन्य देशों मुक़ाबले तकनीकी दक्षता के मामले में भारत ज्यादा सक्षम है. इस कार्यक्रम की शुरुआत जानबूझकर जवाहर लाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ादी के पहले ही कर दी गई थी जब उन्होंने कांग्रेस की नेशनल प्लानिंग कमेटी की स्थापना की थी. बोस की जगह तो जल्द ही गांधी ने ले ली, लेकिन नेहरू इस कार्यक्रम के साथ लगातार बने रहे. ये नेहरू ही थे जिन्होंने विज्ञान और तकनीक का महत्व समझा. भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप उन्होंने आर्थिक नीतियों के बारे में गांधी के नियमों को दरकिनार अपनी पूरी ताक़त लगा दी थी जिससे आधुनिकता के साथ पूरी रफ्तार के साथ दौड़ा जा सके. नाभिकीय ऊर्जा का महत्व समझ कर भाभा के नेतृत्व में नाभिकीय शोध के एक कार्यक्रम की स्थापना की. साराभाई इस कड़ी में दूसरे वैज्ञानिक थे. साराभाई के संबंध नेहरू और गांधी से उस समय से थे जब गांधी को साबरमती आश्रम को चला पाने में परेशानी महसूस हो रही थी. साराभाई का योगदान भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए अभूतपूर्व है.

यह वही भारत था जो औद्योगिक विकास के साथ हरित क्रांति के लिए भी समर्पित था. इसने आईटी सेक्टर में भी अपनी जगह बनाई. अब इसने अंतरिक्ष कार्यक्रम के भी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई है और सभी बातों से ऊपर पूर्व राष्ट्रपति कलाम हमें इस बात की याद दिलाते हैं कि भारत किस तरह उन लोगों की इज़्ज़त करता है जिन्होंने रक्षा तकनीक के लिए काम किया है. भारतीय राजनीति विकास और तकनीक के साथ-साथ ग़रीबी दूर करने को लेकर एक जनमत बना हुआ है. सावरकर और नेहरू एक दूसरे से उतने ही अलग थे जितने की दुनिया के कोई भी दो व्यक्ति आपस में हो सकते हैं. लेकिन भारत ने इन दोनों के विकास पथ का अनुसरण किया. हम सभी को गांधी के नैतिक साहस और कांग्रेस का नेतृत्व करने के लिए श्रद्धांजलि देनी चाहिए. हमें हिंद स्वराज को पढ़ना तो चाहिए, लेकिन इसे भारत के ब्लूप्रिंट की तरह नहीं देखना चाहिए. ■

feedback@chauthiduniya.com

सूचना का अधिकार
चौथी दुनिया की पहल

सरकारी अस्पताल में दवाई नहीं मिलती

चौथी दुनिया ब्यूरो

देश के कुछ राज्यों में सरकारी अस्पताल का नाम लेते ही एक बदहाल सी इमारत की तस्वीर जेहन में आ आती है. डॉक्टरों की लापरवाही, बिस्तरों एवं दवाइयों की कमी, चारों तरफ़ फैली गंदगी के बारे में सोच कर आम आदमी अपना इलाज सरकारी अस्पताल के बजाय किसी निजी नर्सिंग होम में कराने का फ़ैसला ले लेता है. लेकिन इस अव्यवस्था के ख़िलाफ़ आवाज़ न उठाना क्या जायज़ है? एक आम आदमी की हैसियत से आप और हम सरकार को कर देते हैं तो सरकार से अपने द्वारा दिए गए कर का हिसाब मांगना भी हमारी ही ज़िम्मेदारी है. अच्छी स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराना सरकार की ज़िम्मेदारी है. अगर सरकार अपनी ज़िम्मेदारी निभाने में लापरवाही बरतती है तो क्या आप इसके लिए पांच साल तक इंतज़ार करेंगे? लोकतंत्र में पहले ऐसी मजबूरी थी, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि अब आपके पास सूचना का अधिकार क़ानून है. इस क़ानून के ज़रिए आप सरकार की ज़िम्मेदारी तय कर सकते हैं. सरकार को उसकी लापरवाही के बारे में बताया जा सकता है. इस अंक में सरकारी दवाइयों के बारे में चर्चा की गई है. आम लोगों की सरकारी अस्पताल के मामले में सबसे ज़्यादा शिक़ायतें दवाइयों की कमी से ही जुड़ी होती हैं. यह शिक़ायत जायज़ भी होती है. दरअसल, हर सरकारी अस्पताल में दवाइयों की ख़रीद के लिए सरकार पैसा मुहैया कराती है. समस्या यहीं से शुरू होती है. इस बात के लिए कोई कारगर मशीनरी नहीं होती, जो दवाइयों की ख़रीद और जारी किए गए पैसों की जांच करे. नीचे से ऊपर तक के अधिकारी मिल-बांटकर पैसा हज़म कर जाते हैं. भुगतना पड़ता है बेचारे ग़रीब आदमी को, जो पैसों की कमी के चलते सरकारी अस्पताल में इलाज कराने जाता है. वहां उससे बाहर की (निजी) दुकानों से दवा ख़रीदने के लिए कह दिया जाता है.

लेकिन अब आप सरकारी अस्पतालों की यह हालत बदल सकते हैं. सूचना क़ानून के ज़रिए आप अस्पताल और उससे संबंधित सरकारी विभाग से पूछ सकते हैं कि अस्पताल के स्टॉक में अभी कितनी दवा है, कितनी दवा इस अस्पताल के लिए ख़रीदी गई, कब-कब ख़रीदी गई, कितने पैसों में ख़रीदी गई. आप ग़रीबों के बीच बांटी जाने वाली नि:शुल्क दवा के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. उदाहरण के लिए सरकारी नीति के तहत टीबी जैसी गंभीर बीमारी के लिए डॉट्स नामक दवा मरीजों के बीच मुफ्त बांटने का प्रावधान है. आप अस्पताल प्रशासन से यह जान सकते हैं कि किसी खास समय सीमा के भीतर कितने मरीजों की बीच उक्त दवा का वितरण किया गया. आप दवा ख़रीदने के लिए ज़िम्मेदार अधिकारियों के नाम और पदनाम के बारे में भी पूछ सकते हैं. ज़ाहिर है, जब आप इतने सारे सवाल पूछेंगे तो अधिकारियों पर दबाव बनेगा. जब दबाव बनेगा तो स्थितियां भी सुधरेंगी. इस अंक में हम इसी मसले से संबंधित आरटीआई आवेदन प्रकाशित कर रहे हैं, जिसका इस्तेमाल कर आप अपने गांव और शहर के सरकारी अस्पतालों की स्थिति में सुधार ला सकते हैं, वहां दवाइयों की कमी दूर कर सकते हैं. हमें उम्मीद है कि आप सभी इस आवेदन का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे और दूसरे लोगों को भी इसके इस्तेमाल के लिए प्रेरित करेंगे. ■

आवेदन का प्रारूप
(अस्पताल में दवाइयों की कमी)

सेवा में, **दिनांक.....**
लोक सूचना अधिकारी
(विभाग का नाम)
(विभाग का पता)

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन

महोदय,
-----स्थित-----अस्पताल के संबंध में निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध कराई जाएं:

1. दिनांक---से---के बीच अस्पताल के लिए कुल कितनी दवाएं ख़रीदी गईं. दवाइयों के ख़रीदने एवं उन्हें अस्पताल/ चिकित्सा केंद्र के स्टॉक में रखे जाने से संबंधित रजिस्टर की पिछले---महीने की प्रति उपलब्ध कराएं.
2.उपरोक्त समय के बीच कुल कितनी रकम की दवाई यहां आने वाले मरीजों को नि:शुल्क बांटी गई? नि:शुल्क दवाइयां प्राप्त करने वाले मरीजों की संख्या बताएं और उनके नाम-पते आदि जिस रजिस्टर में लिखे जाते है, उस रजिस्टर की पिछले---महीने की प्रति उपलब्ध कराएं.
3.अस्पताल के लिए दवाइयां ख़रीदने तथा वितरण के लिए नियुक्त अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं संपर्क के पते उपलब्ध कराएं.
4.इस दौरान जिन एजेंसियों से दवाएं खरीदी गईं, उन एजेंसियों का पूरा विवरण उनके नाम और पते के साथ उपलब्ध कराएं.
5. इस अस्पताल में मुख्य रूप से किन-किन बीमारियों से संबंधित दवाइयां नि:शुल्क वितरित की जाती हैं.
6.अस्पताल द्वारा दवाइयों का नि:शुल्क वितरण किस आधार पर किया जाता है. मैं आवेदन शुल्क के रूप में दस रुपये अलग से जमा कर रहा/रही हूं.

भवदीय

नाम.....
पता.....

यदि आपने सूचना क़ानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं, तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा सूचना का अधिकार क़ानून से संबंधित किसी भी सुज़ाव या परामर्श के लिए आप हमें ई-मेल कर सकते हैं या पत्र लिख सकते हैं. हमारा पता है :

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश, पिन -201301 ई-मेल : rti@chauthiduniya.com

राशिफल

मेष (21 मार्च से 20 अप्रैल)
इस सप्ताह रुके हुए कार्यों में सफलता प्राप्त होगी. वाहन चलाते समय सावधानी बरतें. भागदौड़ के साथ-साथ खर्च भी बढ़ेगा. किसी मांगलिक कार्य में आप शामिल हो सकते हैं. शत्रुओं से सावधान रहें. शत्रु परास्त होंगे.

वृष (21 अप्रैल से 20 मई)
इस सप्ताह आप फायदा प्राप्त करने में सफल नहीं होगे. परिवार और संतान की चिंता बनी रहेगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. विद्यार्थियों को प्रतियोगी परिक्षाओं में परिश्रम से सफलता प्राप्त होगी. नौकरीपेशा और व्यापारी दोनों की आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी. अचानक यात्रा पर जाने का योग है.

मिथुन (21 मई से 20 जून)
इस सप्ताह आपकी आय बढ़ेगी और बचत भी होगी. कार्य को लेकर मानसिक तनाव रहेगा. व्यवसायी के लिए समय अच्छा रहेगा. स्वास्थ्य उतार-चढ़ाव वाला रहेगा. समाज में आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी. पारिवारिक सदस्यों से मनमुटाव हो सकता है, संयम बरतें.

कर्क (21 जून से 20 जुलाई)
इस सप्ताह कार्यस्थल पर प्रतिस्पर्धा का अनुभव हो सकता है. व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा. नौकरीपेशा लोग अपने घर-बार बनाने में लगे रहेंगे. पैसे के लेन-देन से सम्बंधित तनाव बढ़ सकता है. पारिवारिक दायित्व बढ़ेगा. विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे.

सिंह (21 जुलाई से 20 अगस्त)
इस सप्ताह आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखे. नौकरीपेशा और व्यापारी, दोनों की प्रगति में रुकावट रहेगी. संपत्ति खरीदते समय दस्तावेज जांच-परख कर ही कोई निर्णय लें. दांपत्य जीवन अच्छा रहेगा. विद्यार्थियों की पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी. अचानक यात्रा पर जाने से बचें.

कन्या (21 अगस्त से 20 सितंबर)
इस सप्ताह आपको कार्यस्थल पर मिश्रित फल प्राप्त होगा और आप उत्साहित रहेंगे. व्यापारी यदि किसी कानूनी मामले में उलझे हैं तो उन्हें उससे छुटकारा मिलेगा. किसी पैतृक संपत्ति से संबंधित समस्या हो सकती है. पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा. विद्यार्थी अपनी उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत रहेंगे.

तुला (21 सितंबर से 20 अक्टूबर)
इस सप्ताह आपके विरोधी हावी रहेंगे, आप विचलित न हों. खर्चों में बढ़ोतरी होगी. नौकरीपेशा लोगों को उनके अधिकारी से फायदा मिलेगा. परिवार में वृद्ध व्यक्ति का ध्यान दें. व्यवसायियों को प्रतिस्पर्धा करने वाले लोगों से सावधान रहने की जरूरत है. बाहर खाने से बचें अन्यथा स्वाथ्य बिगड़ सकता है.

वृश्चिक (21 अक्टूबर से 20 नवंबर)
इस सप्ताह आपको अधिकांश कार्यों में सफलता मिलेगी और आप आर्थिक लाभ की स्थिति में रहेंगे. नए वाहन और संपत्ति खरीद की योजना बनेगी. दांपत्य और संतान सुख बढ़ेगा. नौकरीपेशा लोगों को स्थानांतरण से संबन्धित समाचार मिलेगा.

धनु (21 नवंबर से 20 दिसंबर)
इस सप्ताह आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी. कर्ज से निजात मिलेगी और धन अर्जन की नई दिशाएं बनेंगी. आपके अन्दर सकारात्मक उर्जा का प्रवाह रहेगा. आपकी धार्मिक और सामाजिक कार्यों में रूचि घटेगी. निवेश के नए रास्ते बनेंगे. नए स्थान के भ्रमण की योजना पर अभी जाने से बचें.

मकर (21 दिसंबर से 20 जनवरी)
इस सप्ताह अपनी रणनीति में बदलाव लाने की बात करेंगे और आप उसमे सफल होंगे. आपकी उर्जा और उत्साह बढ़ेगा. इस सप्ताह अपने आत्मविश्वास को नियंत्रण में रखें. इस सप्ताह कुल मिलाकर आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. बुजुर्ग के स्वास्थ्य का ध्यान रखें. भाई बहनों का पूर्ण सहयोग मिलेगा.

कुंभ (21 जनवरी से 20 फरवरी)
इस सप्ताह आपकी अचल संपत्ति बढ़ाने की योजना बनेगी और प्रयास सफल भी रहेगा. मन में पारिवारिक मनोरंजन की बात आएगी और आप उचित समय निकाल पाएंगे. दाम्पत्य जीवन में सुख का अनुभव करेंगे और संतान का सुख भी प्राप्त होगा.

मीन (21 फरवरी से 20 मार्च)
इस सप्ताह आप नई सोच के साथ चलने में सफल होंगे. इस सप्ताह आपका हौसला बढ़ा रहेगा और अपने संतुलित मिजाज से बड़े कार्यों को भी आसानी से करने में सफल होंगे. इस सप्ताह आपका सामाजिक दायरा भी बढ़ेगा. आपकी धार्मिक प्रवृत्ति बढ़ेगी और सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी.

ज़रा हट के

सूअर ने पार किया तैरकर समुद्र

कहा जाता है कि कुत्ते बहुत अच्छे तैराक होते हैं, लेकिन एक सूअर समुद्र पार कर एक देश से दूसरे देश पहुंच गया. जिस द्वीप पर वह पहुंचा था उस द्वीप के लोगों को यकीन नहीं हो पा रहा था कि कोई सूअर ऐसा कारनामा कैसे कर सकता है. फ्रांस के एक तट से करीब 7 मील समुद्र की दूरी तय करके इस द्वीप पर पहुंचने वाला ये सूअर लोगों में उत्सुकता का केंद्र बना हुआ है. स्थानीय लोगों की हैरानी की एक खास वजह ये भी है कि ये द्वीप काफी अंदर है और यहां तक पहुंच पाना काफी मुश्किल काम है. बाहर से आने वाले यहां हेलीकॉप्टर की मदद से ही आ पाते हैं. शुरू में पानी से भीगा होने के कारण लोग इसे पहचान नहीं पाए, उन्हें लगा कि ये कोई सूअर है, लेकिन पानी सूखने के बाद पता चला कि ये एक जंगली सूअर है. लोगो को अभी तक विश्वास नहीं हो पा रहा है कि यह कैसे समुद्र तैरकर पार किया. ■

इतनी तीखी मिर्च कि हाथ जला देगी

क्या किसी मिर्च से आपका हाथ जल सकता है? मिर्च भी इतनी तीखी हो सकती है? लेकिन ऐसा है. ये मिर्च का पौधा ट्री ऑफ फायर नाम से मशहूर है. यह कोई आम पौधा नहीं है, बल्कि बहुत ही अनोखा है. इस पौधे पर 1000 से ज्यादा मिर्चें फलती हैं, लेकिन खास बात यह है कि इस मिर्च को नंगे हाथ नहीं पकड़ा जा सकता. आप सोच रहे होंगे कि इन मिर्चों में ऐसा क्या है? इस मिर्च को नंगे हाथ से पकड़ने पर हाथों में असहनीय जलन शुरू हो जाती है. ये मिर्च इतनी तीखी है कि इन्हें दस्ताने पहनकर ही तोड़ा जा सकता है. ये मिर्च जालापेनो मिर्च की तुलना में 120 गुना अधिक तीखी होती है. हालांकि इसकी खेती शुरू हुए बहुत कम समय हुआ है. किसानों ने साल 2005 में इसकी खेती शुरू की थी. डोरसेट नगा नाम की इस मिर्च को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने के लिए भी प्रस्तावित किया गया है. इन मिर्चों को उगाने वाली जॉय मिचुएड बताती हैं कि इन्हें हाथ से पकड़ना तो संभव नहीं है, लेकिन इन्हें उठाने के दौरान आंखों में भी पानी भर जाता है. खुद को जलन से सुरक्षित रखने के लिए वो हाथों में दो-दो दस्ताने पहनती हैं और आंखों पर चश्मा लगाती हैं. उनका कहना है कि जहां मिर्च के पौधे पर आम तौर पर अधिकतम 700 मिर्च फलती हैं, वहीं इस पर 1000 से ज्यादा मिर्चें फलती हैं. ■

पंडित और बाराती रोबोट

आज कल दूरी और समय न मिल पाने के कारण शादियों में कम लोग ही जा रहे हैं, जिसके कारण शादियों मेहमानों कमी हो रही है. अब विज्ञान ने भी उसके लिए ने उपाय खोज लिए हैं. अब रोबोट शादियों में मेहमान बन कर आ सकते हैं. ये रोबोट साइज में तो छोटे होंगे पर कई तरह की भूमिकाओं में नजर आ सकते हैं. दो फुट का यह रोबोट पुरोहित बन सकता है, तो साथ ही दुल्हन के सहायक के रूप में भी दिखाई दे सकता है. यह मेहमानों की भी भूमिका अदा कर सकता है. इस रोबोट के अविष्कारक जॉन शिमिंग ने बताया, जब मैंने साल 2012 में पहला होम-मेड रोबोट बनाया तो मेरे दोस्त मार्क और सारा शादी के मौके पर उसकी उपस्थिति को लेकर मज़ाक कर रहे थे. मैंने उनसे कहा मैं एक परंपरागत रोबोट बना रहा हूं, लेकिन इसकी विशेषताओं का विस्तार किया जाए तो अन्य लोग भी रोबोट की सेवाएं लेने में रुचि लेंगे. जापानी पति-पत्नी तोमोहिरो शिबाता और सातोको का मानना है कि आधुनिक शादी रोबोट के बिना संभव नहीं है. साल 2010 में हुई इस जोड़े की शादी में आई-फ़ेरी नाम के रोबोट का खास योगदान था. इस रोबोट की क़ीमत तब 46,000 हज़ार यूरो थी. साल 2014 तक रोबोट के माध्यम से शादी और ज़्यादा लोगों तक उपलब्ध हो जाएगी. इस बीच 'वेडिंगबोट ऑस्कर' रोबोट की लांचिंग के चलते लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो

चोरों ने बेशकीमती मूर्तियां स्पीड पोस्ट से लौटाईं

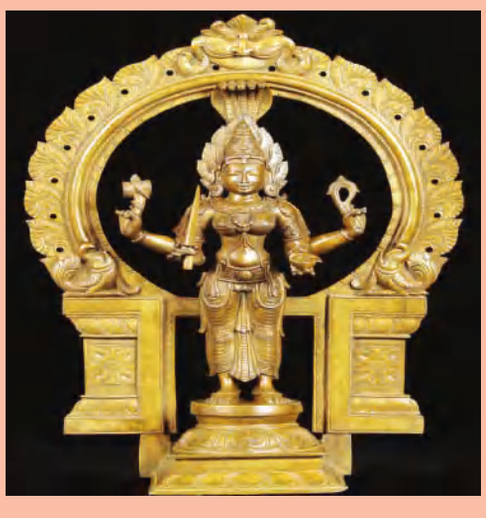

कर्नाटक में मूडबिद्री शहर के एक मशहूर जैन मंदिर से कुछ महीने पहले प्राचीन मूर्तियां चोरी हो गई थी, लेकिन आपको जानकर हैरानी हागी चोरों ने चोरी की गई प्राचीन बेशकीमती मूर्तियों को पूलिस को वापस लौटा दिए. पुलिस आयुक्त मनीष कार्बिकर ने बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उन्हें स्पीड पोस्ट के जरिए एक पार्सल भेजा है, जिसमें चोरी की गई 15 बेशकीमती मूर्तियां पुलिस को वापस की गई हैं. पुलिस आयुक्त के कार्यालय में आए पार्सल में 750 ग्राम वजन वाली 5 छोटी मूर्तियां थी. मिली जानकारी के मुताबिक जुलाई में चोरों ने मंदिर से 25 मूर्तियां चुराई थी. जिनमें से कुछ सोने की थीं और उनमें हीरे जड़े हुए थे. ओडिशा पुलिस ने इस मामले में दो चोरों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से कुछ मूर्तियां और सोना बरामद किया था. इस बीच पुलिस ने स्पीड पोस्ट भेजने वाले की जानकारी नहीं दी है. उन्होंने कहा कि पार्सल में लिखा नाम पता गलत भी हो सकता है. ■

म्यांमार में वहां की सरकार द्वारा एक विशेष पहल की जा रही है. सरकार चाहती है कि म्यांमार के अल्पसंख्यकों के लिए स्वतंत्रता और उनके अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए. दूसरी तरफ म्यांमार सरकार अपने यहां के केरन और काशीन जैसे सशस्त्र समूहों से भी बात कर उन्हें लोकतंत्र की मुख्यधारा में शामिल करना चाहती है, जो सरकार के विरुद्ध सशस्त्र गतिविधियां जारी रखे हुए हैं, ताकि शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके.

म्यांमार

अमन की ओर बढ़ते क़दम

म्यांमार में दशकों से अल्पसंख्यकों के साथ वहशियाना व्यवहार होता रहा है. वर्तमान सरकार ने वहां के अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता और उनके अधिकारों की सुनिश्चितता के लिए एक नई पहल की है. हालांकि सरकार की ये पहल जब तक अल्पसंख्यकों के अधिकार सुनिश्चित नहीं करती, तब तक म्यांमार में नई सुबह की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती.

राजीव रंजन

संपूर्ण विश्व को एक गहन विमर्श की ज़रूरत है कि आख़िर विश्व के लगभग हर देश में और ख़ासतौर पर एशियाई देशों में सरकारों का रुख़ उनके अपने ही अल्पसंख्यक नागरिकों के प्रति सांप्रदायिक क्यों हो चुका है? इस सवाल का अनदेखी कर हम महीने या साल भले ही गुजार दें, लेकिन इस सवाल से हम लंबे समय तक मुंह नहीं चुरा सकते. और अगर इस सवाल का जवाब हम समय रहते नहीं ढूंढ़ पाए तो ये अल्पसंख्यक समुदाय कई गुटों और कई सशस्त्र समूहों के रूप में सरकार और व्यवस्था के सामने अवतरित होंगे. जैसा कि भारत, श्रीलंका और म्यांमार सहित विश्व के अन्य देशों में हो रहा है. लगता है म्यांमार की सरकार अपने यहां उठने वाली इस चिंगारी को कुछ हद तक समझ भी गई है, लेकिन जब तक अल्पसंख्यक समुदायों का अधिकार उन्हें नहीं मिलता, जब तक सशस्त्र समुदायों से रचनात्मक बातें नहीं होती, म्यांमार सरकार पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि म्यांमार सरकार के हाथ वहां की अल्पसंख्यक जनता के खून से लथपथ हैं.

लोकतंत्र कितना सार्थक

4 जनवरी, 1948 को म्यांमार को आजादी मिली. 1962 में सैनिक जुनटा ने म्यामांर में तख्ता पलट कर सैन्य शासन लगा दिया, जिसका अंत 2011 में आम चुनाव के साथ हुआ, जब चुनाव के बाद थीन शीन राष्ट्रपति बने. दुनिया ने इसे म्यांमार में नई सुबह के तौर पर लिया. लोकतंत्र की स्थापना के बाद वहां की अवाम के साथ-साथ अल्पसंख्यक समुदायों में यह आशा जगी कि उनके विरुद्ध जातीय भेदभाव और हिंसा सहित अन्य अपराधों का अंत हो जाएगा, लेकिन 2012 में म्यांमार में बौद्ध और रोहिंग्या मुसलमान समुदायों के बीच हुए भीषण दंगों के कारण 90 हजार से ज्यादा लोग विस्थापित हुए और कइयों की जानें भी गईं. म्यांमार में कथित लोकतंत्र की स्थापना के बाद वहां रोहिंग्या मुसलमानों पर सुनियोजित नरसंहारों का दौर शुरू हुआ, जिससे इंसानियत कांप उठी. म्यांमार सरकार का मानना है कि रोहिंग्या समुदाय के लोग अवैध रूप से बसे हैं, जबकि इस समुदाय के लोग सदियों से यहां रह रहे हैं. तानाशाही खत्म होने के बाद भी अल्पसंख्यकों की स्थिति में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ.

सरकार की नई पहल

म्यांमार में वहां की सरकार द्वारा एक विशेष पहल की जा रही है. सरकार चाहती है कि म्यांमार के अल्पसंख्यकों के लिए स्वतंत्रता और उनके अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए. दूसरी तरफ म्यांमार सरकार केरन और काशीन जैसे सशस्त्र समूहों से भी बात कर उन्हें लोकतंत्र के मुख्यधारा में लाना चाहती है, जो सरकार के विरुद्ध सशस्त्र गतिविधियां जारी रखे हुए हैं, ताकि शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके. हालांकि अपनी इस पहल को लेकर म्यांमार सरकार कितनी ईमानदार है, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन सरकार की ये घोषित पहल जब तक अल्पसंख्यकों के अधिकारों के रूप में जमीन पर नहीं उतरती, म्यांमार सरकार पर विश्वास करना मुश्किल है. सरकार पर इस अविश्वास के अपने कारण हैं, जिसे समझने के लिए हमें म्यांमार में अल्पसंख्यकों की स्थिति को समझना होगा.

अल्पसंख्यकों की बदतर स्थिति

पिछले कई दशकों से म्यांमार के रोहिंग्या अल्पसंख्यकों को म्यांमार में जन्म लेने के बावजूद भी वहां की सरकार उन्हें अपने यहां का निवासी नहीं मानती है और न ही उन्हें अल्पसंख्यकों का दर्जा दे रही है. इसी कारण समय के साथ म्यांमार में लगभग 130 जातीय समूह अस्तित्व में आते गए. हालात इतने बुरे हैं कि उन्हें म्यांमार से निकाला व भगाया जाता रहा है और म्यांमार के पड़ोसी देश भी उन्हें स्वीकार नहीं करते. रोहिंग्या को वे सहूलियतें भी नहीं मिलतीं, जो वहां के बौद्ध निवासियों को मिलती हैं. दरअसल, म्यांमार के बौद्धों का मानना है कि रोहिंग्या बांग्लाभाषी हैं और वे म्यांमार के मूल निवासी नहीं हैं. बात यहीं समाप्त नहीं हो जाती, बांग्लादेश भी उन्हें अपना नागरिक मानने को तैयार नहीं दिखता. हालांकि भारत ने इन अल्पसंख्यकों को अपने यहां जगह दी है. आज भी बड़ी संख्या में रोहिंग्या मुसलमान शरणार्थी भारतीय शिविरों में रह रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी राहत की बात है, वह यह है कि अब सरकार ने काशीन स्टेट की राजधानी मेटीकीना के मजोई हॉल में इन समूहों के साथ वार्ता आरंभ कर दी है, जो म्यांमार के सामाजिक ताने-बाने में सुधार को लेकर एक नई पहल है.

जिस तरह से भारत में नक्सलवादी अपने अधिकारों के लिए हथियार उठाकर सरकार से दो-दो हाथ करने को मजबूर हैं, कुछ ऐसा ही हाल है म्यांमार के छोटे-छोटे सशस्त्र समूहों का, जिन्हें उनके अधिकारों से वहां की सरकार वंचित रखे हुए है. फलस्वरूप ये सशस्त्र समूह अपने अधिकारों के लिए व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं. इनमें कुछ ऐसे समूह हैं, जिनका दायरा काफ़ी बड़ा है और इनकी सहमति के बिना सरकार के सुधारों की यह पहल कामयाब नहीं हो सकती. म्यांमार में हाल के मेटीकीना मीटिंग को अब तक के सबसे बड़े प्रयास और सफलता के रूप में देखा जा रहा है. बहरहाल, सरकार और इन सशस्त्र समूहों के बीच दशकों से जो दूरी बनी हुई थी और विश्वास का अभाव था, इसे बहाल करने में कुछ समय तो लगेगा ही. लिहाज़ा, इस असाधारण मेटीकीना मीटिंग से कुछ उम्मीदें पैदा हुई हैं.

भारत पर प्रभाव

म्यांमार भारत का पड़ोसी देश है. इसलिए इस देश में हो रहे किसी भी तरह के बदलाव से भारत अछूता नहीं रह सकता. आज अगर म्यांमार में अल्पसंख्यक समुदायों की स्वतंत्रता और उनके अधिकारों की पहल की जा रही है, तो इन सुधारों से भारत का बोझ भी हल्का होगा, क्योंकि भारत में काफी संख्या में रोहिंग्या शरणार्थी रह रहे हैं. कोई भी शरणार्थी अगर हमारे देश में शरण लेता है तो उन्हें उस देश द्वारा अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराना जरूरी हो जाता है. भारत के लिए यह एक अलग सिरदर्द है. दूसरी तरफ रोहिंग्या शरणार्थियों को लेकर यहां राजनीतिक पार्टियों ने सरकार पर समय-समय पर दबाव भी बनाए हैं. इसी दबाव को देखते हुए दिल्ली सरकार ने रोहिंग्या शरणार्थियों को एक बार दिल्ली से बाहर भी खदेड़ा था. भारत में चुनावी दौर चल रहा है. अगर हम रोहिंग्या शरणार्थियों को अपने यहां से खदेड़ते हैं, तो यह अपने यहां के मुस्लिमों को नाराज करने जैसी स्थिति होगी और सरकार ऐसा कभी नहीं चाहेगी. दूसरी तरफ भारत सीधे तौर पर म्यांमार के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, क्योंकि यह म्यांमार की संप्रभुता को चोट पहुंचाने के समान होगा या म्यांमार के आंतरिक मामले में दखल देने के समान होगा. चूंकि म्यांमार में 2 फीसद भारतीय मूल के लोग रहते हैं, इसलिए इसे अनदेखा भी नहीं किया जा सकता. एल एन सिंघवी कमेटी के रिपोर्ट के अनुसार, सबसे ज्यादा प्रवासी भारतीय म्यांमार में रहते हैं. एक और चिंता इस बात की है कि अगर किसी देश के आंतरिक हालात ठीक नहीं हैं और उस देश का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भारत के साथ कोई संबंध है तो उस देश की सहायता कर या उससे दूरी न बनाकर हम अपने देश के कुछ खास समुदाय के लोगों से बैर मोल ले लेंगे. जैसा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार की घटना पर भारत सैद्धांतिक रूप से विरोध दर्ज कराता है. इसी तरह भारत को म्यांमार के अल्पसंख्यक मुसलमानों के प्रति सरकार और लोगों के रुख को भांपते हुए उचित निर्णय लेने होंगे. ऐसे ही भारत के अपने पड़ोसियों के साथ संबंध ठीक नहीं चल रहे हैं और यदि भारत सरकार म्यांमार के मसले पर संजीदगी से निर्णय नहीं लेती तो वह चीन की गोद में जाकर बैठ जाएगा, जो भारतीय कूटनीति की हार होगी. अर्थात हमें उक्त देश के प्रति उदासीन या मौके की नजाकत को समझते हुए अपने उचित कूटनीति का प्रदर्शन करना होगा. जैसा कि अभी हाल ही में श्रीलंका के मुद्दे पर हुआ, जिसमें तमिलों के दबाव में हमने अपनी विदेश नीति को ही ताक पर रख दिया और प्रधानमंत्री राष्ट्रमंडल देशों के सम्मेलन में भाग लेने श्रीलंका नहीं गए. जुनटा शासन के दौरान भी भारत म्यांमार के साथ आर्थिक संबंध बनाए रखने में कामयाब रहा. उस दौरान भारत ने सितवे बंदरगाह भी बनाया, जिससे म्यांमार के साथ व्यापार के नये रास्ते भी खुले और म्यांमार के लिए भारत एक बेहतरीन बाजार के रूप में सामने आया. इस बंदरगाह के कारण भारत से म्यांमार सामानों की ढुलाई बहुत कम समय में होने लगी, जिससे भारत को काफी फायदा हुआ. इतना ही नहीं, म्यांमार में लोकतंत्र की स्थापना के साथ ही भारत का आर्थिक संबंध और अधिक सुदृढ़ हुआ है. म्यांमार की उपेक्षा से भारत म्यांमार के बीच न सिर्फ लंबे समय से चले आ रहे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध प्रभावित होंगे, बल्कि आर्थिक हित भी प्रभावित होंगे. अभी हाल ही में भारत के बोधगया में हुए ब्लास्ट को लेकर म्यांमार ने भारत को अपनी चिंता से अवगत कराया था. म्यांमार की चिंता इस बात से थी कि बोधगया ब्लास्ट का प्रभाव म्यांमार पर पड़ सकता था, क्योंकि म्यांमार में अल्पसंख्यक रोहिंग्या मुसलमान और बौद्धों के बीच भीषण हिंसक घटनाएं हुईं थीं. इस बात से समझा जा सकता है कि पड़ोसी म्यांमार की स्थिति भारत के लिए कितना संवेदनशील है. ऐसे में भारत के लिए यह जरूरी हो जाता है कि वह म्यांमार के साथ अपने संबंधों को कूटनीतिक तरीकों से तय करे, ताकि उसके साथ संबंध अनुकूल रहे. ■

कोई भी शरणार्थी अगर हमारे देश में शरण लेता है तो उन्हें उस देश द्वारा अंतरराष्ट्रीय क़ानून के तहत मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराना ज़रूरी हो जाता है. भारत के लिए यह एक अलग सिरदर्द है. दूसरी तरफ रोहिंग्या शरणार्थियों को लेकर यहां राजनीतिक पार्टियों ने सरकार पर समय-समय पर दबाव भी बनाए हैं. इसी दबाव को देखते हुए दिल्ली सरकार ने रोहिंग्या शरणार्थियों को एक बार दिल्ली से बाहर भी खदेड़ा था. भारत में चुनावी दौर चल रहा है. अगर हम रोहिंग्या शरणार्थियों को अपने यहां से खदेड़ते हैं, तो यह अपने यहां के मुस्लिमों को नाराज़ करने जैसी स्थिति होगी और सरकार ऐसा कभी नहीं चाहेगी.

feedback@chauthiduniya.com

साई

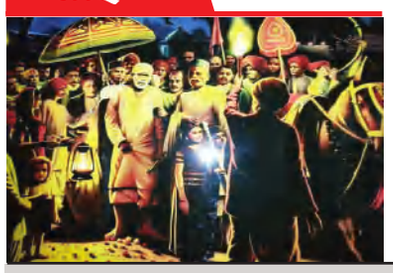

बाबा के दर्शन से भक्तों को अनेक प्रकार का लाभ पहुंचता था. अनेकों निष्कपट और स्वस्थ बन गए, दुष्टात्मा पुण्यात्मा में बदल गए. अनेकों कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए और अनेकों को मनोवांछित फल की प्राप्ति हो गई. बिना कोई रस या औषधि का सेवन किए, बहुत से अंधों को पुनः दृष्टि प्राप्त हुई, पंगुओं की पंगुता नष्ट हो गई. कोई भी उनकी महानता का अन्त न पा सका.

एक बार...

साईं हैं दया के सागर

चौथी दुनिया ब्यूरो

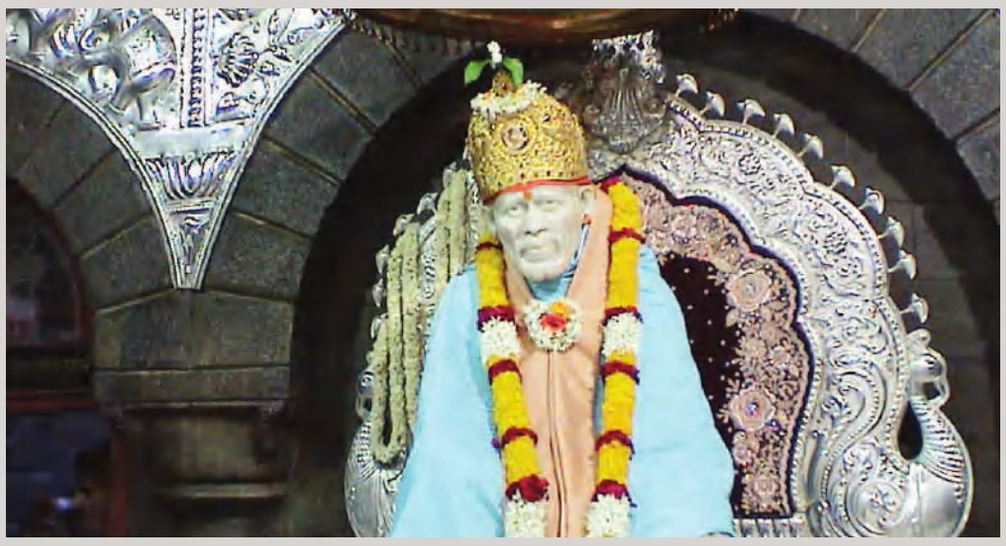

साई बाबा समस्त यौगिक क्रियाओं में पारंगत थे. 6 प्रकार की क्रियाओं के तो वे पूर्ण ज्ञाता थे. 6 क्रियायें, जिनमें धोती (एक 3 फुट चौड़े व 22 फुट लम्बे कपड़े के भीगे हुए टुकड़े से पेट को स्वच्छ करना), खण्ड योग (अर्थात अपने शरीर के अवयवों को पृथक–पृथक कर उन्हें पुनः पूर्ववत जोड़ना) और समाधि आदि भी सम्मिलित हैं. यदि कहा जाए कि वे हिन्दू थे तो आकृति से वे मुसलमान प्रतीत होते थे. कोई भी यह निश्चयपूर्वक नहीं कह सकता था कि वे हिन्दू थे या मुसलमान. वे हिन्दुओं का रामनवमी उत्सव यथाविधि मनाते थे और साथ ही मुसलमानों का चन्दनोत्सव भी. वे उत्सव में दंगलों को प्रोत्साहन तथा विजेताओं को पर्याप्त पुरस्कार देते थे. गोकुल अष्टमी को वे गोपाल–काला उत्सव भी बड़ी धूमधाम से मनाते थे. ईद के दिन वे मुसलमानों को मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आमंत्रित करते थे. एक समय मोहर्रम के अवसर पर मुसलमानों ने मस्जिद में ताजिए बनाने तथा कुछ दिन वहां रखकर फिर जुलूस बनाकर गांव से निकालने का कार्यक्रम किया. साईबाबा ने केवल चार दिन ताजियों को वहां रखने दिया. यदि कोई उन्हें हिन्दू घोषित करें तो वे सदा मस्जिद में निवास करते थे और यदि मुसलमान कहे तो वे सदा वहां धूनी प्रज्ज्वलित रखते थे तथा अन्य कर्म, जो कि इस्लाम धर्म के विरुद्ध है, जैसे चक्की पीसना, शंख तथा घंटानाद, होम आदि कार्य करना, अन्नदान और अर्घ्य द्वारा पूजन आदि सदैव वहां चलते रहते थे.

यदि कोई कहे कि वे मुसलमान थे तो कुलीन ब्राम्हण और अग्निहोत्री भी अपने नियमों का उल्लंघन कर सदा उनको साष्टांग नमस्कार किया करते थे. जो उनके स्वदेश का पता लगाने गए, उन्हें अपना प्रश्न ही विस्मृत हो गया और वे उनके दर्शनमात्र से मोहित हो गया. इसका निर्णय कोई न कर सका कि यथार्थ में साई बाबा हिन्दू थे या मुसलमान. इसमें आश्चर्य ही क्या है जो अहं व इन्द्रियजन्य सुखों को तिलांजलि देकर ईश्वर की शरण में आ जाता है तथा जब उसे ईश्वर के साथ अभिन्नता प्राप्त हो जाती है, तब उसकी कोई जाति–पाति नहीं रह जाती. इसी कोटि के साई बाबा थे, जो जातियों और प्राणियों में किंचित मात्र भी भेदभाव नहीं रखते थे. कुत्ते भी उनके भोजन–पात्र में मुंह डालकर स्वतंत्रतापूर्वक खाते थे, लेकिन उन्होंने कभी कोई भी आपत्ति नहीं की. ऐसा अपूर्व और अद्भुत साई बाबा का अवतार था. बाबा अखण्ड सच्चिदानन्द थे. उनकी महानता और अद्वितीय का बखान कौन कर सकता है. जिसने उनके चरण–कमलों की शरण ली, उसे साक्षात्कार की प्राप्ति हुई. अनेक सन्यासी, साधक और अन्य जन भी साईबाबा के पास आया करते थे. बाबा भी सदैव उनके साथ चलते–फिरते, उठते–बैठते, उनसे वार्तालाप कर उनका चित्तरंजन किया करते थे. अल्लाह मालिक सदैव उनके होठों पर था. वे कभी भी विवाद और मतभेद में नहीं पड़ते थे तथा सदा शान्त और स्थिर रहते थे. परन्तु कभी–कभी वे क्रोधित हो जाया करते थे. वे सदैव ही वेदान्त की शिक्षा देते थे. अमीर और गरीब दोनों उनके लिए एक समान थे. साई स्वयं ज्ञानावतार होकर भी वे सदैव अज्ञानता का प्रदर्शन करते थे. उन्हें आदरसत्कार से सदैव अरुचि थी. इस प्रकार साई बाबा का वैशिष्टय था. वे शरीरधारी, लेकिन कर्मों से उनकी ईश्वरीयता स्पष्ट झलकती थी. शिरडी के सकल नर–नारी उन्हें परमब्रह्मा ही मानते थे.

साई ने शिरडी में प्रायः समस्त मंदिरों का उन्होंने जीर्णोंधार किया. तात्या पाटील के द्वारा शनि, गणपति, शंकर पार्वती, ग्राम्यदेवता और हनुमानजी आदि के मंदिर ठीक करवाए. उनका दान भी विलक्षण था. दक्षिणा के रुप में जो धन एकत्रित होता था, उसमें से वे किसी को बीस रुपये, किसी को पंद्रह रुपये या किसी को पचास रुपये, इसी प्रकार प्रतिदिन स्वेच्छापूर्वक वितरण कर देते थे. प्राप्तिकर्ता उसे शुद्ध दान समझता था. बाबा की भी सदैव यही इच्छा थी कि उसका उपयुक्त रीति से व्यय किया जाय.

बाबा के दर्शन से भक्तों को अनेक प्रकार का लाभ पहुंचता था. अनेकों निष्कपट और एकदम स्वस्थ बन गए, दुष्टात्मा लोग भी पुण्यात्मा में बदल गए. अनेकों कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए और अनेकों को मनोवांछित फल की प्राप्ति हो गई. बिना कोई रस या औषधि सेवन किए, बहुत से अंधों को पुनः दृष्टि प्राप्त हुई, पंगुओं की पंगुता नष्ट हो गई. कोई भी उनकी महानता का अन्त न पा सका. उनकी कीर्ति दूर–दूर तक फैलती गई और भिन्न–भिन्न स्थानों से यात्रियों के झुंड के झुंड शिरडी आने लगे. बाबा सदा धूनी के पास ही आसन जमाए रहते और वहीं विश्राम किया करते थे. वे कभी स्नान करते और कभी स्नान किए बिना ही समाधि में लीन रहते थे. वे सिर पर एक छोटी सी साफी, कमर में एक धोती और तन ढंकने के लिए एक अंगरखा धारण करते थे. प्रारम्भ से ही उनकी वेशभूषा इसी प्रकार थी. अपने जीवनकाल के पूर्व में वे गांव में चिकित्साकार्य भी किया करते थे. रोगियों का निदान कर उन्हें औषधि भी देते थे और उनके हाथ में अपरिमित यश था. इस कारण से वे अल्प काल में ही योग्य चिकित्सक विख्यात हो गए. यहां एक घटना का उल्लेख किया जाता है कि एक भक्त की आंखें बहुत लाल हो गई थी. उन पर सूजन भी आ गई थी. शिरडी सरीखे छोटे ग्राम में डाक्टर कहां मिलता तब बाबा के भक्त रोगी को बाबा के पास लेकर आए. इस प्रकार की पीड़ा में डॉक्टर प्रायः लेप, मरहम, अंजन, गाय का दूध तथा कपूरयुक्त औषधियों को प्रयोग में लाते हैं, लेकिन बाबा की औषधि तो सर्वथा ही भिन्न थी. उन्होंने भिलावां पीस कर उसकी दो गोलियां बनाई और रोगी के नेत्रों में एक–एक गोली चिपका कर पट्टी से आंखें बांध दी. दूसरे दिन पट्टी हटाकर नेत्रों के ऊपर जल के छींटे छोड़े. सूजन कम हो गई और आंखे ठीक हो गईं. नेत्र शरीर का एक अति सुकोमल अंग है, लेकिन बाबा की औषधि से कोई हानि नहीं पहुंची, लेकिन आंखों की व्याधि दूर हो गई.

बाबा बाल्यकाल से ही यौगिक क्रियाएं किया करते थे और उन्हें जो अवस्था प्राप्त हो चुकी थी, उसका सत्य ज्ञान किसी को भी नहीं था. चिकित्सा के नाम से उन्होंने कभी किसी से एक पैसा भी लेना स्वीकार नहीं करते थे. अपने उत्तम लोकप्रिय गुणों के कारण उनकी कीर्ति दूर–दूर तक फैल गई. उन्होंने अनेक निर्धनों और रोगियों को स्वास्थ्य प्रदान किया. मसीहो के मसीहा साई ने कभी अपने स्वास्थ्य की चिंता न कर अनेक विघनों का सामना किया तथा स्वयं असहनीय वेदना और कष्ट सहन कर सदैव दूसरों की भलाई की और उन्हें विपत्तियों में सहायता पहुंचाई. वे सदा कल्याणार्थ चिंतित रहते थे. साई हमेशा दयालु भाव रहते थे सब पर एक समान कृपा दृष्टि बनाए रखते थे. ■

feedback@chauthiduniya.com

> यदि कोई कहे कि वे मुसलमान थे तो कुलीन ब्राह्मण और अग्निहोत्री भी अपने नियमों का उल्लंघन कर सदा उनको साष्टांग नमस्कार किया करते थे. जो उनके स्वदेश का पता लगाने गए, उन्हें अपना प्रश्न ही विस्मृत हो गया और वे उनके दर्शनमात्र से मोहित हो गया. इसका निर्णय कोई न कर सका कि यथार्थ में साई बाबा हिन्दू थे या मुसलमान. इसमें आश्चर्य ही क्या है जो अहं व इन्द्रियजन्य सुखों को तिलांजलि देकर ईश्वर की शरण में आ जाता है तथा जब उसे ईश्वर के साथ अभिन्नता प्राप्त हो जाती है, तब उसकी कोई जाति–पाति नहीं रह जाती.

साई भक्तों!

आप भी चौथी दुनिया को साई से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, साई से आप कब और कैसे जुड़े. साई की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साई को क्यों पूजते हैं. कैसे बने आप साई भक्त. साई बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है. साई बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

चौथी दुनिया
एफ–2, सेक्टर–11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर), उत्तर प्रदेश, पिन–201301
ई–मेल feedback@ chauthiduniya.com

योग से मन को प्रसन्नता मिलती है

डॉ. अभय बंग

मन में उठनेवाले शब्दों, वाक्यों को ही हम विचार कहते हैं. ये वाक्य या शब्द अकेले नहीं आते. वे अपने साथ भाव भी लेकर आते हैं. अपनी स्मृतियों तथा पुराने अनुभवों पर आधारित प्रतिक्रिया अर्थात भाव. फिर यह प्रतिक्रिया कुछ भावों के प्रति अनुकूल तो कुछ के प्रति प्रतिकूल हो सकती है. किसी को पाने की लालसा तो किसी से अनिच्छा होना–इसी को राग–द्वेष(राग–अनुराग) कहा जाता है. कठिनाई विचारों से नहीं है, उनके साथ आने वाली राग द्वेष रूपी प्रतिक्रिया से होती है. मुक्ति विचारों से नहीं, अपितु विचारों की प्रतिक्रिया स्वरूप मन में उठनेवाले राग– द्वेष व तृष्णा से मिलनी चाहिए. पतंजलि के योगश्चित्तवृत्ति निरोधः

वचन में योग का अर्थ है चित्त की वृत्ति का निरोध, विचारों का निरोध नहीं. विपश्यना की आन–पान साधना भी यही सिखाती है. आरईटी भी यही सिखाती है. मन में निर्मित होने वाले विचारों में, वाक्यों में न उलझते हुए उनकी ओर केवल तटस्थ वृत्ति से देखना है. विचारों और वाक्यों की नदी सतत प्रवाहमान है, लेकिन उसमें डुबकियां न खाते हुए, तट पर बैठकर शांति से उस प्रवाह को देखना है. नदी बहती रहे हमें क्या? लेकिन उसमें डूबने से बचने के लिए यदि हम नदी के प्रवाह को बांध बनाकर रोकने का प्रयास करेंगे, तो वह प्रकृति के नियमों के विरुद्ध होने की वजह से रौद्र रूप धारण कर लेगा और अंत में बांध टूट ही जाएगा. उसकी बजाए यदि हमने उस नदी से बाहर निकलकर, तट पर बैठने की कला साध ली तो प्रश्न सुलझ जाएगा. विचार व संवेदनाओं को बंद करना संभव नहीं है. वह व्यर्थ की छटपटाहट है. बल्कि वही एक नई वृत्ति, नया लक्ष्य अथवा आवेग बन जाता है. फिर तो सब कुछ व्यर्थ. हमें तो उनमें न उलझते हुए उनकी ओर देखना भर सीखना है. विपश्यना अर्थात विशेष पश्यना, देखना बिना उलझे देखने की साधना अथवा अभ्यास माने ध्यान. ध्यान यह एक एकाग्रता की साधना नहीं, निर्विचार अवस्था की साधना भी नहीं. साक्षात्कार की तो बिल्कुल ही नहीं. वह तो निर्विकार रूप से देखने की कला का अभ्यास भर है. एक दिन यह गांठ अचानक खुल गई और समझ में आया कि, अरे मैं किस मृगजल के पीछे दौड़ रहा था और उसके कारण असंतुष्ट भी हो रहा था? भ्रम से लड़ रहा था. भ्रम से लड़ना भूत से लड़ने के समान है. जो है ही नहीं, उससे लड़कर कैसे जीत पाऊंगा? तो सबसे बढ़िया उपाय है–लड़ाई छोड़ो और उस भ्रम की ओर शांति से देखते हुए यह समझ लो कि वह भ्रम है. लड़ाई खत्म, द्वंद भी खत्म.

विमला ताई, विपश्यना सिखाने वाले गोयनका, विनोबा, कृष्णमूर्ति–सभी ने यह कह रखा था. उत्तर पहले से ही उपलब्ध थे. मेरे सुनने और पढ़ने में भी थे. केवल उनके मेरे भीतर पैठने के लिए मेरी तैयारी होना बाकी था. मेरा क्षण आना बाकी था. निराश न होते हुए प्रतीक्षा को ही साधना कहते होंगे. मेरे प्रयत्नों से मेरे प्रश्नों के उत्तर मिले यह कहना धृष्टता होगी. प्रयत्न जारी रहने पर प्रयत्न के कारण थकान आती है, आंखें खुलती हैं, मन में शरणागति आती है, विनम्रता आती है और उसके आते ही उत्तर स्वयं मिलता है. मेरी वैचारिक स्पष्टता बढ़ती ही जा रही थी. मुक्ति अथवा ईश्वर दर्शन संबंधी अवास्तविक

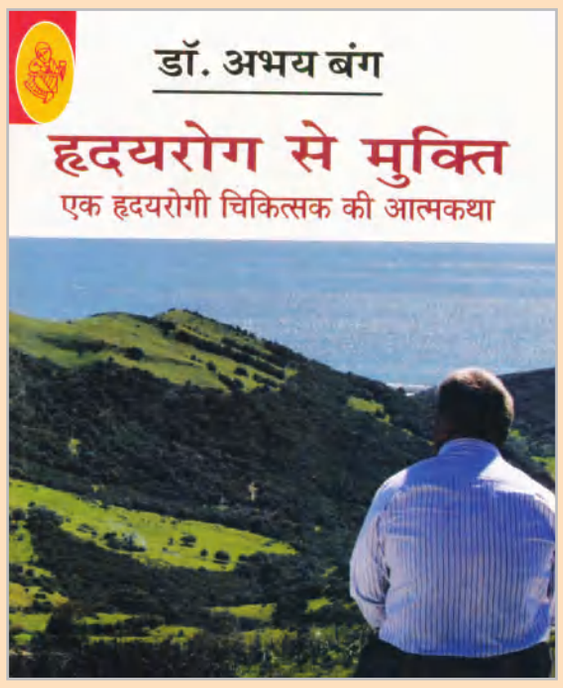

काल्पनिक अपेक्षाएं धीरे–धीरे समाप्त होती जा रहीं थीं. जैसे–जैसे वे कम हो रहीं थी वैसे–वैसे मन की बेचैनी भी कम होती गई. मन का संभ्रम और संशय कम हुआ. रास्ता मेरी समझ में आ गया था. उस पर मैं कैसे कहां पहुचूंगा, इसका नक्शा भी स्पष्ट हो गया था. अब बस अभ्यास की जरूरत थी. योगाभ्यास के कारण क्या संभव हुआ और क्या नहीं, ये दोनों बता देना चाहिए. योगाभ्यास द्वारा रूढ़ अर्थ में परमेश्वर दर्शन हो पाता है या नहीं, यह मुझे नहीं मालूम. परंतु मनोकायिक स्तर पर अवश्य ही लाभ होता है. शरीर निरोगी, मन उल्लसित व जीवन स्फूर्तिवान हो जाता है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत अनुभव है. ऐसा क्योंकर संभव है? बचपन की निर्मलता, किशोरावस्था की उत्कटता और तरूणाई का जोश व आशावादिता–ये अतिशयप्रबल सकारात्मक अनुभव होते हैं. जीवन को स्फूर्तिमय बनाए रखने वाले. याद है, बचपन में खरगोश या तोता या कुत्ता कितने अपने लगते थे? उनसे हम कितना एकरूप हो सकते थे? तब मैं और मेरा प्रबल नहीं थे, अतः एकरूपता सहज साध्य थी. तरूणाई में तो यह उत्कटता इतनी तीव्र थी कि, मुझे याद है, एक बार साईकिल से कॉलेज जाते हुए पान की दुकान पर बज रहे रेडियो से अचानक लता का एक गीत सुनाई दिया. एक दिव्य स्पर्श कानों के द्वारा सारे शरीर में भर गया और शरीर में झनझनाहट जाग उठी. अकस्मात सारा विश्व मानो एक विलक्षण प्रकाश में नहाने लगा.

लता की वह दिव्य आवाज और प्रकाश में नहाए हुए उस विश्व की अनुभूति करता हुआ मैं वहां ठगा–सा खड़ा रह गया ऐसी उत्कटता सारी दुनिया को बदलकर न्यायपूर्ण व सुखी बनाने का तरूणाई का आशावाद. विश्व की भलाई के लिए अपना जीवन दांव पर लगाने के लिए उत्सुक. यही तीव्र संवेदनक्षम झंकृत अवस्था जीवन को सींचती थी.

आगे चलकर व्यावहारिकता से भरे जंग में कब मैं प्रबल होता गया और मेरे और गैर के रूप में कब संसार बंटता चला गया, इसका मुझे पता ही न चला. धीरे–धीरे संवेदनशीलता और उत्कटता कम होती गई. उम्र बढ़ने का परिणाम परिपक्वता अथवा व्यावहारिकता कहकर मैं उसे स्वीकारता चला गया, लेकिन रस सुखता चला गया. योगाभ्यास से वह रस पुनः लौट आया. मुझमें फिर जीवन का संचार हुआ. प्राणायाम और योग हमें क्षण में घटित होने वाले अनुभवों के प्रति सजग व संवेदन शील बनाते हैं. यह वाक्य मानो योग का मर्म है. अभी का यह वर्तमान क्षण, यह सांस शरीर की यह संवेदना, यह जागृति–यही इस क्षण का सत्य है. उस सत्य के प्रति मन को तथा बोध को जाग्रत करने का काम योग करता है. योगाभ्यास अर्थात वर्तमान क्षण में घटने वाले अनुभवों के प्रति संवेदनक्षम होने का अभ्यास. सेन्सिटिविटी ट्रेनिंग इससे इसी देह में इन्ही आंखों से, इसी क्षण प्रत्येक क्षण, सत्य दर्शन की संवेदनक्षमता मिलती है.(क्या इसी को साक्षात्कार दर्शन आदि कहा जाता है) जो वास्तव में हो रहा है उसी में आनंद दृढ़ना होता है. इससे जीवन में गायब हुई ताजगी लौट आती है. पारलौकिक आध्यात्मिक स्पष्टीकरण छोड़ भी दिए जाएं तब भी, मनोकायिक स्तर पर योग से मन को प्रसन्नता मिलती है और फिर मन प्रसन्न हो जाए तो और क्या चाहिए? विनोबा जी ने क्या ही सुंदर कहा है–जीवन के सारे दुःख दूर हो जाएं तो मन प्रसन्न हो जाएगा, यह कोरा भ्रम है. मन प्रसन्न हो जाए तो जीवन के सारे दुःख दूर हो जाएंगे. संक्षेप में, ध्यान के कारण शरीर व मन के तानपुरे के तार सुंदर सुर में लग जाते हैं. ■

राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली से प्रकाशित

feedback@chauthiduniya.com

एक बार...

मन में चोर

एक राजा इत्र का बहुत शौकीन था. एक दिन वह दरबार में अपने कपड़ों में इत्र लगा रहा था. अचानक इत्र की एक बूंद नीचे गिर गई. राजा ने सबकी नजरें बचाकर उसे उठा लिया, लेकिन पैनी नजर वाले मंत्री ने यह देख लिया. राजा ने भांप लिया कि मंत्री ने उसे देख लिया है. दूसरे दिन जब दरबार लगा, तो राजा एक मटका इत्र लेकर बैठ गया. मंत्री सहित सभी दरबारियों की नजरें राजा पर गड़ी थीं. थोड़ी देर बाद जब राजा को लगा कि दरबारी चर्चा में व्यस्त हैं, तो उसने इत्र से भरे मटके को ऐसे लुढ़का दिया, मानो वह अपने आप गिर गया हो और इत्र बहने लगा. राजा ने ऐसी मुद्रा बनाई, जैसे उसे इत्र के बह जाने की कोई परवाह न हो. इत्र बह रहा था. राजा उसकी अनदेखी किए जा रहा था.

मंत्री ने यह देखकर कहा– राजासाहेब गलती माफ हो, लेकिन यह आप ठीक नहीं कर रहे हैं. जब किसी इंसान के मन में चोर होता है तो वह ऐसे ही करता है. कल आपने जमीन से इत्र उठा ली तो आपको लगा कि आपसे कोई गलती हो गई है. आपने सोचा कि आप तो राजा हैं, आप जमीन से भला क्यों इत्र उठाएंगे, लेकिन वह कोई गलती थी ही नहीं. एक इंसान होने के नाते आपका ऐसा करना स्वाभाविक था, लेकिन आपके भीतर राजा होने का जो घमंड है, उस कारण आप बेचैन हो गए और कल की बात की भरपाई के लिए बेवजह इत्र बर्बाद किए जा रहे हैं. सोचिए आपका घमंड आपसे क्या करवा रहा है. यह सुनकर राजा लज्जित हो गया.

शिक्षा : घमंड में आकर कोई कार्य नहीं करना चाहिए

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

> पुस्तकालयों के प्रति उपेक्षा की जो सबसे बड़ी वजह है वो है हमारी शिक्षा पद्धति. हमारी शिक्षा पद्धति ही इतनी दोषपूर्ण है कि वहां पुस्तकालयों पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जाता है. जिस तरह से देशभर में अंग्रेजी माध्यम स्कूलों का जाल फैला है उसने भी पुस्तकालयों को स्कूल की शोभा भर बना दिया है. अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में इस बात पर ज़ोर तो रहता है कि छात्रों को खेलकूद, नृत्य संगीत से लेकर स्केटिंग में रुचि विकसित की जाए, लेकिन क्या इन स्कूलों में छात्रों को पुस्तकालयों से उपन्यास या कहानी या कोई अन्य किताब पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है.

पुस्तकालयों को बचाने की मुहिम

अनंत विजय

आजकल हिंदी साहित्य के तमाम मसले सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक पर हल हो रहे हैं. विवाद से लेकर विमर्श तक. कुछ लेखकों को फेसबुक की अराजक आज़ादी ने एक ऐसा मंच मुहैया करवा दिया है जहां वो अपनी अपनी कुंठा का सार्वजनिक प्रदर्शन करते हैं. कोई वहां बेहतरीन कवि, कहानी, उपन्यासकार, आलोचक और पत्रकार की सूची चिपकाते रहते हैं तो कई लोग उसको अपने प्रचार का प्लेटफॉर्म मानकर उपयोग कर रहे हैं. फेसबुक किसी भी मुद्दे या घटना के ख़िलाफ़ या समर्थन के अभियान का मंच भी बन गया है. इस आभासी दुनिया की अराजक आज़ादी के दौर में कुछ गंभीर मसले भी अभी फेसबुक पर उठ रहे हैं. इसी तरह का एक गंभीर अभियान फेसबुक पर चल रहा है– चलो करनाल. साहित्यकारों और साहित्यप्रेमियों से करनाल जाने की अपील इस वजह से की जा रही है कि वहां के पाश पुस्तकालय को बंद करने की साज़िश हो रही है. पाश पुस्तकालय ने करनाल और आसपास के इलाके में साहित्यिक सांस्कृतिक चेतना जगाने का और एक सांस्कृतिक संस्कार विकसित करने का काम किया है. वहां पुस्तकालय के अलावा देश भर के लेखकों और रंगकर्मियों का जमावड़ा होता रहा है. लेकिन अब उस साहित्यक सांस्कृतिक केंद्र को बंद करने की कोशिश की जा रही है. हिंदी का साहित्य समाज इससे उद्वेलित है. कुछ दिनों पहले इस तरह की ख़बरें आई थीं कि दिल्ली की मशहूर और ऐतिहासिक लाइब्रेरी– दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पा रहा है. दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी बदहाल है, वहां मूलभूत सुविधाओं का अभाव है. कर्मचारियों के वेतन पर संकट के अलावा पुस्तकालय की किताबों और पत्र–पत्रिकाओं को सहेजने के लिए भी आवश्यक धनराशि की कमी है. लिहाजा ऐतिहासिक महत्व की किताबें नष्ट हो रही हैं या उनके नष्ट होने का ख़तरा उत्पन्न हो गया है. कमोबेश यही हालत देशभर के पुस्तकालयों का है. यह हालत तो तब है कि जबकि पुस्तकालयों में किताबों की सरकारी ख़रीद के लिए लंबा चौड़ा बजट है. किताबों की ख़रीद के लिए संस्कृति मंत्रालय के अधीन राजा राम मोहन राय के नाम से एक ट्रस्ट है. यह ट्रस्ट देशभर के सरकारी और गैरसरकारी पुस्तकालयों को किताबों की ख़रीद के लिए अनुदान देता है. इस ट्रस्ट में विभिन्न मंत्रालयों और सरकारी विभागों के अधिकारियों की अलग अलग समिति होती है. इसके अलवा सांसदों के स्थानीय विकास निधि में भी एक निश्चित धनराशि पुस्तकों के लिए आरक्षित करने का भी प्रावधान है. सांसद उस धनराशि का उपयोग हर साल अपने इलाके के स्कूलों में किताबें ख़रीदने के लिए अनुदान के तौर पर दे सकते हैं. बावजूद इसके हमारे देश में पुस्तकालय मरणासन्न हो रहे हैं. एक ज़माना था जब पुस्तकालयों की अहमियत इतनी ज्यादा थी कि उसके बगैर छात्रों और शोधार्थियों का काम ही नहीं चलता था. मैं कई ऐसे लेखकों को जानता हूं जो किसी लेखक की रचनावली पर काम करने के सिलसिले में कोलकाता के नेशनल लाइब्रेरी में महीनों तक किताबें और पत्र–पत्रिकाएं छानते रहे हैं. मुझे नब्बे के दशक के अपने दिल्ली विश्वविद्यालय के शुरुआती दिन भी याद आते हैं जब हम अपने छात्र जीवन के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस के सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी में नियमित जाया करते थे. यह नियमितता वैसी ही थी जैसी कि दफ्तर जाने की होती है. तय समय पर घर से निकल जाना और फिर भोजनावकाश के बाद फिर से वहां जाकर शाम तक डटे रहना. पुस्तकालय में पढ़ने के माहौल के अलावा भी नियमितता की एक अन्य वजह थी. वह वजह थी वहां पहुंचने वालों छात्रों की भीड़. अगर आप दस मिनट भी लेट हो गए तो आपको लाइब्रेरी में जगह नहीं मिलती थी और आपको निराश होकर वापस लौटना पड़ता था. लेकिन अब वहां के हालात भी बदलने लगे हैं. सभी लाइब्रेरी की तरह वो भी उदासनीता का शिकार होने लगा है.

पुस्तकालयों के प्रति उदासीनता और उनकी बदहाली के लिए हमें इसके सामाजिक और अन्य कारणों की पड़ताल करनी चाहिए. जब हम

अपने आसपास देखते हैं तो ये सारी वजहें हवा में तैरती नज़र आती हैं. कई विद्वानों का मानना है कि पुस्तकालयों की दुर्गति के लिए इंटरनेट ज़िम्मेदार है. अब लोगों की मुट्ठी में मौजूद इंटरनेट युक्त मोबाइल फोन और टैबलेट पर गूगल बाबा हर वक्त हर तरह की मदद को तैयार रहते हैं. आपने कुछ सोचा और पलक झपकते वो आपके सामने लाखों परिणाम के साथ हाजिर है. इस तर्क में ताक़त है और हो सकता है कि पुस्तकालयों के प्रति हमारी उपेक्षा का यह भी एक कारण हो. लेकिन पुस्तकालयों के प्रति उपेक्षा की जो सबसे बड़ी वजह है वो है हमारी शिक्षा पद्धति. हमारी शिक्षा पद्धति ही इतनी दोषपूर्ण है कि वहां पुस्तकालयों पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जाता है. जिस तरह से देशभर में अंग्रेजी माध्यम स्कूलों का जाल फैला है उसने भी पुस्तकालयों को स्कूल की शोभा भर बना दिया है. अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में इस बात पर ज़ोर तो रहता है कि छात्रों को खेलकूद, नृत्य संगीत से लेकर स्केटिंग में रुचि विकसित की जाए, लेकिन क्या इन स्कूलों में छात्रों को पुस्तकालयों से उपन्यास या कहानी या कोई अन्य किताब पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है. अगर हम इसका उत्तर ढूंढते हैं तो अंधकार दिखाई देता है. आज हमारी शिक्षा प्रणाली में परीक्षा में आने वाले अंक इतने महत्वपूर्ण हो गए हैं कि उसके अलावा किसी अन्य चीज़ पर छात्रों, अध्यापकों और अभिभावकों का फोकस ही नहीं रहता है. छात्रों की इस तरह से कंडीशनिंग की जाने लगी है कि उसके लिए पाठ्य पुस्तकों के अलावा अन्य किसी पुस्तक का महत्व ही नहीं रह गया है. अन्य पुस्तकों का महत्व रहे भी क्यों क्योंकि वो पाठ्य पुस्तक तो हैं भी नहीं.

आज हालात यह है कि नई पीढ़ी के छात्र–छात्राओं को लाइब्रेरी कार्ड का तो पता है लेकिन उनको लाइब्रेरी का कैटलॉग देखना आता हो, इसमें संदेह है. कार्ड तो इसलिए पता है क्योंकि नामांकन के साथ ही आपका लाइब्रेरी कार्ड बन जाता है. कैटलॉग देखना सीखने के लिए तो पुस्तकालय जाना होगा. वहां जाना किसी भी स्कूल में अनिवार्य नहीं है. इन अंग्रेजी स्कूलों में लाइब्रेरी पीरियड भी होता है लेकिन उसमें बच्चे पुस्तकालय से ज्यादा वक्त स्कूल परिसर से लेकर खेल के मैदान में बिता देते हैं. स्कूल के अलावा अगर हम इसके सामाजिक वजहों को देखों तो वहां भी पुस्तक को लेकर एक ख़ास क़िस्म की उपेक्षा का भाव दिखाई देता है. आज बच्चों के जन्मदिन के मौक़े पर दिए जाने वाले उपहार में किताबें नहीं ही होती हैं. इलेक्ट्रॉनिक गेम्स से लेकर बल्ले और गेंद तक उपहार में दिए जा रहे हैं. मां–बाप के अंदर भी अपने बच्चों को पुस्तक देने की प्रवृत्ति लगभग ख़त्म होती जा रही है. इन सामाजिक वजहों से जब पुस्तक को लेकर उपेक्षा का भाव लगातार मज़बूत होता जा रहा है तो उसके आलय यानि पुस्तकालय का उपेक्षित होना तो स्वाभाविक है.

दूसरी बात जो पुस्तकालयों की उपेक्षा को लेकर है वह है पुस्तकालयों में किताबों की ख़रीद. पूरे हिंदी जगत को यह तथ्य पता है कि राजा राम मोहन राय ट्रस्ट में किताबों की ख़रीद या फिर उसकी अनुशंसा में किस तरह के खेल होते हैं. अंट–शंट किताबों की सरकारी ख़रीद होती है. कुछ गंभीर पाठक जब नई कृतियों की तलाश में अपने पास के पुस्तकालय में पहुंचता है तो वहां स्तरहीन किताबें देखकर उसका मन खट्टा हो जाता है. अगली बार पुस्तकालय जाने से पहले वो दस बार सोचता है. अगर कहीं जाने के लिए किसी को भी दस बार सोचना पड़े तो समझ लीजिए की उपेक्षा की ज़मीन तैयार हो रही है. हमारे देश के पुस्ताकालयों के साथ भी ऐसा ही हो रहा है. अगर हमें अपने देश में पुस्तकालय या पढ़ने की संस्कृति का विकास करना है तो सर्वप्रथम हमारी शिक्षा प्रणाली की ख़ामियों को दूर करना होगा. पाठ्य पुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तकों के बारे में एक ऐसा मैकेन्जिम बनाना होगा कि नई पीढ़ी के लड़के–लड़कियां उन्हें भी पढ़ें. इसके अलावा समाज में जागृति पैदा करने के लिए सरकारी और गैरसरकारी संगठनों को काम करना होगा ताकि मां–बाप अपने बच्चों को किताबों के क़रीब ले जाएं. सरकारी ख़रीद में हो रहे घपलों पर लगाम लगाने के लिए भी जतन करने होंगे. अगर हम ये तीन काम भी कर लेते हैं तो हमें विश्वास है कि कोई भी पाश पुस्तकालय को बंद करने की साज़िश नहीं रच पाएगा, मशहूर पुस्तकालय उपेक्षा के शिकार नहीं होंगे. अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो फिर पुस्तकालय इतिहास के खंडहर बन जाएंगे. ■

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं.)
anant.ibn@gmail.com

कविता

बाढ़ वीचि

कला कौशल

दूर–दूर तक एक–सा मंज़र
जहां तक जाती है नज़र
एक विध्वंसक बहाव तारी है
कहां गए गांव
गांव के टोले
टोले के घर
घर के चूल्हे और
चूल्हों से उठते धुएं?
सब के सब कहां चले गए
अक्षयवट और पीपल
ठाकुरवाड़ी और अजानगाह भी
नहीं बचे
पैठनी–पगुराती भैंसें और पशु
मलाहों की दंड–पतवारें
और जालें भी बह गईं
दिशाएं क्षितिज से लटकी रोती हैं
घड़ी ठिठक कर सोती हैं
हाय! जहां तक जाती नज़र
एक–सा मंज़र!

किताब मिली

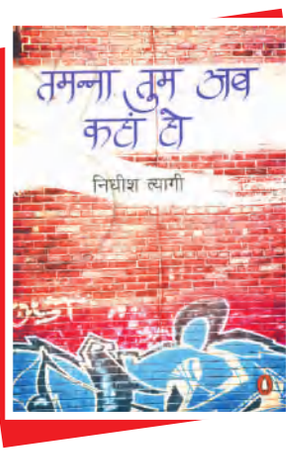

पुस्तक	लेखक
तमन्ना तुम अब कहां हो	निधीश त्यागी
प्रकाशक	**मूल्य**
पेंगुइन बुक्स	150 रुपये

हाल ही में पेंगुइन बुक्स से पत्रकार निधीश त्यागी की एक क़िताब आई है–*तमन्ना तुम कहां हो*. यह क़िताब हमारे आसपास घटने वाली तमाम छोटी–बड़ी घटनाओं का एक संग्रह है, जिसे लेखक ने एक अलग दृष्टि से देखने की कोशिश की है. बेहद छोटी–छोटी कहानियां संस्मरण स्वरूप लिखी गई हैं, जो संवेदना, सीख और विडंबनाओं को एक साथ कहती चलती हैं. जिस शैली में क़िताब लिखी गई है, गद्य का यह मिजाज़ हिंदी गल्प में कथा–लघुकथा ओर आधुनिकता–उत्तर आधुनिकता के भेद लांघते हुए नई भंगिमा का आगाज़ है. अपने नये मिजाज़ के कारण क़िताब पाठकों को बेहद पसंद आएगी.

लेखक और प्रकाशक इस कॉलम के लिए अपनी किताबें हमें भेज सकते हैं.
चौथी दुनिया
एफ–2, सेक्टर–11, नोएडा–201301
ई–मेल: feedback@chauthiduniya.com

श्रद्धांजलि

राजस्थानी लोककथा का सूरज अस्त हुआ

कृष्णकांत

यह दौर भारतीय साहित्य का शोक काल है. एक महीने के भीतर पांच बड़े साहित्यकारों का जाना निश्चित ही बहुत बड़ी क्षति है. नई कहानी आंदोलन को मुकाम तक पहुंचाने वाले राजेंद्र यादव, आलोचक परमानंद श्रीवास्तव, व्यंग्यकार–पटकथा लेखक केपी सक्सेना, उसके बाद बाल साहित्य को अभूतपूर्व योगदान देने वाले हरिकृष्ण देवसरे और लोक कथाओं के अप्रतिम चितेरे विजयदान देथा अब हमारे बीच नहीं हैं. इन विभूतियों का जाना साहित्य जगत में एक ऐसा शून्य छोड़ गया है, जो कभी नहीं भरा जा सकेगा.

विजयदान देथा भारतीय साहित्य का वह नाम है जिसने लोकसाहित्य को अंतरराष्ट्रीय बनाया. बिज्जी के नाम से मशहूर विजयदान देथा वह महान कथाकार है जो राजस्थानी लोक में रचा–बसा है और यही उनकी अंतरराष्ट्रीय पहचान है. उन्होंने राजस्थानी में लिखना शुरू किया और अपनी उम्र के आख़िरी पड़ाव तक हिंदी समेत भारतीय साहित्य जगत में छा गए. वे अपनी रचनाओं के माध्यम से युगों तक हमारे बीच रहेंगे, लेकिन हमने रचे जाने वह संभावना खो दी है जो सिर्फ़ बिज्जी में थी.

विजयदान देथा हिंदी के आख़िरी क़िस्सागो थे. हालांकि, लिखना उन्होंने राजस्थानी में शुरू किया था, जिसकी संविधान में मान्यता नहीं है, लेकिन अपने सशक्त लेखन से बिज्जी ने यह साबित किया कि भाषाओं–बोलियों के बारे में मान्यताओं की बहस ही व्यर्थ है. जो रचेगा, वह बचेगा. उनका लगभग पूरा ही साहित्य हिंदी में उपलब्ध है और हिंदी जगत ने उन्हें वह जगह दी है, जिसके वे हक़दार थे. वे किसी भी हिंदी लेखक से ज्यादा पढ़े और सराहे जाते हैं. उनकी कहानियां हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि हैं. उनके बारे में यह सवाल उठते रहे हैं कि वे मौलिक कथाकार हैं या लोकवार्ताकार? क्योंकि उनकी ज्यादातर रचनाएं लोककथाओं पर आधारित थीं, लेकिन बिज्जी ने पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रहीं लोककथाओं को आवाज़ दी ही, उन्हें नई भाषा, नए शिल्प और नये स्वर और तेवर के साथ पेश किया. उनके अपने नये स्वर ने उन लोककथाओं को भी मौलिक बना दिया और बिज्जी फिल्म से लेकर थियेटर और साहित्य की दुनिया के चहेते रचनाकार बन गए.

बिज्जी एक सितंबर, 1926 को राजस्थान के जोधपुर जिले के बोरुदा गांव में जन्म थे. आजीवन में गांव में ही रहने वाले बिज्जी ने राजस्थानी में करीब 800 छोटी–बड़ी कहानियां लिखीं, जिनका कई भाषाओं में अनुवाद हुआ. उन्हें साहित्य अकादमी और पद्मश्री से सम्मान से सम्मानित किया गया था. यहां तक कि गांव में रहकर रचने वाले इस कलमकार ने साबित किया कि बड़े रचनाकार सिर्फ़ दिल्ली या मुंबई में नहीं होते. उन्होंने राजस्थान के गांव से ही बॉलीवुड को भी आकर्षित किया और उनकी कई कहानियों पर फिल्में बनीं. श्याम बेनेगल ने उनकी कहानी चरणदास चोर पर इसी नाम से फिल्म बनाई. रंगकर्मी हबीब तनवीर ने इसी कहानी पर नाटक चरणदास चोर निदेर्शित किया, जिसका अबतक 20 हजार से अधिक मंचन हो चुका है. प्रकाश झा ने उनकी कहानी पर फिल्म बनाई परिणति तो मलि कौल ने दुविधा कहानी पर इसी नाम से फिल्म बनाई. दुविधा कहानी पर ही बाद में अमोल पालेकर ने शाहरुख खान और रानी मुखर्जी के साथ पहेली फिल्म बनाई. विजयदान देथा पूरे जीवन दिल्ली के साहित्यिक शोरगुल से दूर रचनाकर्म में लगे रहे. वे राजस्थानी में ही लिखते रहे और राजस्थान कभी नहीं छोड़ा. रवींद्रनाथ टैगोर के बाद बिज्जी भारतीय उपमहाद्वीप के अकेले रचनाकार हैं, जिन्हें 2011 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था. हालांकि, उस साल का नोबेल पुरस्कार स्वीडिश कवि थॉमस ट्रांसटोमर को मिला. जब इस पर बिज्जी की प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने कहा, यह पुरस्कार मैं उसी दिन जीत गया था, जिस दिन मुझे नामित किया गया. यह संतोष देने वाली बात है कि जिस भाषा को अपने देश में ही संवैधानिक पहचान नहीं मिली है, उस भाषा का लेखक नोबेल पाने वालों की सूची में है.

महान कथाकार विजयदान देथा का पूरा जीवन कठिनाइयों, संघर्षों, शोक और वियोगों से भरा रहा. जब वे चार वर्ष के थे, उनके पिता सामंती हिंसा का शिकार हो गए. पिता की हत्या के बाद उनका परिवार भयावह आर्थिक संकट के दौर से गुजरा. बाद में बिज्जी

के सर एक के बाद एक पुत्र, प्रपौत्र, पत्नी और परिजनों के आकस्मिक वियोग का पहाड़ टूटा. लेकिन बिज्जी का जीवट रचनाकार इन सब मुश्किलें लड़ता हुआ रचनात्मकता की बुलंदियों पर पहुंचा. बिज्जी ने कविताएं भी लिखीं और उपन्यास भी. हालांकि, उन्हें पहचान मिली लोककथाओं से. उनके बारे में इतालो काल्विनो ने लिखा है कि हम अपने भीतर की भाषा को बदल नहीं सकते और जीवन भर वह हमारे साथ रहती है. रहती वह हम सबके भीतर है, लेकिन उसकी पुकार सुनने वाले कान पाने के लिए विजय दान देथा होना पड़ता है जिसके पास उसका जवाब देने की ज़ुबान भी हो. हम जानते हैं कि पुकार तब तक सुनी गई मानी नहीं जाती जब तक उसका उत्तर न दिया जाए.

विजयदान देथा प्रकृति के घोर प्रशंसक थे. फूल–पत्तियां पेड़, पक्षी, तालाब, जानवर आदि उनके प्रिय पात्र भी रहे. उन्होंने बच्चों के लिए साहित्य रचा. बिज्जी रवीन्द्र नाथ टैगोर के घोर प्रशंसक थे. वे शरतचंद्र को बेहद मानते थे. एंटन चेखव से गहरे प्रभावित थे. विश्व साहित्य की उन्हें गहरी जानकारी थी. रूसी साहित्य का उनपर बहुत प्रभाव था. उनकी अपनी मजबूत वैचारिक प्रतिबद्धता थी जिस पर वे आजीवन जमे रहे और उनको आवाज़ देते रहे. उन्होंने भले ही राजस्थानी लोककथाओं को कलमबद्ध किया, लेकिन यह वाचिक परंपरा को लिपिबद्ध करने तक की सीमित नहीं रहा. उन्होंने लोकरंग में मौजूदा समय और समाज तथा मनुष्य की चिंताओं मिलाकर ऐसा कैनवस रचा, जो अभूतपूर्व साबित हुआ. उन्होंने जो लोक चित्र रचा वह व्यापक सामाजिक संदर्भों से ओतप्रोत रहा. वे अपनी कहानियों के ज़रिये जीवन भर सामाजिक रूढ़ियों और सामंतवादी ताक़तों का विरोध करते हुए आम आदमी पक्ष में खड़े रहे. मानवीय गरिमा, आधुनिकता और प्रगतिशीलता की चेतना को उन्होंने सर्वोपरि मानकर रचनाएं कीं. राजस्थानी में चौदह खंडों में प्रकाशित बातां री फुलवारी पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला. उनका कहना था कि राजस्थान में क़दम–क़दम पर कथाएं बिखरी पड़ी हैं. मैंने जो कुछ लिखा है, वह सागर में बूंद जैसा है.

गांधी की हत्या के दो महीने बीतते ही हरिवंशराय बच्चन, सुमित्रानंदन पंत और नरेंद्र शर्मा ने गांधी के बारे में किताबें लिखीं. इनकी आलोचना में विजयदान देथा ने एक क़िताब लिखी– बापू के तीन हत्यारे. इस क़िताब ने काफ़ी हलचल मचाई. इसमें देथा का कहना था कि नाथूराम गोडसे ने गांधी के शरीर को मारा, लेकिन इन तीनों लेखकों ने गांधी की आत्मा को मारा.

बिज्जी अपने ढंग के अकेले ऐसे रचनाकार थे जिन्होंने लोक में प्रचलित साहित्य और आधुनिक साहित्य के बीच एक बहुत ही मज़बूत कड़ी स्थापित की. उनके जाने से राजस्थानी साहित्य के साथ–साथ पूरे भारतीय साहित्य जगत का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा ख़ाली हो गया. हालांकि, वे भारतीय मानस में लोककला को पहचान देने वाले एक समर्थ रचनाकार के रूप में जीवित रहेंगे. उनको नमन! ■

feedback@chauthiduniya.com

नोकिया का नया बजट फोन आशा 503

- हैंडसेट- (जीएसएम) थ्री जी सपोर्ट
- कैमरा-5 एमपी
- सिम-(2जी, 3जी)ड्यूल
- फ्लैश-लेड फ्लैश
- रैम-128-512
- डिस्प्ले-3 इंच

नोकिया अब अपना नया हैंडसेट आशा 503 लेकर आ रहा है. नोकिया ने इससे पहले अपना आशा सिरीज के फोन आशा 501 को मार्केट में काफी पसंद किया गया था. सूचना के अनुसार नोकिया इस हैंडसेट को साल के अंत तक लांच कर देगा. बड़े कैमरे के साथ यह हैंडसेट कई रंगों में उपलब्ध होगा और इसमें एलईडी फ्लैश भी लगा है.

मीडिया में लीक हुई खबरों के अनुसार इसमें पावर बटन, वाल्यूडम रॉकर बटन, ऑडियो जैक पोर्ट और माइक्रो-यूएसबी पोर्ट दिया गया है. इस फोन में लाइन इंसटैंट मैसेजिंग ऐप्लिकेशन प्रीलोडेड है. यह हैंडसेट पोलीकार्बोनेट और ग्लौस डिजाइन में होगा, इस हैंडसेट का डिस्प्ले तकरीबन 3.2 से 3.4 इंच के बीच है. इस हैंडसेट में 1-1.5 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर लगा हुआ है. जैसी की संभावना है इसकी जीपीयू और रैम की क्षमता 128 से 512 एमबी के बीच रह सकती है. यह हैंडसेट 3 जी सपोर्ट करेगा और यह ड्यूल सिम फोन होगा.■

पल्सर का नया अवतार

बजाज की इस टेक्नोलॉजी ने रफ्तार की दुनिया को नई पहचान दी है. अभी कंपनी ने इसकी कीमत के बारे कोई राय नहीं दिया है. इसमें 4 स्ट्रोकवाला 200सीसी इंजन लगा हुआ है और इसका इंजन 4 वॉल्ब वाला लिक्विड कूल इंजन है.

बजाज की नई मॉडल बजाज पल्सर भारतीय सड़को पर जल्द ही तहलका मचाएगी. कंपनी पल्सर 200एसएस को बाजार में उतारने की पूरी तैयारी कर ली है. बजाज की पल्सर सीरीज की सभी बाईकों ने ग्राहको का भरोसा जीता है. कंपनी ने ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए दिसंबर के अंत तक पल्सर 200एसएस को लांच करेगी. इस बाईक में भी डीटीएसआई (डिजिटल ट्विन स्पार्क इग्निशन) इंजन लगा हुआ है. बजाज की इस टेक्नोलॉजी ने रफ्तार की दुनिया को नई पहचान दी है. अबी कंपनी ने इसकी कीमत के बारे कोई राय नहीं दिया है. इसमें 4 स्ट्रोकवाला 200सीसी इंजन लगा हुआ है और इसका इंजन 4 वॉल्ब वाला लिक्विड कूल इंजन है. इस नई बजाज पल्सर की माईलेज 53किमी/प्र.ली तक है और इसकी अधिकतम रफ्तार 135 किमी/प्रतिघं से ज्यादा है. पल्सर 200एसएस की टार्क क्षमता 18.3 एनएम-8000 आरपीएम तक है. इसमें 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और यह बाइक सेल्फ स्टार्ट है. ईंधन टैंक की कुल क्षमता 12 लीटर तक है. इसमें सुरक्षा के लिहाज से स्टैंड अलार्म भी लगा हुआ है.■

मुंबई में स्थित कस्टम बाईक बनाने वाली वेर्देची नामक एक फर्म है जो मोटो मोरिनी के साथ मिलकर इस इटली की बाइक को भारत में बेचेगी. अभी कंपनी ने यह नहीं बताया है कि अपने कौन से मॉडल को भारत में लॉन्च करेगी.

गुपचुप शुरू आईपैड मिनी की बिक्री

एप्पल अपने किसी भी उत्पाद की बिक्री शुरू करने से पहले उसकी लॉन्चिंग करता है, लेकिन कंपनी ने इस बार सिर्फ एक प्रेस रिलीज जारी करके ही आईपैड मिनी की बिक्री शुरू कर दी है.

- स्क्रीन- 7.9 इंच
- रिजॉल्यूशन- 2048 x 1536 पिक्सल्स
- प्रति इंच पिक्सल- 326
- कैमरा- 5 एमपी रियर फेसिंग

एप्पल ने अपने मिनी आई पैड की बिक्री बिना किसी प्रचार के शुरू कर दी है. एप्पल ने पहली बार अपने किसी उत्पाद की बिक्री चुपचाप शुरू की है. एप्पल अपने किसी भी उत्पाद की बिक्री शुरू करने से पहले उसकी लॉन्चिंग करता है, लेकिन कंपनी ने इस बार सिर्फ एक प्रेस रिलीज जारी करके ही आईपैड मिनी की बिक्री शुरू कर दी है. मीडिया में ऐसी खबरें आ रहीं है कि एप्पल के पास अभी पर्याप्त संख्या में आईपैड मिनी उपलब्ध नहीं है, इसी कारण कंपनी ने इसकी लॉन्चिंग के बजाए सिर्फ प्रेस रिलीज जारी करके इसकी बिक्री शुरू कर दी है. आईपैड मिनी की सबसे बड़ी खासियत है इसका डिस्प्ले रिजॉल्यूशन बहुत अच्छा है. एप्पल ने इसे रेटिना डिस्प्ले का नाम दिया है. इसमें वायरलेस और एलटीई सेलुलर कनेक्टिविटी भी मौजूद है, साथ ही इसमें एक पॉवर एफिशिएंट चिप ए-7 लगा हुआ है.

मिनी आईपैड सिल्वर और ग्रे रंगों में उपलब्ध है. 16 जीबी के आईपैड की कीमत 25 हजार रुपये रखी गई है और सेलुलर कैपबल मॉडल की कीमत 52 हजार रुपये से शुरू होगी. यह दुनिया के सभी प्रमुख शहरों में उपलब्ध है.■

भारतीय सड़कों पर दौड़ेगी विदेशी बाइक

बाइक के शौकीन लोगों के लिए अच्छी खबर है कि विदेशी बाइक कंपनी मोटो मोरिनी अब भारत में भी बाइक बेचने के तैयारी कर ली है. ये इटली की मोटर बाईक कंपनी है, लेकिन इस बाइक के बारे में कम ही लोग जानते हैं. मुंबई में स्थित कस्टम बाइक बनाने वाली वेर्देची नामक एक फर्म है जो मोटो मोरिनी के साथ मिलकर इस इटली के बाईक को भारत में बेचेगी. अभी कंपनी ने यह नहीं बताया है कि अपने कौन से मॉडल को भारत में लॉन्च करेगी. भारत में मिलने वाली कस्टम बाइक में मोरिनी के इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि अन्य पार्ट्स वेर्देची के इस्तेमाल होंगे. मोटो मोरिनी कंपनी की स्थापना 1937 में अल्फांसो मोरिनी द्वारा की गई थी. इस कंपनी के बाइक्स ने ग्रैंड पिक्स ऑफ नेशंस में 6 रिकार्ड बनाए थे. मोटो मोरिनी कंपनी की अभी तीन बाइक्स कोर्सारो, गेनपासो 1200 और स्क्रेंबलर 1200 प्रोडक्शन में हैं, जिनको कंपनी भारतीय बाजार में उतार सकती है. इस मॉडल की कीमत 16 लाख रुपये से शुरू हो सकती है. ■

सस्ते दाम में मोटोरोला मोटो जी स्मार्टफोन लॉन्च

- कैमरा-फ्लैश के साथ 5 मेगापिक्सल्स
- फ्रंट कैमर-1.3 मेगापिक्सल्स कैमरा
- बैटरी-2070 एमएएच
- डिस्प्ले-4.5 इंच
- कनेक्टिविटी ऑप्शंस में वाई-फाई, ब्लूटूथ, 3 जी जीपीएस/ए-जीपीएस और ग्लोनास शामिल हैं.

मोटोरोला ने अपना मोटो जी स्मार्टफोन लांच कर दिया है. गूगल की सबसिडियरी कंपनी मोटोरोला अब इस स्मार्टफोन को भारत में भी लाएगी. 8 जीबी स्टोरेज वाले मोटोरोला मोटो जी की कीमत लगभग 11,300 रुपये है और 16 जीबी स्टोरेज वाले मोटोरोला मोटो जी की कीमत लगभग 12,600 रुपए है. यह फोन जी एंड्रायड 4.3 पर चलता है. इसका डिस्प्ले 1280X720 पिक्सल्स रिजॉल्यूशन और 329 पीपीआई(पिक्सल/इंच) वाला 4.5 इंच का है. कार्निंग गरिला ग्लास 3 में एज-टु-एज टेक्नॉलजी से टच एक्स्पीरियंस बेहतर मिलता है. मोटोरोला मोटो जी में 1.2 गीगाहर्ट्ज क्वाड-कोर क्वॅालकॉम स्नैपड्रैगन(कोर्टेक्स ए-7) प्रोसेसर, एड्रिनो 305 जीपीयू(ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट) और 1जीबी रैम है. इसमें पीछे की तरफ एलईडी फ्लैश के साथ 5 मेगापिक्सल्स और आगे की तरफ 1.3 मेगापिक्सल्स का कैमरा है. इसका मेन कैमरा एचडी(720पी) विडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है. मोटोरोला मोटो जी में बाहर और भीतर वॉटर-रेजिस्टेंट नैनो-कोटिंग की गई है. इसमें 2070 एमएएच बैटरी है. इसमें एफएम रेडियो के साथ 65 जीबी गूगल ड्राइव स्टोरेज की सुविधा है. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो feedback@chauthiduniya.com

1 लीटर में 30 का माइलेज देगी.

पेट्रोल के बढ़ते दाम के कारण भारत के सभी कार निर्माताओं की नजरें डीजल कारों के उत्पाद पर टीकी हैं. इसी कारण खरीदारों को ध्यान में रखते हुए मारुति सुजुकी पहली बार 800सीसी की क्षमता वाली डीजल कार लांच करेगी. मारुति सुजुकी की 800 सीसी पेट्रोल इंजन की कारों का ग्राहकों में खूब जादू चला है. भारत में मारुति 800 पेट्रोल ने अपनी बिक्री से रिकार्ड कायम किया था. इस सस्ती कार की किफायती माइलेज और आरामदायक इंटीरियर ने लोगों का दिल जीत लिया था.

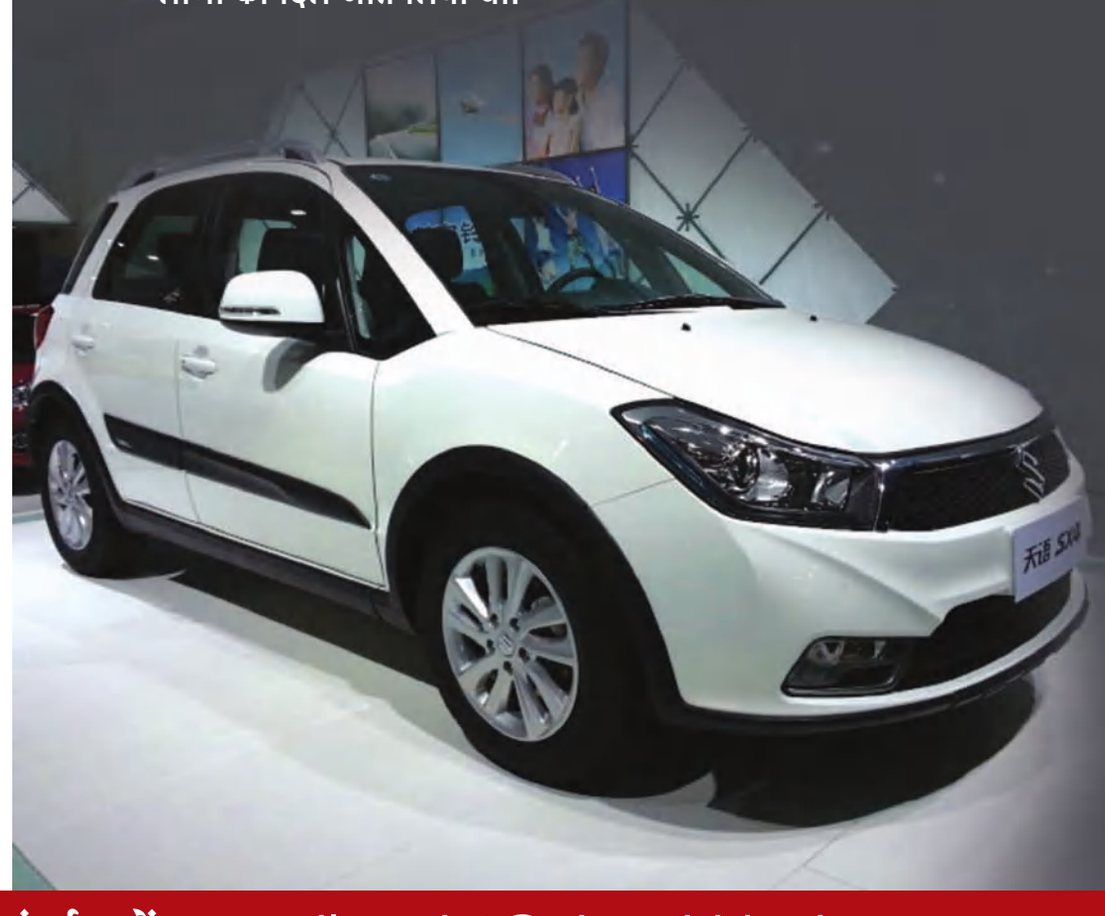

कार के लिए मशहूर मारुति सुजुकी एक सस्ती और छोटी डीजल कार मार्केट में लांच करेगी. भारत में पहली बार 800 सीसी की डीजल इंजन कार नजर आएगी. इस कार को आम आदमी के लिहाज से बनाया जा रहा है.

जहां पेट्रोल के बढ़ते दाम के कारण भारत के सभी कार निर्माताओं की नजरें डीजल कारों के उत्पाद पर टिकी हैं. इसी कारण खरीदारों को ध्यान में रखते हुए मारुति सुजुकी पहली बार 800सीसी की क्षमता वाली डीजल कार लांच करेगी. मारुति सुजुकी की 800 सीसी पेट्रोल इंजन की कारों का ग्राहकों पर खूब जादू चला . भारत में मारुति 800 पेट्रोल ने अपनी बिक्री से रिकार्ड कायम किया था. इस सस्ती कार की किफायती माइलेज और आरामदायक इंटीरियर ने लोगों का दिल जीत लिया था. इस 800 पट्रोल इंजन को मारुति ने ऑल्टो में भी इस्तेमाल किया. मारुति का इस इंजन को बनाने का मकसद बेहतर ईंधन क्षमता देना है. मारुति 800 डीजल की ईंधन क्षमता 30 किमी प्रतिघंटा होगी. मारुति सुजुकी की नई वाईएल7 अपनी पुरानी वर्जन ए-स्टार और जेन एस्टिलो की अगली पीढ़ी के रूप में दिखेगी. इसके साथ ही एसएक्स4 की भी नई अपडेटेड मॉडल अगले साल लॉन्च की सकती है■.

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

लारा का खेल तकनीकी रूप से इतना सुदृढ़ था कि सचिन भी उनके सामने उन्नीस दिखाई पड़ते थे. उनका एक कवर ड्राइव टिकट के पूरे पैसे वसूल करा देता था. लारा लंबी पारी खेलने में माहिर थे. 1994 में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 375 रनों की मैराथन पारी खेली और विश्व कीर्तिमान अपने नाम कर लिया

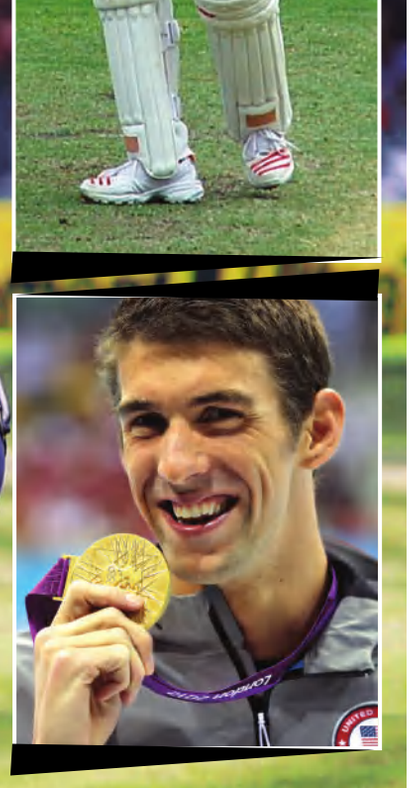

खेलों का ध्रुवतारा

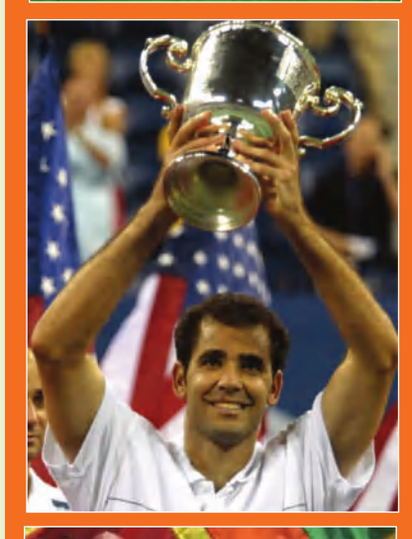

नवीन चौहान

सचिन तेंदुलकर क्रिकेट की दुनिया के हैली धूमकेतु हैं. जिस तरह हैली धूमकेतु को व्यक्ति अपने जीवनकाल में एक या दो बार देख पाता है उसी तरह सचिन जैसे महान खिलाड़ी को खेलता व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में एक या दो बार देख पाता है. ये इस पीढ़ी की खुशनसीबी है कि उन्होंने सचिन जैसे बल्लेबाज को साक्षात खेलते देखा और उनके खेल का लुत्फ उठाया. यह ठीक उसी तरह है जिस डॉन ब्रैडमेन को बल्लेबाजी करता देखने वाले बड़े गर्व के साथ कहते हैं मैंने डॉन बैडमैन को खेलते देखा है. सचिन का उदय भारत में खेलों के लिए बदलाव वाला था. सचिन के पदार्पण के बाद विभिन्न खेलों के महानतम खिलाड़ी आए अपना जौहर दिखाया और चले गए. उसके बाद नए खिलाड़ी आए और उनके रिकॉर्ड को तोड़कर नई इबारत लिख दी. लेकिन सचिन अपनी जगह डटे रहे. चार दशकों की आगोश में फैले उनके क्रिकेट करियर में जीवन का हर रंग दिखाई दिया. 1999 के विश्वकप के दौरान पिता की मृत्यु का शोक भूलकर देश के लिए विश्वकप में खेलना यह बताता है कि उनके लिए क्रिकेट के क्या मायने हैं. उनकी रग-रग में क्रिकेट बसता है, चमचमाते सितारों के बीच सचिन ने अपनी जगह बनाई और दुनियाभर में अपनी चमक बिखेरी. कई जगह तो लोगों ने सचिन को पहले जाना और क्रिकेट को बाद में. एक कप्तान के रूप में वे सफल नहीं हो सके शायद यही उनके इंसान होने का एहसास दिलाता है.

आइए विभिन्न खेलों के कुछ ऐसे खिलाड़ियों पर नज़र डालते हैं जो सचिन के बाद खेलों की दुनिया में आए, अपनी चमक बिखेरी और ओझल हो गए. सचिन ध्रुव तारे की तरह लगातार चमकते रहे और भारतीय क्रिकेट को एक नई दिशा देते रहे.

पीट सेंप्रास: सर्वकालिक महानतम टेनिस खिलाड़ियों में शुमार अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी पीट सेंप्रास ने अपने करियर में 14 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते. उनका अंतरराष्ट्रीय टेनिस करियर 1988 में शुरू हो गया था लेकिन उन्होंने अपना पहला ग्रैंडस्लैम खिताब 1990 में अमेरिकी ओपन के रूप में जीता था. सचिन तब तक दो टेस्ट शतक लगा चुके थे. सचिन और सेंप्रास ने एक साथ अपने खेल की ऊंचाइयों को छुआ. 1997 तक वह 9 ग्रैंड स्लैम खिताब जीत चुके थे. 1993 से 1998 तक लगातार छह साल वो विश्व के नंबर एक खिलाड़ी रहे. जो कि ओपन इरा में अब तक एक रिकॉर्ड है. उन्होंने ग्रैंडस्लैम में 84 प्रतिशत मैच जीते और ग्यारह साल तक कम से कम एक ग्रैंड स्लैम फाइनल में पहुंचने में कामयाब हुए. तब तक सचिन भी अपने खेल से पूरी दुनिया का दिल जीत चुके थे. 1996 विश्व कप में उनके खेल के दम पर भारत सेमीफाइनल तक आ गया था. 1997 में क्रिकेट की बाइबिल कही जाने वाली विजडन पत्रिका ने उन्हें साल के पांच सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में जगह दी और उन्हें विवियन रिचर्ड्स के बाद एक दिवसीय क्रिकेट का दूसरा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बताया.

माइकल शूमाकर: रफ़्तार के बादशाह कहे जाने वाले जर्मन फार्मूला वन चालक माइकल शूमाकर ने पहली बार 1991 में फार्मूला वन रेस में भाग लिया. जब शूमाकर ने पहली रेस में भाग लिया था उससे कुछ महीने पहले एक ऑस्ट्रेलियाई पत्रिका ने सचिन की फोटो अपने कवर पेज पर छापी और उन्हें ज्वेल ऑफ इंडियन क्राउन कहा था. शूमाकर ने अपने करियर की पहली रेस 1992 में जीती और 1994 में पहली बार विश्वचैंपियन बने. शूमाकर वर्ष 2000 से 2005 तक लगातार पांच बार और करियर में कुल सात बार विश्वचैंपियन के ताज पर कब्जा किया. शूमाकर ने करियर में कुल 91 रेसें जीतीं. जिसमें से 72 रेस फरारी के लिए जीतीं. शूमाकर, फेरारी की जोड़ी फार्मूला वन में जीत का पर्याय बन गई थी. शूमाकर ने 2006 में फार्मूला वन को अलविदा कह दिया. लेकिन एक बार फिर उन्होंने 2010 में वापसी की. 2010 से 2012 तक तीन सीजन में वह एक भी जीत नहीं दर्ज कर सके. सचिन के बाद शुरूआत करने वाले शूमाकर दूसरी बार फार्मूला वन को अलविदा कह चुके हैं. लेकिन सचिन ने 200 वां टेस्ट खेलकर 24 साल लंबे अपने करियर को अलविदा कह दिया.

शेन वॉर्न: 1992 के ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान सचिन तेंदुलकर ने जिस मैच में 148 रनों की शतकीय पारी खेली थी, वह मैच शेन वार्न के करियर का पहला टेस्ट मैच था. उस मैच में शेन वार्न को 150 रन खर्च करके केवल एक विकेट मिल सका. सीरीज के अगले मैच में वार्न को बाहर बैठना पड़ा. लेकिन उन्होंने जब दोबारा वापसी की उसके बाद फिर मुड़ कर नहीं देखा. सचिन और वार्न की जंग कई सालों तक सुर्खियां बनी, सचिन हमेशा वार्न की गेंदबाजी के आगे बीस साबित हुए. वार्न टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट और 700 विकेट के पड़ाव को पार करने वाले पहले क्रिकेटर बने. दो साल तक सर्वाधिक टेस्ट विकेट लेने का रिकॉर्ड वार्न के नाम रहा. वार्न ने अपने टेस्ट करियर में कुल 708 विकेट लिए. आज भी वह दुनिया के दूसरे सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. उनके नाम एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक 96 विकेट लेने का रिकॉर्ड भी दर्ज है. उन्होंने यह कारनामा 2005 में किया था. सचिन शेनवार्न के साथ 1998 में सर डॉन ब्रैडमैन से उनके घर मुलाकात के लिए पहुंचे थे. सचिन और वार्न दोनों को विजडन ने अपने 150 वर्ष पूरे होने पर अपनी ड्रीम टीम में भी जगह दी है. वार्न ने 2007 में क्रिकेट को अलविदा कह दिया. वार्न ने अपने करियर में भारत के खिलाफ 14 टेस्ट मैच खेले, इस दौरान उन्हें केवल एक ही बार पारी में पांच विकेट मिले, वह भी उस टेस्ट मैच में जिसमें सचिन नहीं खेल रहे थे.

ब्रायन लारा: सचिन के समकालिक और सर्वकालिक महान बल्लेबाज ब्रायन चार्ल्स लारा ने अपना क्रिकेट करियर 1990 में पाकिस्तान के खिलाफ शुरू किया था. 1993 में अपने करियर के पांचवें टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 277 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर लारा ने धूम मचा दी थी. सचिन तब तक सचिन भी टेस्ट मैंचों में 6 शतक लगा चुके थे. एक आक्रामक क्रिकेटर के रूप में वे अपनी पहचान बना रहे थे. लारा का खेल तकनीकी रूप से इतना सुदृढ़ था कि सचिन भी उनके सामने उन्नीस दिखाई पड़ते थे. उनका एक कवर ड्राइव टिकट के पूरे पैसे वसूल करा देता था. लारा लंबी पारी खेलने में माहिर थे. 1994 में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 375 रनों की मैराथन पारी खेली और विश्व कीर्तिमान अपने नाम कर लिया. सचिन लगातार बेहतरीन क्रिकेट खेलते रहे, लेकिन उन्हें अपने करियर के पहले दोहरे शतक के लिए दस साल लंबा इंतजार करना पड़ा. तब तक लारा एक तिहरा और दो दोहरे शतक लगा चुके थे. सचिन की तरह लारा भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन करते थे. लारा के 375 रनों के रिकॉर्ड को मैथ्यू हैडेन ने 2004 में जिंबाब्वे के खिलाफ 385 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर तोड़ दिया. उस रिकॉर्ड को लारा ने टेस्ट इतिहास का पहला चौहरा शतक लगाकर फिर से अपने नाम कर लिया. प्रथम श्रेणी क्रिकेट का सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड भी लारा के नाम दर्ज है उन्होंने 501 रनों की नाबाद पारी काउंटी क्रिकेट में डरहम के खेलते हुए बनाया था. लारा के संन्यास लेने के बाद ही सचिन सर्वाधिक टेस्ट रन बनाने के उनके रिकॉर्ड को तोड़कर टेस्ट क्रिकेट में रनों के सिरमौर बने थे.

मुथैया मुरलीधरन: दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ऑफ स्पिनर मुथैया मुरलीधरन और विवादों का साथ बहुत गहरा था. मुरली ने अपने टेस्ट करियर का आगाज 1992 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया था. मुरली ने अपने टेस्ट करियर में 133 टेस्ट खेले और 22.72 की औसत से 800 विकेट लिए. उन्होंने टेस्ट मैचों में 67 बार पारी में पांच या उससे ज्यादा विकेट हासिल किए. भारत के खिलाफ उन्होंने 22 टेस्ट खेले और 105 विकेट हासिल किए. 1996 में विश्वकप जीतने वाली श्रीलंकाई टीम का हिस्सा रहे मुरली तब तक टेस्ट मैचों में केवल छह बार पांच विकेट हासिल कर सके थे. मुरली ने 1997 में 100 टेस्ट विकटों का पड़ाव पार किया था. तब तक सचिन एक स्टार बन गए थे और अपने करियर के चरम पर पहुंच रहे थे. तब तक सचिन टेस्ट में 11 और वनडे में 12 शतक बना चुके थे. इसके बाद मुरली ने अपनी कलाई का ऐसी जादू दिखाया कि आज उनके नाम टेस्ट(800) और एकदिवसीय मैचों(534) में सर्वाधिक विकट लेने का रिकॉर्ड दर्ज है. सचिन के खिलाफ मुरली भी शेनवार्न की तरह बेहतरीन प्रदर्शन नहीं कर सके. सचिन को बॉलिंग करना उनके लिए भी हमेशा एक चुनौती रहा.

जिनेदिन जिदान: फुटबॉल के बेहतरीन खिलाड़ियों में शुमार फ्रांस के जिनेदिन जिदान ने अपने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल करियर का आगाज 1994 में चेक गणराज्य के खिलाफ किया था. यह एक दोस्ताना मैच था इसमें जिदान को सब्स्टीट्यूट खिलाड़ी के रूप में खेलने का मौका मिला था. इस समय तक सचिन को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलते हुए पांच साल बीत चुके थे और वे टेस्ट क्रिकेट में 1998 में जिदान ने पहली बार फीफा विश्वकप में भाग लिया. जिदान ने ब्राजील के खिलाफ खेले गए फाइनल मुक़ाबले में दो महत्वपूर्ण गोल कर फ्रांस को विश्वविजेता बना दिया और रातों रात स्टार बन गए. इसके बाद जिदान ने वर्ष 2000 में फ्रांस को यूरो कप विजेता बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की. उन्हें प्रतियोगिता के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया. इसके बाद 2002 के विश्वकप के पहले दौर में सेनगल जैसी टीम ने डिफेंडिग टीम को विश्वकप से बाहर का रास्ता दिखा दिया. 2006 के विश्वकप से पहले जिदान ने सन्यास ले लिया. 2006 के विश्वकप में जगह पाने के लिए संधर्ष कर रही फ्रांसीसी टीम के तात्कालिक कोच ने जिदान को वापसी करने का आग्रह किया. जिदान ने वापसी की और कप्तान के रूप में टीम की कमान संभाली. इसके बाद फ्रांस की टीम ने मुड़कर नहीं देखा. इटली के खिलाफ बराबरी पर रहे फाइनल मुक़ाबले में पेनल्टी शूट आउट के पहले डिफेंडर मारको मातेराज़ी के सीने पर सिर से वार(हेड बट) करने के कारण बाहर कर दिया गया. पेनल्टी शूट आउट के बाद इटली विश्व कप विजेता बना. इसके बाद जिदान ने फुटबॉल को अलविदा कह दिया.

माइकल फेल्प्स: तैराकी के अमेरिकी गोल्डन बॉय माइकल फेलप्स ने पहली बार ओलंपिक में 2004 में भाग लिया था. तब तक सचिन के नाम टेस्ट में 34 और एक दिवसीय में 37 शतक दर्ज थे. एथेंस में हुए इस ओलंपिक में छह स्वर्ण और दो कांस्य सहित कुल आठ पदक जीते थे. इसके बाद 2008 में बीजिंग ओलंपिक में फेल्पस ने अपना बेहतरीन प्रदर्शन जारी रखा और ओलंपिक इतिहास में एक ही ओलंपिक में आट स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड बनाया. 2008 में सचिन सर्वाधिक टेस्ट रन बनाने के रिकॉर्ड के बेहद करीब पहुंच गए थे. 2007-08 सीजन में 24 साल बाद ऑस्ट्रेलियाई धरती पर भारत को एकदिवसीय चैंपियन बनाने में मुख्य भूमिका निभाई थी. 2012 में लंदन ओलंपिक में चार स्वर्ण और दो रजत पदक जीतने में सफलता हासिल की. उन्होंने लंदन ओलंपिक के बाद ओलंपिक में 18 स्वर्ण और कुल 22 पदक जीतने के बाद तैराकी को अलविदा कह दिया. तब सचिन 100 अंतरराष्ट्रीय शतक बना चुके थे. सचिन ने दिसंबर 2012 में वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी. ■

डॉन ब्रैडमेन को बल्लेबाजी करता देखने वाले बड़े गर्व के साथ कहते हैं मैंने डॉन बैडमैन को खेलते देखा है. सचिन का उदय भारत में खेलों के लिए बदलाव वाला था. सचिन के पदार्पण के बाद विभिन्न खेलों के महानतम खिलाड़ी आए अपना जौहर दिखाया और चले गए. उसके बाद नए खिलाड़ी आए और उनके रिकॉर्ड को तोड़कर नई इबारत लिख दी. लेकिन सचिन अपनी जगह डटे रहे. चार दशकों के आगोश में फैले उनके क्रिकेट करियर में जीवन का हर रंग दिखाई दिया.

navinchauhan@chauthiduniya.com

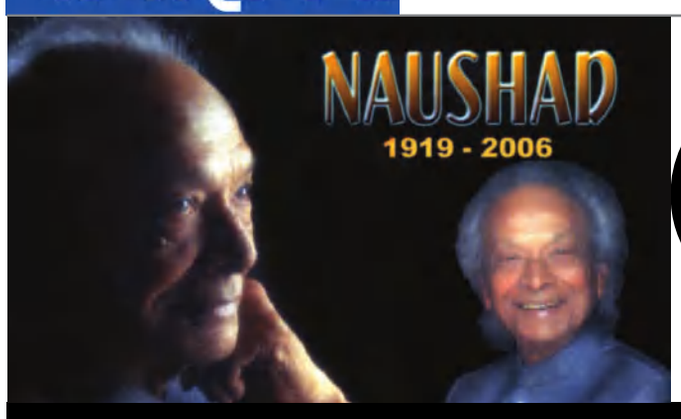

नौशाद ने मशहूर धारावाहिक द सोर्ड ऑफ टीपू सुल्तान का संगीत दिया. नौशाद की आखिरी फिल्म 2006 में ताजमहल थी. नौशाद ने फिल्म मेकिंग में भी किस्मत आजमाई और कामयाब भी हुए. बतौर निर्माता उन्होंने 1950 में फिल्म बाबुल का निर्माण किया. फिल्म में दिलीप कुमार, मुनव्वर सुल्तान और नर्गिस मुख्य भूमिका में थे.

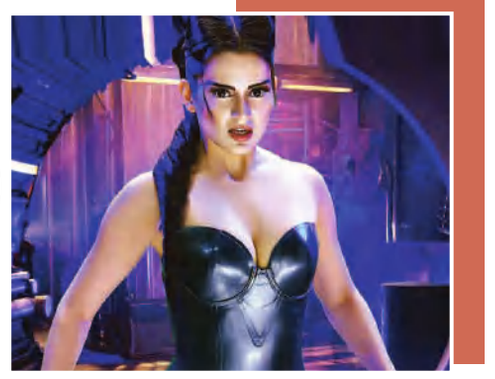

नौशाद की याद में

सिफ़र से शिखर तक का सफर तय करने में इंसान की पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन जब हुनर और किस्मत का साथ हो तो वह एक जिंदगी में कई जिंदगी जी लेता है और दुनिया के लिए खूबसूरत मिसाल साबित होता है. हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के प्रख्यात संगीतकार नौशाद अली की.

एम एच पाशा

नौशाद का जन्म 25 दिसंबर, 1919 को तहज़ीब और नज़ाकत के शहर लखनऊ में हुआ. बचपन से ही उनका मन संगीत में बसता था. नौ साल की उम्र में वे अमीनाबाद की संगीत यंत्र दुकान पर नौकरी करने लगे. वे रोज़ सुबह दुकान खुलते ही सभी संगीत वाद्ययंत्रों की अच्छी तरह सफाई करते और उन्हें जी भर कर छूते. दुकानदार रोजाना चाय पीने बाहर जाता. इस बीच मौका देखकर वे वाद्ययंत्रों पर हाथ आज़माते. एक दिन मालिक समय से पहले आ धमका और नौशाद हारमोनियम बजाते पकड़े गए. नौशाद डर गए. उन्हें ठंड में भी पसीना आ रहा था, क्योंकि मालिक बहुत ही गुस्सैल था, पर मालिक यह देख कर बहुत ही खुश हुआ. उसने कहा तुम काफी अच्छा बजाते हो, तुमने बताया नहीं. उसने खुश होकर वह हारमोनियम नौशाद को दे दिया और कहा कि रोज़ाना रियाज़ किया करो. बालक नौशाद की खुशी का ठिकाना न रहा. नौशाद ने उस्ताद उमर अंसारी से संगीत की शिक्षा शुरू कर दी, इस बात से उनके पिता बेहद नाराज थे. एक दिन उनके पिता ने साफ शब्दों मे कह दिया कि अगर संगीत सीखना है तो घर छोड़ दो और अगर घर में रहना है तो संगीत छोड़ दो. नौशाद ने अपने पिता से कह दिया कि घर आपको मुबारक हो. और मन में ठान लिया कि घर छोड़ना मंजूर है, पर संगीत नहीं. उन पर कई पाबंदियां लगीं, कई बार रात को घर के दरवाजे बंद कर दिए जाते थे तो उनकी दादी चुपके से उन्हें घर में आने देतीं. इसी बीच किसी तरह उन्होंने मैट्रिक पास किया और वे लखनऊ के विंडसर एंटरटेनर म्यूजिकल ग्रुप के साथ दिल्ली, मुरादाबाद, जयपुर, जोधपुर और सिरोही की यात्रा पर चले गए. कुछ ही दिनों बाद वह म्यूजिकल ग्रुप बिखर गया और वे बेराजगार हो गए. तब उनके एक दोस्त आदिल ने उनसे कहा कि मुंबई में नाचती, गाती, बोलती फिल्में शुरू हुई हैं. वहां जाओ, वहीं तुम्हारे इस फन को पहचान मिलेगी. उसी वक्त नौशाद ने फैसला कर लिया और मुंबई रवाना हो गए. 1935 में 16 साल की उम्र में वह मुंबई आ गए. 16 साल के नौशाद ने दादर के ब्रॉडवे सिनेमाघर के सामने की फुटपाथ को अपना आशियाना बनाया. उन्होंने सपना देखा कि एक दिन इस सिनेमाघर में मेरी फिल्म लगेगी. और लग गए अपने सपने को साकार करने में. सपना सच हुआ फिल्म बैजू बावरा से. जी हां उसी सिनेमा हॉल में रिलीज हुई यह फिल्म. तब नौशाद ने कहा कि यहां तक पहुंचने में मुझे सत्रह साल लग गए.

अपने स्ट्रगल के दिनों में एक दिन अख़बार में उन्होंने खबर पढ़ी कि न्यू पिक्चर्स के नाम से एक कंपनी शुरू हुई है. वहां संगीतकार की जरूरत है. वे फौरन इंटरव्यू के लिए पहुंचे. वहां उनकी मुलाक़ात उस्ताद झंडे ख़ां साहब से हुई जो उस समय नामी संगीतकार थे. उन्होंने पियानो बजवा कर नौशाद का ट्रायल लिया. नौशाद उसमें पास हो गए और उनको 40 रुपये माहवार की नौकरी पर रख लिया गया. यहां उन्हें बतौर सहायक संगीतकार काम किया. नौशाद ने अपना नाम बादल कर एनए दास यानी नौशाद अली दास रख लिया था. बाद में फिर उन्होंने अपना असली नाम रख लिया, और इसी नाम से पहचान बनाने का फैसला किया. नौशाद को ऑफर मिला फिल्म सुनहरी मकड़ी में हारमोनियम बजाने से, लेकिन फ़िल्म पूरी नहीं हुई. पर यहीं से नौशाद की किस्मत बदली. उनकी मुलाकात गीतकार दीनानाथ मधोक (डीएन) से हुई. उन्होंने नौशाद का परिचय इंडस्ट्री के दिग्गजों से कराया.

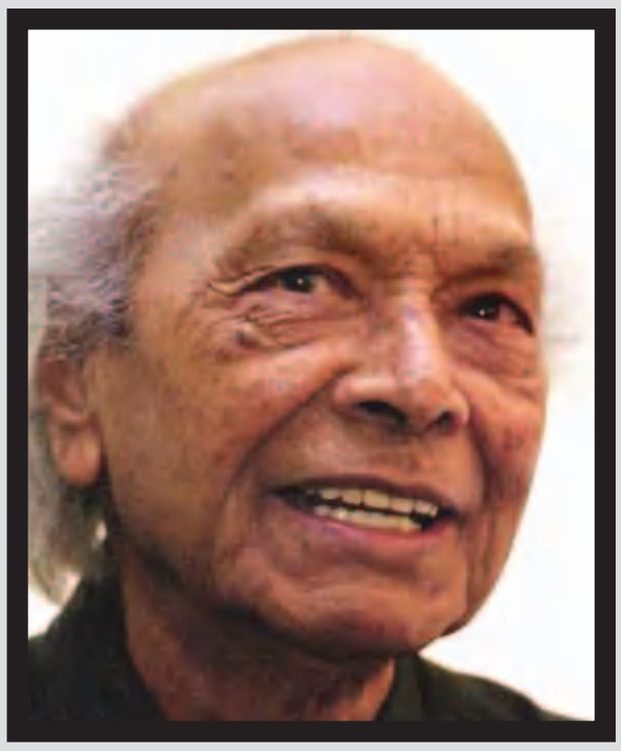

1940 में बतौर संगीतकार उनकी पहली फिल्म प्रेम नगर थी. दूसरी फिल्म स्टेशन मास्टर आई, यह फिल्म भी सफल रही. फिर नौशाद ने पीछे मुड़कर नहीं देखा. 64 साल तक वे एक के बाद एक उम्दा और लाजवाब संगीत देते रहे.

मुग़ल-ए-आज़म, बैजू बावरा, अनमोल घड़ी, शारदा, आन, संजोग, दीदार जैसी फिल्मों के गानों ने संगीत के मायने बदल दिए. बैजू बावरा के गानों मन तड़पत हरि दर्शन..., ओ दुनिया के रखवाले..., आदि ने उन्हें सर्वश्रेश्ठ संगीतकार का पहला फ़िल्मफेयर अवॉर्ड दिलाया. फिल्म दीदार के गीत बचपन के दिन भुला न देना, हुए हम जिनके लिए बर्बाद, ले जा मेरी दुआएं, ले जा परदेश जाने वाले गानों ने फ़िल्म को लंबे समय तक चलने का नया कीर्तिमान स्थापित करने में मदद की. प्यार किया तो डरना क्या...और फिल्म मुग़ल-ए-आज़म के गानों ने नौशाद को संगीत की बुलंदियों का शहंशाह बना दिया. उन्होंने सुरैया को 13 साल की उम्र में गाने का मौका दिया. अमीरबाई कर्नाटकी, निर्मलादेवी, उमा देवी आदि को प्रोत्साहित कर आगे लाने का श्रेय भी उन्हें जाता है. निर्मलादेवी से शारदा में, उमा देवी(टुनटुन) की आवाज का इस्तेमाल दर्द फिल्म में अफ़साना लिख रही हूं...के लिए किया. मुकेश की दर्दभरी आवाज को भी संगीत प्रेमियों तक लाने का श्रेय नौशाद को जाता है. नौशाद ने दिलीप कुमार के लिए मुकेश और राज कपूर के लिए मोहम्मद रफी की आवाज़ इस्तेमाल किया. उनके देशभक्ति के गानों ने लोगों के दिलों में देशप्रेम का जज़्बा भरा. उन्होंने फिल्म शाहजहां में हीरो की भूमिका कर रहे कुंदनलाल सहगल से भी गीत गवाए. माना जाता था कि सहगल बगैर शराब पिए नहीं गा सकते. नौशाद ने सहगल से बगैर शराब पिए गाने को कहा. तब सहगल ने कहा, बगैर पिए मैं नहीं गा सकता. नौशाद ने सहगल से शराब पी कर गाना गवाया. उसी गाने को बगैर शराब पीए भी उन्होंने गवाया. सहगल ने अपने गाए दोनों गाने सुन कर कहा कि काश तुम पहले मिले होते. शाहजहां के गीत जब दिल ही टूट गया..., और कितना नाजुक है दिल... कालजयी सिद्ध हुए.

उन्होंने ही मो. रफी को मौका दिया. दरअसल हुआ यह कि निर्देशक कारदार मियां के पास एक लड़का सिफारिशी पत्र लेकर आया. उन्होंने कहा कि फिलहाल तो कोई गुंजाइश नहीं है. पर मैं समूह (कोरस) में गवा सकता हूं. गीत के बोल थे, हिंदू हैं हम, हिंदुस्तां हमारा, हिंदू-मुस्लिम की आंखों का तारा. इसमें गायकों को लोहे के जूते पहनाए गए, क्योंकि गाते समय पैर पटकना था, जिससे जूतों की आवाज का इफेक्ट आ सके. गाने की समाप्ति पर लड़के ने जूते उतारे तो उसके पैरों में छाले पड़ चुके थे. यह देख नौशाद ने लड़के के कंधे पर हाथ रख कहा, जूते टाइट थे तो तुम्हें बता देना था. इस पर उस लड़के ने कहा, आपने मुझे काम दिया, यही मेरे लिए बड़ी बात है. तब नौशाद ने कहा कि तुम एक दिन महान गायक बनोगे और उनकी बात सच हुई.

नौशाद ने मशहूर धारावाहिक द सोर्ड ऑफ टीपू सुल्तान का संगीत दिया. टाइटल सॉन्ग को बहुत सराहा गया. नौशाद की आखिरी फिल्म 2006 में ताजमहल थी. फिल्म के निर्माता निर्देशक अकबर ख़ान थे. नौशाद ने फिल्मों मे भी किस्मत आजमाई और कामयाब भी हुए. उन्होंने बतौर निर्माता 1950 में फिल्म बाबुल का निर्माण किया. फिल्म में दिलीप कुमार, मुनव्वर सुल्तान और नर्गिस मुख्य भूमिका में थे. 1955 में उनकी फिल्म उड़न खटोला आई. मुख्य कलाकार निम्मी और दिलीप कुमार थे. 1958 में उन्होंने मालिक फिल्म का निर्माण किया, जिसके संगीतकर गुलाम मोहम्मद थे. नौशाद ने बतौर लेखक पालकी और तेरी पायल मेरे गीत जैसी फिल्में लिखी. उनकी ज़्यादातर फिल्मों ने सिल्वर और गोल्डेन जुबली मनाई. फिल्म मदर इंडिया भारत की पहली ऐसी फिल्म थी, जिसे ऑस्कर में नॉमिनेट किया गया था. 1982 में उन्हें दादा साहब फाल्के अवॉर्ड, 1984 में लता मंगेशकर, 1984 में अमीर खुसरो, 1992 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार, और 1992 मे भारत सरकार ने पद्म भूषण सम्मान दिया. अपने अंतिम दिनों में वे कहते थे कि आज भी मेरी संगीत की तालीम पूरी नहीं हुई है और न ही मैं अच्छा संगीत दे सका. 5 मई, 2006 को इस दुनिया से वे रुखसत हो गए. नौशाद को मुंबई के जुहू कब्रिस्तान में दफनाया गया. ■

feedback@chauthiduniya.com

कृष 3 ने किया शानदार कलेक्शन

राकेश रोशन की होम प्रोडक्शन फिल्म कृष 3 ने अब तक 255 करोड़ की कमाई कर ली है. इस फिल्म ने अब तक सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों, आमिर की थ्री इडियट्स और शाहरुख की चेन्नई एक्सप्रेस, को भी पीछे छोड़ दिया है. शुरुआती मात्र 4 दिनों में फिल्म ने देश-विदेश से जबर्दस्त कलेक्शन किया. 4 दिन में फिल्म में 100 करोड़ रुपये कमा लिए. कृष 3 की कामयाबी से खुद राकेश रोशन भी हैरान हैं. रिलीज के पहले ही दिन फिल्म ने 25.30 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. दिल्ली, यूपी, मुंबई, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा सहित ज्यादातर जगहों पर पहले दिन 60 से 97 फीसदी का कलेक्शन करके नया रिकॉर्ड बनाया. कृष 3 रिलीज करने वाले ज्यादातर सिंगल स्क्रीन थिएटरों का कलेक्शन 70 से 100 फीसदी तक रहा. वहीं, दिल्ली एनसीआर, यूपी के मल्टिप्लेक्सों की औसत ऑक्यूपेंसी 57 से 99 फीसदी रही. शुक्रवार को 25.30 करोड़, शनिवार को फिल्म ने 23.38 करोड़ और बॉक्स ऑफिस पर साल के सबसे कमजोर दिन माने जाने वाले दीवाली के दिन 24.57 करोड़ का कलेक्शन किया. ओवरसीज में भी पहले 3 दिनों में 16.98 करोड़ कमाए. इसी के साथ रिलीज हुई मिकी वायरस ने लगभग 7.09 करोड़ का कलेक्शन किया, तो वहीं वेक अप इंडिया ने 50 से 60 फीसदी का नेट कलेक्शन करके प्रोडक्शन कंपनी को राहत दी.

कृष 3 की कामयाबी की वजह

फिल्म की रिलीज से पहले ही इसके गाने और प्रोमो दर्शकों को खूब भा रहे थे. इस फिल्म में कंगना के शानदार लुक को भी खूब पसंद किया गया. ऋतिक रोशन भी इस फिल्म में काफी अच्छे लगे. फिल्म के प्रोमो और गाने रिलीज से पहले ही हिट होने के संकेत दे रहे थे. इसके अलावा, फिल्म की सफलता के कई और कारण भी रहे.

दरअसल कृष 3 रिलीज होने के पहले दो शुक्रवार को ऐसी फिल्में रिलीज हुई थीं, जो दर्शकों को आकर्षित नहीं कर पाईं. पिछले शुक्रवारों को रिलीज हुईं बॉस और मिक्की वायरस दोनों फिल्में दर्शकों को आकर्षित नहीं कर पाईं. दर्शक लंबे समय से एक ऐसी फिल्म के इंतजार में थे, जिसे पूरे परिवार के साथ देखा जा सके. उनकी इस उम्मीद पर कृष 3 खरी उतरी.

कृष 3 की रिलीज डेट ने भी फिल्म की सफलता में बड़ी भूमिका निभाई. कृष शुक्रवार को रिलीज हुई थी. शुक्रवार की शाम से ही लोग दीवाली मना रहे थे. शुक्रवार से लेकर रविवार तक लोगों ने फिल्म देखी. वहीं सोमवार और मंगलवार की छुट्टी होने का लाभ भी फिल्म को मिला.

तीसरी सबसे बड़ी वजह फिल्म का सुपरहीरो एंगल रहा है. भारत में बड़ी संख्या में ऐसे युवा दर्शक हैं, जिन्हें हॉलीवुड की सुपरहीरो फिल्में रास आती हैं. दस साल से कम उम्र वाले छोटे बच्चों की भी ऐसी बड़ी संख्या हैं. सुपरहीरो का दर्शकों में क्रेज का लाभ भी कृष 3 को मिला.

दीवाली के अगले दिन भी लोगों ने फिल्म देखी. इस दिन फिल्म ने एक दिन में सबसे ज्यादा कमाई करने का रिकॉर्ड बनाया. फिल्म ने करीब 36 करोड़ की कमाई की. इससे पहले यह रिकॉर्ड चेन्नई एक्सप्रेस के नाम था.

ऋतिक रोशन और सुपरहीरो की जुगलबंदी ने भी फिल्म को हिट करवाने में बड़ी भूमिका निभाई. दर्शकों ने हर बार ऋतिक रोशन को सुपरहीरो के रूप में पसंद किया है. फिल्म के हॉलीवुड इफेक्ट और मजबूत विलेन भी फिल्म की सफलता के कारण बने.■

बाबूभाई थीबा
मेहनत से मिला मुक़ाम

बॉलीवुड में आज इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर एसोसिएशन में टीवी के चेयरमैन, टाइटल कमेटी के चेयरमैन और डिस्प्यूट कमेटी के को-कॉन्विनर जैसे मुख्य पदों पर आसीन हैं बाबूभाई थीबा. फिल्म और टेलीविज़न प्रोड्यूसर बाबू भाई ने अपने कॅरियर की शुरुआत मशहूर फिल्म कलाकार विनोद खन्ना के सेक्रेट्री के रूप में की. फिल्म जगत के सबसे बड़े सम्मान दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित बाबू भाई थीबा आज किसी परिचय के मोहताज नहीं.

सेक्रेट्रीशिप आपका शौक है या पेशा ?

मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूं. शुरुआती दिनों में मैंने ऑल इंडिया रेडियो में नौकरी की. मैं फिल्मस्टार्स का इंटरव्यू करता था. तब उनसे सवाल करता कि आपको कितना पैसा मिलता है. उनका जवाब होता, लाखों रुपये. तब मुझे लगता था कि उनके आई क्यू लेवेल से मेरा आई क्यू लेवेल तो कहीं ज़्यादा है. जबकि मेरी सैलरी सिर्फ 8 हज़ार रुपये हैं. जब मेरे बाल सफ़ेद हो जाएंगे, तब मेरी सैलरी होगी 25 हज़ार रुपये. मुझे लगा कि ईमानदारी और मेहनत के साथ ज्यादा कमाई करनी है तो फिल्म इंडस्ट्री का रुख़ करना चाहिए.

आप कब मुंबई आए?

मैं वर्ष 1972 में मुंबई आया.

आपने शुरुआत कब की?

मैं जाने माने प्रोड्यूसर मनमोहन देसाई के पास गया और उनसे काम करने की इच्छा जताई. उन्होंने कहा कि यहां अलग तरह की योग्यता चाहिए और वो आपके पास नहीं हैं. बेहतर है आप वापस चले जाएं. मेरे लिए यह चैलेंज था. एक साल मेहनत करने के बाद मैं मनमोहन देसाई प्रोडक्शन में हेड ऑफ प्रोडक्शन था. यहां मेरी मुलाकात विनोद खन्ना से हुई. तब उनके सेक्रेटरी मुकेश बट्ट थे. मुकेश बीमार थे और उन्हें असिस्टेंट की ज़रूरत थी. उन्होंने मुझे ट्रायल पर रखा. मुकेश के अस्पताल से आने के बाद विनोद खन्ना ने उन्हें कहा कि यह लड़का अच्छा काम करता है. फिर उन्होंने मुझे कंटिन्यू किया. कुछ ही समय बाद बॉलीवुड में जिनके पास अच्छे सेक्रेटरी नहीं थे, उन्हें मेरा नाम सुझाया जाने लगा. फिर मुझे स्टार्स के फोन आने लगे. पहले मेरे पास तीन चार आर्टिस्ट थे. बाद में मेरे पास 15 ऐक्टर्स हो गए. मैं पहला सेक्रेटरी था, जिसने अपना ऑफिस खोला और बहुत सारे लोगों को स्टाफ रखा.

आपने बड़े स्टार्स के साथ काम किया. क्या आजकल ऐक्टर्स का दखल ज़्यादा बढ़ गए हैं ?

कोई भी इंडस्ट्री डिमांड और सप्लाई पर चलती है. बड़े स्टार, जिनके नाम से फिल्म बिकती है. उन्हें लगता है कि मेरे नाम से फिल्म बिकती है, तो क्यों न अपना प्राइज़ अपने स्टेटस के हिसाब से लूं. पहले के कलाकर अभिनय से दिल से जुड़े होते थे. आज के कलाकर अभिनय को सिर्फ पेशा समझते हैं.

आपने फिल्में भी प्रोड्यूस की हैं. कैसा अनुभव रहा?

मेरी सारी गुजराती फिल्में सिल्वर जुबली थीं. बढ़िया अनुभव था. पर फिल्म मेकिंग से मुझे खास फायदा नहीं हुआ. हालांकि मैंने लागत वसूल कर ली. यह समय मुनाफे के लिए अच्छा है. हम हॉलीवुड कि इकोनॉमी के करीब आ गए हैं. इंटरनेशनल फिल्म इंडस्ट्री के भी क़रीब हम पहुंच रहे हैं, यह अच्छी बात है.

आपका फेवरेट ऐक्टर कौन है?

आज के समय में मेरा फेवरेट एक्टर सलमान ख़ान हैं.

आपका फेवरेट डाइरेक्टर कौन है?

मेरे फेवरेट डाइरेक्टर हैं अब्बास मस्तान.

आपके फेवरेट प्रोड्यूसर कौन हैं ?

यश चोपड़ा थे, जिन्होंने बेहतरीन फिल्में दीं.

क्या आप सनी लियोनी के सेक्रेटरी बनेंगे ?

प्रिन्सिपली देखा जाए तो, मैं उनके साथ काम ना करूं, लेकिन प्रोफेशनली देखा जाए तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है.

बॉलीवुड के इंटरनेशनल बिज़नेस को कैसे देखते हैं?

सिनेमा के इंटरनेशनल बिज़नेस को आप फिल्मों और टेलीविजन के कलेक्शन को देखकर समझ सकते हैं. पहले 100 प्रतिशत में से 80 प्रतिशत कलेक्शन इंडिया से होती थी. 20 प्रतिशत ओवरसीज़ से होती थी. आज सिनेरियो यह हो गया है कि हमारी 50 प्रतिशत इनकम इंडिया से होती है और 50 प्रतिशत ओवरसीज से होती है.

आपकी सेवाओं के लिए फिल्मों के सबसे बड़े सम्मान दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है. क्या आप इसके हक़दार हैं ?

अगर भारत सरकार ने मुझे इसका हक़दार समझा है तो इस पर सवाल उठाने वाला मैं कौन हो सकता हूं.

इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर एसोसिएशन में आप टेलीविजन प्रोग्राम्स के चेयरमैन हैं. क्या आप इस जिम्मेदारी को निभा पाते हैं?

सच कहूं तो मैं पूरी तरह से इस जिम्मेदारी को नहीं निभा पा रहा, लेकिन

कोशिश रहती है कि जितना बन पड़े करूं.

इन दिनों किन तरह की परेशानियों का सामना टेलीविजन प्रोड्यूसर्स फ़ेस कर रहे हैं?

टेलीविजन प्रोड्यूसर्स की सबसे बड़ी समस्या है चैनल का बढ़ता दख़ल. चैनल बड़े से बड़े प्रोड्यूसर को आजादी नहीं देता कि वो अपना क्रिएटिव दिमाग लगा सकें. किसी भी तरह की क्रिएटीवीटी दिखा सकें. अपने हिसाब से आर्टिस्ट ला सकें , सेट्स लगा सकें, शूटिंग कर सकें. खुद टेक्निशियंस चुन सकें. अब प्रोड्यूसर सिर्फ एक्ज़ीक्यूटिव प्रोड्यूसर बन कर रह गया है. चैनल मालिक बस चैनल की नौकरी करते हैं.

इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर असोसिएशन की डिसप्यूट कमेटी के आप को-कॉन्विनर हैं. आप वहां किस तरह के डिसप्यूट फ़ेस करते हैं?

डिसप्यूट कमेटी में तरह तरह के केस आते हैं. फाइनेंसर और प्रोड्यूसर के डिसप्यूट, प्रोड्यूसर और टेक्नीशियन्स के बीच, प्रोड्यूसर और रायटर के बीच, प्रोड्यूसर और म्यूजिक डाइरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर्स के बीच. ज्यादातर इसमें पैसे और नाम का झगड़ा होता है. जज की कुर्सी पर बैठ कर हमें दोनों तरफ कि बात सुनकर इंसाफ करना पड़ता है.

क्या आप सेक्रेट्रीशिप को आर्टिस्ट मैनेजमेंट का नाम दे सकते हैं?

ये सभी भविष्य के स्टार्स हैं. इसलिए इन्हें मैं सेलेब्रीटी कहूंगा. इसे मैं मैनेजमेंट सेलेब्रेटी का नाम दूंगा. ■

साक्षात्कर्ता - एम एच पाशा, डीएमएल मुंबई

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

25 नवंबर-01 दिसंबर 2013

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467

बिहार-झारखंड

मोदी को रोकने की जद्दोज़हद

जदयू ने पहले चरण में 12 स्थानों पर संकल्प रैली करने का निर्णय किया है. इसकी शुरुआत मोतिहारी से सात दिसंबर से होगी और पटना साहिब में आकर 16 फरवरी को आखिरी संकल्प रैली होगी. कोशिश की गई है कि इन रैलियों में लगभग सभी जिलों की भागीदारी हो . मसलन लखीसराय की रैली में इस जिले के अलावा मुंगेर, जमुई, शेखपुरा और बाढ़ के कार्यकर्ता भी शामिल होंगे. इसी तरह दूसरी रैलियों में भी अन्य जिलों को समाहित कर दिया गया है. प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह कहते हैं कि संकल्प रैली में संबंधित जिलों के कार्यकर्ता, विधायक, सांसद और पदाधिकारी सभी शामिल होंगे.

सरोज सिंह

मुंह पर भले ही भाजपा को छोड़कर किसी दल का कोई नेता कुछ न कहे पर यह बात तो सभी अंदरखाने स्वीकार कर रहे हैं कि हुंकार रैली के बहाने नरेंद्र मोदी ने बिहार में जो धमाकेदार दस्तक दी उससे प्रदेश के कई स्थापित राजनीतिक व जातीय समीकरण बहुत तेजी से बदल रहे हैं. इसी बदलाव ने सत्ताधारी जदयू के अलावा राजद, लोजपा और कांग्रेस की नींद हराम कर दी है. अब तैयारी इस बदलाव की बयार पर लगाम लगाने की हो रही है. राजद तो खुलकर कह रही है कि उसका मुकाबला भाजपा से है न कि जदयू से. कांग्रेस व लोजपा भी इस सच्चाई को समझ रही हैं. एहसास तो जदयू को भी हो गया है पर सार्वजनिक तौर पर इस दल के नेता कुछ कहने से परहेज कर रहे हैं. हां, शिवानंद तिवारी ने राजगीर शिविर में मोदी की चुनौती से पार्टी को रूबरू कराने की कोशिश जरूर की पर इस दौरान उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा था. हुंकार रैली के बाद एक बार फिर नरेंद्र मोदी आए और उन्होंने बची हुई महफिल भी लूट ली. मारे गए लोगों के घरों पर जाकर उन्होंने भावनाओं का मरहम लगाकर यह जता दिया कि उनके अंदर एक भावुक दिल भी है. पलटवार करने की बारी नीतीश कुमार की थी और उन्होंने किया भी. लेकिन उन्हें भी एहसास है कि अब वक्त जुबानी जंग का नहीं बल्कि जमीनी जंग का है क्योंकि लोकसभा चुनाव माथे पर है. अगर अभी से ही मोदी के प्रभाव को नहीं रोका गया तो इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है. इसलिए बिना समय गंवाए सभी दल जनता के बीच जाने की तैयारी में हैं. बड़ी तैयारी जदयू और राजद की तरफ से हो रही है.

जदयू ने पहले चरण में 12 स्थानों पर संकल्प रैली करने का निर्णय किया है. इसकी शुरुआत मोतिहारी से सात दिसंबर को होगी और पटना साहिब में आकर 16 फरवरी को आखिरी संकल्प रैली होगी. कोशिश की गई है कि इन रैलियों में लगभग सभी जिलों की भागीदारी हो. मसलन लखीसराय की रैली में लखीसराय के अलावा मुंगेर, जमुई, शेखपुरा और बाढ़ के कार्यकर्ता भी शामिल होंगे. इसी तरह दूसरी रैलियों में भी अन्य जिलों को समाहित कर दिया गया है. प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह कहते हैं कि संकल्प रैली में संबंधित जिलों के कार्यकर्ता, विधायक, सांसद और पदाधिकारी सभी शामिल होंगे. जदयू ने सामाजिक सद्भाव बनाए रखने, बिहार को विशेष दर्जा दिलाने और पार्टी को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है जिसे लेकर ये रैलियां आयोजित की गई हैं. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार से भी इन रैलियों में शामिल होने का आग्रह किया गया है. बताया जा रहा है कि इनमें से कुछ रैलियों में नीतीश कुमार शामिल होंगे. जानकार सूत्र बताते हैं कि जदयू इन रैलियों के बहाने अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाना चाहती है और आगे आने वाले चुनावों के लिए उन्हें मानसिक तौर पर इस तरह तैयार कर देना चाहती है वह नमो लहर का मुकाबला कर सकें. इन संकल्प रैलियों के बाद जदयू कुछ स्थानों पर बड़ी रैलियां करने का भी मन भी बना चुकी है. यह सब संकल्प रैली में मिले फीडबैक के हिसाब से होगा.

कब-कब कहां होगी जद यू की संकल्प रैली

frfFk	LFkku	'kkfey ftys
07 दिसम्बर	मोतिहारी	पूर्वी चम्पारण, पश्चिम चम्पारण व शिवहर
15 दिसम्बर	पूर्णियां	पुर्णियां, कटिहार, किशनगंज व अररिया
21 दिसम्बर	मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी व वैशाली
28 दिसम्बर	दरभंगा	दरभंगा, मधुबनी व समस्तीपुर
18 जनवरी	गया	गया, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद व अरवल
22 जनवरी	लखीसराय	लखीसराय, मुंगेर, जमुई, शेखपुरा व बाढ़
25 जनवरी	मोहनियां	भोजपुर, रोहतास, कैमूर व बक्सर
29 जनवरी	भागलपुर	भागलपुर, नवगछिया व बांका
01 फरवरी	गोपालगंज	छपरा, सीवान व गोपालगंज
06 फरवरी	सहरसा	सहरसा , सुपौल व मधेपुरा
12 फरवरी	बेगूसराय	बेगूसराय व खगड़िया
16 फरवरी	पटना साहिब / फतुहा	पटना, पटना ग्रामीण व नालन्दा

नरेंद्र मोदी को रोकना जदयू के लिए जीवन मरण का प्रश्न बन गया है. ऐसा इसलिए भी है कि अगर लोकसभा चुनाव में नमो लहर ने अपना काम कर दिया तो फिर विधानसभा चुनावों से पहले जदयू में भारी भगदड़ मच सकती है और सरकार पर भी खतरा हो सकता है. इसलिए जदयू के रणनीतिकार पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में ही नमो लहर को रोक दिया जाए.

नरेंद्र मोदी को रोकना जदयू के लिए जीवन मरण का प्रश्न बन गया है. ऐसा इसलिए भी है कि अगर लोकसभा चुनाव में नमो लहर ने अपना काम कर दिया तो फिर विधानसभा चुनावों से पहले जदयू में भारी भगदड़ मच सकती है और सरकार पर भी खतरा हो सकता है. इसलिए जदयू के रणनीतिकार पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आने वाली आफत को टालने के लिए यह जरूरी है कि लोकसभा चुनाव में ही नमो लहर को रोक दिया जाए. यही तैयारी कमोवेश राजद की तरफ से भी है. लालू प्रसाद की गैरहाजिरी राजद को दोहरा झटका दे रही है. पार्टी आशंकाओं से घिरी है. राजद के आधार वोट यादव व मुसमलमानों पर भाजपा व जदयू की नजर लगी हुई है. बाबा रामदेव यादवों को मनाकर भाजपा की तरफ करने में लगे हैं तो नीतीश कुमार ने मुसलमानों को अपने पाले में करने के लिए अपने सारे घोड़े खोल दिए हैं. ऐसे में लालू प्रसाद का मैदान में न होना राजद को नुकसान पहुंचा रहा है. डैमेज कंट्रोल के लिए राबड़ी देवी 18 नवंबर से परिवर्तन रैली के लिए निकल रही है. परिवर्तन रैली के प्रथम चरण में राबड़ी देवी बिहार के सभी प्रमंडलों में आम सभा करेंगी. इसके बाद जिला मुख्यालयों सहित अन्य विधानसभा क्षेत्रों में भी राबड़ी देवी परिवर्तन रैली को संबोधित करेंगी.

पहली रैली गया प्रमंडल के शेरघाटी में होगी. इसके बाद 21 नवंबर को पटना प्रमंडल के पालीगंज में, 25 नवंबर को तिरहुत प्रमंडल के मीनापुर में, 27 नवंबर को शाहाबाद प्रभाग के कोचस में, 30 नवंबर को मुंगेर प्रमंडल के लखीसराय में तथा 8 दिसंबर को दरभंगा प्रमंडल के जीवछ घाट में आम सभा को संबोधित करेंगी. मकसद साफ है कि कार्यकर्ताओं के साथ ही साथ आम आवाम को भी यह संदेश दिया जाए कि राजद ही विकल्प है इसलिए नरेंद्र मोदी की बातों में वक्त बर्बाद न किया जाए और एक सुंदर बिहार बनाने के लिए राजद का साथ दिया जाए. लोजपा ने भी 28 नवंबर को पटना के श्रीकृष्ण मेमोरियल हाल में स्थापना दिवस और 23 फरवरी को पटना के गांधी मैदान में रैली करने का फैसला किया है.

कांग्रेस तो फिलहाल उहापोह में फंसी है पर जल्द ही गठबंधन को लेकर वह कोई फैसला लेगी ताकि नमो लहर को रोकने में वह कारगर भूमिका निभा सके. वाम दल भी नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की ओर निहार रहे हैं. लेकिन इन सब के बीच भाजपा ने भी हुंकार रैली में मिली बढ़त को आगे बढ़ाने का फैसला किया है. भाजपा ने जनता व कार्यकर्ता से जुड़ने का अपना लंबा प्रोगाम तय कर लिया है. भाजपा 15 नवंबर से 11 मार्च 2014 तक जिला, प्रखंड और पंचायत स्तरीय कई कार्यक्रम करेगी. इस दौरान पार्टी गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की बन रही प्रतिमा के निर्माण के लिए कार्यकर्ताओं और किसानों से लौह संग्रह करेगी. इसी क्रम में पार्टी सभी प्रखंडों में 15 दिसंबर को मैराथन दौड़ का आयोजन भी करेगी. 15 जनवरी, 2014 से 15 फरवरी, 2014 तक जिलों में लोकसभा व जिला सम्मेलनों का आयोजन करेगी. भाजपा ने अनुसूचित जाति, जनजाति, दलित व महादलित को जोड़ने के लिए 27 जनवरी से 12 फरवरी तक जिलों में रविदास जयंती का आयोजन करने का फैसला लिया है. पटना में राज्यस्तरीय रविदास जयंती समारोह का आयोजन 14 फरवरी को होगा. इसी तरह 15 फरवरी से नौ मार्च तक जिलों में पार्टी मत्स्जीवी सम्मेलनों का आयोजन होगा. भाजपा जुब्बा सहनी की पुण्यतिथि पखवाड़ा भी मनाएगी. 11 मार्च को पार्टी मुजफ्फरपुर में जुब्बा सहनी के शहादत दिवस पर विशाल मत्स्यजीवी सम्मेलन भी आयोजित करेगी. चार से 21 फरवरी तक भाजपा सभी जिलों में कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाएगी. पटना में 22 जनवरी को राज्यस्तरीय कर्पूरी जयंती समारोह का आयोजन होगा. 16 से 30 दिसंबर तक भाजपा 122 विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ता सम्मेलन करेगी. कहा जा सकता है कि तैयारी हर तरफ से है. होड़ आगे निकलने की और जनता का भरोसा जीतने की है इसमें कौन कितना सफल हो पाएगा यह आने वाला वक्त ही बताएगा.■

feedback@chauthiduniya.com

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

» एक नज़र «

अतीक बने राष्ट्रीय सचिव

पूर्वी चम्पारण जिले के केसरिया थाना क्षेत्र के कुण्डवा निवासी व भाकपा के युवा नेता अतीक अहमद खां को इंसाफ संगठन का राष्ट्रीय सचिव चुना गया है. भाकपा द्वारा आयोजित राष्ट्रीय अधिवेशन में खां के नाम की घोषणा हुई. खां को राष्ट्रीय सचिव बनाये जाने पर बधाईयों का तांता लगा हुआ है. युवा नेता मो. खां को राष्ट्रीय सचिव चुने जाने पर भाकपा के कई नेताओं ने बधाई दी है. बधाई देने वालों में केसरिया विधान सभा क्षेत्र पूर्व प्रत्याशी कामरेड रामशरण प्रसाद यादव, किसान सभा के जिला कार्यकारी अध्यक्ष कामरेड चौरसिया ध्रुव प्रसाद, पूर्व नप इपाध्यक्ष राजेन्द्र सिंह, नेजाम अहमद खां, मो. याकुब, युवा अध्यक्ष तेज कुमार सिंह, मो. नवीजान, शेख आजी साहेब, मो.फते अहमद खां, तसलीमुद्दीन मस्तान, मस्जिद मियां, अंचल मंत्री गया प्रसाद, पूर्व प्रमुख नारायण किशोर प्रसाद, मो. कौशर, लालबाबू प्रसाद, नारायण किशोर राय, त्रिभुवन प्रसाद समेत कई नेता शामिल हैं.

नगर मंत्री बने अनिल

भाजयुमो नगर अध्यक्ष विनोद वालिया ने अनिल कुमार आजाद को बैरगनिया का नगर मंत्री मनोनीत किया है. मनोनयन पर स्थानीय विधायक मोतिलाल प्रसाद, भाजपा नेता गणेश बाबा, मोहन सिंह, राम अयोध्या प्रसाद समेत अन्य ने श्री आजाद को बधाई दी है.

– विनोद कुमार

विधायक ने चेक बांटा

सीतामढ़ी जिले के रुन्नीसैदपुर प्रखंड कार्यालय परिसर में स्थानीय जदयू विधायक गुड्डी देवी ने लाभार्थियों के बीच चेक का वितरण किया. मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लाभार्थियों के बीच चेक का वितरण करते हुए विधायक ने कहा कि गरीबों की मदद ही राज्य सरकार की मंशा है. इसी के तहत उक्त योजना का श्रीगणेश किया गया है. पुपरी एसडीओ अखिलेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में कुल 387 लाभार्थियों के बीच 5-5 हजार रुपये का चेक वितरित किया गया. मौके पर प्रमुख संगीता देवी, महिला प्रसार पदाधिकारी नीलू कुमारी, सांख्यिकी पर्यवेक्षक नवीन किशोर, प्रखंड बीस सूत्री अध्यक्ष प्रहलाद महतो, प्रखंड जदयू अध्यक्ष रामचंद्र सिंह, जाकिर हुसैन व बीएलओ अनिल कुमार सिंह समेत अन्य थे.■

– विभा सिन्हा

मुंह चिढ़ा रहा है जलमीनार

नगर पंचायत के वार्ड सदस्य जेड अहमद, शकुंतला देवी, श्याम सहनी, सबरा खातून समेत अन्य का कहना है कि जलमिनार से सप्लाई वाले अधिकांश नालियों में लिकेज है. पूर्व में तीन बार मोटर भी जला था. तब स्थानीय लोगों के हंगामे के बाद मोटर तो लगा दिया गया लेकिन विद्युत सेवा बहाल रहने के बाद भी इसे चालू नहीं किया गया.

राम नारायण

आंकड़ों की बाजीगरी करके बिहार सरकार लगातार कहती है कि हमारे यहां विकास की बयार बह रही है. लेकिन एक सच यह भी है कि प्रशासनिक उदासीनता की वजह से सीतामढ़ी जिले के बेलसंड अनुमंडल मुख्यालय के लोगों के लिए पेयजल समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है.

एक ओर सूबे की सरकार विभिन्न योजनाओं के तहत जन समस्याओं का निदान करने का दंभ भर रही है वहीं दूसरी ओर वर्षों पूर्व से बंद पड़े इस जलमिनार को चालू कराने की दिशा में समुचित प्रयास नहीं किया जा रहा है. 13 वार्डों वाले बेलसंड नगर पंचायत की आबादी तकरीबन 20 हजार है. स्थानीय लोगों को शुद्ध पेयजल मुहैया कराने को लेकर तकरीबन तीन दशक पूर्व अनुमंडल मुख्यालय में जल मीनार का निर्माण कराया गया. सरकारी योजना के तहत करीब 8 लाख की लागत से निर्मित जलमिनार का लाभ आम लोगों को दिला पाने में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग अबतक नकारा साबित हो रही है. अनुमंडल, प्रखंड, अंचल व बेलसंड थाना के समीप लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के स्थानीय कार्यालय परिसर में मौजूद जल मीनार पिछले तकरीबन एक दशक से बंद पडा है. जबकि विभागीय स्तर पर कार्यपालक व कनीय अभियंता समेत करीब आधा दर्जन कर्मचारी प्रतिनियुक्त किये गये हैं. लेकिन ये कर्मचारी शायद ही कभी नजर आते हैं.

नगर पंचायत के वार्ड सदस्य जेड अहमद, शकुंतला देवी, श्याम सहनी, सबरा खातून समेत अन्य का कहना है कि जलमिनार से सप्लाई वाले अधिकांश नालियों में लिकेज है. पूर्व में तीन बार मोटर भी जला था. तब स्थानीय लोगों के हंगामे के बाद मोटर तो लगा दिया गया लेकिन विद्युत सेवा बहाल रहने के बाद भी इसे चालू नहीं किया गया. प्रखंड जदयू अध्यक्ष राम प्रवेश भगत, राजद अध्यक्ष जगन्नाथ राय, समाजसेवी जितेंद्र प्रसाद गुप्ता व जिला कांग्रेस के महासचिव महेश मांझी समेत अन्य का कहना है कि राज्य सरकार की सजगता के बाद भी जलमिनार का दिखावा बने रहना एक पहेली से कम नहीं है. नगर पंचायत अध्यक्ष नागेंद्र झा का कहना है कि सभी वार्डों में नाले के पुर्ननिर्माण की मांग की जा रही है. परंतु इस दिशा में अब तक कोई पहल नहीं की जा सकी है. बताया जाता है कि इस गंभीर पेयजल संकट से निजात को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधि व प्रशासनिक अधिकारी उदासीन बने हुए हैं. इसका खामियाजा विशेष तौर से समाज के गरीब व पिछडे.लोगों को भुगतना पड़ता है. चर्चाओं पर यकीन करें तो इस समस्या के निदान के प्रति समय रहते अगर ध्यान नहीं दिया गया तो निकट भविष्य में आंदोलन की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है. वैसे आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाने की योजना भी बनाई जाने लगी है.■

जगन्नाथ राय

जितेंद्र प्रसाद गुप्ता

महेश मांझी

नागेंद्र झा

राम प्रवेश भगत

feedback@chauthiduniya.com

फर्टीलाइजर पर सिर्फ लफ्फाजी करते हैं नेता

विकास नहीं होने के पीछे जिले की जनता कांग्रेस पार्टी को भी उतना ही दोषी करार दे रही है. देश का दूसरा तेलशोधक कारखाना बरौनी रिफाइनरी है. बरौनी रिफाइनरी के बाद देश में जितने भी रिफाइनरी की स्थापना की गई उनकी शोधन क्षमता में काफी बढ़ोतरी की गई. साथ ही सभी रिफाइनरी के साथ पेट्रोकेमिकल कारखाने की स्थापना भी की गई. लेकिन डा. श्रीकृष्ण सिंह की अनमोल देन बरौनी रिफानरी का न तो समुचित विस्तार हुआ और न ही पेट्रोकेमिकल कारखाना की स्थापना हुई. वर्त्तमान में कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय सरकार ने पिछले दिनों मंत्रिमंडल की बैठक में पारित प्रस्ताव में बरौनी खाद कारखाना के साथ भी सौतेला व्यवहार किया. केंद्रीय मंत्रिमंडल के इस फैसले का जवाब भी जिले की जनता लोकसभा चुनाव में देगी.

सुरेश चौहान

पूर्व के लोकसभा चुनावों की तरह इस बार भी बरौनी का बंद खाद कारखाने एवं पेट्रोकेमिकल कारखाने के नहीं लगने को राजनीतिक दल चुनावी जंग का हथियार बनाने में जुटी हैं. सभी राजनीतिक दल इसे चुनावी शतरंज का मोहरा बनाकर एक बार फिर जिले की जनता को ठगने के लिए कदम बढ़ा रही हैं. जिस दल की सरकार ने बरौनी खाद कारखाने को बंद करने का निर्णय लिया, उसी दल के राष्ट्रीय नेता अब लोकसभा चुनाव के पूर्व इस कारखाने को पुनर्जीवित करने के लिए संसद में धरना देने की घोषणा करते हैं. आखिर ऐसे नेता जिले की जनता को कब तक गुमराह करते रहेंगे. जबकि केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने बंद पड़े खाद कारखाने को दोबारा चालू करने के प्रस्ताव में बरौनी खाद कारखाना को शामिल ही नहीं किया है. जिले की जनता यह भूली नहीं है कि जब केंद्र में एनडीए की सरकार थी. अटल विहारी वाजपेयी की सरकार में बिहार के कई मंत्री शामिल थे इसी काल में बरौनी खाद कारखाना को बंद करने का निर्णय लिया गया था.

गौरतलब है कि जिस समय बरौनी खाद कारखाना को बंद करने की साजिश चल रही थी, वांछित उत्पादन नहीं होने का हवाला दिया गया था. लेकिन इस समय वास्तविक स्थिति यह थी कि बरौनी खाद कारखाना उत्पादन का रिकार्ड कायम किया था, बावजूद इसके इसे बीमार घोषित किया गया. उस समय केंद्र में मंत्री रहे बिहार के तमाम नेता मौन साधे रहे. बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव पारित किया कि भविष्य में यदि देश में बंद खाद कारखाना को पुन: चालू करने का निर्णय लिया जाएगा तो बरौनी खाद कारखाने को प्राथमिकता दी जाएगी. केंद्रीय मंत्रिमंडल का यह निर्णय बिहारवासियों को सिर्फ सांत्वना देने के लिए था.और यह पोल वर्त्तमान यूपीए सरकार की मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव से खुल गया. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के बन्द पड़े खाद कारखाना को पुनर्जीवित का प्रस्ताव पारित किया है. लेकिन इस प्रस्ताव की सूची में बरौनी खाद कारखाना का नाम गायब है.

जिस एनडीए के शासनकाल में बरौनी खाद कारखाने को बंद करने का निर्णय लिया गया उसी एनडीए की महत्वपूर्ण घटक भाजपा अब लोकसभा चुनाव से पूर्व इसे सियासी मुद्दा बनाना चाहती है. पिछले दिनों नरेंद्र मोदी के हुंकार रैली में हुए सीरियल बम ब्लास्ट में प्रांण गंवाने वाले जिले के विन्देश्वरी चौधरी के अकिलश यात्रा में पहुंचे पार्टी के राष्ट्रीय नेता व सांसद डा. सीपी ठाकुर ने घो-षणा की कि बंद पड़े बरौनी खाद कारखाने को पुनर्जीवित करने एवं पेट्रोकेमिकल कारखाने की स्थापना के लिए भाजपा संघर्ष करेगी और संसद में धरना देगी. जिस पार्टी की सरकार ने बरौनी खाद कारखाने को बन्द किया इसी पार्टी के नेता अब लोकसभा चुनाव से पूर्व उसे पुनर्जीवित करने के लिए संसद में धरना देने की बात कहते हैं तो आम जनता के गले के नीचे उनकी बातें नहीं उतर रही है.

जिले की जनता को वह दिन भी याद है जब केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान, लालू प्रसाद यादव एवं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तिकड़ी ने काफी तामझाम से बरौनी उर्वरक नगर के मैदान में आयोजित जनसभा को सम्बोधित करते हुए सम्मिलित स्वर में घोषणा की थी कि बरौनी खाद कारखाने का शीघ्र ही उद्धार किया जाएगा लेकिन इस 'शीघ्र'का दर्शन आजतक नहीं हुआ. जिले की जनता इसे भूली नहीं है और डा. सीपी ठाकुर के बयानबाजी को वोट की राजनीति से जोड़कर देख रही है.

विकास नहीं होने के पीछे जिले की जनता कांग्रेस पार्टी को भी इतना ही दोषी करार दे रही है. देश का दूसरा तेलशोधक कारखाना बरौनी रिफाइनरी है. बरौनी रिफाइनरी के बाद देश में जितने भी रिफाइनरी की स्थापना की गई इसकी शोधन क्षमता में काफी बढ़ोतरी की गई. साथ ही सभी रिफाइनरी के साथ पेट्रोकेमिकल कारखाने की स्थापना भी की गई. लेकिन डा. श्रीकृष्ण सिंह की अनमोल देन बरौनी रिफानरी का न तो समुचित विस्तार हुआ और न ही पेट्रोकेमिकल कारखाना की स्थापना हुई. वर्तमान में कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय सरकार ने पिछले दिनों मंत्रिमंडल की बैठक में पारित प्रस्ताव में बरौनी खाद कारखाना के साथ भी सौतेला व्यवहार किया. केंद्रीय मंत्रिमंडल के इस फैसले का जवाब भी जिले की जनता लोकसभा चुनाव में देगी.

बरौनी खाद कारखाने को घाटे में ले जाने के पीछे भाकपा को भी जवाबदेह माना जाता है. प्रबंधन पर दबाव बनाकर आवश्यकता से अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति कराना और छोटी-छोटी बातों पर भी प्रबंधन के सामने धरना-प्रदर्शन करना भाकपा यूनियन की दिनचर्या में शामिल था. एक ओर अत्यधिक कर्मचारी रहने से आर्थिक बोझ बढ़ रहा था तो दूसरी ओर धरना प्रदर्शन से उत्पादन प्रभावित हो रहा था. बरौनी खाद कारखाने के बन्द होने एवं बरौनी रिफाइनरी के साथ पेट्रोकेमिकल कारखाना स्थापित नहीं किए जाने के पीछे मुख्य कारण रहा जिले के नेताओं में जुझारूपन एवं समर्पण का अभाव. वर्तमान से लेकर पिछले कई सांसदो में जिले के विकास के प्रति कोई मानसिकता नहीं रही. उनके पास जिले के विकास की कोई योजना नहीं रही और विकास की नई योजना लाने में सर्वथा विफल रहे जिसका प्रतिफल जिले की जनता भुगत रही है. ■

जिस एनडीए के शासनकाल में बरौनी खाद कारखाना को बंद करने का निर्णय लिया गया इसी एनडीए की महत्वपूर्ण घटक भाजपा अब लोकसभा चुनाव से पूर्व इसे सियासती मुद्दा बनाना चाहती है. पिछले दिनों नरेंद्र मोदी के हुंकार रैली में हुए सीरियल बम ब्लास्ट में प्राण गंवाने वाले जिले के विन्देश्वरी चौधरी के अस्थिकलश यात्रा में पहुंचे पार्टी के राष्ट्रीय नेता व सांसद डा. सीपी ठाकुर ने घो-षणा की कि बंद पड़े बरौनी खाद कारखाने को पुनर्जीवित करने एवं पेट्रोकेमिकल कारखाना की स्थापना के लिए भाजपा संघर्ष करेगी और संसद में धरना देगी.

feedback@chauthiduniya.com

» एक नज़र «

हस्तकला में सिद्धहस्त हैं सुंदरका

कला के प्रति सच्ची निष्ठा का भाव रखने वाला एक दिन समाज में सम्मान का हकदार बन ही जाता है. इस तथ्य को सही साबित कर दिखाया है सीतामढ़ी शहर की सामाजिक कार्यकर्ता राजेश कुमार सुंदरका की पत्नी प्रो. ज्योति सुंदरका ने. पिछले 7 सालों से वे दिपावली के मौके पर बाल गोपाल के माध्यम से विशेष आयोजन करती आ रही हैं. श्री-गणेश-लक्ष्मी की मनोहारी प्रतिमा हो अथवा भगवान की आकर्षक पोशाक. घर से लेकर दरवाजे तक सजाने वाली माला हो या वंदनवार, सभी में प्रो. ज्योति के लगनशीलता एवं कठिन परिश्रम की झलक दिखाई पड़ती रही. उनके कलाकारी की चर्चा पूरे जिले में है. प्रो. ज्योति कहती हैं कि मकसद पर्व के मौके पर पैसा कमाना नहीं बल्कि देश की सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए लोगों को प्रेरित करना है.

– ब्रजेश

अतिक्रमण से जनता परेशान

सरकारी फरमान व प्रशासनिक कवायद के बाद भी बैरगनिया नगर पंचायत क्षेत्र में अतिक्रमण जारी है. आलम है कि स्थानीय पटेल चौक समेत अन्य चौक व चौराहों से होकर गुजरना लोगों के लिए सजा के समान हो गया है. सड़क पर सजने वाले अस्थाई दुकानों से लेकर तांगा व टैंपो वालों की मनमानी लोगों के लिए परेशानी को और बढ़ा रहा है. स्थानीय प्रशासनिक उदासीनता की वजह से ही अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गयी है. वरिष्ठ भाजपा नेता गणेश बाबा व मोहन सिंह ने स्थानीय प्रशासन से जल्द अतिक्रमण की समस्या से निजात दिलाने की मांग की है.

– विनोद कुमार

मुख्यमंत्री पहुंचेंगे गढ़पुरा

बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री व आधुनिक बिहार के निर्माता डा. श्री कृष्ण सिंह का 126वां जयंती समारोह उनके जन्म स्थान खनमा गांव में मनाया गया. खनमा नवादा जिला में है. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यहां आना पहली बार हुआ था. इस कार्यक्रम में मुंगेर के सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, विधान पार्षद नीरज कुमार सहित कई गणमान्य लोगों ने शिरकत की. इस दौरान बेगूसराय के गढ़पुरा नमक सत्याग्रह गौरव यात्रा समिति के सदस्यों ने महासचिव राजीव कुमार के नेतृत्व में वहां पहुंच कर मुख्यमंत्री को एक मोमेंटो भेंट किया. समिति के सदस्यों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंप स्वतंत्रता आंदोलन की धरोहर गढ़पुरा के नमक सत्याग्रह स्थल को संरक्षित करने व इसे पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने को कहा. मुख्यमंत्री ने सदस्यों को भरोषा दिलाया कि जल्द ही स्थल का विकास किया जाएगा साथ ही यह भी कहा कि वे खुद भी गढ़पुरा पहुंचेंगे. मुख्यमंत्री से मिलने वालों में मथुरा सहनी, मो. हासिम, अर्जुन प्रसाद सिंह, बालमुकुंद सिंह आदि थे. ■

– सुरेश चौहान

आपस में भिड़ेंगे नक्सली संगठन, भुगतेगी जनता

सुनील सौरभ

बिहार-झारखण्ड की सीमा से लगे गया जिले का सीमावर्ती क्षेत्र नक्सलियों के वर्चस्व की लड़ाई में संभावित खूनी संघर्ष से दहशत में है. आर्थिक रूप से थोड़े बहुत भी मजबूत परिवार अपना पुश्तैनी घर-गांव छोड़कर पलायन करने लगे हैं. एक तरफ प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी का डर तो दूसरी ओर इसके विरोधी तृतीय प्रस्तुति कमेटी नामक नक्सली संगठन खड़ा है. ऊपर से पुलिस का खौफ अलग है. इसका सीमावर्ती क्षेत्र यानि इमामगंज विधानसभा क्षेत्र है. यहां से बिहार विधानसभा के अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी प्रतिनिधि हैं. यह क्षेत्र पूरी तरह परस्पर विरोधी दोनों नक्सली संगठन की सामानान्तर सरकार की जद में है.

गत 22 सितम्बर को टीपीसी ने इमामगंज के पथरा गाँव से आपराधिक घटनाओं मे शामिल रहने वाले मन्टू सिंह, वकील सिंह, परसिया गांव के वरमेश्वर भारती व नावाडीह गांव के रामेश्वर यादव को अगवा कर 26 सितम्बर को जन अदालत लगाकर सजा दी. सभा में अपराधिक घटनाओं में शामिल लोगों को 10-10 लाठी पिटाई करने के बाद चेतावनी देकर छोड़ दिया गया. ग्रामीणों को आशंका थी कि टीपीसी चारो लोगों की हत्या कर देगा. लेकिन अगवा लोगों के परिजनों की गुहार पर जनअदालत लगाकर आगे से अपराधिक घटनाएं नहीं करने की चेतावनी दी गई. इन सभी पर विभिन्न संगठनों के नाम पर लेवी वसूलने, चोरी करने, गुंडागर्दी करने, गोली मारने, बलात्कार करने समेत अनेक आरोप थे. इन सभी के पास से टीपीसी ने 2 पुलिस रायफल, 4 रेग्युलर बंदूक, 9एमएम की कार्बाइन भी जब्त किया था. जो काम पुलिस को करना चाहिए वह टीपीसी कर रहा है. दिन दहाड़े इमामगंज के जंगल में टीपीसी ने चारो अपराधी तथा इससे बरामद हथियारों को भी प्रदर्शित किया. वहीं दूसरी ओर टीपीसी ने अपने विरोधी भाकपा माओवादी को भी इमामगंज में पोस्टर चिपकाकर चेतावनी दी है कि निर्दोष लोगों की हत्या बंद करो नहीं तो हमें भी बाध्य होकर कार्रवाई करनी पड़ेगी. तृतीय प्रस्तुति कमेटी की जनअदालत ने गया जिले के शेरघाटी अनुमण्डल के पुलिस पदाधिकारियों की नींद उड़ा दी है. गया के वरीय आरक्षी अधीक्षक ने शेरघाटी अनुमण्डल के सभी थानों को अलर्ट कर दिया है. इन्ही सब घटनाओं से झारखण्ड की सीमा से लगे डुमरिया, इमामगंज, बांकेबाजार प्रखण्ड के ग्रामीण दहशत में हैं. टीपीसी की कार्रवाई के विरोध में भाकपा माओवादी की ओर से भी कार्रवाई की आशंका लोग जता रहे हैं. ऐसा हुआ तो दोनो प्रतिबंधित नक्सली संगठन के वर्चस्व की लड़ाई में खूनी संघर्ष में निर्दोष लोगों की जानें जा सकती हैं. इसी संभावित आशंका से लोग सहमे हैं. इस साल गत 27 मार्च को तृतीय प्रस्तुति कमेटी ने बिहार की सीमा से लगे झारखण्ड के चतरा जिले के लकरबंधा जंगल में भाकपा माओवादी के नेता गया जिला निवासी ललेश समेत शिर्ष 10 कमांडरों की हत्या कर दी थी. इस घटना से बिहार झारखण्ड का सीमावर्ती क्षेत्र महीनों दहशत में रहा था. इस घटना के बाद भाकपा माओवादी को बहुत कमजोर भी हो गयी है. अब जबकि टीपीसी बिहार की सीमा में घुसकर पुलिसिया तर्ज पर कार्रवाई कर रहा है तो इससे पुलिस की कार्यशैली पर भी लोग प्रश्नचिन्ह खड़ा कर रहे हैं.

इस क्षेत्र में के लोगों के साथ समस्या है कि एक तरफ पहाड़ है तो दूसरी तरफ खाई जाएं तो किधर जाएं? नतीजा है कि शरीफ-निर्दोष तथा शांति पंसद लोग इसी बहाने धीरे-धीरे गांव से पलायन करने को मजबूर हैं.■

feedback@chauthiduniya.com

सारण में बिछने लगी चुनावी बिसात

2009 में इस क्षेत्र से विभिन्न दलों के नेताओं ने राजद के टिकट के लिए अथक प्रयास किया था और परिणाम भी राजद के पक्ष में ही गया था. वहीं इस बार विभिन्न दलों के नेता भाजपा से टिकट पाने को आतुर दिख रहे हैं. हाल ही में हुए उपचुनाव में जो नेता जदयू व राजद से टिकट के लिए अंतिम समय तक प्रयासरत रहे वही बदले राजनीतिक घटनाक्रम में भाजपा और नमो का राग अलाप रहे हैं.

चन्द्रप्रकाश राज

सारण का महराजगंज लोकसभा क्षेत्र लगातार चर्चा में रहा है. पिछले दिनों चर्चे की वजह थी कि यहां हुए उपचुनाव में राजद के प्रत्याशी प्रभुनाथ सिंह ने एनडीए के उम्मीदवार व जदयू नेता पीके शाही को 1.37 लाख से ज्यादा मतों के अंतर से हराया था. जबकि जदयू भाजपा के बड़े-बड़े नेताओं ने महीनों तक यहां कैम्प किया था. हार के बाद जदयू भाजपा के बीच आरोप-प्रत्यारोप भी खूब हुआ था. जदयू नेताओं ने यह आरोप भी लगाया था कि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने शाही को हराया है वहीं भाजपा का कहना था कि यह किसी एक पार्टी की नहीं बल्कि गठबंधन की हार है. बहरहाल गठबंधन टूटने के बाद महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र का नजारा बिल्कुल ही बदल-बदला सा है. यह देखने को मिल रहा है कि क्षेत्र के विभिन्न दलों के नेताओं की दिल-चस्पी अचानक से भाजपा में बढ़ गई है.

अभी से ही इस क्षेत्र से भाजपा का टिकट पाने को पार्टी समेत अन्य दलों के नेताओं ने दिल्ली, अहमदाबाद तथा नागपुर तक के चक्कर लगने शुरू कर दिए हैं. बताते चलें कि सारण में चार लोकसभा सीट है और इन चारों में से महाराजगंज हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है. छपरा का अमनौर, मढ़ौरा, गरखा, छपरा सदर विधानसभा क्षेत्र महाराजगंज की सीमा से मिलते हैं. वहीं सिवान का सिवान शहर, दरौंदा, रघुनाथपुर की सीमा और गोपालगंज लोकसभा क्षेत्र का बरौली व बैकुंठपूर भी महराजगंज लोकसभा क्षेत्र की सीमाओं को घेरते हैं. यही वजह है कि महराजगंज से चली राजनीतिक लहर पूरे सारण प्रमंडल को प्रभावित करती रही है. मालूम हो कि 2009 में इस क्षेत्र से विभिन्न दलों के नेताओं ने राजद के टिकट के लिए अथक प्रयास किया था और परिणाम भी राजद के पक्ष में ही गया था. वहीं इस बार विभिन्न दलों के नेता भाजपा से टिकट पाने को आतुर दिख रहे हैं. हाल ही में हुए उपचुनाव में जो नेता जदयू व राजद से टिकट के लिए अंतिम समय तक प्रयासरत रहे वही बदले राजनीतिक घटनाक्रम में भाजपा और नमो का राग अलाप रहे हैं.

छपरा के भाजपा विधायक व पूर्व मंत्री जर्नादन सिंह सिग्रीवाल इन दिनों छपरा से अधिक महराजगंज क्षेत्र में ज्यादा सक्रिय नजर आने लगे हैं. वहीं तरैयां के भाजपा विधायक जनक सिंह भी अपने लोकसभा क्षेत्र महाराजगंज में लगातार संपर्क अभियान में जुटे हुए हैं. मशरख के पूर्व विधायक व महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी तारकेश्वर सिंह भी अपने दलबल के साथ नमो का जाप करते हुए महाराजगंज के चक्कर काट रहे हैं. श्री सिंह इस क्षेत्र से 2009 में चुनाव लड़ चुके हैं, और उन्हें लगभग पचासी हजार मत प्राप्त हुए थे.

वहीं अन्य दलों के नेता भी भाजपा में न केवल अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं बल्कि अपनी पार्टी से नाता तोड़ भाजपा में शामिल होकर लगातार कार्यकर्ताओं से संपर्क कर रहे हैं. जदयू नेता रहे ई. सच्चिदानंद राय से यह सिलसिला शुरू हुआ और लगातार बढ़ता ही जा रहा है. भाजपा में शामिल हो कर राय ने टिकट के लिए अपनी ओर से तैयारी शुरू कर दी है. बताया जाता है कि राय ने हुंकार रैली के लिए भाजपा को काफी संसाधनों से भी सहयोग किया था. यह सीट पिछले दो लोकसभा चुनाव से राजद के कब्जे में है. सूत्र बताते हैं कि जिले के दूसरे दल के कई वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री भाजपा के एक बड़े नेता से लगातार संपर्क में बने हुए हैं. हालांकि वे तब तक दल नहीं बदलेंगे जब तक कि उन्हें अपना स्थान नजर नहीं आ जाता. भुमिहार समाज के कई बड़े भाजपा नेता भी इस क्षेत्र पर दावा करते हुए हुंकार रैली में उपस्थिति दर्ज कराई थी. इस कड़ी में दिल्ली में राजनीति करने वाले दिनेश प्रताप सिंह व ई. सच्चिदानंद राय की दावेदारी को भाजपा के प्रदेश नेता व मानवाधिकार मंच के उपाध्यक्ष प्रबोध कुमार सिंह भी मजबूत उम्मीदवार बता रहे हैं. पिछले संसदीय उपचुनाव में यह स्थिति जदयू के साथ थी. इसका खामियाजा भी जदयू को भुगतना पड़ा था. अब बदली हुई परिस्थिति में जदयू के टिकट के लिए दौड़ लगाने वाले कई नेता प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लगातार भाजपा के शीर्ष नेताओं के संपर्क में हैं. वहीं कई नेता भाजपा के साथ-साथ जदयू से भी टिकट की आस लगाए हुए नजर आ रहे हैं. महराजगंज लोकसभा क्षेत्र का इतिहास काफी समृद्ध रहा है. यह समाजवादियों का गढ़ माना जाता रहा है. इस क्षेत्र से पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर व भारत सरकार के कई पूर्व मंत्री भी प्रतिनिधित्व कर चुके हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

Enjoy with Nature
MOULDED FURNITURE
NATURE MOULDED FURNITURE
1 YEAR GUARANTY
WINNER OF NATIONAL AWARD
Contact : 9386595926, 9334115955

संतुलित आहार बेहद जरूरी
ariskon Pharma Pvt.Ltd.
ACOBA CAP/SYP/INJ
Carbo - XT
Ferrous Ascorbate with Folic Acid Tab.
AREX
ASRFEN-P
ECTALOPAM
SLIMLEX
NOKSIRA Pharma Pvt.Ltd.
A Division of AriskonPharma

समस्या आपकी समाधान Dr. Advice से
प्रश्न : मेरे ससुर जी के आंख में मोतियाबिंद की शिकायत है और वे ऑपरेशन से बचना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में CINERARIA MARITIMA REPL डालना उचित होगा।
भी समर्थ नहीं हो पाता हूँ। स्थायी उपचार बतायें। सुधीर सिंह, जयपुर
उत्तर : सुधीर जी! बाबासीर की रोकथाम के लिये आप पाइलेलैक्स लिफलेट के
Breastriim Oil का सुबह-शाम दिये गये निर्देश के अनुसार 3 माह तक मसाज करें। इसके नियमित इस्तेमाल से सीना का विकास आयेगा एवं आप आकर्षक नजर आएंगी।
REPL प्लाजा, तीसरा तल्ला पटना - 801505
विस्तृत जानकारी के लिए सम्पर्क करें 9304291051
किसी भी रोग संबंधी निदान के लिए Dr. Advice पुस्तिका (होमियोपैथिक) निकटतम स्टॉकिस्ट से मुफ्त प्राप्त करें।
REPL द्वारा जनहित में प्रकाशित

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

सांप्रदायिकता की राजनीति

सांप्रदायिकता का विरोध सिर्फ़ इसलिए करना क्योंकि नरेंद्र मोदी सांप्रदायिक हैं या नरेंद्र मोदी की पार्टी सांप्रदायिक है या फिर कांग्रेस का विरोध इसलिए करना क्योंकि कांग्रेस सांप्रदायिकता का विरोध कर रही है और जो सांप्रदायिकता का विरोध करते हैं, उन्हें कांग्रेस को वोट देना चाहिए. ये ऐसे तर्क हैं, जिन तर्कों पर अगर फ़ैसले लिए जाएं तो फ़ैसले निहायत ग़लत होंगे. सांप्रदायिकता एक ऐसा शब्द है, जिस शब्द की परिभाषा आज तक हर-एक ने अपनी-अपनी तरह से की है. लेकिन सांप्रदायिकता का रिश्ता जब एक बड़े तबके से हो यानी हिंदुस्तान की 80 प्रतिशत या 90 प्रतिशत जनता से हो, तब सांप्रदायिकता का मतलब समझने में न केवल सावधानी बरतनी चाहिए, बल्कि उसका वही मतलब समझना चाहिए, जिस मतलब का रिश्ता 80 प्रतिशत लोगों से जुड़ता हो.

सांप्रदायिकता का आरोप झेलने वाले दल या व्यक्ति ये कैसे मान लेते हैं कि मुसलमानों का विरोध करना ही सांप्रदायिकता है या जो लोग मुसलमानों का विरोध करते हैं, वे लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे ही देंगे. क्या भारतीय जनता पार्टी ने ये घोषित कर दिया है कि उन्हें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए या उन्होंने ये घोषित कर दिया है कि 2014 के चुनाव में यदि भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो मुसलमानों को इस देश में दोयम दर्जे के नागरिक के रूप में माना जाएगा या जाना जाएगा? उन्हें जो संविधान ने हक़ दिए हैं, वो हक़ छीन लिए जाएंगे.

सांप्रदायिकता का आरोप झेलने वाले दल या व्यक्ति ये कैसे मान लेते हैं कि मुसलमानों का विरोध करना ही सांप्रदायिकता है या जो लोग मुसलमानों का विरोध करते हैं, वे लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे ही देंगे. क्या भारतीय जनता पार्टी ने ये घोषित कर दिया है कि उन्हें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए या उन्होंने ये घोषित कर दिया है कि 2014 के चुनाव में यदि भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो मुसलमानों को इस देश में दोयम दर्जे के नागरिक के रूप में माना जाएगा या जाना जाएगा? उन्हें जो संविधान ने हक़ दिए हैं, वो हक़ छीन लिए जाएंगे. सांप्रदायिकता की पहचान लिए भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी क्या उन आर्थिक नीतियों का विरोध करते हैं, जिन्हें सांप्रदायिकता विरोध के नाम पर अपने को पेश करने वाले कांग्रेस पार्टी के लोग कर रहे हैं. क्या सांप्रदायिकता के आरोप से सनी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को ये अधिकार मिल जाता है कि गुजरात में कुपोषण पैदा करना या कुपोषण को अनदेखा करना उनका हक़ है? क्या भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को इस बात का भी हक़ मिल जाता है कि किसानों के फ़सलों की क़ीमत किसानों को सीधे न मिलने देना है? क्या उनका कोई ज़िम्मा नहीं बनता? या फिर क्या नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को इस बात का भी हक़ मिल जाता है कि शिक्षा में सबको हिस्सा न मिले, इसके ऊपर उनसे कोई सवाल नहीं पूछ सकता.

लेकिन क्या ये भी नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को हक़ मिल जाता है कि वो अपनी आर्थिक नीतियां भी न स्पष्ट करें. वो ये भी न बताएं कि विकास के दायरे से 70 प्रतिशत जनता बाहर है, उसे विकास के दायरे में कैसे लेकर आएंगे या फिर वो लोगों को ये भी नहीं बताना चाहते कि उनके रिश्ते किनसे, कैसे होंगे.

इससे विपरीत सवाल कांग्रेस से पूछे जा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी सांप्रदायिकता विरोध के नाम पर सड़कें, शिक्षा, अस्पताल, भ्रष्टाचार जैसी चीज़ों को मुद्दा मानती है या नहीं मानती है? या केवल सांप्रदायिकता का विरोध या नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का विरोध ही उसका एकमात्र एजेंडा है? क्या कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र को, जिसे उसने 2004 और 2009 में देश के सामने रखा, ये आंकलन पेश करेगी कि उसने इसमें से कितनी चीज़ें लागू कीं और कितनी चीज़ें नहीं लागू कीं. कांग्रेस पार्टी के सरकार के एक मंत्री कहते हैं कि सच्चर कमेटी की सिफ़ारिशों को 90 प्रतिशत के आसपास लागू कर दिया गया है. ज़मीन पर कहीं कुछ दिखाई नहीं देता और समझ में तो ये भी नहीं आता कि सच्चर कमेटी की सिफ़ारिशें थीं क्या? दरअसल, सच्चर कमेटी ने बीमारी की पहचान की, लेकिन उस बीमारी की दवा सुझाने का काम रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने किया. इस पूरी दौड़ में, इस पूरे शोर में कांग्रेस पार्टी ने सच्चर कमेटी का तो नाम लिया, लेकिन कभी भी रंगनाथ मिश्रा कमीशन का नाम ही नहीं लिया. इसलिए मुझे ये लगता है कि सच्चर और रंगनाथ मिश्रा के बीच का अंतर कांग्रेस कभी पाटना भी चाहती है या नहीं पाटना चाहती और इन सवालों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को क्या कहना है? नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ऐसे सवालों के ऊपर ख़ामोश हैं.

अगर हम देखें तो दोनों की आर्थिक नीतियां एक हैं. लोगों के प्रति कैसी जवाबदेही होनी चाहिए, उसके बारे में दोनों पार्टियां बिल्कुल एक हैं. भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोज़गारी, शिक्षा और स्वास्थ्य के सवाल पर दोनों पार्टियां कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ख़ामोश हैं और दोनों के ही प्रधानमंत्री पद के दावेदार एक तरफ़ नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ़ राहुल गांधी इन सवालों को छूना ही नहीं चाहते. एक सांप्रदायिकता का विरोध करता है और दूसरा कहता है कि सांप्रदायिकता एक छद्म शब्द है. लेकिन दोनों ही चाहते हैं कि जो बुनियादी सवाल हैं, वे देश के लोगों के सामने ही न आएं. देश का छात्र और देश का नौजवान इस बाज़ीगरी में तमाशबीन बनकर खड़ा हुआ है. दोनों ही पार्टियां छात्रों और नौजवानों की 18 साल से लेकर 25 साल के उम्र तक की इस पीढ़ी को एक नई अंधेरी सुरंग में धकेल रही हैं. ज़रूरत इस बात की है कि इस पीढ़ी को ज़िम्मेदार लोग बताएं कि देश के बुनियादी सवाल क्या हैं और उन बुनियादी सवालों पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का रुख़ क्या हो, इसका सवाल पूछने का नौजवानों को और छात्रों को हौसला दें, क्योंकि अगर छात्र और नौजवान ये सवाल नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी से पूछेगा तो उसे समझ में आएगा कि किसे वोट देना है, किसे नहीं वोट देना है या दोनों में से किसी को वोट नहीं देना है. ■

editor@chauthiduniya.com

मंगल अभियान और आधुनिक भारत

मेघनाद देसाई

कांग्रेस एक हथियार था जिसका इस्तेमाल महात्मा गांधी ने जनता के संघर्ष के लिए किया. लेकिन इसका इस्तेमाल उन्होंने अपने तानाशाही नियमों के तहत किया. कांग्रेसियों ने हमेशा गांधी का पालन किया लेकिन उनके नियमों का नहीं. कांग्रेसियों ने गांधी जी के नेतृत्व का स्वागत तो किया, लेकिन सिर्फ़ आज़ादी पाने तक. उसके बाद वे गांधी जी से परे हो गए और कांग्रेस को शासन करने के हथियार की तरह इस्तेमाल किया, जबकि गांधी चाहते थे इसका विलय कर दिया जाए.

लगभग एक शताब्दी पूर्व लंदन में दो भारतीयों की मुलाक़ात हुई. उनमें जो ज्यादा उम्र का था, वह दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीयों के मानवाधिकार के मामले को लेकर वहां पहुंचा था और दूसरा नौजवान ऊर्जा से भरपूर था और भारत से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए समर्पित. दोनों में भारत के भविष्य को लेकर लंबी बहस हुई. नौजवान ने मज्जिनी और गरीबाल्डी के बारे में सूक्ष्मता से अध्ययन किया था. इन लोगों (मज्जिनी और गरीबाल्डी) ने इटली के एकीकरण और उसे स्वंतत्रता दिलाने में बड़ा योगदान किया था. नौजवान मज्जिनी की आत्मकथा का मराठी में अनुवाद करने पर भी विचार कर रहा था. नौजवान चाहता था कि औद्यो-गीकरण और आधुनिकता के मामले में भारत यूरोप का अनुकरण करे. लेकिन उम्रदराज व्यक्ति इस विचार से भयग्रस्त था. वह चाहता था कि भारत आधुनिकता, मशीनों, पश्चिमी दवाओं और शहरीकरण को ख़ारिज करे. उम्रदराज व्यक्ति ने वापस दक्षिण अफ्रीका लौटकर अपनी पहली क़िताब लिखी, जिसमें उन्होंने तर्क दिए कि क्यों भारत को आधुनिक मशीनीकरण को ख़ारिज कर देना चाहिए. यह क़िताब थी हिंद स्वराज.

अगले चालीस वर्षों में दोनों के रास्ते भिन्न रहे. उम्रदराज व्यक्ति राष्ट्रपिता बना और उसे भारत की आज़ादी का श्रेय दिया गया. नौजवान ने अपने तमाम साल एकांत कारावास में गुज़ारे और उसके बाद अपना जीवन लेखन और विचारों को प्रतिपादित करने के लिए समर्पित कर दिया. एक पश्चिमी सभ्यता के पैरोकार और आधुनिकतावादी से वह हिंदू सभ्यता के स्वर्णिम अतीत की तरफ़ लौट गया. उसे उम्रदराज व्यक्ति की हत्या में भी फंसाया गया. उसकी पहचान गुम्न रही और एक विभाजनकारी के रूप में हुई. वहीं उम्रदराज व्यक्ति को अंतरराष्ट्रीय ख्याति मिली.

यह दोनों व्यक्ति थे गांधी और सावरकर, जिन्होंने 1909 में आज़ादी के लिए भारत द्वारा अख्तियार किए जाने वाले रास्ते को लेकर आपस में बहस की थी. गांधी चाहते थे कि कम से कम सरकार और हस्तशिल्प के साथ भारत गांवों का गणतंत्र बने. भारत ने उनकी तो पूजा की, लेकिन उनके सुझाए रास्तों को बुरी तरह नकार दिया. उनके सबसे अच्छे शिष्य जवाहर लाल नेहरू के विचार सावरकर से पूरी तरह मिलते थे. वे भी भारत के लिए आधुनिकीकरण और औद्योगीकरण चाहते थे. मंगलयान को अपने रास्ते भेज कर भारत ने एकबार फिर गांधी के विचारों को नकारकर सावरकर और नेहरू के विचार को चुना है. सावरकर को अब आधुनिकतावादी के बजाए हिंदुत्ववादी के तौर पर पहचाना जाता है. हालांकि, उनकी भारत के बारे महात्वाकांक्षा उसी प्रकार विकासोन्मुखी थी जैसी किसी भी दूसरे की होती है.

कांग्रेस एक हथियार था जिसका इस्तेमाल महात्मा गांधी ने जनता के संघर्ष के लिए किया. लेकिन इसका इस्तेमाल उन्होंने अपने तानाशाही नियमों के तहत किया. कांग्रेसियों ने हमेशा गांधी का पालन किया लेकिन उनके नियमों का नहीं. कांग्रेसियों ने गांधी जी के नेतृत्व का स्वागत तो किया, लेकिन सिर्फ़ आज़ादी पाने तक. उसके बाद वे गांधी जी से परे हो गए और कांग्रेस को शासन करने के हथियार की तरह इस्तेमाल किया, जबकि गांधी चाहते थे इसका विलय कर दिया जाए. सिर्फ़ गांधीवादी ही गांधी के सिद्धांतों में विश्वास करते रहे, लेकिन उनके जाने के बाद गांधीवादियों की कोई क़ीमत नहीं रह गई.

भारत की स्थिति इस समय विश्व में सशक्त रूप में मौजूद है. न केवल इसलिए क्योंकि यह एक आध्यात्मिक और नैतिक शक्ति है, बल्कि इसलिए कि यह आर्थिक और सैन्य ताक़त बन चुका है. मंगल पर भेजा गया यह यान सिद्ध करता है कि अन्य देशों मुक़ाबले तकनीकी दक्षता के मामले में भारत ज्यादा सक्षम है. इस कार्यक्रम की शुरुआत जानबूझकर जवाहर लाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ादी के पहले ही कर दी गई थी जब उन्होंने कांग्रेस की नेशनल प्लानिंग कमेटी की स्थापना की थी. बोस की जगह तो जल्द ही गांधी ने ले ली, लेकिन नेहरू इस कार्यक्रम के साथ लगातार बने रहे. ये नेहरू ही थे जिन्होंने विज्ञान और तकनीक का महत्व समझा. भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप उन्होंने आर्थिक नीतियों के बारे में गांधी के नियमों को दरकिनार अपनी पूरी ताक़त लगा दी थी जिससे आधुनिकता के साथ पूरी रफ्तार के साथ दौड़ा जा सके. नाभिकीय ऊर्जा का महत्व समझ कर भाभा के नेतृत्व में नाभिकीय शोध के एक कार्यक्रम की स्थापना की. साराभाई इस कड़ी में दूसरे वैज्ञानिक थे. साराभाई के संबंध नेहरू और गांधी से उस समय से थे जब गांधी को साबरमती आश्रम को चला पाने में परेशानी महसूस हो रही थी. साराभाई का योगदान भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए अभूतपूर्व है.

यह वही भारत था जो औद्योगिक विकास के साथ हरित क्रांति के लिए भी समर्पित था. इसने आईटी सेक्टर में भी अपनी जगह बनाई. अब इसने अंतरिक्ष कार्यक्रम के भी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई है और सभी बातों से ऊपर पूर्व राष्ट्रपति कलाम हमें इस बात की याद दिलाते हैं कि भारत किस तरह उन लोगों की इज़्ज़त करता है जिन्होंने रक्षा तकनीक के लिए काम किया है. भारतीय राजनीति विकास और तकनीक के साथ-साथ ग़रीबी दूर करने को लेकर एक जनमत बना हुआ है. सावरकर और नेहरू एक दूसरे से उतने ही अलग थे जितने की दुनिया के कोई भी दो व्यक्ति आपस में हो सकते हैं. लेकिन भारत ने इन दोनों के विकास पथ का अनुसरण किया. हम सभी को गांधी के नैतिक साहस और कांग्रेस का नेतृत्व करने के लिए श्रद्धांजलि देनी चाहिए. हमें हिंद स्वराज को पढ़ना तो चाहिए, लेकिन इसे भारत के ब्लूप्रिंट की तरह नहीं देखना चाहिए. ■

feedback@chauthiduniya.com

करीब सात एकड़ भूखण्ड पर पसरे इस अस्पताल के लिए आलीशान भवन भी बनकर तैयार हुआ. इस अस्पताल के लिए लाखों के चिकित्सीय अत्याधुनिक उपकरण भी मंगाए गए. बड़े तामझाम और गाजे–बाजे के साथ 18 सितम्बर 1995 को बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने स्वास्थ्य मंत्री महावीर प्रसाद और क्षेत्रीय विधायक अब्दुल गफूर की मौजूदगी में इस अस्पताल का विधिवत उद्घाटन भी किया था.

रंटु मंडल बदल रहे हैं अररिया के समीकरण

अजातशत्रु अग्रवाल

जनार्दन यादव | लक्ष्मी नारायण मेहता | प्रदीप सिंह | विजय कुमार मंडल | रंटु मंडल

अररिया संसदीय क्षेत्र से भाजपा के दावेदारों में फारबिसगंज के पूर्व विधायक लक्ष्मी नारायण मेहता एवं नरपतगंज के पूर्व विधायक जर्नादन यादव का भी नाम जिले में उछलने लगा है. मेहता एवं यादव दोनों ही अपने-अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर काफी सक्रिय हैं और इसके लिये हर संभव राजनीतिक दांव आजमाने को तैयार हैं.

लोकसभा चुनाव 2014 को लेकर अररिया संसदीय क्षेत्र में लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो चुकी है. आरोप–प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है. प्रतिदिन टिकट के दावेदारों की संख्या भी बढ़ती जा रही है. सभी खुद को एक–दूसरे से बेहतर बताने के होड़ में लगे दिख रहे हैं. वर्तमान में इस सीट पर भाजपा के प्रदीप कुमार सिंह का कब्जा है और भाजपा के लिए इस कब्जे को बनाए रखना काफी मायने रखता है. चुनावी सुगबुगाहट को लेकर भाजपा में संभावित प्रत्याशियों की संख्या बढ़ने लगी है. यही वजह है कि वर्तमान सांसद श्री सिंह के पिछले पांच साल के क्रियाकलापों पर पक्ष एवं विपक्ष में उगलियां उठ रही हैं। जहां सांसद स्वयं अपने विकास कार्य को लेकर अति आत्मविश्वास में हैं और उनके समर्थक इसका जोर–शोर से गुणगान भी कर रहे हैं, वहीं सांसद के विरोधी उनके नकारात्मक पहलुओं को भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के पास उजागर कर रहे हैं।

गठबंधन से अलग होने के बाद भाजपा ने सभी जिलों में विश्वासघात रैली का आयोजन किया. इसी क्रम में जब अररिया जिले की विश्वासघात रैली के दौरान पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी व प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडेय की मौजूदगी में युवा नेता राजा रमण भास्कर उर्फ रंटु मंडल ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, यह चर्चा का विषय बना हुआ है. वहीं राजनीतिक जानकारों का मानना है कि रंटु की जाति के मतदाताओं की संख्या अररिया संसदीय क्षेत्र में लाखों में है और इसका लाभ उन्हें मिल सकता है. इसको लेकर रंटु स्वयं भी काफी उत्साहित हैं। मंडल का उत्साह भाजपा की हुंकार रैली के दौरान भी दिखा. चर्चा है कि रंटु मंडल अपने साथ तकरीबन पांच दर्जन से अधिक चार पहिया वाहनों पर सैकड़ों समर्थकों के साथ पटना पहुंचे थे. जानकारों के अनुसार अररिया संसदीय क्षेत्र के कई दिग्गज भी इस बात का आकलन कर रहे हैं और इसकी जानकारी पार्टी के आला नेताओं तक पहुंचा रहे हैं। मंडल जाति के लोगों की मानें तो उनका कहना है कि वोट हमारा तो प्रतिनिधि भी हमारा होना चाहिए. रंटु मंडल भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता व पूर्व केन्द्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन को अपना आदर्श मानते हैं। गत लोकसभा चुनाव में उन्होंने अररिया संसदीय क्षेत्र का पिछली पांच बार तक प्रतिनिधित्व करने वाले सुकदेव पासवान से ज्यादा मत लाकर काफी चर्चा पाई थी. रंटु पूर्णिया के पंचायती राज पदाधिकारी स्व. राजेन्द्र मंडल के पुत्र हैं और उनकी छवि भी दबंग मानी जाती है. उनके संपर्क प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी मजबूत बताए जाते हैं। लोगों की माने तो मंडल की युवा वर्ग में काफी लोकप्रियता है. वे समाजसेवा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में गहरी रुचि रख युवाओं का हमेशा उत्साहवर्द्धन करते हैं। अररिया संसदीय क्षेत्र को भाजपा का प्रभाव वाला क्षेत्र माना जाता है क्योंकि इस संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले छह विधानसभा सीटों में से चार विधानसभा फारबिसगंज, नरपतगंज, रानीगंज एवं सिकटी में भाजपा के विधायक हैं। वर्तमान में राज्य के पूर्व मंत्री विजय कुमार मंडल जदयू में शामिल हो चुके हैं और इनकी दावेदारी भी जदयू में काफी मजबूत मानी जा रही है.

अररिया संसदीय क्षेत्र से भाजपा के दावेदारों में फारबिसगंज के पूर्व विधायक लक्ष्मी नारायण मेहता एवं नरपतगंज के पूर्व विधायक जर्नादन यादव का भी नाम जिले में उछलने लगा है. मेहता एवं यादव दोनों ही अपने–अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर काफी सक्रिय हैं और इसके लिये हर संभव राजनीतिक दांव आजमाने को तैयार हैं. नरपतगंज के पूर्व भाजपा विधायक जनार्दन यादव का कहना है कि वर्तमान सांसद प्रदीप कुमार सिंह अपने कार्यकाल में न तो दलित–महादलित वर्ग के लिए और न ही आदिवासी–अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोगों के विकास के लिये कोई ऐसा उल्लेखनीय विकास कार्य किया है जिसके दम पर आगामी चुनाव में इन वर्गों का समर्थन प्राप्त होने की संभावना है. ठीक इसी प्रकार फारबिसगंज–सहरसा बड़ी रेल लाइन के परिवर्तन कार्य को लेकर सांसद न ही सक्रिय हैं, जबकि इस रेल खंड पर पूर्व में चलने वाली छोटी रेल लाइन के भी उखाड़ने की वजह से ट्रेन का परिचालन सालों से बंद है. इस कारण लोगों को आवागमन में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है तथा सड़क मार्ग से अधिक किराया देकर यात्रा करनी पड़ती है. यादव का कहना है कि नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र के भाजपा बहुल क्षेत्रों में से बसमतिया, घुरना, फुलकाहा आदि क्षेत्रों के लोगों में भी सांसद के प्रति उत्साह नहीं है क्योंकि बड़े विकास कार्यों की तो बात छोड़ दें, जल निकासी के लिए छोटी–छोटी नालियों का निर्माण भी कराने में सांसद सिंह सफल नहीं हो पाए हैं. बहरहाल यूं तो लोकसभा चुनाव की तिथि की घोषणा नहीं हुई है लेकिन संभावित उम्मीदवार अपने–अपने स्तर पर अपनी–अपनी गोटी सजाने में जुट गए हैं। भाजपा के लिए यह सीट काफी महत्व–पूर्ण है. वजह यह है कि वर्तमान में इस पर इसका कब्जा है और किसी भी सूरत में इस कब्जे को वह खोना नहीं चाहेगी चाहे इसके लिए उसे वर्तमान सांसद के स्थान पर जीतने वाला दूसरा कोई उम्मीदवार ही चुनावी मैदान में उतारना पड़े. इसके लिए प्रदेश के आलाधिकारी भी गुप्त रूप से जिला से लेकर प्रखंड एवं पंचायत कमेटियों से जीतने वाले प्रत्याशियों की फीडबैक प्राप्त करवा रहे हैं. बहरहाल अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी क्योंकि आने वाले कुछ महीनों के उपरांत ही अररिया जिले से भाजपा के संभावित प्रत्याशी के नाम का खुलासा हो पाएगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

चंपारण

मुसलमानों को रिझाने की हो रही है कोशिश

इन्तेजारुल हक

मोतिहारी परिसदन में भारत सरकार के पूर्व मंत्री अशरफ अली फातमी

चंपारण का राजनीतिक तापमान इन दिनों काफी बढ़ गया है और सियासत की दुकानें सजने लगी हैं. अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को पाने या फिर जनता के करीब जाने के लिए आए दिन नेता व कार्यकर्ता नए–नए तरीके अपना रहे हैं. स्थिति यह है कि सत्ताधारी नेताओं के साथ–साथ अन्य दलों के नेताओं की भी आवाजाही अगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तेज हो गई है. शहर से लेकर पंचायत के क्षेत्रों में भी नेता बिना ढूंढ़े ही मिल जाएंगे. किसी भी प्रकार से हर कोई यह जताने की कोशिश में लगा दिखता है कि वही चंपारण की जनता के सबसे करीब है. लेकिन चंपारण में इनदिनों राजनीति की दो ही धारा देखने को मिल रही हैं, एक नरेंद्र मोदी के पक्ष की तो दूसरी विरोध की.

राजद मुस्लिम वोटरों को नरेन्द्र मोदी का भय दिखाकर फिर से उन्हें अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रही है. इसी लिहाज से राजद आगामी 14 दिसम्बर को मोतिहारी में विशाल मुस्लिम सम्मेलन कराने की तैयारी कर रही है. वहीं भाजपा अपने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेन्द्र मोदी के नाम पर जनता को अपनी ओर आकर्षित करने में जुटी हुई है. कहीं नरेन्द्र मोदी के नाम पर नमो टी–स्टॉल खुलवाया जा रहा है तो कहीं नमो क्रिकेट मैच कराकर युवाओं को आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है. भाजपा के स्थानीय सांसद राधामोहन सिंह, विधायक प्रमोद कुमार, सचिन्द्र सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष सुनिल मणि तिवारी, पूर्व जिलाध्यक्ष पंडित चन्द्रकिशोर मिश्रा, राजेन्द्र गुप्ता आदि भाजपा के नेता इस मुहिम में लगे हुए हैं और केन्द्र की यूपीए सरकार पर निशाना साधते हुए जनता से सीधा जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष व भारत सरकार के पूर्व मानव संसाधन मंत्री अशरफ अली फातमी के चंपारण दौरे के बाद राजद के नेता काफी सक्रिय हो गए हैं और मुस्लिम सम्मेलन में ऐतिहासिक भीड़ जुटा कर अन्य दलों को अपनी शक्ति का एहसास दिलाने में जुटे हुए हैं. राजद के वरिष्ठ नेता डा. शमीम अहमद, मुख्तार आलम, युवा राजद के जिलाध्यक्ष ई. एहतेशाम अहमद, नसीमा खातुन, इमादुल हक खां के साथ–साथ राजद जिलाध्यक्ष बच्चा प्रसाद यादव, मोतिहारी विधान सभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी राजेश गुप्ता उर्फ बब्लू गुप्ता व मुन्नी लाल यादव आदि इस मुहिम की कमान संभाले हुए हैं. हालांकि इस सम्मेलन में मुसलमानों की कितनी भीड़ जमा होगी और इसका राजनीतिक असर क्या होगा यह तो समय बताएगा किन्तु अभी से ही तमाम राजनीतिक दलों की नजर इस सम्मेलन पर लगी हुई हैं. वहीं सत्ताधारी दल जदयू भी सरकार की उपलब्धियों को मुद्दा बनाकर जनता के बीच पहुंच रही है और जनता को एक बार फिर अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रही है. साथ ही यहां भी जदयू नरेंद्र मोदी पर तीखे प्रहार करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है. दूसरी तरफ युवा जदयू के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व राज्य सभा सांसद स्वर्गीय मतीउर्रहमान के पुत्र फैसल रहमान द्वारा स्थानीय नगर भवन के मैदान में आयोजित अखिल भारतीय मुशायरा व कवि सम्मेलन में उमड़ी ऐतिहासिक भीड़ व मुशायरे की कामयाबी की चर्चा भी राजनीतिक गलियारों में हो रही है. चर्चा है कि इस मुशायरे से जदयू को काफी लाभ हुआ है. कुल मिलाकर चंपारण की राजनीति इन दिनों काफी तेज है और लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं. स्थिति यह हो गई है कि भ्रष्टचार व महंगाई जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर अधिकांश दलों के नेताओं ने अभी से ही अपनी चुप्पी साध ली है और राजनीति मुसलमानों को रिझाने और नरेंद्र मोदी तक ही केंद्रित हो गई है.■

अवधेश कुमार शर्मा

अनाथालयों की त्रिवेणी है बेतिया

अनाथ बच्चों के पालन–पोषण और उनकी बेहतर जिंदगी के लिए पश्चिम चंपारण का बेतिया शहर जाना जाता है. इस शहर को अनाथालयों की त्रिवेणी भी कहा जाता है. पूरे बिहार का यह पहला ऐसा शहर है जहां तीन अनाथालय हैं और तीनों का इतिहास अपने आप में अद्भुत है.

सबसे पहले यहां होलीक्रॉस सोसाइटी द्वारा बानुछापर में 'फकीराना' नाम से अनाथ आश्रम की स्थापना की गई. होलीक्रॉस सोसाइटी की धर्म बहनों ने रोग पीड़ित व्यक्तियों की सेवा व चिकित्सा के साथ अनाथ बच्चों की जिम्मेदारी भी अपने कंधों पर उठाई. बच्चों के लिए भोजन, वस्त्र, चिकित्सा और शिक्षा की व्यवस्था की गई. होलीक्रॉस सोसाईटी की तर्ज पर मुस्लिम समुदाय ने भी 20 वीं सदी के तीसरे दशक में यतीमखाना स्थापित किया. बेतिया नगर थाना के समीप 1928 में यतीमखाना बदरिया का निर्माण किया गया. यतीमखाने की स्थापना का श्रेय तत्कालीन सामाज सेवी मौलाना मो. शाहदुल्लाह महमूदी बेतियावी को जाता है. शुरुआती दौर में 25 लड़कियों समेत 75 अनाथों की रहने की व्यवस्था की गई. आगे चलकर लोगों ने चम्पारण के विभिन्न हिस्से में इस यतीमखाना के नाम से लगभग 15 बीघा जमीन जकात स्वरूप दी. इस जमीन की उपज से यतीमों का भरण–पोषण आसानी से चलने लगा. यतीमखाना बदरिया के यतीम बच्चों की तालीम के लिए सरकारी प्राथमिक विद्यालय संचालित है. निजी स्तर पर लड़कियों के लिए हाई स्कूल की स्थापना की गई है.

इसाई और मुस्लिम समुदाय के सेवा–भाव से प्रभावित हो कर हिन्दुओं में भी अनाथालय खोलने की इच्छा हुई. बड़ा रमना के दक्षिण बेतिया राज की जमीन पर 10 अक्टूबर 1946 को श्री विशेश्वरनाथ हिन्दू अनाथालय की स्थापना की गई. बेतिया राज द्वारा बसाए गए व्यवसायी विशेश्वरनाथ के पुत्र मदनलाल अग्रवाल ने अनाथालय की स्थापना का सराहनीय काम किया. उन्होंने अनाथ बच्चों के पालन–पोषण तथा अनाथालय को स्वावलंबी बनाने के इद्देश्य से 55 बीघा भूमि दान स्वरूप दी, जिसमें बागीचे भी हैं. इसके बाद 5 सदस्यीय ट्रस्ट बनाकर अनाथलय संचालन का दायित्व ट्रस्ट को सौंप दिया गया. यहां 18 वर्ष की आयु के लड़कों और 15 वर्ष आयु की लड़कियों को रखने की व्यवस्था है. ■

अस्पताल बना, उद्घाटन हुआ और ताला लटक गया

मनोज ठाकुर

प्रशासन की लापरवाही, बदइंतजामी और सरकारी पैसे के दुरूपयोग का नजारा देखना है तो चले आइए सहरसा के चंद्रायण रेफरल अस्पताल में. लोग इसे भुतहा अस्पताल भी कहते हैं. बता दें कि पूर्वी और पश्चिमी तटबंध के भीतर बसी सहरसा और सुपौल जिले की करीब 15 लाख की आबादी के लिए आवागमन का एक मात्र साधन नाव है. लोगों को इस पार से उस पार जाने में घंटों के वक्त लगता है. ऐसे में मुसीबत तब भयावह हो जाती है जब लोग बीमार होते हैं. यही वजह है कि समय से इलाज नहीं होने की वजह से अधिकांश लोग असमय मृत्यु के शिकार हो जाते हैं.

इलाके के लोगों को स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा मिलने के ख्याल से जिले में करीब 14 करोड़ की लागत से नवहट्टा प्रखण्ड के चन्द्रायण स्थित पूर्वी तटबंध के किनारे पर रेफरल अस्पताल का निर्माण कराया गया. करीब सात एकड़ भूखण्ड पर पसरे इस अस्पताल के लिए आलीशान भवन भी बनकर तैयार हुआ. इस अस्पताल के लिए लाखों के चिकित्सीय अत्याधुनिक उपकरण भी मंगाए गए, बड़े तामझाम और गाजे–बाजे के साथ 18 सितम्बर 1995 को बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने स्वास्थ्य मंत्री महावीर प्रसाद और क्षेत्रीय विधायक अब्दुल गफूर की मौजूदगी में इस अस्पताल का विधिवत उद्घाटन भी किया था. लेकिन ठीक अगले ही दिन 19 सितम्बर 1995 को इस अस्पताल में यह कहकर ताले जड़े गए की यहाँ पर एक सप्ताह के बाद डॉक्टर और चिकित्साकर्मी आएंगे. लेकिन वर्षो बीत गए, सरकारें बदल गईं पर आजतक इस अस्पताल में वह समय नहीं आया कि इसके ताले खुल पाते. अबतक यहां न कोई डाक्टर और न ही किसी कर्मी की ही पदस्थापना ही हुई. महज नाम भर के इस अस्पताल को लोग अब भूत बंगला कहने लगे हैं. स्थिति यह है कि अब यह धीरे–धीरे खंडहर में तब्दील होते जा रहा है. अब तो यहां के लोग भी यह उम्मीद छोड़ चुके हैं कि इस अस्पताल के दिन कभी बहुरेंगे.

अस्पताल में बंद कुछ मंहगे उपकरणों की चोरी हो गई तो बचे उपकरण जंग के हवाले है. पूरा भवन जर्जर हो चुका है और परिसर की स्थिति तो और भी खराब है. इसका निर्माण तो राजद के शासनकाल में हुआ लेकिन इलाके के लोग नीतीश सरकार से भी नाराज देखे जा रहे हैं. लोगों का कहना है कि नीतीश इतने सालों के शासनकाल में भी इस अस्पताल को चालू नहीं करवा पाए तो किस बात का विकास. प्रणव राधव, जिला पार्षद प्रवीण आनन्द, अतीउल्लाह कारी, सत झा, छोटे लाल राम और मुखिया मनोज पासवान आदि लोगों ने बताया कि अब इलाके के मरीजों को मुख्यालय या कहीं दूरस्थ इलाके में ले जाना पड़ता है जिस क्रम में कइयों की मौत भी हो जाती है. स्थिति यह है कि स्थानीय लोग विभागीय उदासीनता और सरकार के उपेक्षापूर्ण रवैये से परेशान होकर आंदोलन करने के मन बना रहे हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

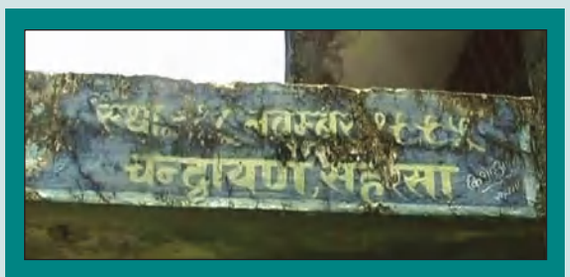

अस्पताल में बंद कुछ मंहगे उपकरणों की चोरी हो गई तो बचे उपकरण जंग के हवाले हैं. पूरा भवन जर्जर हो चुका है और परिसर की स्थिति तो और भी खराब है. इसका निर्माण तो राजद के शासनकाल में हुआ लेकिन इलाके के लोग नीतीश सरकार से भी नाराज देखे जा रहे हैं.

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

25 नवंबर- 01 दिसंबर 2013

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467

उत्तर प्रदेश- उत्तराखंड

अजय कुमार

माया की योजनाओं पर चला सपा का डंडा

समाजवादी सरकार ने एक बार फिर बसपा सुप्रीमो मायावती को करारा झटका दिया है. सत्ता में रहते माया के ड्रीम प्रोजेक्ट्स ने सुर्खियां बटोरी थीं तो सत्ता से बेदखल होने के बाद माया शासनकाल की चार ड्रीम योजनाओं को राज्य सरकार ने सीधे अपने हाथ में लेकर बसपा से टकराव मोल ले लिया है. रमाबाई अम्बेडकर मैदान, कांशीराम ग्रीन गार्डेन एवं जन सुविधा परिसर, बौद्ध विहार तथा शांति उपवन को अखिलेश सरकार लाल बत्ती से नवाजे गए माननीयों के आलीशान दफ्तरों में बदलने जा रही है. इसके लिए सरकार की तरफ से गाइड लाइन भी तय कर दी गई है. अभी तक उक्त स्मारकों, संग्रहालयों, पार्कों और उपवनों का रख-रखाव, प्रबंधन और सुरक्षा एवं अनुरक्षण के लिए बनी समिति के पास था. नई व्यवस्था के तहत चारों प्रोजेक्ट के रख-रखाव की जिम्मेदारी राज्य सम्पत्ति विभाग के पास होगी. बसपा ने इस पर कड़ा विरोध जताया है, लेकिन सपा सरकार अपने फैसले से टस से मस नहीं हुई है. हां, यह जरूर है कि माया के ड्रीम प्रोजेक्ट में किसी भी तरह का स्थायी निर्माण और परिवर्तन नहीं किया जाएगा. बताते चलें की अखिलेश यादव ने सत्ता हासिल करने के बाद ही कह दिया था कि माया राज में बने स्मारकों, पार्कों तथा संग्रहालयों को जनोपयोगी बनाया जाएगा, जिसको लेकर लंबे समय से सरकार में मंथन भी चल रहा था. एक तरफ स्मारकों आदि के कमरे मंत्रियों को कार्यालय बनाने के लिए दे दिए गए हैं तो दूसरी तरफ एक अन्य अहम फैसले में बसपा राज की 11 परियोजनाओं की फाइलें भी बंद कर दी गई हैं. आने वाले दिनों में माया की स्वप्निल इमारतों में सपा का झंडा, लाल बत्ती लगी गाड़ियां दौड़ती दिखेंगी तो बसपा शासनकाल की 11 परियोजनाओं पर डंडा चलने से सपा-बसपा के बीच की खाई और भी गहरा गई है.

माया राज के तमाम निर्णयों को बदलने में लगी सपा सरकार ने बसपा काल में शुरू की गई 11 बड़ी परियोजनाओं को भी बंद करके ठंडे बस्ते में डाल दिया है. यह सभी परियोजनाएं मायावती सरकार में बनी थीं, जो लखनऊ के अलावा कानपुर, गाजियाबाद, वाराणसी, इलाहाबाद तथा आगरा में प्रस्तावित थीं.

पहले बात माया के ड्रीम प्रोजेक्ट कहलाने वाले इन स्मारकों आदि में मंत्रियों के कार्यालय बनाने की. सपा सरकार में मंत्री का दर्जा हासिल करीब दो दर्जन नेताओं को इसमें कार्यालय आवंटित किए गए हैं. सात दर्जा हासिल मंत्रियों के कार्यालय कांशीराम ईको ग्रीन गार्डेन में होंगे. सरकार की मंशा के अनुरूप नए कार्यालय बनाने के लिए स्मारक के अफसरों को अपना सामान समेटने का आदेश दे दिया गया है. मायावती सरकार में बने स्मारकों की देखरेख के लिए लगभग 6500 कर्मचारी व अधिकारियों की भर्ती हुई थी. उनके बैठने के लिए स्मारकों में हुई वातानुकूलित भी बनाए गए थे. उनको अब नई जिम्मेदारी सौंपी जाएगी.

कांशीराम ईको ग्रीन गार्डन के प्रशासनिक भवन के एक ब्लाक में सात मंत्री का दर्जा हासिल नेताओं के कार्यालय बनेंगे तो दूसरे ब्लाक को भी कार्यालय के लिए देने का आदेश हो गया है. कांशीराम स्मारक व बौद्ध बिहार शांति उपवन में बने दफ्तरों को भी खाली करा लिया गया है. इस संबंध में फैसला 24 अक्टूबर को मुख्य सचिव जावेद उस्मानी की अध्यक्षता में हुई बैठक में पहले ही लिया जा चुका है.

मंत्री का दर्जा प्राप्त जिन नेताओं को कार्यालय आवंटित किए गए हैं उसमें व्यावसयिक शिक्षा परिषद के सलाहाकार फरजन्द अहमद, सामान्य प्रशासन विभाग में सलाहाकर डॉ पीके राय, राजनीतिक पेंशन विभाग के सलाहकार हनुमान प्रसाद, जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान के अध्यक्ष मनोज राय धूपचण्डी, सामान्य पारिश्रमिक सलाहकार समिति की सलाहकार विद्यावती राजभर, हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग के सलाहकार मोहम्मद तौकीर दजा खां, बेसिक शिक्षा विभाग की सलाहकार जिया खान,

समाज कल्याण विभाग के सलाहकार नईमुल हसन आयुष विभाग के सलाहकार कृष्णपाल सिंह और सार्वजनिक उद्यम विभाग के सलाहकार राम सिंह राणा भी शामिल हैं. रमाबाई रैली स्थान के पास बने भव्य वी-वीआईपी गेस्ट हाउस व स्मारकों के कर्मचारियों के लिए बने आवास को सरकार ने राज्य संपत्ति विभाग को देने का आदेश बीते माह (नवंबर) के मध्य में दिया था.

माया राज के तमाम निर्णयों को बदलने में लगी राज्य सरकार ने इसके साथ ही एक अन्य अहम फैसले में बसपा काल में शुरू की गई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फार्मूले पर आधारित 11 बड़ी परियोजनाओं को भी बंद करके ठंडे बस्ते में डाल दिया है. यह सभी परियोजनाएं मायावती सरकार में बनी थीं, जो लखनऊ के अलावा कानपुर, गाजियाबाद, वाराणसी, इलाहाबाद तथा आगरा में प्रस्तावित थीं. आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की इन सभी योजनाओं की अनुमानित लागत करीब बीस अरब रुपये थी.

राज्य में सत्ता की बागडोर बदलते ही इन योजनाओं का कामकाज वैसे तो तभी से रुक गया था, लेकिन औपचारिक रूप से कोई फैसला न होने के कारण सरकारी फाइलों में फिलहाल सभी योजनाएं चल रही थीं और उनकी समीक्षा रिपोर्ट भी बनती थी. बताते हैं कि अखिलेश सरकार की तरफ से इन योजन-ाओं को बंद करने का औपचारिक तौर पर निर्णय लेने के बाद अब इन योजनाओं की फाइलें भी बंद हो गई हैं. अब न तो इनकी समीक्षा होगी और न ही संबंधित विकास प्राधिकरणों से रिपोर्ट मांगी जाएगी.

बात उक्त योजनाओं की करें तो दक्षिण राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश में भी विकास की गाड़ी दौड़ाने के लिए माया सरकार ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का फार्मूला ईजाद किया था और सबसे पहले आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की डेढ़ दर्जन परियोजनाओं को इसके तहत मंजूरी मिली थी. सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, पार्किंग, रिंग रोड तथा ट्रांसपोर्ट नगर बसाने की इन योजनाओं का नाम बसपा संस्थापक कांशीराम के नाम पर रखा जाना था. वैसे जमीनी हकीकत की बात कि जाए तो बसपा सरकार में इन सभी परियोजनाओं में कागजों पर खूब काम हुआ था, लेकिन इसके लिए कोई निवेशक नहीं मिलने पर यह योजनाएं अमली जामा नहीं पहन पा रही थीं. जिन 11 परियोजनाओं को बंद किया गया है, इसमें राजधानी लखनऊ, कानपुर, मेरठ और आगरा में एक-एक सुपर स्पेशियलिटी हास्पिटल एवं मेडिकल कालेज की परियोजनाएं प्रमुख थीं. इसमें आगरा के मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल को छोड़कर प्रत्येक की लागत 350-350 करोड़ थी. आगरा की परियोजना सौ करोड़ की थी. इन परियोजनाओं में निवेशक को एक रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर पर लीज पर जमीन दी जानी थी.

राजनीतिक पंडित इसे बसपा-सपा की आपसी रंजिश से जोड़कर देख रहे हैं. इन लोगों का कहना है कि दोनों ही सत्ता हासिल करते ही बदले की राजनीति शुरू कर देते हैं. आज जो अखिलेश सरकार कर रही है, वही काम माया ने 2007 में विधान सभा चुनाव जीतने के बाद किया था. बदले की राजनीति के कारण ही राज्य में जब सपा सरकार आई तो कांशीराम शहरी गरीब आवास योजना कांशीराम बालिका शिक्षा योजना, कांशीराम समग्र विकास योजना सहित तमाम योजनाओं को बंद करने का फैसला हुआ और उनके स्थान पर नई योजनाएं लाई गई हैं. शासन के हवाले से पता चलता है कि माया राज की इन सभी परियोजनाओं का परीक्षण कराने के बाद राज्य सरकार ने अनुपयोगी माना है.

बसपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश सरकार पर बदले की भावना से कार्रवाई करने का आरोप लगाते हुए कहा कि समाजवादी नेताओं को दलितों के प्रेरणा स्थल रास नहीं आते हैं, यह उनकी दलित विरोधी मानसिकता की परिचायक है. जानबूझ कर दलितों का नामोनिशान मिटाया जा रहा है. ऐसी तानाशाह सरकार को दलित जनता चुनावों के समय करारा जबाव देगी. ■

feedback@chauthiduniya.com

सपा को पिछड़ों से आस

रवि प्रकाश

समाजवादी पार्टी के रणनीतिकारों को लगता है कि 2014 के लोकसभा चुनाव के समय उसका पिछड़ा कार्ड वोट दिलाने वाला साबित होगा. सामाजिक न्याय और 17 पिछड़ी जातियों की अधिकार यात्रा की सफलता से शीर्ष नेतृत्व उत्साहित है. यात्रा के जगह-जगह स्वागत से सपाइयों के हौसले बुलंद रहे तो यात्रा की सफलता ने विपक्षियों की आंखों में चुभन पैदा कर दी है. राजनीतिक पंडितों को भी लगता है कि सपा का पिछड़ा कार्ड चुनावी नतीजों का रुख बदल सकता है. वैसे, भी मुजफ्फनगर दंगों के बाद सपा अपने वोट बैंक को लेकर काफी आशंकित है. उसे डर सता रहा है कि कहीं उसका मुस्लिम प्रेम पिछड़ों को इससे दूर न कर दें. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट मतदाता तो सपा के खिलाफ हौसले बुलंद किए हुए हैं ही, अन्य कुछ बिरादरियों के लम्बरदारों को भी सपा का मुस्लिम प्रेम रास नहीं आ रहा है. प्रदेश की आधी से अधिक आबादी पिछड़ों की है और भाजपा, कांग्रेस, बसपा सभी की उन पर नजर लगी है. सपा तो पिछड़ों को प्रोन्नति में आरक्षण के नाम पर काफी समय से सियासत कर रही है. भाजपा और बसपा भी इधर कुछ दिनों से पिछड़ों को साधने के लिए अपने तरकश से नए-नए तीर निकाल रहे हैं. फिलहाल यह वोट बैंक किधर जाएगा, इसको लेकर कोई पुख्ता दावा फिलहाल नहीं किया जा सकता है. खासकर भाजपाइयों द्वारा यूपी में मोदी को विकास पुरुष के अलावा पिछड़ा वर्ग के नेता के तौर पर पेश किए जाने से सपा बेचैन चल रही है.

भारत की कुल जनसंख्या में 56 प्रतिशत भाग पिछड़ी किसान जातियों का है. करीब-करीब यही प्रतिशत यूपी में भी है. पिछड़ों को आरक्षण की राजनीति की बात की जाए तो यह काफी पुरानी है. पिछड़ों को आरक्षण दिए जाने की मांग सर्वप्रथम समाजवादी नेता डॉ. राम मनोहर लोहिया ने उठाई थी. उन्होंने नारा दिया था सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, सौ में पाए पिछड़े साठ, देश में सबसे पहले मण्डल कमीशन की रिपोर्ट को मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश में लागू किया था, जिसकी वजह से पिछड़े वर्गों को 27 प्रतिशत नौकरी में

आरक्षण देकर और पंचायती राज में संशोधन कर स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्गों को 27 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व देकर उन्हें मजबूत किया. यही नहीं पहली बार शिक्षा में पिछड़े वर्गों के नौजवानों को सरकारी नौकरियों के योग्य बनाया. सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं को मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था के लिए फीस की प्रतिपूर्ति एवं वजीफा तथा लड़कियों के लिए शादी अनुदान, बीमारी अनुदान तथा बेकार नौजवानों को कम्प्यूटर ट्रेनिंग एवं अन्य योजनाओं के माध्यम से आर्थिक अनुदान देकर उन्हें स्वावलम्बी बनाने का कार्य समाजवादी पार्टी की सरकार में किया गया.

लोकसभा में पिछड़ों को प्रोन्नति में आरक्षण संबंधी बिल का समर्थन मुलायम ने किया था, यह कहना गलत नहीं होगा कि आजकल सियासत के नाम पर अगड़े एवं पिछड़े वर्गों तथा मुस्लिमों और अनुसूचित जाति वर्गों के बीच सामाजिक विषमता व विद्वेष फैलाकर लड़ाने का काम राजनेताओं द्वारा खूब किया जा रहा था. पिछड़े वर्ग की अन्य पिछड़ी जातियों की सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति अनुसूचित जातियों से भी बुरी है. उनको समाजवादी पार्टी ने अनुसूचित जाति में मिलाने का फैसला लिया था. मुलायम सिंह यादव ने अपने मुख्यमंत्रित्वकाल में 10 अक्टूबर 2005 को अध्यादेश द्वारा राजभर, निशाद, प्रजापति, मल्लाह, कहार, कश्यप, कुम्हार, धीमर, बिन्द, भर, केवट, धीवर, बाथम, मछुआ, मांझी, तुरहा, गौड़ को अनुसूचित जाति की भांति सुविधाएं देना प्रारम्भ कर दिया था.

बसपा सरकार ने 2007 में ये सारे लाभ छीन लिए. पुन: 2012 में समाजवादी पार्टी सरकार बनने पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कैबिनेट और विधान मण्डल में प्रस्ताव पारित कराकर केन्द्र सरकार को भेजा है. सपा नेता और प्रवक्ता राजेन्द्र चौधरी कहते हैं कि यह बिडम्बना है कि भाजपा और बसपा के साथ कांग्रेस ने भी पिछड़ों और अति पिछड़ों के हितों पर गम्भीर चोट पहुंचाई है और आज वे उनके पक्ष में खड़े होने पर समाजवादी पार्टी पर हमलावर हो रहे हैं. तीनों की मिलीभगत से एक बड़ी जनसंख्या को उसके हक से वंचित रहना पड़ा है. समाजवादी पार्टी ने हमेशा सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्धता जताई है. मुलायम सिंह यादव ने तो उसके लिए वर्षो संघर्ष किया और जेल यातना भी भोगी. जिन्होंने कुछ नहीं किया, वे दिखावे के लिए नाटक कर रहे हैं.

चुनावी बेला में उत्तर प्रदेश में पिछड़ों को आरक्षण और विरोध स्वर का हर तरफ सुनाई दे रहा है तो इसे इत्तेफाक नहीं कहा जा सकता है. बसपा प्रोन्नति में आरक्षण के खिलाफ है तो अदालत ने कुछ समय पूर्व सम्पन्न पिछड़ों का कोटा बढ़ाने की सपा की मुहिम को झटका दिया था. ऐसे में इस संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि लोकसभा चुनाव में पिछड़ा कार्ड काफी अहम साबित होगा. वैसे भी प्रदेश में करीब आधी आबादी पिछड़ों की ही है. सपा चाहती थी कि 2014 के लोकसभा चुनाव से पूर्व केन्द्र सरकार पिछड़ों को प्रोन्नति में आरक्षण के मामले में संसद में कानून बना दे, ताकि सपा उसका फायदा उठा सके, लेकिन बसपा के विरोध के चलते सपा को मुंह की खानी पड़ गई थी. ■

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

आवश्यकता है

संवाददाता, विज्ञापन प्रतिनिधि, प्रसार प्रतिनिधि

चौथी दुनिया के लिए उत्तर प्रदेश के सभी मंडल और जिला मुख्यालयों पर अनुभवी संवाददाताओं, विज्ञापन और प्रसार प्रतिनिधियों की. पारिश्रमिक योग्यता अनुसार. शीघ्र आवेदन करें.

E-mail- konica@chauthiduniya.com
ajaiup@chauthiduniya.com
चौथी दुनिया F-2, सेक्टर 11, नोएडा
(गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश-201301,
PH : 120-6450888, 6451999

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

नौकरानी हत्याकांड

सांसद पत्नी की क्रूरता

दर्शन शर्मा

जौनपुर के बसपा सांसद धनंजय सिंह की नौकरानी की हत्या उनके लिए जी का जंजाल बन गई है. हालांकि इसके पहले वह कई ऐसे मामलों में साफ बचते आए हैं. उनके विरुद्ध एक मामला पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान तब आया था, जब जौनपुर से इंडियन जस्टिस पार्टी के प्रत्याशी बहादुर सोनकर की हत्या हुई थी. सोनकर की लाश बबूल के पेड़ से लटकती पाई गई थी. तत्कालीन बसपा सरकार ने इसकी जांच सीबीसीआइडी के सुपुर्द कर दी थी. एक अन्य मामले में बसपा सरकार ने उन्हें दोहरे हत्याकांड में जेल भेजा था. 2001 में स्वास्थ्य विभाग के परिवार कल्याण महानिदेशक डा. बच्ची लाल हत्याकांड के आरोप भी उन पर लगे थे, लेकिन सुबूत के अभाव में वे छूट गए. लेकिन नौकरानी की हत्या सांसद और उनकी पत्नी पर भारी पड़ रही है.

पुलिस पूछताछ में नौकरानी मीना के बयानों ने सांसद की सारी दबंगई काफूर कर दी है. मीना ने मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान दिये हैं, वे रोंगटे खड़े करने वाले हैं. मीना ने बताया कि सांसद का तीन वर्ष का बेटा अगर पेशाब करते वक्त रो जाता, तो जो नौकर या नौकरानी इसे पेशाब कराने ले जाता था, उसे पेशाब पीने पर मजबूर किया जाता था. इतना ही नहीं ठीक से खाना नहीं बनाने पर जागृति ने झाड़ू से पिटाई करके उसके बाल तक काट दिये थे. मीना ने बताया कि एक बार राखी को इतना मारा गया था कि डंडा ही टूट गया था. सांसद भी मारपीट करते थे, हालांकि वह क्रूर तरीके से नहीं पीटते थे. लेकिन उन्होंने जागृति को कभी रोकने का प्रयास नहीं किया. शायद वह ऐसा पत्नी के डर से नहीं करते थे. मीना के इन बयानों से सांसद दंपत्ति की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं. पुलिस सांसद के खिलाफ हत्या के षड़यंत्र में शामिल होने की और जागृति पर पोक्सो व यौन शोषण की धाराएं लगाने पर विचार कर रही है. दिल्ली की पटियाला हाउस की एक अदालत में दाखिल अर्जी में कैमरों के फुटेज व हार्ड डिस्क का डाटा सुरक्षित रखने के आदेश देने की मांग की गई है.

सांसद व उनकी पत्नी जागृति सिंह पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिए गए थे. धनंजय सिंह पर सबूत मिटाने तथा जागृति पर हत्या, जानलेवा हमला व जेजे एक्ट की धारा 23 व 26 लगाई गई है. बहरहाल पुलिस धनंजय सिंह के साइथ एवेन्यू स्थित आवास से बरामद एक वीडियो रिकार्डर की क्लीपिंग प्राप्त करने की कोशिश कर रही थी. पुलिस ने सिर्फ छड़ी, सरिया, हिरण की सींग और अन्य चीजें पाई हैं, जिनका इस्तेमाल नौकरानी की प्रताड़ना में किया जाता था. तीन डॉक्टरों के पैनल द्वारा किए गए पोस्टमार्टम की जांच में 40 वर्षीय राखी के चेहरे, सिर, छाती, कूल्हे, तलवे पर चोटों के निशान पाए गए हैं. उसके शरीर एवं हाथ पर ऐसे निशान थे, जो गर्म पानी डालने के बाद होते हैं. उसके शरीर पर प्रेस से जलाने के निशान मिले हैं. रिपोर्ट यह बताती है कि राखी की मौत पिटाई की वजह से हुई है. ■

सांसद पत्नी ने पार कर दी हैवानियत की हद

राकेश पान्डेय

स्त्री शब्द सुनते ही जेहन में एक मां, बेटी या बहन जैसे रिश्तों के ममतामयी अक्स उभर आते हैं. इन रिश्तों के बारे में कभी नकारात्मक विचार दिमाग में आते ही नहीं, लेकिन अफसोस! अब वह सब होने लगा है जिसके बारे में आप कभी कल्पना भी नहीं करते थे. उत्तर प्रदेश के जौनपुर जनपद के बाहुबली सांसद धनंजय सिंह की पत्नी जागृति सिंह के बारे में आजकल छप रही खबरें कुछ ऐसी ही चुगली करती हैं. धनंजय सिंह और विवादों का तो चोली दामन का रिश्ता रहा है, लेकिन उनकी डाक्टर पत्नी डेन्टिस्ट हैं और दिल्ली के नामचीन राममनोहर लोहिया अस्पताल में नियुक्त है. जाहिर है वह कभी सुर्खियों में नहीं रही, लेकिन पिछले दिनों उनके आवास पर एक नौकरानी के मर्डर के बाद जो बातें सामने आ रही हैं, उसे सुनने के बाद यही समझ में आता है कि डाक्टर साहिबा जेहनी तौर पर बीमार हैं और उनका इलाज किए जाने की जरूरत है. आप हमारे कहने पर मत जाइये, सांसद दम्पत्ति के अत्याचार की शिकार हुई नौकरानी राखी की दर्दनाक कहानी पर गौर कीजिए, राखी तो जुल्म सहने के साथ इस दुनिया से रुखसत हो गई लेकिन एक अन्य मेड मीना और नाबालिग नौकर ने धनंजय और जागृति के जुल्मो-सितम दास्तां सुनाकर सबको हैरत में डाल दिया है. मीना हास्पिटल में एडमिट है और नौकर जो फरार है, खौफ के साये में है उनके बदन पर गर्म प्रेस से दागे जाने और डन्डे से पीटे जाने के निशान बताते हैं कि जागृति के भीतर की स्त्री अपनी सारी संवेदनाएं खो चुकी थी. पुलिस को दिए अपने बयान में धनंजय ने कहा है कि राखी की हत्या के बाद जागृति ने उन्हें फोन कर बुलाया था और कहा था कि नहीं आए तो मैं तीन साल के अपने बेटे की हत्या कर दूंगी. इससे साबित होता है कि ये औरत इन्सान कहे जाने के लायक भी नहीं है. सांसद और उनकी पत्नी की क्रूरता ने घरेलू नौकरों की जिन्दगी के दर्द को उभार कर रख दिया है. इस कांड ने इस कमजोर तबके की वकालत करने वालों का दावा करने वालों की पोल खोल दी है. महानगरों में मेड्स को एजेन्सीज के थ्रू हायर किया जाना आम है. एजेन्सी वाले अपना कमीशन लेने के बाद बेफिक्र हो जाते हैं. इन नौकरों की न तो उन्हें कोई चिन्ता होती है और न ही सिस्टम को हम संसद से लेकर तमाम जगहों पर चाइल्ड लेबर से लेकर घरेलू नौकरों के हित संरक्षण की बात तो करते हैं लेकिन सच्चाई यह है कि इस तबके के दर्द भरी कहानी खाड़ी देशों में काम कर रहे गुलामों से कम नहीं है. वक्त की यह मांग है कि इस सांसद दम्पत्ति के इलाज के बहाने ही कुछ ऐसा किया जाए कि एक नौकर को गुलामी से मुक्ति मिल जाए. ■

किसान और मुसलमान पर मेहरबान मुलायम

दर्शन शर्मा

राजनीतिक अखाड़े में सामने वाले को पटकनी देना मुलायम सिंह का पुराना शौक रहा है. धुरंधर पहलवान रहे मुलायम सिंह अटूट विश्वास और ध्येय, धैर्य के धनी माने जाते हैं. अपनी इसी पहचान की बदौलत सपा प्रमुख ने उत्तर प्रदेश में नरेन्द्र मोदी की रैलियों में उमड़े जनसमूह का जवाब अपने घरेलू मैदान मैनपुरी में जनसैलाब जुटाकर दिया. उनका पूरा ध्यान सपा के वोट बैंक मुसलमानों और किसानों पर टिका रहा. उनका कहना रहा कि इन दोनों ने देश के विकास में सबसे ज्यादा योगदान किया है. किसानों के लिए खेती घाटे का धंधा बनती जा रही है. किसानों को फसलों का लाभकारी मूल्य नहीं मिलता. देश के सामने बड़ी चुनौतियां हैं. केंद्र सरकार इन चुनौतियों का सामना करने में नाकाम रही है. लाखों किसान मजदूर भूख से मर रहे हैं. देश में 2.10 लाख किसानों और मजदूरों की भूख से मौत हो चुकी है. उन्होंने मुसलमानों के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि दस्तकारी में मुसलमानों का बड़ा योगदान है. पूरे देश में मुसलमान सबसे गरीब, निरक्षर और पिछड़े हुए हैं. यही कारण है कि सपा पहले भी उनके साथ थी आज भी है और हमेशा रहेगी. मुसलमान और किसान ही देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. केंद्र सरकार सच्चर आयोग की रिपोर्ट को मुसलमानों के हित में लागू नहीं कर रही हैं. कांग्रेस की सत्ता में वापसी नहीं होनी है और मोदी तो सिर्फ टीवी और गुजरात तक सीमित हैं. उन्होंने वीर अब्दुल हमीद और मिसाइल मैन एपीजी अब्दुल कलाम की भी तारीफ की.

> अपने संसदीय क्षेत्र मैनपुरी में भारी जनसमूह देख मुलायम सिंह विरोधियों पर जमकर बरसे. उन्होंने बसपा सरकार की खामियों को गिनाते हुए कहा माया राज में इतनी अंधेरगर्दी थी कि जनता का एक काम नहीं हुआ. 25 हजार करोड़ रुपये बिजली का कर्ज छोड़कर चली गई. बसपा शासन में पत्थरों और स्मारकों पर धन लगाया गया. 2014 में केंद्र में तीसरे मोर्चे की सरकार बनेगी. 80 में 80 सीटें जीतकर सपा सबसे बड़े दल के रूप में उभरेगी, हम तीसरे मोर्चे की सरकार बनाने में कामयाब होंगे.

अपने संसदीय क्षेत्र मैनपुरी में भारी जनसमूह देख मुलायम सिंह विरोधियों पर जमकर बरसे. उन्होंने बसपा सरकार की खामियों को गिनाते हुए कहा माया राज में इतनी अंधेरगर्दी थी कि जनता का एक काम नहीं हुआ. 25 हजार करोड़ रुपये बिजली का कर्ज छोड़कर चली गई. बसपा शासन में पत्थरों और स्मारकों पर धन लगाया गया. 2014 में केंद्र में तीसरे मोर्चे की सरकार बनेगी. 80 में 80 सीटें जीतकर सपा सबसे बड़े दल के रूप में उभरेगी, हम तीसरे मोर्चे की सरकार बनाने में कामयाब होंगे. 17 गैरकांग्रेस, गैर भाजपा दलों की बैठक के साथ तीसरे मोर्चे के गठन की शुरूआत हो चुकी है. मोर्चे में सपा सबसे बड़ा घटक दल है. उन्होंने दावा किया कि यदि दिल्ली में सरकार बनी तो गरीबों को मुफ्त अनाज मिलेगा. सपा प्रमुख ने विधानसभा चुनाव में मैनपुरी, इटावा, कन्नौज सहित सभी संसदीय सीटें जीतने का दावा किया. उन्होंने भावुकता भरे लहजे में कहा, यहां का चुनाव हमें आप लोग लड़ाएंगे. अपने रिश्तेदारों को चिट्ठी भेजो. चुनाव गंभीरता से लेना. क्रिश्चियन ग्राउंड में उमड़ी भीड़ में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा, अब वक्त आ गया है कि जनता केंद्र में मौजूदा यूपीए सरकार एवं राज्य की समाजवादी सरकार के कामकाज की तुलना करे. उन्होंने मोदी पर कटाक्ष किया कि असली लड़ाई टीवी पर नहीं, बल्कि जमीन पर होगी. उन्होंने कहा कि आजमगढ़ रैली के बाद यह सपा की दूसरी सबसे बड़ी रैली है. प्रदेश की जनता चुनाव को तैयार है. मैनपुरी नेताजी का संसदीय क्षेत्र है, इसलिए यहां के लोगों के लिए यह कठिन परीक्षा की घड़ी है. जैसे विधानसभा में सपा को जिताया, लोकसभा में हमारा साथ दें. रैली में शरीक नगर विकास मंत्री आजम खां ने कहा कि मुजफ्फरनगर दंगों पर मुसलमानों को मुझसे शिकायत है, लेकिन मैंने मुसलमानों की वकालत में कोई कमी नहीं रखी है. मेरे लिबास में लाख पैबंद सही, लेकिन धब्बा एक भी नहीं हैं. गुजरात जैसे हालात से देश को बचाने के लिए सपा को मजबूत करना हम सबकी जिम्मेदारी है. आजम ने कहा कि कुछ ताकतें चाहती हैं कि मुसलमान सपा से नाराज हो जाएं और कातिल देश पर काबिज हो जाएं. इस साजिश को समझने की जिम्मेदारी मुसलमानों की है, जब भी सपा की सरकार बनती है, तभी ऐसा होता है, क्योंकि इस सरकार को मुसलमान अपना मानता है. मलायम सिंह ही असली जननायक हैं.

बहरहाल विपक्ष का कहना है कि मुलायम सिंह ने अपने संसदीय क्षेत्र में रैली कर हताशा और सियासी कमजोरी का सबूत दिया है. वहीं यह रैली उनकी घबराहट का प्रतीक है. अपने क्षेत्र में तो कमजोर नेता ही रैलियां करते हैं. मुलायम सिंह जान चुके हैं कि मुसलमानों में उनका प्रभाव खत्म हो रहा है. पिछड़ी जातियां उनसे नाखुश हैं. उनका जनाधार खिसक रहा है. बीजेपी नेताओं का मानना है कि नरेन्द्र मोदी का उत्तर प्रदेश की पिछड़ी जातियों पर बढ़ता प्रभाव भी मुलायम की चिंता का सबसे बड़ा कारण है. मोदी ने रैली में यदुवंशियों का जिक्र कर सपा प्रमुख की धड़कने और तेज कर दी हैं. इसीलिए मुलायम सिंह बार-बार जिक्र करते रहते हैं कि मोदी के मंसूबे पूरे नहीं होंगे. ■

feedback@chauthiduniya.com

संगीनों के साए में निपटी मोदी की रैली

राकेश चंद्र श्रीवास्तव

अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था और आतंक के साए में नरेन्द्र मोदी की विजय शंखनाद रैली 8 नवंबर को उत्तर प्रदेश के जिला बहराइच में शांतिपूर्ण सम्पन्न हुई तो शासन-प्रशासन ने राहत की सांस ली. भाजपाई आशंकित थे कि आतंक का साया कहीं यहां भी न दिखाई पड़ जाए. अगर ऐसा होता तो मोदी की रैली में भीड़ जुटाना मुश्किल हो जाता, लेकिन मोदी के चाहने वालों ने दहशत फैलाने वालों को करारा जवाब दिया. भीड़ की जुटान ने भाजपाइयों के चेहरों पर खुशी ला दी तो पटना रैली में धमाके से आहत नमो के तेवर बहराइच और भी तीखे हो गए. मोदी ने जहां देश में स्थिरता और विकास के लिए केन्द्र में भाजपा की सरकार बनना जरूरी बताया, वहीं बम बन्दूक और पिस्तौल की राजनीति करने वालों तथा इंडियन मुजाहिदीन को जड़ से उखाड़ फेंकने का संकल्प भी दोहराया.

कांग्रेस, सपा और बसपा को एक ही थाली का चट्टा-बट्टा बताते हुए उन्होंने तीनों दलों पर खूब हमला बोला और यहां तक कह दिया कि जो सत्ता के नशे में डूबे हैं, उन्हें भी संकट का एहसास है. वंशवाद की राजनीति करने वाले एक परिवार के हाथ में सत्ता होने के बाद भी यूपी का विकास नहीं हो पाया. मोदी ने भ्रष्टाचार और महंगाई के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताया. कानपुर रैली में नरेन्द्र मोदी जो चुनावी रोडमैप तय कर गए थे, बहराइच में भी उसी के अनुरूप जमकर बोले. मोदी ने न हिन्दुत्व का राग अलापा और न अयोध्या का. जबकि यहां से केवल 120 किलो मीटर दूरी पर राम की नगरी बसी हुई है. अवध प्रान्त की प्रथम रैली में अपने एक घण्टे के संबोधन में मोदी ने न तो राम मंदिर का जिक्र किया और न ही बहराइच से सटे जिले बलरामपुर से 1957 में पहली बार सांसद बने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का ही जिक्र किया. उन्होंने राम मंदिर आन्दोलन के नायक लालकृष्ण आडवानी का भी नाम नहीं लिया. हालांकि राम मंदिर नायक रहे कल्याण सिंह भी मौजूद थे, लेकिन उन्होंने भी मोदी के कसीदे पढ़ने के आलावा राम मंदिर, अटल और आडवाणी का नाम लेने से परहेज किया. सांसद योगी आदित्यनाथ ने जरूर राम मंदिर निर्माण और नेपाल सीमा पर आईएसआई की करतूतों का मुंहतोड़ जवाब देने की बात कही. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कांग्रेस, बसपा और सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि यह दल यूपी के विकास में बाधक रहे हैं. बहराइच से गोरखपुर तक कोई भी ट्रामा सेन्टर नहीं है. नरेन्द्र मोदी ने बहराइच को ब्रह्मा की नगरी और बुद्ध की तपोस्थली बताते हुए कहा कि 2001 में संगठन महामंत्री रहते हुए वे बहराइच आए थे और इसके बाद वे गुजरात के मुख्यमंत्री बने. बहराइच ऋषियों और वीरों की भूमि है, जिन्हें मैं प्रणाम करता हूं. मोदी इस रैली में राष्ट्रवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ जमकर बोले. अवध प्रान्त की इस रैली में उमड़ी लाखों की भीड़ ने सपा, कांग्रेस और बसपा को बेचैन कर दिया है. भारत नेपाल सीमा से सटे बहराइच जिले में दाऊद का खानसामा जिबराइल, आतंकी इरफान, पाक आतंकी मसरूर, फरार इंडियन मुजाहिददीन का आंतकी अफजल उस्मानी की एक सप्ताह पूर्व हुई गिरफ्तारी तथा बाद में आंतकी इरफान के फरार होने तथा नेपाल सीमा पर 10 लाख रुपये के इनामी आतंकी तहसीन अख्तर की चहलकदमी से पुलिस व खुफिया एजेंसियों के समक्ष यह चुनौती थी कि वे नरेन्द्र मोदी की रैली को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करा सकें. बहराइच से सटे नेपाल में आईएसआई की बढ़ती गतिविधियों और आतंकवाद की धमाचौकड़ी के बीच मोदी की रैली का सफलतापूर्वक सम्पन्न हो जाना किसी जादुई करिश्मे से कम नहीं है. अवध प्रांत के 16 सांसद और 82 विधायकों वाले क्षेत्र की इस रैली में मोदी का राम मंदिर और हिंदुत्व के मुद्दों पर कुछ न बोलना काफी चर्चा में रहा. इस रैली में स्थानीय मुसलमानों ने भी भारी संख्या में शिरकत की. रैली के लिए व्यपारियों ने जहां अपनी दुकानें बन्द रखीं, वहीं स्कूलों में भी आज अवकाश रहा. भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस रैली की सफलता के लिए काफी मेहनत की थी. भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अमित शाह, प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकान्त बाजपेयी पूर्व अध्यक्ष कलराज मिश्र, ओमप्रकाश सिंह, सांसद लालजी टंडन, विनय कटियार सहित स्थानीय नेताओं श्यामकरन टेकडीवाल, पूर्व मंत्री ददन मिश्रा, प्रदेश सचिव अनुपमा जायसवाल भी उपस्थित रहे. इस रैली की सफलता के लिए नेपाल के लोगों ने भी शिरकत की. हालांकि, नरेन्द्र मोदी और राजनाथ सिंह हेलीकॉप्टर से लखनऊ रवाना हो गए. लेकिन इन नेताओं का राम मंदिर और हिंदुत्व के मुद्दे पर न बोलने का निहितार्थ ढूंढा जा रहा है. मोदी की रैली सम्पन्न हो जाने से खुफिया एजेसियों और प्रशासन ने राहत की सांस ली . ■

पूर्वांचल में कांग्रेस को मिल रही चुनौती

मारकण्डेय प्रसाद सिंह

प्रदेश में फिर से सत्ता में वापसी का ख्वाब देख रही कांग्रेस को पूर्वी इत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2014 के लिए उम्मीदवार ढूंढे नहीं मिल रहे. इधर यूपी में नरेन्द्र मोदी के बढ़ते असर से कांग्रेस हाईकमान सहित पार्टी के शीर्ष नेता बेचैन दिख रहे हैं. मगर फिर भी अफरा-तफरी, भीड़-भाड़ और गरम बहस का चुनावी माहौल लगातार गरमाया हुआ है. टिकटार्थियों के घमासान से कांग्रेस के बड़े नेता छिप-छिप कर मीटिंग कर रहे हैं. कांग्रेस हाईकमान तक पहुंच रखने वाले पूर्वांचल में कांग्रेस के कद्दावर नेताओं के यहां रात 1:30 बजे तक बैठकें चल रही हैं. टिकाटार्थियों के हुजूम के छंटने की सबसे ज्यादा उम्मीद बड़े नेता कर रहे हैं. लोक सभा चुनाव आने से पहले राजनीतिक बिसात पर साइबर आपराधियों ने भी दस्तक देनी शुरू कर दी है. उत्तर प्रदेश में देवरिया जनपद के सलेमपुर में कांग्रेस हाईकमान राहुल गांधी की रैली से माहौल बना जरूर, परन्तु स्थानीय क्षत्रपों की गुटबाजी में चौपट होने का खतरा भी बरकरार है. खेमेबाजी पर अंकुश लगाने में नेतृत्व की बेबसी भी किसी से छिपी नहीं है. कांग्रेसजनों की खींचतान से सलेमपुर रैली भी अछूती नहीं रही. यह दीगर है कि राहुल गांधी के नाम पर उमड़ी भीड़ के आगे आन्तरिक विवाद गम्भीर रूप नहीं ले सका. पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलिया, गाजीपुर, देवरिया, गोरखपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संतकबीरनगर सहित आस-पास के अन्य जिलों में गुटबाजी के कमोबेश ऐसे ही हालात हैं. कई खेमे में बंटे स्थानीय कांग्रेस कार्यकताओं में तनातनी आए दिन दिखती है. इसके चलते विधानसभा चुनाव 2012 में कांग्रेस ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में अपनी कई सीटें गवां दी थीं. अब सलेमपुर को ही लें. यहां रैली तो हुई पर इतनी सफल नहीं जितनी उम्मीद थी. इसका एक मात्र कारण रहा स्थानीय नेताओं के दिल आपस में नहीं मिलते. बलिया में पूर्व मंत्री बच्चा पाठक, राजधारी सिंह व कांग्रेस में अपनी गहरी घुसपैठ रखने वाले नेता डॉ. भोला पाण्डेय के बीच का विवाद कांग्रेस की लुटिया डुबो रहा है. कमोवेश यही स्थिति पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों की है. गुटबाजी का नतीजा रहा की पूर्वांचल के अधिकांश संसदीय क्षेत्रों में पार्टी को दमदार प्रत्याशी का टोटा रहता है. वाराणसी, चन्दौली, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, बस्ती तथा आस-पास के अन्य जिलों में पार्टी भले ही कमजोर हो परन्तु कांग्रेस जनों की खेमेबाजी बेहद मजबूत है. इसकी जानकारी के बावजूद प्रदेश के कुछ नौकरशाह आज भी कांग्रेस टिकटार्थियों की लाइन में लगे दिख रहे हैं. प्रदेश में पूर्वांचल की राजनीति की प्रमुख केन्द्र माने जाने वाले कुशीनगर संसदीय सीट पर सभी की निगाहे हैं और कांग्रेस के कद्दावर नेता तथा केन्द्र सरकार में गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर है. इस संसदीय सीट पर बसपा ने संगम मिश्र को उतारा है तो सपा ने अपने ही पार्टी के विधायक राधेश्याम को उम्मीदवार बनाया है. जो भी हो लोकसभा चुनाव 2014 इस बार यहां अत्यन्त चुनौती भरा होगा.

भरोसेमंद सूत्रों के मुताबिक बदलते परिदृष्य में कांग्रेस भी अपने को बदलना चाहती है. इसके विपरीत कांग्रेस नेतृत्व ने हाल के दिनों में गैर कांग्रेसी पृष्ठभूमि के कई नेताओं को सरकार या संगठन में अहम भूमिका देकर या राज्य का ताकतवर सुबेदार बनाकर अपनी सांगठनिक सोच का संकेत दिया है. जरूरत के हिसाब से गैर कांग्रेसी पृष्ठभूमि के लोगों को पार्टी में लाकर ओहदा देने या काम का न होने पर फिर किनारे लगाने के मामले में भी कांग्रेस का कोई जवाब नहीं है. ■

मिड-डे और मनरेगा को लेकर केन्द्र-राज्य में रार

संजय सक्सेना

केन्द्र सरकार की अति महत्वाकांक्षी मनरेगा और मिड डे मील जैसी कल्याणकारी योजनाओं को लेकर दिल्ली और लखनऊ की सरकार के बीच रार बढ़ती जा रही है. आरोप-प्रत्यारोप के इस खेल में कभी सपा सरकार का तो कभी मनमोहन सरकार का पलड़ा भारी लगता है, लेकिन इसका नुकसान गरीब मजदूरों और स्कूल में पढ़ने वाले छोटे-छोटे बच्चों को भुगतना पड़ रहा है. एक तरफ केन्द्र सरकार उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना में लापरवाही का आरोप अखिलेश सरकार पर लगा रही है तो दूसरी तरफ राज्य सरकार इस बात से आहत है कि मनरेगा में इसे मांग के हिसाब से केन्द्र बजट नहीं दे रहा है, जिससे यूपी में मनरेगा ठप होने की स्थिति में पहुंच गया है. राज्य सरकार ने अपने हाथ खड़े करते हुए कहा है कि अगर वित्तीय वर्ष 2012-14 के लिए मांग के हिसाब से बजट न मिला तो मनरेगा में हो रहे तमाम काम रुक सकते हैं. प्रदेश ने तुरंत 1555 करोड़ रुपये की मांग की है, ताकि मनरेगा के काम चलता रहे. अगर ऐसा नहीं होता है तो सूबे की 52 हजार ग्राम पंचायतों में से तमाम में काम अवरुद्ध हो जाएगा. वहीं केन्द्र सरकार का रोना है कि प्रदेश मनरेगा के भ्रष्टाचार का गढ़ बन गया है. पैसा फाइलों में तो खर्च दिखाया जा रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत अलग है. केन्द्र का कहना है कि ग्रामीण इलाकों में खेती के कामों में महिलाओं की बराबर की भागीदारी दिखाई देती है, लेकिन मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी के मामले में यूपी काफी पिछड़ा हुआ है. यहां तक कि सोनिया गांधी और डिंपल यादव के संसदीय क्षेत्र में भी मनरेगा से महिलाओं को जोड़ने का काम नहीं हो पा रहा हैं. यूपी में मनरेगा में मात्र 19 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी हो रही है जो देश में सबसे कम है. बिहार जैसे राज्य में भी 30 प्रतिशत की महिला भागीदारी है, जबकि उत्तराखंड में 45 और छत्तीसगढ़ जैसे पिछड़े राज्य में यह प्रतिशत 46 है. मनरेगा गाइड लाइन की बात की जाए तो इसके अनुसार भी कम से कम 33 प्रतिशत भागीदारी महिलाओं की होनी ही चाहिए. एक तरफ मनरेगा में महिलाओं की कम भागीदारी को लेकर केन्द्र राज्य पर हमलावर है तो राज्य सरकार का कहना है कि इसके लिए केन्द्र सरकार की दोषपूर्ण बीपीएल सूची जिम्मेदार है, जिसके आधार पर जॉब कार्ड बनाए गए थे. वहीं कांग्रेसी नेता आरोप लगाते हैं कि अखिलेश सरकार मनरेगा में तमाम व्यवधान डाल कर ऐसे हालात पैदा कर देना चाहती है, जिससे यह महत्वाकांक्षी योजना फ्लाप हो जाए. मनरेगा की तरह मिड डे मील योजना भी केन्द्र और राज्य सरकार के रिश्तों में कड़वाहट घोल रही है. सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी योजनाओं के प्रति उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरह बेपरवाह है, उसका ताजा प्रमाण है केंद्र सरकार की जांच पड़ताल में राज्य में मिड डे मील योजना के क्रियान्वयान में खामियों के तथ्य सामने आना. केंद्रीय स्तर पर मिड डे मील की निगरानी के लिए बने तंत्र ज्वाइंट रिव्यू मिशन की ओर से उत्तर प्रदेश के दो जिलों में इस योजना के सभी पहलुओं की समीक्षा में जिस तरह यह सामने आया कि न तो सभी स्कूली बच्चों को भोजन मिलता है और न ही गुणवत्ता की जांच के लिए कोई प्रभावी तंत्र है. इससे स्वत: यह स्पष्ट हो जाता है कि इस योजना का क्रियान्वयन कामचलाऊ तरीके से किया जा रहा है. यह दुर्भाग्य केवल एक-दो योजनाओं की वास्तविकता तक सीमित नहीं है. कुछ ऐसा ही उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य से जुड़ी अनेक योजनाओं के संदर्भ में भी सामने आ रहा है. जब सामाजिक क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाओं का यह हाल है तो फिर यह सहज ही समझा जा सकता है कि जनकल्याण से जुड़ी अन्य अनेक योजनाओं की क्या स्थिति होगी? ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि एक ओर तो राज्य सरकार यह दावा करती है कि वह समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और दूसरी ओर यह सामने आ रहा है कि सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी योजनाओं पर ही सबसे अधिक लचर तरीके से अमल किया जा रहा है. यह स्थिति तो यही बताती है कि शासन प्रशासन में जनकल्याण से जुड़ी योजनाओं पर सही तरह अमल सुनिश्चित करने की इच्छाशक्ति ही नहीं हैं यदि ऐसा नहीं होता तो वे योनजाएं भी लचर क्रियान्वयन का शिकार नहीं होती, जिनके लिए धन की कहीं कोई कमी नहीं है. राज्य सरकार मनरेगा की तरह मिड डे मील योजना के क्रियान्वयन में गडबड़ी के संदर्भ में इस तर्क की भी आड़ नहीं ले सकती कि इसके पास समुचित तंत्र का अभाव है. मिड डे मील योजना में खामी के तथ्य पहले से जर्जर प्राथमिक शिक्षा के ढांचे पर एक और धब्बे की तरह है. यह हैरान करने वाला है कि राज्य सरकार न तो प्राथमिक विद्यालयों में पठन पाठन के स्तर को दुरुस्त कर पा रही है और न ही मिड डे मील योजना की खामियों को दूर कर पा रही है.

बहरहाल, चाहे मनरेगा हो या फिर मिड डे मील योजना या फिर केन्द्र/राज्य सरकार की स्वास्थ्य संबंधी स्कीमें, इससे गरीबों को भले ही कोई फायदा न मिला हो लेकिन नेताओं और नौकरशाहों के लिए यह योजनाएं सोने का अंडा देने वाली रहीं. इन योजनाओं में भ्रष्टाचार के कारण कई अधिकारियों और कर्मचारियों को जान से हाथ छोना पड़ गया तो तमाम नेता जेल की सलाखों के पीछे चले गए. हजारों करोड़ का बंदरबांट करके सबने खूब माल कमाया. तब न केन्द्र को उसकी सुध आई न राज्य सरकार को चुनावी बेला में ढिंढोरा पीटा जा रहा है. ■

feedback@chauthiduniya.com

मनरेगा के मजदूर तलाशेंगे लुप्तप्राय नदियां

संदीप कश्यप

उत्तर प्रदेश सरकार ने मनरेगा योजना के अंतर्गत राज्य के सभी जिलों में लुप्तप्राय नदियों (छोटी सूखी नदियों/बड़ी नदियों की स्थानीय सहायक नदियां) और जलस्रोतों को पुनर्जीवित करने का बीड़ा उठाया है. ग्राम्य विकास विभाग को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है.जिलाधिकारियों के माध्यम से प्रत्येक जिले में खतरे में पड़े उपलब्ध जलस्रोतों एवं लुप्तप्राय नदियों का सर्वेक्षण शीघ्र पूरा करके मनरेगा के माध्यम से उन्हें पुनर्जीवित करने का कार्य शुरू किया जाएगा. मनरेगा के अपर आयुक्त रंजन कुमार ने बताया कि मनरेगा के अन्तर्गत जनपद फतेहपुर में ससुर खदेरी प्रथम एवं ससुर खदेरी द्वितीय नाम से दो स्थानीय नदियां प्रवाहित होती है, जिनका फैलाव 04 विकास खण्डों में फैला है. जनपद में दोनों नदियों का प्रवाह क्षेत्र की लम्बाई लगभग 46 किमी है, जिसके पश्चात उक्त नदियां यमुना नदी में समाहित हो जाती है. इस 46 किमी के विस्तार में कई स्थान ऐसे है, जहाँ नदी के लिए पर्याप्त गहराई एवं किनारे अवशेष नहीं थे, जिसके कारण समय के साथ-साथ नदी के अस्तित्व पर न सिर्फ अत्याधिक बुरा प्रभाव पड़ा अपितु आस-पास के क्षेत्रों को भी तमाम जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ता था. उक्त क्षेत्रों में जलभराव एवं कतिपय क्षेत्रों में जल स्तर के बहुत अधिक गिरने की समस्या भी होती थी. श्री रंजन कुमार ने बताया कि इसके लिए 12.8 करोड़ की परियोजना विस्तृत प्लानिंग के अन्तर्गत बनाई गई और इसे अलग-अलग चरणों में क्रियान्वित करने का निर्णय लिया गया. इसके लिए पूरी वर्क साइट को चिन्हित कर पृथक-पृथक प्रभारी नियुक्त किए गए हैं. परियोजना के विस्तार का अनुमान इस आंकड़े से लगाया जा सकता है कि इसमें प्रतिदिन 1000 से 1500 श्रमिकों द्वारा कार्य किया गया. झील से सम्बन्धित परियोजना पर अब तक लगभग 38000 मानव दिवस सृजित किये जा चुके है एवं लगभग 78,200 क्यूबिक मी मड को बाहर निकाला जा चुका है. इसी प्रकार नदी से सम्बन्धित परियोजना पर लगभग 96,900 मानव दिवसों का सृजन किया गया है एवं 186400 क्यूबिक मी मिट्टी की खुदाई की जा चुकी है. मनरेगा के अन्तर्गत इतने विस्तृत परिक्षेत्र में कार्य कराए जाने का समस्त भारत में यह एक अलग उदाहरण है एवं इसकी सराहना भारत सरकार के स्तर पर भी की जा रही है. मनरेगा के अधिकारी कहते हैं कि इस परियोजना के क्रियान्वयन से विस्तृत प्रभाव छोड़ने वाले लाभ हुए हैं यथा- जनपद के ऐसे गाँव जो पिछले वर्षो में जलमग्न हो जाते थे, में इस वर्ष सामान्य जीवन निर्वहन किया गया. ऐसे कई गांव देखे गए हैं जहाँ जलाभाव के कारण धान की खेती नहीं की जा सकती थी वहां इस साल धान की पौध लगाई गई है एवं क्षेत्र में अच्छी खेती दिखाई पड़ रही है. झील में जल के ठहराव के कारण स्थानीय जल स्तर में भी प्रभावी सुधार हुआ है. झील में इस वर्ष वर्षा ऋतु में लगभग 90,000 क्यूबिक मी पानी संरक्षित हुआ है. मनरेगा योजनान्तर्गत ऐसी परियोजनाओं को अन्य जनपदों में भी क्रियान्वित करने के लिए जनपद स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित/प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे सामान्य जन के लाभार्थ एवं दूरगामी स्थायी परिणाम देने वाले ऐसी परियोजनाओं को अधिक से अधिक स्थानों पर क्रियान्वित किया जा सके. ■

नहीं रुक रही नेपाल सीमा पर तस्करी

दशरथ प्रसाद यादव

तुलसीदास ने लिखा है- जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा. मगर सुरसा के शरीर से निकलने के रास्ते बनाने के लिए अति लघु रूप में हनुमान ने अपना काम बना लिया था. यह बात बस्ती, सिद्धार्थनगर, महराजगंज, गोरखपुर क्षेत्र में सक्रिय उन लोगों के लिए उपयुक्त बैठती है जो नेपाल-भारत सीमा के आरपार तस्करी कर पैसा बटोरने में लगे हैं. ऐसा नहीं है कि सीमा पर चौकसी कम है. चौकसी तो खूब बढ़ी है. बढ़नी-अलीगढ़वा से लेकर सोनौली एवं बिहार तक एसएसबी के जवान लगे हुए हैं. ऊपर से बस्ती, गोरखपुर मण्डल की पुलिसिंग भी हैं. लेकिन तस्करी में लगे लोग जैसे-जैसे अपने रूप को बढ़ाने में लगे रहे हैं वैसे -वैसे ही व्यवस्था भी बढ़ी लेकिन तब झट से बतर्ज हनुमान जी लघुरूप करके इसी व्यवस्था के मुंह में घुसकर वे अपने मकसद में कामयाब भी होते जा रहें हैं. बीस पच्चीस वर्ष पहले सोनौली के खुले मार्ग से सोने के जेवरात पहनाकर दुल्हन या स्त्री के माध्यम से सोना लाने की बात हो या किसी कार में तस्करी कर सोना लाते वक्त वे हादसे में कई किलो सोना के बन्दरबाट की कहानी कथित तौर पर तैरती रहती थी जिससे जुड़े लोग आज भी इससे लाभान्वित होते बताए जाते हैं लेकिन इस पूरे क्षेत्र से मानव तस्करी के साथ सोने की तस्करी बदस्तूर जारी है.

> साधु बाबा की बात पर चाहे सोना खोजिये या न खोजिये पर नेपाल सीमा पर सोना खोजेंगे तो जरूर कुछ न कुछ मिलेगा ही. लेकिन जहां तक सोनौली बार्डर की बात है, बताया जाता है कि चालू वर्ष एवं पिछले एक साल में तीन करोड़ से अधिक की धनराशि की सोने की तस्करी पकड़ में आई. कितनी धनराशि का सोना निकल गया . इतने अधिक सोने की तस्करी का माल पकड़ में आने से सुरक्षाकर्मियों में भी सनसनी तो रहती ही है. हां, क्षेत्र की जनता में हैं मस्ती चाहे वह गोरखपुर, महराजगंज, या हो मण्डल बस्ती.

साधु बाबा की बात पर चाहे सोना खोजिए या न खोजिऐ पर नेपाल सीमा पर सोना खोजेंगे तो जरूर कुछ न कुछ मिलेगा ही. अब बढ़नी के लोग बताने से रहे लेकिन जहॉ तक सोनौली बार्डर की बात हैं बताया जाता हैं कि चालू वर्श एवं पिछले एक साल में तीन करोड़ से अधिक की धनराषि की सोने की तस्करी पकड़ में आयी. कितनी धनराषि का सोना निकल गया – खुदा जाने. इतनी अधिक सोने की तस्करी का माल पकड़ में आने से सुरक्षाकर्मियों में भी सनसनी तो रहती ही हैं. हॉ, क्षेत्र की जनता में हैं मस्ती चाहे वह गोरखपुर, महराजगंज, या हो मण्डल बस्ती. पिछले कई साल में मूल्य भाव के नाते सोने की तस्करी रुकी थी. फिर भी सीमावर्ती क्षेत्रों में दोनों ओर के नवधनाड्यों की संख्या बढ़ती ही जा रही हैं, जो सोचनीय हैं.

यदि देखा जाए तो नेपाल से भारत को सोने की तस्करी वर्श 1912 से बढ़ती ही गयी हैं. ऑकडो के अनुसार वर्श 1912 में सितम्बर माह में काठमाण्डू से दिल्ली बस से लगभग 62 लाख रूपये मूल्य का सोना सुरक्षाकर्मियों ने पकडा था. बीच – बीच में थोड़ी बहुत पकड़ धकड़ तो चलती रही. आठ अगस्त 1913 को सोनौली कस्टम की टीम ने 36 सोने के बिस्कुट पकड़े थे. यह सोना गुजरात निवासी यतीन कुमार हरसुख लाल के पास पकड़ा गया था. लगभग 1 करोड़ 20 लाख रूपये मूल्य के सोने के साथ ही 30 अगस्त को महाराष्ट्र निवासी राजा राम डगडू सावंत के पास से 7 लाख रूपये का सोना पकड़ा गया. अक्टूबर माह में गांधी जयन्ती के दिन केरल निवासी नित्योजाव के पास से लगभग 1 लाख 28 हजार रूपये का सोना पकडा गया तो 16 अक्टूबर 1913 को गोरखपुर निवासी पति पत्नी लाट दम्पत्ति को ठूठी बारी सीमा पर 34 लाख रूपये मूल्य के साथ पकड़ा गया. अभी एक सप्ताह पूर्व 25 अक्टूबर को गोरखपुर इंदिरा बाल बिहार के पास नौतनवा निवासी पंकज जायसवाल को पकड़ा गया. कस्टम ने उनके पास से 32 लाख रुपये का सोना बरामद किया. 27 अक्टूबर 1913 को दिल्ली काठमाण्डू नेपाली टूरिस्ट बस से लगभग 25 लाख रूपये का सोना आदि बरामद किया गया. यह स्थिति वास्तव में एएलार्मिगं हैं.

अब यह तो पकड़े गए सोना की स्थिति है. जिसे नही पकड़ा जा सका वह इसमें कहां? इसकी चिन्ता किसी न किसी को करनी ही चाहिए. बढ़नी से लेकर अली-गढ़वा, सोनौली ठूठीबारी के मार्ग से कोरियर का काम करने वालों पर नजर रखने की जरूरत है. यह कार्य क्षेत्रीय जनता एवं स्थानीय पुलिस के सहयोग से हो सकता हैं. बेहतर हो कि क्षेत्र में बढ़ते नवधनाड्यों को चिन्हित किया जाय और उनकी गति विधियों को भी. उनके गोरखपुर दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता, पटना, लखनऊ के कनेक्शन्स को भी खंगाला जाय इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर कस्टम, एसएसबी, स्थानीय पुलिस के साथ दोनों देशों के काउन्टर पार्ट के बीच समन्वय और तालमेल बने तो अंकुश लग सकता है. ■

> भाजपा ने चुनाव में जनता से वायदा किया था कि सत्ता में आते ही आयोग गठित कर तीन महीने के भीतर जांच पूरी कराकर दोषियों को सजा देंगे. जांच आयोग गठित हुए, तीन करोड़ रुपया खर्च हुआ. न जांच पूरी हुई और न ही किसी को सजा मिली और 56 घोटालों का डर दिखाकर भाजपा ने अपने पांच साल पूरे कर डाले. 2012 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का मुख्य मुद्दा भाजपा के पांच साल के घोटाले ही थे.

उत्तराखंड में घोटालों की बाढ़

राजकुमार शर्मा

जिस उत्तराखंड को लोग देवभूमि अथवा वीरभूमि के नाम से जानते थे, अपने 13 वर्ष की उम्र में लोग अब इस प्रदेश को भ्रष्टाचार और घोटालों के लिए जानते हैं. उत्तराखंड में जिन लोगों पर भ्रष्टाचार से लड़ने की जिम्मेदारी थी, उन्हीं के दामन दागदार निकले. जांचों की रस्मअदायगी हुई, न तो किसी पर आंच आनी थी, न ही किसी पर आई. अलबत्ता कांग्रेस-भाजपा में नूराकुश्ती खूब लड़ी गई. बारी-बारी से सत्ता में रही भाजपा और कांग्रेस ने एक दूसरे को बचाने का ही काम किया, करोड़ों खर्च के बावजूद न कोई दोषी कानून की गिरफ्त में आया और न ही किसी ने सबक लिया. राज्य की उम्र बेशक कम हो, भ्रष्टाचार के मामलों में इसने पुराने राज्यों को भी पीछे छोड़ दिया. 13 सालों में दर्जनों घोटालों ने प्रदेश को पीछे धकेला. यहां भ्रष्टाचार में सियासी मिलीभगत का लंबा सिलसिला है. 2007 के विधानसभा चुनाव में भाजपा का मुख्य चुनावी मुद्दा कांग्रेस सरकार के 56 घोटालों का था.

भाजपा ने चुनाव में जनता से वायदा किया था कि सत्ता में आते ही आयोग गठित कर तीन महीने के भीतर जांच पूरी कराकर दोषियों को सजा देंगे. जांच आयोग गठित हुए, तीन करोड़ रुपया खर्च हुआ. न जांच पूरी हुई और न ही किसी को सजा मिली और 56 घोटालों का डर दिखाकर भाजपा ने अपने पांच साल पूरे कर डाले. 2012 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का मुख्य मुद्दा भाजपा के पांच साल के घोटाले ही थे. कांग्रेस ने भी वायदा किया था कि सैफ विंटर गेम से लेकर महाकुंभ, सिटूर्जिया घोटालों के लिए अलग से जांच आयोग गठित होगा और छह महीने भीतर दोषियों को चिन्हित कर अभियोजन चलाया जाएगा. पहले भाटी आयोग बना, आयोग के अध्यक्ष केवलराम भाटी को राजनीतिक कारणों से इस्तीफा देना पड़ा. उसके बाद उनकी जगह त्रिपाठी आयोग गठित हुआ. इस मामले में कांग्रेस भी भाजपा की राह पर है. सत्ता में आए दो साल बीत गए, नतीजा

ढाक के तीन पात ही रहा. मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा घोटालों के आरोपी निशंक से गलबंहिया किए घूम रहे हैं. यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भ्रष्टाचार का दंश झेल रहे राज्य को पेशे से जज रहे विजय बहुगुणा को जनता के साथ न्याय करने की जिम्मेदारी सौंपी थी. जज साहब अपने नामी गिरामी पिता पहाड़ के चंदन हेमवती नन्दन के नाम पर भी कालिख उड़ेलने में कोई कोर कसर नही छोड़ रहे हैं. भाजपा के प्रति उनकी मेहरबानी की वजह से जनता उनके लिए चोर-चोर मौसेरे भाई की कहावत कहती है.

राज्य का दून कचहरी स्थित शहीद उद्यान राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर उन प्रदर्शनकारीयों से पटा रहा, जिन्होंने राज्य निर्माण के लिए कुर्बानी दी थी. आज वही लोग जनता की मूलभूत सुविधाओं के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे थे. उत्तराखंड राज्य आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाली मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा की चाची अंशी बहुगुणा को अपनी पहचान, सम्मान और पेंशन के लिए एक बार फिर धरने और प्रदर्शन का सहारा लेना पड़ रहा है. इसके लिए आत्मदाह करने भी वे तैयार हैं, ताकि शायद इसके बाद मुख्यमंत्री की आंखें खुलें. उन्हें सबसे ज्यादा दु:ख इस बात का है कि अब उनका भतीजा उन्हें पहचानता भी नहीं है. जब दून में लोग जश्न की तैयारी कर रहे थे तब अंशी चाची खुले आसमान में धरना दे रही थीं.

उत्तराखंड को अलग करने की मांग के पीछे बड़ी वजह पहाड़ के युवाओं को रोजगार न मिलना और पलायन रही. राज्य बनने के 13 साल बाद ये समस्याएं घटी नहीं और विकराल होती गईं. आज स्थिति यह है कि पहाड़ पर गांव के गांव खाली होकर खंडहर हो रहे हैं, जबकि सात लाख से अधिक युवा आज भी नौकरी की बाट जोह रहे हैं. राज्य बनने के बाद पहाड़ों में पूंजी निवेश और बेरोजगारी की स्थिति चौंका देने वाली है.

सरकार के उद्योग निदेशालय की एक रिपोर्ट यह कहती है कि उत्तराखंड में अब तक 7739 करोड़ का पूंजी निवेश हुआ और 1,59,660 लोगों को रोजगार मिला, पर्वतीय जिलों की स्थिति दयनीय है. पहाड़ी जनपदों में रुद्रप्रयाग में 827 उद्योग लगे, जिनमें 2137 लोगों को रोजगार मिला. इसी तरह चंपावत में 752 उद्योगों में 1665 युवाओं को रोजगार मिला. जबकि बागेश्वर में 716 उद्योग लगे और 1510 लोगों को रोजगार मिला. अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, पौड़ी, टिहरी, चमोली और उत्तरकाशी में बेरोजगारी का आंकड़ा 30 हजार से 60 हजार तक है. राज्य गठन के बाद पर्वतीय जिलों की पूरी तरह अनदेखी हुई. थोड़ा बहुत विकास जो हुआ वह मैदानी जिलों हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर और देहरादून तक ही सिमटकर रह गया. जनता विकास को तरसती रही और इन 13 वर्षों में मंत्री और अफसर विदेशों की सैर करते रहे.

राज्य आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि देने शहीद स्थल पहुंचे मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा का विरोध कर रहे आंदोलनकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. वन अधिकार कानून लागू करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर पंडित दीनदयाल पार्क में तीन दिन से उपवास कर रहे महिला मंच के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को शहीद स्थल के अंदर प्रवेश न करने देने का ऐलान किया था. इसके लिए वे शहीद स्थल के गेट पर बैठ गईं. पुलिस से महिला मंच के करीब 25-30 महिला व पुरुष कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री के पहुंचने से पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. पुलिस ने कुछ ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया जो शहीदों को श्रद्धांजलि देने शहीद स्थल आए थे. राज्य आंदोलनकारियों ने स्थापना दिवस पर आंदोलनकारियों की गिरफ्तारी की तीव्र भर्त्सना की है. उन्होंने कहा कि राज्य के लिए लाठी-डंडे खाने वाले आंदोलनकारियों को स्थापना दिवस पर गिरफ्तार करना आंदोलनकारियों का अपमान है. ■

सांसद निधि खर्च करने में राज्यलक्ष्मी सबसे आगे

रेनु शर्मा

आम चुनाव निकट आते-आते प्रदेश के लोकसभा सांसदों की सांसद निधि के खर्च में जबरदस्त उलटफेर हो रहा है. 29 अगस्त तक जहां केंद्रीय मंत्री व हरिद्वार सांसद हरीश रावत खर्च में सबसे आगे थे, वहीं करीब सवा दो महीने में 10 नवम्बर तक के आंकड़ों के मुताबिक माला राज्यलक्ष्मी शाह पहले, हरीश रावत दूसरे, केसी सिंह बाबा तीसरे, प्रदीप टम्टा चौथे और सतपाल महाराज फिर से अंतिम स्थान पर हैं. सांसद निधि को लेकर यह ट्रेंड भी देखा जाता रहा है कि चुनाव बहुत करीब आने पर चुनाव में ज्यादा से ज्यादा लाभ लेने के लिए सांसद निधि अंतिम समय पर ही खर्च करते हैं. बहुत संभव है कि ज्यादातर सांसद अंत में ही यह धन खर्च करवाने के लिए जोर लगाएं. वैसे सांसद निधि के खर्च को इस बात का पैमाना माना जा सकता है कि प्रदेश का कौन सा सांसद अपने क्षेत्र के विकास को लेकर कितना गंभीर है. इस नजरिये से देखा जाए तो भाजपा सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह सबसे तेज साबित हुई हैं. केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडीएस-एमपी लैड्स) के ताजा आंकड़ों के मुताबिक टिहरी से भाजपा सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह 81.22 फीसद सांसद निधि का इस्तेमाल करवा कर पहले स्थान पर हैं. केंद्रीय जल संसाधन मंत्री व हरिद्वार के सांसद हरीश रावत 71.76 फीसद उपयोग के साथ दूसरे स्थान पर खिसक गए हैं, जबकि नैनीताल के कांग्रेसी लोकसभा सांसद केसी सिंह बाबा अपनी सांसद निधि का 68. 93 फीसद इस्तेमाल कर तीसरे स्थान पर हैं. अल्मोड़ा सांसद प्रदीप टम्टा 65.57 फीसद सांसद निधि इस्तेमाल कर चौथे स्थान पर हैं. गढ़वाल सांसद सतपाल महाराज के सांसद निधि के खर्च में जरा सा भी सुधार नहीं हुआ है. वे प्राप्त कुल निधि के 36.78 फीसद इस्तेमाल कर फिर से सबसे पीछे हैं. सांसद निधि के इस साल 29 अगस्त तक के आंकड़ों के हिसाब से सतपाल महाराज 36.78 फीसद खर्च के साथ पांचवें नंबर पर ही थे. हरीश रावत 102.96 फीसद खर्च के साथ पहले, माला राज्य लक्ष्मी शाह 70.96 फीसद खर्च के साथ दूसरे, प्रदीप टम्टा 65.30 फीसद खर्च के साथ तीसरे, केसी सिंह बाबा 44.52 प्रतिशत खर्च के साथ चौथे स्थान पर थे. ■

सोनिया-राहुल को मिल सकती है संजय से चुनौती

अजय कुमार

अमेठी (सुल्तानपुर) के राज घराने से संबंध रखने वाले कांग्रेसी और सुल्तानपुर के सांसद संजय सिंह एक बार फिर भगवा रंग में रंगने जा रहे हैं. भाजपा आलाकमान ने कभी दस जनपथ के करीबी रहे संजय को भगवा चोला पहना कर गांधी परिवार के खिलाफ ही मोहरा बनाने की ठानी है. काफी समय से कांग्रेस में अपने आप को हाशिये पर महसूस कर रहे संजय सिंह ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए करीब-करीब भाजपा से हाथ मिला लिया है, बस कुछ मुद्दों पर बात होनी बाकी रह गई है. इस आधार पर कहा जा सकता है कि 2014 के आम चुनाव में यदि अमेठी में राहुल गांधी के खिलाफ ताल ठोंकते और रायबरेली में सोनिया के विरुद्ध प्रचार करते दिखें तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए. संजय सिंह को लेकर भाजपा का उत्साह ऐसे ही नहीं परवान चढ़ रहा है. उसे पता है कि संजय सिंह के परिवार को यहां बेहद सम्मान पूर्वक देखा जाता है, इसी के बल पर वह गांधी परिवार की तमाम कोशिशों के बाद भी 1998 में कैप्टन सतीश शर्मा को यहां धूल चटा चुके हैं. सोनिया गांधी के खिलाफ भी करीब डेढ़ लाख से ज्यादा वोट तक जुटाने में सफल रहे थे.

272 का जादुई आंकड़ा छूने को बेताब भाजपा संजय सिंह के सहारे सोनिया-राहुल को घेरना चाहती है, ताकि मजबूर होकर दोनों को अपने संसदीय क्षेत्र में अधिक से अधिक समय देना पड़े. कहा जाता है कि इस संबंध में नरेन्द्र मोदी ने भी हामी भर दी है. बस, एक पेंच फंस रहा है. संजय सिंह अमेठी में राहुल के खिलाफ चुनाव लड़ने और सोनिया के खिलाफ प्रचार के एवज में अपने राजनैतिक भविष्य की गारंटी चाहते हैं. भाजपा नेता कह रहे हैं कि अगर वह चुनाव जीते और केन्द्र में भाजपा की सरकार बनी तो उन्हें मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन संजय सिंह का मानना है कि राहुल को हराना आसान नहीं होगा. ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है. इसीलिए वह शिकस्त की दशा में राज्यसभा की सदस्यता की गारंटी चाहते हैं. बस यही पेंच उलझा हुआ है. भाजपा ने अभी इस संबंध में कोई फैसला नहीं किया है.

दरअसल, करीब आने के पीछे संजय सिंह और भाजपा दोनों की ही अपनी-अपनी मजबूरी है. कांग्रेस के दूर होकर संजय के पास भाजपा में जाने के अलावा अन्य कोई ठोस विकल्प नहीं है, वहीं भाजपा को भी सोनिया-राहुल को चुनौती देने के लिए संजय सिंह से अच्छा नेता नहीं मिल सकता है. संजय सिंह के भाजपा में आने की चर्चा तो काफी दिनों से चल रही थी, परंतु इस चर्चा को पंख तब लगे जब गत दिनों अमेठी के भूपति भवन में संजय सिंह के जन्म दिन समारोह में कांग्रेस के एक-दो चेहरों के अलावा बड़ी संख्या में भाजपा नेताओं की उपस्थिति देखी गई. हालांकि जब सांसद संजय सिंह और पत्नी अमिता सिंह से इस संबंध में बताया कि यह पारिवारिक कार्यक्रम था, इसमें इनके घर के लोग शामिल हुए थे, इसे राजनीति से जोड़कर नहीं देखा जा सकता है. वहीं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विजय पाठक ने इस संबंध में कहा कि मोदी की लोकप्रियता के बाद तमाम लोग पार्टी में आना चाहते हैं, पर संजय सिंह के भाजपा में आने के संबंध में उन्होंने किसी भी तरह की जानकारी से इन्कार किया. ■

वोटबैंक की जुबानी जंग कर रहे हैं नेता

शिवनाथ चतुर्वेदी

लोकसभा चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है, देश के विभिन्न भागों में सियासी हमले तेज होते जा रहे हैं. शीर्ष नेताओं में आपसी जुबानी जंग तेज हो गई है. मीडिया और राजनैतिक क्षेत्र में इन हमलों को दंगा बताया जा रहा है. ऐसा महसूस किया जा रहा है कि कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों की केन्द्र एवं राज्य सरकारों ने मुस्लिम वोट बैंक के मिशन पर कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है. इस मिशन 2014 के लिए हिन्दू-मुस्लिम समुदाय को चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, इसमें सर्वाधिक भयावह स्थिति यह है कि पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकी मुस्लिम बहुल क्षेत्र में घुसपैठ कर देश में गृहयुद्ध का वातावरण बनाने में लगे हैं. सरकार देश की सीमा सुरक्षा और आन्तरिक सुरक्षा दोनों से खिलवाड़ कर रही है. किश्तवाड़ और पुलवामा में हिन्दू समाज पर बर्बर हमले तुरन्त बाद मुजफ्फरनगर में एक सामाजिक मसले पर पंचायत से घर लौट रहे हिन्दू समुदाय पर हमले के बाद प्रतिक्रिया नें प्रदेश का माहौल दंगों में बदल दिया. इस दंगे में दोनों समुदाय की जान-माल की हानि हुई और सर्वाधिक नुकसान सांप्रदायिक सद्भाव का हुआ. दंगा पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाने की बजाय कांग्रेस, सपा, बसपा, जदयू, कम्युनिस्ट अपने चुनावी मिशन 2014 के तहत हिन्दू मुस्लिमों के बीच दरार को चौड़ा करने में लग गए. इस हमले के मूल में जाने के बजाय इन लोगों ने हमले के लिए हिन्दू संगठनों पर आरोप लगाने शुरू कर दिए ताकि मुस्लिम समाज में हिन्दू संगठन के प्रति भय का वातावरण व्याप्त हो. स्मरण रहे कि ठीक इसी प्रकार गुजरात में साबरमती एक्सप्रेस में हिन्दू यात्रियों को सामूहिक जिन्दा जलाए जाने पर इन छद्म धर्म निरपेक्षी राजनीतिज्ञों नें हत्या के दोषियों पर पर्दा डालने की कोशिश कर इसे दुर्घटना बताकर इसके लिए हिन्दू संगठनों को दोषी ठहराया था. जिसकी प्रतिक्रिया में गुजरात दंगा हुआ और इसके लिए नरेन्द्र मोदी को आज तक कोसा जाता है. तब आज क्यों नहीं उमर अब्दुल्ला और अखिलेश यादव को इसके लिए जिम्मेदार माना जा रहा है, क्या उन दंगों पर केन्द्र सरकार ने अपने दायित्वों का निर्वहन किया? दंगा ग्रस्त क्षेत्रों में एके-47 हथियारों के मिलने के बावजूद तलाशी क्यों रोकी गई? दंगे के समय पुलिस और पीएसी को दंगाइयों पर फायरिंग किए जाने के निर्देश क्यों नहीं दिए गऐ? प्रदेश के मुख्यमंत्री केवल एक समुदाय के आंसू पोंछने क्यों गए? जो लोग अत्याधुनिक हथियारों का जखीरा रखे हुए हैं, उनके विरुद्ध कार्यवाही क्यों नही की जा रही है? किस्तवाड़ घटना पर पर्दा क्यों डाला गया? मुस्लिम समुदाय के बीच छिपे पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादियों की धर-पकड़ क्यों नही की जा रही? इन अनुत्तरित प्रश्नों की प्रकृति पर यदि दोनों समुदाय के लोग विचार करते हुए लोक सभा चुनाव 2014 में अपने मताधिकार का प्रयोग करें तो दंगों को भड़काने वाले मिशन 2014 का पर्दाफाश हो जाएगा. इतना ही नहीं, इस निराशापूर्ण माहौल में जो जागरूक लोग हैं, उन्हें सामने आना चाहिए और अपने सक्रिय कार्यक्रमों द्वारा एक सही विकल्प के विकास का वातावरण तैयार करना चाहिए. लोक सभा चुनाव 2014 के बाद देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, यह कहना अभी यथोचित न होगा, मगर भारतीय जनता पार्टी अपने प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित कर विधिवत लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है. नरेन्द्र मोदी ने अपना राष्ट्रव्यापी दौरा शुरू कर दिया है. पूरे देश में मोदी को लेकर बहस शुरू हो गई है कि वे प्रधानमंत्री होंगे या नहीं. अगर होंगे तो वे कैसे प्रधानमंत्री साबित होंगे. नरेन्द्र मोदी के विकल्प के तौर पर ले देकर राहुल गांधी के नाम की चर्चा हो रही है, पर राहुल अपने अर्न्तविरोधी और भावुक भाषणों के कारण मजबूत स्थिति बना पाने में सफल नहीं हो पा रहे एवं मोदी भी भावुकता का कम सहारा नहीं ले रहे है, जगह-जगह अपने को गरीब परिवार की पृष्ठिभूमि को साबित करने के लिए अपने चाय बेचने के अतीत का स्मरण कराना वे नहीं भूल रहे. सवाल यह है कि देश में बेरोजगारों की फौज तेजी से बढ़ रही है. चहुंओर भ्रष्टाचार तेज उड़ान भर रहा है. इन सब सवालों पर हमारे नेता संजीदा नहीं वे अपनी रैलियों में लगे हैं. जन समस्याओं के खत्म करने के अपने प्रारूप पेश करने की जगह आपस में एक-दूसरे पर कीचड़ उछालने में ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं.

जनतांत्रिक व्यवस्था में यह बातें परेशान करने वाली हैं, लेकिन परेशानी इन बातों से भी है जो चुनावी सभाओं में हमारे नेता करते हैं. उम्मीद की जाती है कि नेता जनता को यह बताएं कि देश के सामने खड़ी समस्याओं से निपटने के लिए उनके पास क्या दृष्टि है? लेकिन यह बातकहीं नहीं दिखायी देती है. यह प्राणशक्ति इमानदारी से आती है और हमारी त्रासदी यह है कि हमारे देश में इमानदार नेतृत्व का अभाव है. एक नेता आता है अपनी पारिवारिक त्रासदी और शहादत की दुहाई देकर हमारी संवेदना जीतने की बात करने लगता है. वह यह नहीं समझना चाहता है कि शहादत अनमोल होती है इसकी कीमत न लगायी जा सकती है और न चुकाई जा सकती है. एक और नेता पचास साल का कार्य 5 साल में करने की बाते करने लगता है, इसकी बाते सुनने में जरूर अच्छी लगती है लेकिन यह नहीं बताता है कि यह जादू कैसे होगा? हमारी चुनावी राजनीति की त्रासदी यह भी है कि बुनियादी मुद्दों की बात हमारा नेतृत्व नहीं कर रहा है वह सिर्फ मुद्दे लपकता दिखायी दे रहा है. पिछले कुछ दिनों में शहजादे और प्रधानमंत्री पद के इम्मीदवार मोदी के बीच मुद्दे लपकने वाले इस राजनीति में रस्साकसी का खेल देश ने खूब देखा है. उम्मीदवार को शाहजादे का अपनी मां के आंसुओं की बात करना गलत लगता है पर चाय बेंचने वाले अपने बचपन को दुहाई देकर गरीबी की भुनाव में कुछ भी गलत नहीं लगता. इन्दिरा गांधी की हत्या के बाद सिक्खों पर हुए अत्याचार की बात तो इन्हें याद रहती है पर 10 साल पहले गुजरात में हुई साम्प्रदायिक हिंसा को वह याद नही रखना चाहते. इस तरह की बाते याद रहनी चाहिये ताकि हम इस बारे में सावधान रहे और ऐसा फिर कभी न हो. लेकिन आम चुनाव की डेहरी पर खड़े देश में जो बातें न भूलना जरूरी है वह यह है कि देश की जरूरत समतावादी समाज है जिसमें सबको आगे बढ़ने का समुचित अवसर मिले. देश की जरूरत है कि समन्वित विकास, एक स्वस्थ्य और प्रगतिशील समाज का निर्माण इन मुद्दों पर हमारा नेतृत्व बात क्यों नही करता? देश को आज जमीनी मुद्दों से जुड़े ठोस चिन्तन करने वाले नेतृत्व की आवश्यकता है.

चौथी दुनिया
आवश्यकता है
संवाददाता, विज्ञापन प्रतिनिधि, प्रसार प्रतिनिधि
चौथी दुनिया के लिए उत्तराखण्ड के सभी मंडल और जिला मुख्यालयों पर अनुभवी संवाददाताओं, विज्ञापन, प्रसार प्रतिनिधियों एवं एजेंसियों के लिए शीघ्र आवेदन करें.
E-mail- konica@chauthiduniya.com
arifali@chauthiduniya.com
चौथी दुनिया F-2, सेक्टर 11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर)
उत्तर प्रदेश-201301,
PH : 120-6450888, 6451999

उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के सभी ज़िलों में वितरण एवं विज्ञापन के लिए संपर्क करें : 0120-6450888, 6451999, मोबाइल : 09266627379